



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276535
CG-DL-E-26092026-276535

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948
No. 569]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त 2026

परिषद् की रिपोर्ट

फा. सं. 104/46/लेखा-1. —

(क) परिचय

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई/संस्थान) की परिषद्, कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 18 की उप-धारा (5बी) की अपेक्षाओं के अनुरूप 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष में संस्थान के कामकाज से संबंधित अपनी 46वीं वार्षिक रिपोर्ट और इसके साथ समेकित लेखों का लेखापरीक्षित लेखा-विवरण एवं इन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

परिषद् द्वारा 19 जनवरी, 2026 से सीएस पवन जी. चांडक और सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर को क्रमशः संस्थान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।

परिषद् की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान परिषद् द्वारा 12 बैठकें आयोजित की गईं।

समितियों का गठन

परिषद् द्वारा गठित विभिन्न स्थायी, गैर-स्थायी समितियों और बोर्ड का विवरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-क में दिया गया है। आयोजित बैठकों और बैठकों में परिषद् और समितियों/बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा परिशिष्ट-ख में दिया गया है।

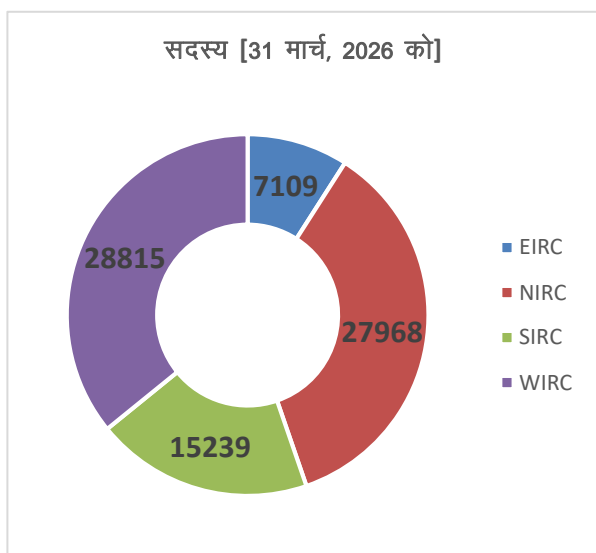
आकड़ों की एक झलक

रिपोर्ट की अवधि के लिए सदस्यों और विद्यार्थियों के क्षेत्रवार आंकड़े निम्नानुसार हैं:

सदस्य					
निम्नानुसार	ईआईआरसी	एनआईआरसी	एसआईआरसी	डब्ल्यूआईआरसी	कुल
31.03.2026	7109	27968	15239	28815	79131
31.03.2025	7009	26998	14132	26969	75108

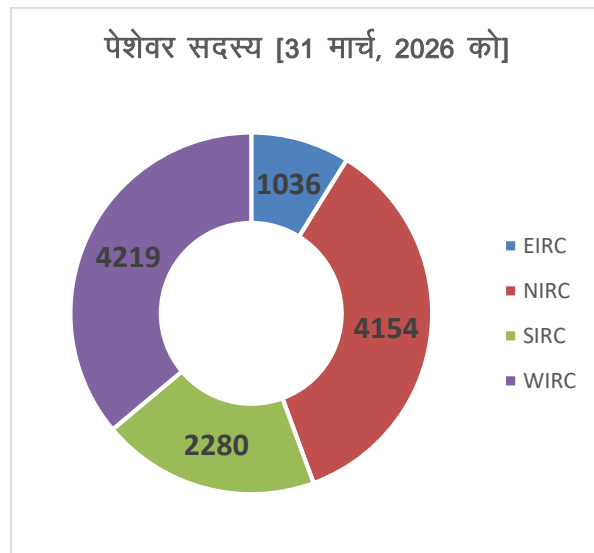
पेशेवर सदस्य					
निम्नानुसार	ईआईआरसी	एनआईआरसी	एसआईआरसी	डब्ल्यूआईआरसी	कुल
31.03.2026	1036	4154	2280	4219	11689
31.03.2025	1023	4101	2210	4140	11474

नियमित कार्यक्रम के छात्र					
निम्नानुसार	ईआईआरसी	एनआईआरसी	एसआईआरसी	डब्ल्यूआईआरसी	कुल
31.03.2026	21364	60151	41414	65821	188750
31.03.2025	20613	57630	40611	64574	183428



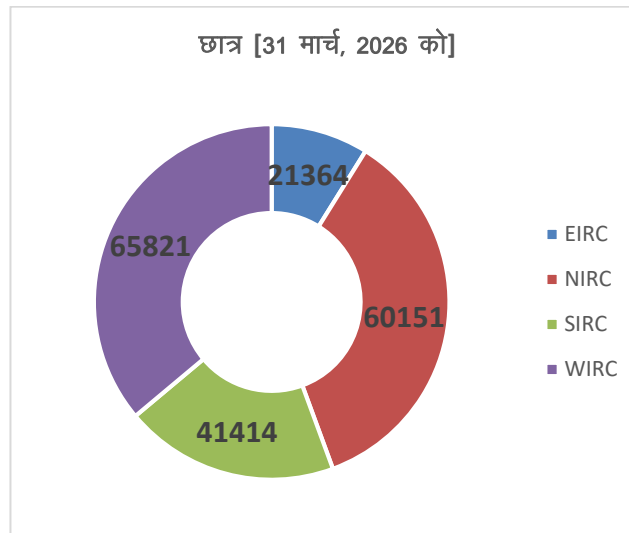
ईआईआरसी

एनआईआरसी



एसआईआरसी

डब्ल्यूआईआरसी



(ख) कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना

संस्थाओं को तेजी से उनकी नीतियों से नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों के आधार पर परखा जा रहा है। आईसीएसआई का अभिशासन संबंधी दृष्टिकोण भी इसी बदलाव को दर्शाता है—ऐसा दृष्टिकोण जो केवल अनुपालन तक सीमित न रहकर रोजमर्रा के निर्णय लेने में दूरदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के भरोसे को शामिल करता है। कंपनी सचिव इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बोर्डरूम में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, जोखिमों की समय रहते पहचान करते हैं और लाभप्रदता को उद्देश्य के साथ संतुलित करते हैं। इस वर्ष की पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से आईसीएसआई ने एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण विचार को और मजबूत किया है: अभिशासन केवल पालन करने के लिए नियमों की किताब नहीं है; यह एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसे व्यवहार में अपनाया जाना चाहिए।

(i) कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता के लिए 25वां आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार, 2025

आईसीएसआई ने भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में बेहतर अभिशासन की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में "कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार" शुरू किए थे। दो दशकों से अधिक समय में, इन पुरस्कारों को कॉर्पोरेट जगत और पेशेवरों के बीच अभिशासन में उत्कृष्टता के मानक और पूरे उद्योग में मानकों को बेहतर बनाने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में व्यापक मान्यता मिली है।

कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया एक कठोर और व्यापक मूल्यांकन ढांचे का पालन करती है। प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी के लिए हर वर्ष उद्योग और पेशेवर क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से युक्त एक विशेषज्ञ समूह गठित किया जाता है। यह समूह मूल्यांकन पद्धति तैयार करने और मूल्यांकन प्रश्नावली तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है। विशेषज्ञ समूह द्वारा तैयार प्रश्नावली के आधार पर प्राप्त उत्तरों के विश्लेषण के पश्चात निष्कर्षों को अंतिम चयन हेतु प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। निर्णायक मंडल में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता सामान्यतः भारत के किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिससे चयन प्रक्रिया में सर्वोच्च स्तर की निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और विशेषज्ञता सुनिश्चित होती है।

कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार के 25वें संस्करण का आयोजन 19 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में किया गया। भारत सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री, माननीय डॉ. राज भूषण चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पद्म श्रीमती पी. टी. उषा सम्मानित अतिथि थीं तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष श्री तुहिन कांता पांडे मुख्य वक्ता और विशेष अतिथि थे। वर्ष 2025 के पुरस्कार विजेता निम्नानुसार हैं:

कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता के लिए 25वां आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार	सूचीबद्ध खंड - द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (बड़ी श्रेणी) - यूनो मिंडा लिमिटेड (मध्यम श्रेणी)
---	--

	• ग्रीक्स कॉटन लिमिटेड (उभरती श्रेणी) असूचीबद्ध खंड • एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मध्यम श्रेणी) • इंटराजिज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (उभरती श्रेणी)
10वां आईसीएसआई सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार	• द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (बड़ी श्रेणी) • टीपी सदरन ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (मध्यम श्रेणी) • आईसीआरए लिमिटेड (लघु और उभरती श्रेणी)
सातवां आईसीएसआई सर्वश्रेष्ठ सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट पुरस्कार	सीएस पी. ईश्वरमूर्ति (प्रिकोल लिमिटेड के लिए जारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए)
पांचवां आईसीएसआई सर्वश्रेष्ठ पीसीएस फर्म पुरस्कार	एस. सी. शारदा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव
चौथा आईसीएसआई व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता पुरस्कार	• पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड (गैर-सेवा क्षेत्र) • एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (सेवा क्षेत्र)
25वां आईसीएसआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड	श्री आर. सी. भार्गव, अध्यक्ष, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

(ii) सचिवीय मानक

कॉरपोरेट अभिशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के अपने निरंतर दृष्टिकोण के अनुरूप, आईसीएसआई ने सचिवीय मानकों को तैयार करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये मानक, जो बोर्ड की प्रक्रियाओं और कॉरपोरेट प्रकटीकरणों के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं, इस दृष्टि से विशिष्ट हैं कि इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त करने वाले दुनिया में अपनी तरह के पहले मानक होने का गौरव प्राप्त है। ये मानक आज भी अभिशासन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रहे हैं और कॉरपोरेट संस्थाओं में प्रक्रियागत एकरूपता तथा अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहे हैं। संस्थान इन मानकों को बनाए रखने और समय-समय पर उनकी समीक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उभरती सर्वोत्तम प्रथाओं और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बने रहें।

कंपनी सचिव विनियम, 1982 के विनियम 105ए के अनुसार, संस्थान ने सचिवीय मानक बोर्ड (एसएसबी) का गठन किया है और इसके सदस्यों का विवरण अनुबंध-क में दिया गया है।

(iii) गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड

केंद्र सरकार द्वारा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 29ए के तहत गठित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (क्यूआरबी) को संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में संस्थान की परिषद को सिफारिशें देने, ऐसी सेवाओं की समीक्षा करने तथा सदस्यों को सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और लागू वैधानिक एवं विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोर्ड में एक अध्यक्ष के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सदस्य और संस्थान की परिषद द्वारा नामित दो सदस्य शामिल होते हैं।

(iv) सहकर्मि समीक्षा बोर्ड

सहकर्मि समीक्षा में संस्थान के अन्य सदस्यों द्वारा किसी प्रैक्टिस यूनिट की प्रणालियों और दृष्टिकोण की जाँच की जाती है, जिसका उद्देश्य सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य खुलेपन और आपसी विश्वास के माहौल में गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कुल 1,400 सहकर्मि समीक्षा प्रक्रियाएं पूरी की गईं और तदनुसार प्रैक्टिस यूनिटों को प्रमाणपत्र जारी किए गए। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सहकर्मि समीक्षकों के पैन्लीकरण के लिए 05 अप्रैल, 2025 को नागपुर में, 10 मई, 2025 को चेन्नई में और 23 अगस्त, 2025 को बेंगलुरु में कुल तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(v) कॉर्पोरेट अभिशासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीजीआरटी)

वर्तमान में संस्थान मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और मानेसर में स्थित चार सीसीजीआरटी केंद्रों का संचालन कर रहा है। मानेसर स्थित केंद्र का उद्घाटन दिसंबर, 2025 में किया गया और इसे उसी समय से संचालन में लाया गया। वर्ष के दौरान सीसीजीआरटी द्वारा संचालित कार्यक्रमों और पहलों का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के खंड 'के' में प्रस्तुत किया गया है।

(vi) ईएसजी और सततता पर आईसीएसआई पहल

आईसीएसआई ने ईएसजी और सततता के क्षेत्र में कई पहल की हैं, जिनका ध्यान उभरते रुझानों और वैश्विक विकास पर नज़र रखने, कंपनी सचिवों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से कॉरपोरेट संस्थाओं को सततता संबंधी उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और सततता के क्षेत्र में सीएस पेशेवरों के लिए नए अवसरों की पहचान करने पर केंद्रित है। इन पहलों का उद्देश्य पेशेवर समुदाय और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता और ज्ञान को बढ़ाना है, ताकि सततता उपायों के उचित कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आईसीएसआई द्वारा की गई प्रमुख ईएसजी और सततता संबंधी पहलें नीचे दी गई हैं:

(क) ईएसजी पर हितधारक सहभागिता टूलकिट

ईएसजी अभिशासन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से, संस्थान ने 31 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2025 को आयोजित 53वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव अधिवेशन में ईएसजी पर हितधारक सहभागिता टूलकिट जारी किया। ईएसजी पर हितधारक सहभागिता टूलकिट एक व्यावहारिक और व्यवस्थित संसाधन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हितधारकों के लिए उपयुक्त सहभागिता संबंधी प्रथाओं के साथ-साथ हितधारक सहभागिता गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करते समय अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। टूलकिट में हितधारक सहभागिता के दौरान अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को भी बताया गया है, ताकि विभिन्न वर्गों के हितधारकों के साथ प्रभावी संचार और सहभागिता को सुगम बनाया जा सके।

(ख) जलवायु परिवर्तन अभिशासन पर आईसीएसआई सिद्धांत

बेहतर अभिशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, संस्थान ने जलवायु परिवर्तन अभिशासन पर आईसीएसआई सिद्धांत (आईपीसीजी) तैयार किए हैं, जिन्हें 31 अक्टूबर – 02 नवंबर, 2025 को आयोजित 53वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव अधिवेशन में जारी किया गया। जलवायु परिवर्तन अभिशासन पर आईसीएसआई सिद्धांत संस्थाओं, उनके बोर्ड और वरिष्ठ नेतृत्व की इस प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं कि वे जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने की क्षमता को अपनी मुख्य व्यावसायिक रणनीति, जोखिम प्रबंधन, कार्य-निष्पादन के मापदंडों और जवाबदेही की व्यवस्थाओं में शामिल करें। इन सिद्धांतों को अपनाकर, संस्थाएं जलवायु अभिशासन के संबंध में अपनी कॉरपोरेट जिम्मेदारी का प्रदर्शन कर सकती हैं।

(ग) आईसीएसआई कम्युनिक – ईएसजी कैटालिस्ट और ईएसजी कॉर्नर

“ईएसजी कैटालिस्ट” आईसीएसआई द्वारा शुरू की गई एक द्विमासिक पहल है जिसका उद्देश्य ईएसजी के बारे में पेशेवरों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए ईएसजी के प्रमुख शब्द, लेख, आशाजनक कार्यप्रणालियाँ और ईएसजी क्षेत्र में नवीनतम विकास साझा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल में “ईएसजी कॉर्नर” नामक एक समर्पित भाग शुरू किया गया है जिसमें ईएसजी से संबंधित नवीनतम समाचार, जानकारी और अपडेट शामिल हैं।

(घ) आईसीएसआई ईएसजी मिशन लाइफ संदेश

सततता को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, आईसीएसआई पेशेवरों और अन्य हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण-अनुकूल सुझाव और ईएसजी पर छोटे, प्रभावशाली संदेश प्रसारित करता है। इन संदेशों का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और भारत सरकार के लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) मिशन के अनुरूप, दैनिक और व्यावसायिक व्यवहार में स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(vii) पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002) पर आईसीएसआई की पहल

आईसीएसआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई से प्रैक्टिस प्रमाणपत्र प्राप्त पेशेवरों के लिए एएमएल और सीएफटी दिशानिर्देश 19 जून, 2023 से प्रभावी हैं, जिसके तहत आईसीएसआई को कंपनी सचिव पेशेवरों के लिए स्व-नियामक निकाय (एसआरबी) के रूप में नामित किया गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आईसीएसआई (एसआरबी) द्वारा संचालित प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

- पेशेवर सदस्यों को पीएमएलए संबंधी प्लायर के मासिक बल्क ई-मेल भेजे जाते हैं।
- पेशेवर सदस्यों को मासिक आधार पर बल्क एसएमएस भेजे जाते हैं।
- ईईई 5.0 के तहत पीएमएलए और एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।
- पीएमएलए पोर्टल में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - आईसीएसआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई से प्रैक्टिस प्रमाणपत्र प्राप्त पेशेवरों के लिए “एएमएल और सीएफटी दिशानिर्देश” पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
 - यूएपीए, 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में नामित व्यक्तियों की सूची

○ आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से संबंधित लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों से संबंधित दस्तावेजों के लिंक

- आईसीएसआई के सोशल मीडिया चैनलों पर नियमित अंतराल पर सोशल मीडिया क्रिएटिव जारी करना।
- पीएमएलए से संबंधित प्रश्नों के लिए समर्पित ई-मेल आईडी pmla@icsi.edu

रिपोर्टिंग संस्थाओं का पंजीकरण: रिपोर्टिंग संस्थाओं को आईसीएसआई के 'पंजीकरण पोर्टल' के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है, जो STIMULATE पर उपलब्ध है। आईसीएसआई ने पीएमएलए पोर्टल भी स्थापित किया है, जहाँ सदस्य सभी अधिसूचनाएँ और एफएटीएफ ग्रे व ब्लैक लिस्ट देख सकते हैं।

(ग) सुविधा और मानकीकरण

(i) रणनीतिक साझेदारियाँ

(क) वाणिज्य एवं उद्योग मंडल

संस्थान ने कोचीन वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों, कार्यरत पेशवरों और कॉरपोरेट अधिकारियों के लिए समसामयिक और पेशेवर रुचि के विषयों पर संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यशालाएँ, सेमिनार, निरंतर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी अन्य विभिन्न गतिविधियाँ/परियोजनाएँ संयुक्त रूप से या अलग-अलग आयोजित करना है।

(ख) भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)

11-12 जुलाई, 2025 को शिलांग में आयोजित आईआईसीए नॉर्थ-ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 के दौरान भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता निर्माण हेतु पाठ्यक्रम और कार्यक्रम शुरू करना तथा दोनों संस्थानों के संयुक्त प्रयासों को दर्शाने वाले आपसी हित के अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

(ग) सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे

संस्थान ने सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसका उद्देश्य रेगटेक, फिनटेक और प्रौद्योगिकी आधारित अन्य क्षेत्रों जैसे उभरते क्षेत्रों में संस्थान के विद्यार्थियों, कर्मचारियों और सदस्यों के कौशल को उन्नत करना है। इस सहयोग का उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक और प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से सीखने, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे हितधारक तेजी से बदल रही तकनीकी प्रगति और उद्योग की आवश्यकताओं से अवगत रह सकें।

(घ) भारत क्लाउड (बीसीडीसी क्लाउड सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड)

संस्थान ने भारत क्लाउड (मेसर्स बीसीडीसी क्लाउड सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसका उद्देश्य सदस्यों को सुरक्षित क्लाउड-आधारित डिजिटल समाधानों और एआई-एकीकृत अनुपालन टूल तक पहुंच प्रदान करना है। इस सहयोग के तहत सदस्यों को विशेष सदस्यता पैकेज, निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम और समर्पित सहायता सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस साझेदारी का उद्देश्य उद्यम-स्तरीय सुरक्षा और उन्नत तकनीकी समाधानों के माध्यम से व्यावसायिक उत्कृष्टता, डिजिटल परिवर्तन और अनुपालन प्रबंधन को मजबूत करना है।

(ड.) टीएसएस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (स्क्रीनज़ा)

संस्थान ने मेसर्स टीएसएस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (स्क्रीनज़ा) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसका उद्देश्य सदस्यों को उन्नत अनुपालन स्क्रीनिंग और निगरानी समाधानों तक पहुंच प्रदान करना है। यह मंच निःशुल्क अनुपालन जाँच, विशेष रियायती मूल्य, समर्पित सहायता और पूर्ण गोपनीयता प्रदान करता है। इसके माध्यम से पेशेवर प्रतिबंधों की स्क्रीनिंग, प्रतिकूल मीडिया की निगरानी, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग और अनुपालन प्रबंधन के अन्य टूल के माध्यम से समुचित जाँच-पड़ताल और विनियामक अनुपालन कर सकते हैं।

(च) आईसीएसआई उद्योग/संस्थागत आउटरीच कार्यक्रम

संस्थान ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, जिसके तहत पूरे भारत में अपने क्षेत्रीय और चैप्टर कार्यालयों को अपने-अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों और ऐसे ही संबद्ध निकायों के साथ स्वतंत्र रूप से पहल करने और समझौता ज्ञापन करने का अधिकार दिया गया है। मुख्यालय की निगरानी में एक व्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रिया, सख्त डेटा संरक्षण प्रोटोकॉल और वार्षिक प्रभाव रिपोर्टिंग के आधार पर तैयार किए गए इस ढाँचे से सभी क्षेत्रीय और शाखा स्तर की साझेदारियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और एकरूपता सुनिश्चित होती है। इन सहयोगों के माध्यम से सदस्यों और विद्यार्थियों को उनकी बदलती जरूरतों के अनुरूप संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और

क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, आईसीएसआई के दिशानिर्देशों के अधीन, पात्र रूप से संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रमों के लिए सीपीई क्रेडिट भी प्राप्त किए जा सकेंगे।

(छ) इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड

आईसीएसआई और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड (इंडिया आईएनएक्स) ने 26 फरवरी, 2026 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ताकि गिफ्ट-आईएफएससी में कंपनी सचिवों के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करके गिफ्ट-आईएफएससी को एक वैश्विक लिस्टिंग केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु परस्पर सहयोग और कार्य किया जा सके।

(ज) इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स

आईसीएसआई ने 15 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स (आईएजीईएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से आईसीएसआई में पंजीकृत प्रैक्टिस कर रही कंपनी सचिव फर्मों (पीसीएस) को भारतीय स्वर्ण उद्योग में आईएजीईएस के मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक पहुंच प्राप्त होगी, जिन्होंने आईएजीईएस से मान्यता प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन कराने में रुचि व्यक्त की है। पीसीएस फर्मों को पूरे भारत में आईएजीईएस के मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी एजेंसी के रूप में आईएजीईएस के साथ सूचीबद्ध होने का अवसर मिलेगा। पात्र संस्थाओं में एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं को शामिल करने के लिए मानदंडों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा, पिछले लगातार 3 वित्तीय वर्षों में औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार की न्यूनतम आवश्यकता को पहले की ₹1 करोड़ की सीमा से घटाकर ₹50 लाख कर दिया गया है।

(ii) ईसीएसआईएन (कर्मचारी कंपनी सचिव पहचान संख्या) एमनेस्टी स्कीम, 2025

संस्थान ने 01 अप्रैल, 2025 से 15 अप्रैल, 2025 तक प्रभावी ईसीएसआईएन एमनेस्टी स्कीम, 2025 शुरू की, जिसे 20 अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दिया गया। ईसीएसआईएन दिशानिर्देशों की प्रभावी तिथि यानी 01 अक्टूबर, 2019 से एमनेस्टी स्कीम की वैधता यानी 20 अप्रैल, 2025 तक जनरेट सभी सक्रिय ईसीएसआईएन एमनेस्टी स्कीम के तहत कवर किए गए।

(iii) यूडीआईएन (विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या) एमनेस्टी स्कीम, 2025

संस्थान ने 1 अप्रैल, 2025 से 15 अप्रैल, 2025 तक मान्य यूडीआईएन एमनेस्टी स्कीम, 2025 शुरू की, जिसे 20 अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दिया गया। 19 अप्रैल, 2024 से स्कीम की समाप्ति तक, यानी 20 अप्रैल, 2025 तक, सभी यूडीआईएन एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र थे।

(iv) आईसीएसआई (पेशेवर कंपनी सचिवों का प्रबंधन एवं विकास) दिशानिर्देश, 2023

संस्थान द्वारा आईसीएसआई पेशेवर कंपनी सचिवों का प्रबंधन एवं विकास) दिशानिर्देश, 2023 को 15 दिसंबर, 2023 से प्रभावी रूप से जारी किया गया था। कुछ मामलों में प्रक्रियात्मक स्पष्टता लाने के लिए, 25 अगस्त, 2025 को आयोजित परिषद की 321वीं (विशेष) बैठक में इन दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।

(v) पीसीएस पोर्टल का पुनर्गठन

संस्थान की वेबसाइट पर पीसीएस पोर्टल का पुनर्गठन किया गया है, ताकि पेशेवर कंपनी सचिवों के लाभ के लिए उपलब्ध विभिन्न सूचनाओं/मार्गदर्शन/दिशानिर्देशों में एकरूपता और स्पष्टता लाई जा सके तथा उन्हें व्यवस्थित किया जा सके।

(vi) क्षेत्रीय और चैप्टर कार्यालयों के लिए सुझाए गए मासिक थीम

संस्थान ने क्षेत्रीय और चैप्टर कार्यालयों के लिए सुझाए गए मासिक थीम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें निर्धारित थीम को महीने के कम से कम एक कार्यक्रम में मुख्य थीम या उप-थीम के रूप में शामिल किया जाना है। यह पहल विषयगत एकरूपता सुनिश्चित करती है और सदस्यों को व्यवस्थित व्यावसायिक विकास का अवसर प्रदान करती है। ऐसे सुझाए गए मासिक थीमों को कंपनी सचिव जर्नल में भी शामिल किया जा रहा है, ताकि मानकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके और सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए एक समान केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

(vii) कंपनी सचिव हितकारी निधि (सीएसबीएफ)

सीएसबीएफ, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत नई दिल्ली के सोसाइटी पंजीयक के पास पंजीकृत एक सोसाइटी है। इसकी स्थापना संस्थान द्वारा वर्ष 1976 में सीएसबीएफ के सदस्य कंपनी सचिवों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को संकट के समय सुरक्षा प्रदान करने और सहारा देने के लिए की गई थी। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कुल 1611 सदस्यों को सीएसबीएफ में सदस्यता दी गई। 31 मार्च, 2026 तक, सीएसबीएफ के 19026 आजीवन सदस्य थे।

सीएसबीएफ की आजीवन सदस्यता के लिए 18 जनवरी, 2026 से 30 जून, 2026 तक रु. 9,000/- के रियायती शुल्क पर एक विशेष अभियान चलाया गया। विशेष अभियान के दौरान सीएसबीएफ की सदस्यता लेने वाले सदस्यों को आईसीएसआई के प्रकाशन भी निःशुल्क प्रदान किए गए।

(घ) सदस्यों की क्षमता निर्माण और उनके लिय अद्यतन ज्ञान**(i) क्षमता निर्माण शृंखला**

क्षमता निर्माण शृंखला (वेबिनार माध्यम) विभिन्न विषयों पर सदस्यों के ज्ञान को अद्यतन करने और कौशल में वृद्धि करने के लिए संस्थान की एक पहल है, जिसका उद्देश्य उन्हें ऐसे कम खोजे गए क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसरों को अपनाने के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी से सुसज्जित करना है। वेबिनार शृंखला का मुख्य ध्यान (i) विषय से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं और कानूनी पहलुओं (ii) उस क्षेत्र में कंपनी सचिवों के लिए उपलब्ध अवसरों (iii) इन अवसरों को अपनाने के लिए आवश्यक कौशल पर है।

(ii) अध्ययन मंडल

आईसीएसआई देश भर में अध्ययन मंडलों के गठन को बढ़ावा देकर सदस्यों के लिए ज्ञान उन्नयन के अवसर सृजित कर रहा है। इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित अध्ययन मंडलों का गठन/नवीनीकरण किया गया:

क्षेत्रीय परिषद	नाम	गठन/नवीकरण
एसआईआरसी	आईसीएसआई का हुबली-धारवाड़ अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
एनआईआरसी	आईसीएसआई का द्वारका अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का रेवाड़ी अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का ग्रेटर नोएडा पश्चिम अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गठन
	आईसीएसआई का रोहिणी अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गठन
डब्ल्यूआईआरसी	आईसीएसआई का महिंद्रा (कॉर्पोरेट) अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का एचटी पारेख मार्ग (कॉर्पोरेट) अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का जामनगर अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का मकरंद एम जोशी एंड कं. (कॉर्पोरेट) अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का सांगली अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का रिलायंस इंडस्ट्रीज (कॉर्पोरेट) अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का एलएंडटी (कॉर्पोरेट) अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का भिलाई अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का सांताक्रुज अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गठन
	आईसीएसआई का जेएसडब्ल्यू (कॉर्पोरेट) अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का महिंद्रा (कॉर्पोरेट) अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का कांदिवली अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का आदित्य बिड़ला समूह (कॉर्पोरेट) अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का एचटी पारेख मार्ग (कॉर्पोरेट) अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण
ईआईआरसी	आईसीएसआई का मध्य कोलकाता अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण
	आईसीएसआई का टॉलीगंज अध्ययन मंडल	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण

(iii) नॉलेज ऑन डिमांड

नॉलेज ऑन डिमांड (केओडी) संस्थान की एक पहल है, जिसके अंतर्गत सदस्यों को संस्थान के एलएमएस मंच पर महत्वपूर्ण विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए रिकॉर्ड किए गए सत्रों को अपनी सुविधा के अनुसार 24x7 देखने और अपने ज्ञान को अद्यतन करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाती है।

(iv) प्रमुख प्रकाशन**(क) मॉडल गवर्नेंस कोड फॉर मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत्स**

संस्थान ने वर्ष 2017 में ग्राम पंचायतों की बैठकों के आयोजन की प्रक्रियाओं को एकरूप बनाने के लिए एक सामाजिक पहल के रूप में “मॉडल गवर्नेंस कोड फॉर मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत्स” जारी की थी। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय-सीमाओं और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, इस संहिता को संशोधित किया गया है, ताकि सभी समय-सारिणियों में समन्वय स्थापित करने वाला एक एकीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराया जा सके। संशोधित संहिता 19 अप्रैल, 2025 को जारी की गई। यह व्यापक संहिता भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों की बैठकों के लिए प्रक्रियाओं को एकरूप बनाना तथा कार्यकुशलता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना है। ग्राम स्तर पर शासन प्रक्रियाओं में सुधार करके, यह संहिता नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन को सुगम बनाती है, ग्रामीण विकास पहलों को बढ़ावा देती है और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में जनता के विश्वास को मजबूत करती है।

(ख) कॉरपोरेट गवर्नेंस – फ्रॉम कंप्लायंस टू एक्सीलेंस (हैंडबुक ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेज), वर्जन 4.0

कॉरपोरेट गवर्नेंस – फ्रॉम कंप्लायंस टू एक्सीलेंस (हैंडबुक ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेज) के चौथे संस्करण में आईसीएसआई के कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के 24वें संस्करण में भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा अपनाए गए अभिशासन तंत्रों का व्यापक विश्लेषण किया गया है। इस प्रकाशन में छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच और उनका उल्लेख किया गया है: बोर्ड की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण, जोखिम प्रबंधन, हितधारकों के मूल्य में वृद्धि, सततता और कार्यस्थल नवाचार। यह प्रकाशन कॉरपोरेट अभिशासन से जुड़े हितधारकों को अनुपालन से आगे बढ़कर उत्कृष्टता हासिल करने में सहायता देने के लिए उपयोगी जानकारी और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

(ग) डिकोडिंग ईएसजी: ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी पर एफएक्यू

यह प्रकाशन ईएसजी और सततता के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली विभिन्न शब्दावलिओं और अवधारणाओं का संकलन है। इस प्रकाशन की संरचना प्रश्न और उत्तर के रूप में तैयार की गई है, जिसमें नीली अर्थव्यवस्था, ग्रीनवॉशिंग और ईएसजी तथा सततता से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है, ताकि पाठकों को ईएसजी और सततता के परिदृश्य की मूलभूत समझ विकसित करने में सहायता मिल सके।

(घ) हैंडबुक ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, वर्जन 3.0

हैंडबुक ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी का तीसरा संस्करण इस बात की जानकारी देता है कि कंपनियां अधिक जिम्मेदार और सतत तरीके से व्यवसाय करने की दिशा में अपने बदलाव को सफलतापूर्वक कैसे प्रबंधित कर सकती हैं। इसमें भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधित विधायी विकास की यात्रा, पुरस्कार मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान चयनित कंपनियों में देखी गई प्रथाओं तथा कॉरपोरेट्स द्वारा अपनी बीआरएस रिपोर्ट तैयार करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन का संकलन किया गया है।

(ङ) मॉडल गवर्नेंस कोड फॉर मीटिंग्स ऑफ ज़िला परिषद

मॉडल गवर्नेंस कोड फॉर मीटिंग्स ऑफ ज़िला परिषद अभिशासन में जिला परिषद की समन्वयकारी भूमिका को दर्शाती है। इसमें विभिन्न समुदायों की अलग-अलग विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामूहिक समृद्धि और कल्याण के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाने की बात की गई है। वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत रूप दिए जाने के बाद से जिला परिषद ग्रामीण शासन की सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती रही है और राज्य की नीतियों तथा समुदाय की आकांक्षाओं के बीच सेतु का कार्य करती है। यह आदर्श गवर्नेंस संहिता बैठकों की प्रक्रियाओं को एकरूप बनाती है तथा जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करती है, जिससे नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन और अधिक प्रभावी ग्रामीण विकास संभव होता है।

(च) मॉडल गवर्नेंस कोड फॉर मीटिंग्स ऑफ पंचायत समिति

यह संहिता ग्राम और जिला प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्तर के रूप में पंचायत समिति की संवैधानिक भूमिका को और मजबूत करती है। यह संहिता प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी बैठकें आयोजित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं प्रदान करती है तथा सुव्यवस्थित विचार-विमर्श, प्रभावी योजना निर्माण, नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेह निर्णय लेने को बढ़ावा देती है। इस प्रकार, यह पंचायत समितियों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सभी के लिए समान सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराने के अपने दायित्व को पूरा करने में सक्षम बनाती है।

(छ) स्टैकहोल्डर एंगेजमेंट टूलकिट ऑन ईएसजी

स्टैकहोल्डर एंगेजमेंट टूलकिट ऑन ईएसजी एक व्यावहारिक और सुव्यवस्थित संसाधन है, जो विभिन्न परिस्थितियों में हितधारकों की पहचान करने, उन्हें शामिल करने और उनके साथ सहयोग करने की प्रक्रिया में उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करती है। यह मार्गदर्शिका हितधारकों की विभिन्न श्रेणियों के साथ प्रभावी संवाद और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हितधारक सहभागिता के दौरान अपनाई जाने वाली प्रमुख सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालती है।

(ज) आईसीएसआई प्रिंसिपल्स ऑन क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस

यह प्रकाशन संस्थाओं, उनके बोर्डों और वरिष्ठ नेतृत्व की इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है कि वे जलवायु अनुकूलन क्षमता को अपनी मूल व्यावसायिक रणनीति, जोखिम प्रबंधन, कार्य-निष्पादन के मापदंडों और जवाबदेही के ढांचे में शामिल करें। इन सिद्धांतों को अपनाकर संस्थाएं जलवायु अभिशासन के क्षेत्र में अपनी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को प्रदर्शित कर सकती हैं। ये सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के हैं और किसी विशेष क्षेत्राधिकार के पक्ष में नहीं हैं, जिसके कारण इन्हें दुनियाभर की किसी भी संस्था द्वारा अपनाया जा सकता है।

(झ) गाइडेंस नोट ऑन मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (जीएन-1)

निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित सचिवीय मानक (एसएस-1), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत आईसीएसआई द्वारा जारी किया गया है, ने जुलाई 2015 में लागू किए जाने के बाद से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बदलती कार्यप्रणालियों को ध्यान में रखते हुए, एसएस-1 में वर्ष 2017 में और फिर वर्ष 2024 में संशोधन किया गया। एसएस-1 का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आईसीएसआई ने गाइडेंस नोट ऑन मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जारी की थी, जिसे एसएस-1 में किए गए संशोधनों के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन किया गया है, ताकि कंपनी अधिनियम के साथ इसकी संगति सुनिश्चित की जा सके।

(ञ) गाइडेंस नोट ऑन जनरल मीटिंग्स (जीएन-2)

द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग्स (एसएस-2), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत आईसीएसआई द्वारा जारी किया गया है, ने जुलाई 2015 में लागू किए जाने के बाद से कॉर्पोरेट अभिशासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बदलती कार्यप्रणालियों को ध्यान में रखते हुए, एसएस-2 में वर्ष 2017 में और फिर वर्ष 2024 में संशोधन किया गया। एसएस-2 का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आईसीएसआई ने गाइडेंस नोट ऑन जनरल मीटिंग्स जारी की थी, जिसे एसएस-2 में किए गए संशोधनों के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन किया गया है, ताकि कंपनी अधिनियम के साथ इसकी संगति सुनिश्चित की जा सके।

(ट) एमएसएमई रेडी रेकनर 2.0

यह भारत में एमएसएमई के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जिसमें छोटे व्यवसायों के लिए कानूनी ढांचे, अनुपालन नियमों और परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों का स्पष्ट विवरण दिया गया है। इसका अद्यतन संस्करण 2.0 इस क्षेत्र से संबंधित हाल के सरकारी नीतिगत बदलावों और नई पहलों को दर्शाता है। यह व्यवसाय से संबंधित अनुपालन का कार्य देखने वाले कंपनी सचिवों और पेशेवरों के लिए एक आवश्यक संदर्भ साधन के रूप में कार्य करता है।

(ठ) नेविगेटिंग लेबर कोड्स: ए हैंडबुक

वर्ष 2019 में बनाए और अधिनियमित किए गए नए श्रम संहिताओं ने समान प्रकृति वाले विभिन्न कानूनों को एक साथ लाकर और समाज के श्रमिक वर्ग को अधिक लाभ एवं राहत प्रदान करके विधायी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। यह प्रकाशन इन कानूनों के लागू होने से होने वाले लाभों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है तथा इन संहिताओं में समाहित विभिन्न विषयों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने का प्रयास करता है।

(ड) गाइडेंस नोट ऑन थर्ड पार्टी एश्योरेंस (बीआरएसआर कोर)

गाइडेंस नोट ऑन थर्ड पार्टी एश्योरेंस (बीआरएसआर कोर) आश्वासन प्रदाताओं, रिपोर्टिंग संस्थाओं और अन्य हितधारकों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार की गई है। इसमें बीआरएसआर कोर प्रकटीकरणों से संबंधित आश्वासन

कार्यों की योजना बनाने, उन्हें पूरा करने और उनकी रिपोर्ट तैयार करने के व्यावहारिक तरीकों का विवरण दिया गया है। इसमें डेटा की गुणवत्ता का आकलन करने, सततता से संबंधित जानकारी पर आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करने, ईएसजी के संदर्भ में महत्वपूर्णता संबंधी विचारों को लागू करने तथा ग्रीनवॉशिंग के जोखिमों से बचने के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया है।

(द) हैडबुक ऑन इंटरनल ऑडिट

यह पुस्तिका आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए एक व्यापक, निर्देशात्मक और मानकीकृत मार्गदर्शिका प्रदान करती है। यह पेशेवरों को कॉरपोरेट अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित कार्यप्रणालियां और सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाने में सक्षम बनाती है। यह महत्वपूर्ण पुस्तिका सांविधिक आवश्यकताओं के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ संगठन की कार्यकुशलता और वित्तीय सत्यनिष्ठा को बढ़ाने में सहायता करती है।

(ण) हैडबुक ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ

यह प्रकाशन उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करता है, जैसे उपभोक्ता संरक्षण की उत्पत्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के रूप में विधायी पड़ाव तथा उनके प्रभाव, उपभोक्ता शिक्षा का महत्व, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और उनके प्रवर्तन को सुनिश्चित करने वाले नियामकीय निकाय जैसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए), उपभोक्ता संरक्षण का वैश्विक परिदृश्य आदि। इसका उद्देश्य व्यापक कॉरपोरेट जगत, उपभोक्ताओं, अभिशासन पेशेवरों, संबंधित नियामकीय निकायों, मीडिया, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्योगों, वाणिज्य मंडलों, विशेष रूप से उपभोक्ता संबंधी अधिकारों पर शोध करने वाली शोध संस्थाओं तथा छात्रों आदि को उपभोक्ता संरक्षण के विषय में जागरूक करना है।

(त) हैडबुक ऑन एंटी-कॉरप्शन लॉज

“हैडबुक ऑन एंटी-कॉरप्शन लॉज” नामक इस प्रकाशन में भ्रष्टाचार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार-रोधी कार्यप्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए नियामकीय ढांचा, भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों के लिए तंत्र, रिश्वतखोरी-रोधी नीति, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थागत कार्यप्रणालियां, रिश्वतखोरी-रोधी कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक मामले आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य उद्योगों, सरकारी निकायों, वाणिज्य मंडलों, अभिशासन पेशेवरों, अन्य निकायों के पेशेवरों, शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं, छात्रों तथा अन्य लोगों के बीच रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के संबंध में व्यापक जागरूकता पैदा करना और गहन जानकारी प्रदान करना है।

(थ) हैडबुक ऑन एसएमई आईपीओ – प्रोसेस एंड लिस्टिंग

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने शोध-आधारित एक प्रकाशन “हैडबुक ऑन एसएमई आईपीओ – प्रोसेस एंड लिस्टिंग” प्रकाशित किया है। इसमें एसएमई के सूचीबद्ध होने की शुरुआत, एसएमई का कामकाज, उभरती अर्थव्यवस्था में एसएमई द्वारा किया जाने वाला मूल्यवर्धन, एसएमई के आईपीओ के सूचीबद्ध होने को नियंत्रित करने वाला विनियामक और कानूनी ढांचा (आईसीडीआर विनियम), सूचीबद्ध होने से पहले की तैयारी, उचित जाँच-पड़ताल आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है।

(द) हैडबुक ऑन कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग

“हैडबुक ऑन कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग” नामक यह प्रकाशन कॉरपोरेट पुनर्गठन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है, जैसे पुनर्गठन के प्रकार, विलगाव, विभाजन, कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन, पुनर्गठन में मूल्यांकन, पुनर्गठन को नियंत्रित करने वाला नियामकीय ढांचा आदि।

(ध) रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स टूलकिट

“रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स टूलकिट” का उद्देश्य भावी और कार्यरत दोनों पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन कार्यों को दक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ करने के लिए आवश्यक ज्ञान, नियामकीय ढांचे, व्यावहारिक साधनों और नैतिक मार्गदर्शन से सुसज्जित करना है। मूल्यांकन की कार्यप्रणालियों से लेकर रिपोर्ट तैयार करने के प्रारूपों तक, कानूनी प्रावधानों से लेकर उदाहरणात्मक मामलों के अध्ययन तक, यह सामग्री सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग का संतुलित समावेश प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। यह प्रकाशन मूल्यांकन कार्य करने वाले पेशेवरों, वित्तीय विश्लेषकों और कॉरपोरेट सलाहकारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है तथा मूल्यांकन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक ‘प्रमुख संदर्भ संसाधन’ के रूप में कार्य करता है।

(v) प्रमुख बेबिनार

(क) मुख्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार

क्र.सं.	विषय	तिथि
1.	अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार (जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिशें)	11 सितंबर, 2025
2.	श्रम संहिताएं (अवलोकन और आगे की कार्ययोजना)	29 नवंबर, 2025

(ख) संयुक्त वेबिनार/सेमिनार

क्र.सं.	विषय	तिथि
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के साथ संयुक्त कार्यक्रम		
1.	आईसीएसआई नई दिल्ली में आयोजित 'प्रभावी ईएसजी और अनुपालन के लिए एआई का समावेश – संधारणीयता और सीएसआर रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता प्राप्त करना' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में संस्थागत भागीदार के रूप में शामिल हुआ।	02 मई, 2025
2.	आईसीएसआई नई दिल्ली में आयोजित 'आईईपीएफ, कारपोरेट निकास और निवेशक संरक्षण' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में संस्थागत भागीदार के रूप में शामिल हुआ।	18 जुलाई, 2025
3.	आईसीएसआई नई दिल्ली में आयोजित 'सेबी (एलओडीआर) और पीआईटी विनियम: कारपोरेट अभिशासन को सुदृढ़ करना और निवेशकों की सुरक्षा' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में संस्थागत भागीदार के रूप में शामिल हुआ।	19 सितंबर, 2025
4.	आईसीएसआई नई दिल्ली में आयोजित 'कारपोरेट पुनर्गठन: विकसित होते कानूनी और अभिशासन ढांचे के साथ कुशल कारपोरेट संरचनाएं' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में संस्थागत भागीदार के रूप में शामिल हुआ।	28 नवंबर, 2025
5.	आईसीएसआई नई दिल्ली में आयोजित 'प्रतिस्पर्धा कानून पर संगोष्ठी में संस्थागत भागीदार के रूप में शामिल हुआ।	12 दिसंबर, 2025
आईआईएम बैंगलोर के साथ संयुक्त कार्यक्रम		
6.	आईसीएसआई बैंगलुरु में आयोजित आईआईएमबी-सीसीजीएस कारपोरेट अभिशासन और संधारणीयता सम्मेलन 2025 में 'कारपोरेट अभिशासन के भविष्य की राह: जवाबदेही और नवाचार' विषय पर शैक्षणिक भागीदार के रूप में शामिल हुआ।	04 जुलाई, 2025
विमेन्स कलेक्टिव फोरम (डब्ल्यूसीएफ) के साथ संयुक्त कार्यक्रम		
7.	आईसीएसआई ने विमेन्स कलेक्टिव फोरम (डब्ल्यूसीएफ) के साथ 'स्पार्क – द 100के कलेक्टिव' के लिए संस्थागत भागीदार के रूप में सहभागिता की। यह पहल मास्टरक्लास के माध्यम से महिला-नेतृत्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों को प्रारंभिक चरण में कानूनी स्पष्टता, अनुपालन संबंधी जानकारी और उद्यम अभिशासन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए है।	24 सितंबर, 2025
आईसीएसआई – शिक्षकों तक पहुंच कार्यक्रम		
8.	आईसीएसआई ने दिल्ली एनसीआर में स्थित प्रतिष्ठित सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों के कुलपतियों/प्रधानाचार्यों/डीनों/ प्रोफेसरों आदि को शामिल करते हुए शिक्षकों तक पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया।	15 जनवरी, 2026

(ग) ईईई 5.0 – मास्टर ज्ञान शृंखला

संस्थान ने वर्ष 2017 से ईईई (सक्षम बनाना, मूल्यांकन करना, उत्कृष्टता प्राप्त करना) वेबिनार शृंखला शुरू की थी, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को कॉरपोरेट और क्षेत्रीय कानूनों के संबंध में उनके ज्ञान को दोहराने, बढ़ाने और अद्यतन करने में सहायता करना है। इस क्षमता निर्माण पहल के दूसरे, तीसरे और चौथे संस्करण क्रमशः 2021, 2023 और 2024 में शुरू किए गए थे। पिछले संस्करणों के समान उद्देश्य और उनमें मिली उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, आईसीएसआई ने ईईई 5.0 – मास्टर ज्ञान शृंखला के तहत इस वेबिनार शृंखला का अगला चरण शुरू किया है। ईईई 5.0 मास्टर ज्ञान शृंखला के तहत 37 सत्र आयोजित किए गए।

(घ) एमसीए उपयोगकर्ता जागरूकता सत्र

एमसीए, आईसीएसआई के सहयोग से, एमसीए-21 संस्करण 3 और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं से संबंधित हितधारकों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से उपयोगकर्ता जागरूकता सत्र और ओपन हाउस सत्र आयोजित करता है।

(vi) प्रमुख पहलें**(क) एमएसएमई और स्टार्टअप कनेक्ट 2025**

आईसीएसआई एमएसएमई और स्टार्टअप कनेक्ट 2025 एमएसएमई और स्टार्टअप बोर्ड की एक पहल है, जो एमएसएमई दिवस मनाने के लिए जून से जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी, जिसका विषय “एमएसएमई और स्टार्ट-अप: विकास को सशक्त बनाना” था, जिसका उद्देश्य स्व-संधारणीय आधार पर सफलता में तेजी लाना था। यह कार्यक्रम पूरे भारत में एक मानक और एक समान संरचना के अनुसार आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्टअप से संबंधित क्षेत्रों में गवर्नेंस पेशेवरों के लिए अवसर पैदा करना तथा कंपनी सचिवों, कॉरपोरेट सलाहकारों और उद्यमियों के लिए क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाना था, ताकि अनुपालनकारी, संधारणीय और पूंजी के लिए तैयार व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके।

(ख) राष्ट्रीय एनसीएलटी पेशेवर कॉन्क्लेव

राष्ट्रीय एनसीएलटी पेशेवर कॉन्क्लेव की शुरुआत आईसीएसआई एनसीएलटी और एनसीएलटी कार्यबल – 2025 से हुई। आईसीएसआई के क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं (चैप्टरों) ने एनसीएलटी पीठों वाले क्षेत्रों में पूरे भारत में इन कार्यक्रमों का आयोजन एक मानक प्रारूप और स्व-संधारणीय वित्तीय मॉडल के अनुसार किया। संबंधित क्षेत्र की एनसीएलटी पीठ के तकनीकी या वित्तीय सदस्यों ने इन कार्यक्रमों में सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। “एनसीएलटी/एनसीएलटी: विवाद समाधान के लिए संपूर्ण कॉरपोरेट क्षेत्राधिकार” विषय के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में उप-विषयों के रूप में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 को शामिल किया गया, जिसमें सांविधिक कानून को न्यायालयीन अभ्यास से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कार्यरत कंपनी सचिवों को वर्तमान राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की व्यवस्थाओं के अनुरूप व्यावहारिक मुकदमेबाजी क्षमताओं से सुसज्जित करना है।

(ग) स्टार्टअप सप्ताह

संस्थान ने जनवरी 2026 में “स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन: डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र का निर्माण” मुख्य विषय के अंतर्गत स्टार्टअप सप्ताह 2026 मनाया। पूरे भारत में आईसीएसआई के क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं (चैप्टरों) ने 12–22 जनवरी, 2026 के दौरान विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। कंपनी सचिवों के लिए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने और भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इन कार्यक्रमों में वित्तपोषण के विकल्प, अनुपालन, निवेश के अवसर, शेयरधारक और शेयर खरीद करार, मूल्यांकन, बौद्धिक संपदा अधिकार, ऋण वसूली और वित्तीय पुनर्गठन जैसे विषयों को शामिल किया गया।

(घ) आंतरिक लेखापरीक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

आंतरिक लेखापरीक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 10 जनवरी, 2026 को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम आंतरिक लेखापरीक्षा 2025 पर आईसीएसआई कार्यबल की एक पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसका गठन आंतरिक लेखापरीक्षा में कंपनी सचिवों की भूमिका का पता लगाने और उसे मजबूत करने तथा सुदृढ़ अभिशासन ढांचे को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। कार्यक्रम ‘आंतरिक लेखापरीक्षा: बेहतर कॉरपोरेट जिम्मेदारी के लिए एक ढांचा’ विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, जोखिम प्रबंधन और प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन को बढ़ावा देने में आंतरिक लेखापरीक्षा के महत्व को रेखांकित करना था।

(ङ) क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थान ने पूरे देश में उभरते आर्थिक अवसरों और क्षेत्रीय विकास पर संवाद और विचार-विमर्श को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय संगोष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित की। इस पहल के तहत, “महत्वाकांक्षी पूर्व” संगोष्ठी 12 सितंबर, 2025 को पटना में “स्टार्टअप, एफपीओ और कृषि-व्यवसाय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी” विषय पर आयोजित की गई, जिसमें स्टार्टअप, एफपीओ और कृषि-व्यवसाय की विकास संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद, “उभरता दक्षिण – महानगरों से परे विकास” संगोष्ठी 17 जनवरी, 2026 को मैसूरु में “डिजिटल क्षितिज – आईटी, एमएसएमई, स्टार्टअप, खाद्य और वस्त्र क्षेत्र पर प्रभाव” विषय पर आयोजित की गई, जिसमें महानगरीय केंद्रों से परे विकास को गति देने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर डिजिटलीकरण के परिवर्तनकारी प्रभाव पर विचार-विमर्श किया गया। उसी दिन, “शानदार पश्चिम” संगोष्ठी पुणे में “3आई के माध्यम से सशक्तीकरण: नवाचार, समावेशन और प्रभाव” विषय पर आयोजित की गई, जिसमें आर्थिक सशक्तीकरण में नवाचार, समावेशन और प्रभाव-आधारित रणनीतियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इन

संगोष्ठियों ने हितधारकों को विचारों का आदान-प्रदान करने, उभरते अवसरों का पता लगाने और व्यापक अर्थव्यवस्था के साथ संस्थान के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किए।

(च) प्रत्यक्ष कर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

संस्थान ने आईसीएसआई के सदस्यों और छात्रों के लिए निःशुल्क 'प्रत्यक्ष कर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम' आयोजित किया। यह कार्यक्रम 10 जुलाई, 2025 से 29 अगस्त, 2025 तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम आभासी माध्यम से आयोजित किया गया और विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्यक्ष कर के विभिन्न पहलुओं पर कुल 30 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(छ) पूंजी बाजार सप्ताह 2025

पूंजी बाजार सप्ताह 2025 के अवसर पर, संस्थान ने पूरे देश में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिनका उद्देश्य पूंजी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में विकास और उभरती प्रवृत्तियों पर विचार-विमर्श करना था। पश्चिम भारत क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआईआरओ) ने 18 दिसंबर, 2025 को मुंबई में अपना कार्यक्रम आयोजित किया, जबकि उत्तर भारत क्षेत्रीय कार्यालय (एनआईआरओ) ने उसी तारीख को दिल्ली में अपना कार्यक्रम आयोजित किया। इसके बाद, दक्षिण भारत क्षेत्रीय कार्यालय (एसआईआरओ) द्वारा 19 दिसंबर, 2025 को चेन्नई में कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूर्वी भारत क्षेत्रीय कार्यालय (ईआईआरओ) द्वारा 10 जनवरी, 2026 को कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विनियामक निकायों और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई, जिनके विचारों ने चर्चाओं को समृद्ध किया और कार्यक्रम की कार्यवाही में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ा। ये पहल हितधारकों के साथ जुड़ने तथा पेशेवरों और उद्योग प्रतिभागियों के बीच पूंजी बाजार विनियमों और प्रथाओं के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के निरंतर प्रयास को दर्शाती हैं।

(ज) आईसीएसआई राष्ट्रीय संधारणीयता सम्मेलन 2025

आईसीएसआई राष्ट्रीय संधारणीयता सम्मेलन 2025 का आयोजन 26-27 जुलाई, 2025 को उदयपुर, राजस्थान में "सुदृढ़ भविष्य की दिशा में संधारणीयता को बढ़ावा देना" विषय पर किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि, राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा तथा विशिष्ट अतिथि, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रो. (डॉ.) गौरव वल्लभ की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। सम्मेलन में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र के लोक सभा सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत की भी उपस्थिति रही।

(vii) पाठ्यक्रम

(क) जीएसएमसी 2.0 में आईएफएससी के लिए आईसीएसआई प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का शुभारंभ

आईएफएससी ढांचे के अंतर्गत एक विशिष्ट करियर बनाने के इच्छुक भावी पेशेवरों, अनुपालन अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों के लिए तैयार किए गए निम्नलिखित तीन विशेष पाठ्यक्रम आईसीएसआई द्वारा 26 फरवरी, 2026 को जीएसएमसी 2.0 में शुरू किए गए।

- आईएफएससी में पूंजी बाजार मध्यस्थों के लिए विनियामक ढांचा पाठ्यक्रम विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र की संक्षिप्त समझ प्रदान करता है, जिसमें आवश्यक अनुपालन, परिचालन और जोखिम प्रबंधन शामिल हैं।
- आईएफएससी में निधि प्रबंधन के लिए विनियामक ढांचा: एआईएफ और खुदरा योजना पाठ्यक्रम एआईएफ और खुदरा योजनाओं का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है तथा मूल्यांकन और वित्तीय मॉडलिंग में व्यावहारिक विशेषज्ञता विकसित करता है।
- आईएफएससी में कॉरपोरेट गवर्नंस पाठ्यक्रम आईएफएससी मध्यस्थों के लिए रणनीतिक नेतृत्व कौशल विकसित करने हेतु व्यावहारिक कार्यशालाओं और मामले के अध्ययनों का उपयोग करता है।

(ख) आईसीएसआई ऑनलाइन क्रैश कोर्स

संस्थान ने विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू किए हैं ताकि विभिन्न कानूनों का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने और ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक कौशल एवं विशेषज्ञता विकसित करने में सदस्यों की सहायता की जा सके। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विषयों पर क्रैश कोर्स आयोजित किया गया था :

कंपनी कानून के संदर्भ में कानूनों की व्याख्या	संबंधित पक्ष के लेन-देन	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी टूल्स	वित्तीय विवरणों को समझना	एनबीएफसी अनुपालन की ए से जेड तक जानकारी
---	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---

(ग) आईसीएसआई सदस्यता उपरांत अर्हता (पीएमक्यू) कोर्स

संस्थान ने सदस्यों के लिए निम्नलिखित विषयों में पीएमक्यू कोर्स आयोजित किए हैं:



(घ) आईसीएसआई सर्टिफिकेट कोर्स

अंतर्दृष्टि प्रदान करने और बेहतर समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, निम्नलिखित क्षेत्रों में सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए गए:

आईएफएससी में निधि प्रबंधन के लिए विनियामक ढांचा: एआईएफ और खुदरा योजनाएं
आईएफएससी में पूंजी बाजार मध्यस्थों के लिए विनियामक ढांचे पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
फॉरेंसिक लेखापरीक्षा
वाणिज्यिक संविदा प्रबंधन
जीएसटी
व्यावसायिक पुनःप्रारंभ: कंपनी सचिव की भूमिका में महिलाएं
पीओएसएच
फेमा
आईपीआर
यूआई व्यवसाय प्रबंधक
प्रतिभूति कानून
स्वतंत्र निदेशक
प्रमाणित सीएसआर पेशेवर
ईएसजी
आईएफएससीए
कॉर्पोरेट पुनर्गठन
प्रतिभूतियों / वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन
आईबीसी

(viii) चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल

चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल संस्थान की सबसे प्रतिष्ठित प्रमुख पत्रिका है, जिसे वर्ष 1971 में शुरू किया गया था। आईएसएसएन वाली इस पत्रिका के राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक लाख से अधिक पाठक हैं। यह पत्रिका उद्योग जगत के पेशेवरों, शिक्षाविदों, मंत्रालयों, सरकारी निकायों और अन्य पेशेवरों के बीच मुद्रित और ऑनलाइन माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की जाती है तथा आईसीएसआई के सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए इसके बारे में जागरूकता भी पैदा की जाती है। यह पत्रिका पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करने वाले प्रमुख ऑनलाइन मंच मैगज़टर् पर भी सूचीबद्ध है।

हर महीने, जर्नल में थीम-आधारित लेख प्रकाशित किए जाते हैं। प्रत्येक अंक में अनुसंधान के लिए एक समर्पित खंड होता है, जिसमें कानूनी और वैचारिक अनुसंधान तथा अनुसंधान विधियों के प्रयोग पर केंद्रित अनुसंधान-उन्मुख लेख प्रकाशित किए जाते हैं। ग्लोबल कनेक्ट खंड में अंतरराष्ट्रीय प्रासंगिकता वाले लेख शामिल किए जाते हैं।

जर्नल में अन्य विषयों के साथ-साथ 'कानूनी जगत' पर सामग्री शामिल होती है, जिसमें हाल के निर्णयों के अद्यतन जानकारी प्रकाशित किए जाते हैं, और 'फ्रॉम द गवर्नमेंट' खंड में संबंधित सरकारी आदेश/परिपत्र प्रकाशित किए जाते हैं।

संस्थान की मासिक पहलों को 'एक्टिविटी हाइलाइट्स' के माध्यम से प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रति संस्थान के नवोन्मेषी दृष्टिकोण के साथ-साथ विभिन्न मान्यताओं और अवसरों के लिए किए गए प्रयासों को प्रकाशित किया जाता है, ताकि सदस्यों को इनके बारे में जानकारी दी जा सके।

'बियॉन्ड गवर्नेंस' पर एक विशेष खंड है, जिसमें रोचक कानूनी मामले के अध्ययन, शब्द-पहेली और पुस्तक समीक्षा शामिल हैं। मिसलेनियस कॉर्नर खंड में कॉरपोरेट गवर्नेंस और अन्य उभरते क्षेत्रों, जैसे नैतिकता, जीएसटी, ईएसजी, एमएसएमई, एआई तथा आरओसी और आरडी के न्यायनिर्णयन आदेशों का सार, से संबंधित हाल की प्रवृत्तियों और सरकारी पहलों को शामिल किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है।

पेशेवर समुदाय के बीच समुद्री क्षेत्र के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए, आईसीएसआई ने मिसलेनियस कॉर्नर खंड के अंतर्गत एक समर्पित "मेरीटाइम कॉर्नर" शुरू किया है, जिसमें समुद्री उद्योग से संबंधित प्रमुख शब्दों और विकासक्रम को शामिल किया जाता है।

एक नई पहल शुरू की गई है। प्रत्येक लेख के अंत में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन करने पर पाठक सीधे आईसीएसआई के यूट्यूब चैनल पर लेखों के ऑडियो संस्करण देख सकते हैं। इससे पाठकों को जर्नल के लेखों/सामग्री को सुनने का विकल्प प्रदान करके उन तक आसान पहुंच मिलती है।

चार्टर्ड सेक्रेटरी कलेक्टर सीरीज: चार्टर्ड सेक्रेटरी कलेक्टर सीरीज, वर्षों के दौरान चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल के विभिन्न संस्करणों और खंडों में बिखरे ज्ञान के मोतियों को एकत्रित करके उन्हें एक ही प्रकाशन में संकलित करने की संस्थान की एक पहल है। 'डायरेक्ट टैक्सेस एंड जीएसटी' शीर्षक के अंतर्गत पांचवां संस्करण जून, 2025 में जारी किया गया।

(ड) मान्यताएं, अभ्यावेदन और सुझाव

(i) आईएफएससीए ने कार्यरत कंपनी सचिवों को अधिमानी निर्गम के अनुपालन को प्रमाणित करने हेतु अधिकृत किया

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने 22 अप्रैल, 2026 के परिपत्र संख्या एफ. सं. आईएफएससीए-पीएलएनपी/16/2024-पूजी बाजार के माध्यम से कार्यरत कंपनी सचिवों को यह प्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया है कि किसी जारीकर्ता द्वारा प्रस्तावित कोई भी अधिमानी निर्गम, "आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियम, 2024 के अंतर्गत अधिमानी निर्गम और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के लिए ढांचा" संबंधी परिपत्र में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।

(ii) आईएफएससी संस्थाओं के लिए आईसीएसआई स्टेवार्डशिप सिद्धांतों को अपनाना

आईएफएससीए ने 23 अक्टूबर, 2025 के परिपत्र के माध्यम से निवेशक संरक्षण को बेहतर करने और सुदृढ़ कॉरपोरेट अभिशासन को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससी में स्टेवार्डशिप कोड पर एक ढांचा पेश किया है। आईएफएससीए ने संस्थान द्वारा जारी 'स्टेवार्डशिप पर आईसीएसआई मार्गदर्शक सिद्धांतों' को स्टेवार्डशिप कोड के रूप में मान्यता दी है, जिसे आईएफएससी में निवेश गतिविधियां करने वाली फंड प्रबंधन संस्थाओं और संस्थागत निवेशकों द्वारा अपनाया जा सकता है।

(iii) प्रमुख अभ्यावेदन

तिथि	विवरण	प्राधिकरण
05.05.2025	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारियों की भर्ती के लिए कंपनी सचिव की योग्यता को शामिल करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	आईबीए
06.06.2025	ई-प्रपत्र एमजीटी-8 के प्रारूप में संशोधन करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	एमसीए
06.06.2025	बंगलुरु और दिल्ली में (एमसीए-21 संस्करण 3 पर वार्षिक फाइलिंग प्रपत्र शुरू किए जाने के संबंध में) एमसीए उपयोगकर्ता जागरूकता सत्र आयोजित करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	
06.06.2025	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 के तहत किसी संस्था को कंपनी में परिवर्तित करने के मामले में निगमन प्रमाणपत्र के प्रारूप में संशोधन का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	

06.06.2025	कंपनी कानून और सीमित देयता भागीदारी कानून निपटान योजना, 2025 (सीएल एवं एलएलएसएस-2025) शुरू करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	
18.07.2025	ई-प्रपत्र एमआर-2 दाखिल करने में देरी के मामले में विलंब की माफी की अनुमति देने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	
01.09.2025	विदेशी निदेशकों के लिए डीआईआर-3 केवाईसी के समय मोबाइल ओटीपी सत्यापन की आवश्यकता में छूट देने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	
12.09.2025	वीसी या ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठकों और असाधारण आम बैठकों को आयोजित करने या डाक मतपत्र के माध्यम से विषयों पर निर्णय लेने की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	
23.09.2025	शेयरधारिता और अन्य गैर-वित्तीय प्रमाणनों के प्रमाणीकरण के लिए कंपनी सचिवों को पात्र पेशेवरों के रूप में शामिल करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	
30.09.2025	एमसीए-21 संस्करण 3 पोर्टल का संचालन – हितधारकों के सामने आने वाली समस्याएं और चुनौतियां	
15.10.2025	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वार्षिक ई-प्रपत्र दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	
10.11.2025	“कंपनी कानून और सीमित देयता भागीदारी कानून निपटान योजना, 2025” शुरू करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	
22.12.2025	एमसीए-21 संस्करण 3 पोर्टल का संचालन – हितधारकों के सामने आने वाली समस्याएं और चुनौतियां	
01.08.2025	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 (1) (बी) की प्रयोज्यता से छूट के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	सेबी
27.08.2025	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 के तहत कंपनी सचिव के पेशे को मान्यता देने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
26.09.2025	ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी सचिवों द्वारा ट्रेड मार्क एजेंट के रूप में कार्य करने के आवेदनों पर कार्रवाई करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
12.11.2025	कार्यरत कंपनी सचिव को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 16 (4) और धारा 32 के तहत उपस्थित होने के लिए अधिकृत करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	भारतीय रिजर्व बैंक
19.02.2026	ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्यरत कंपनी सचिवों को ट्रेड मार्क एजेंट के रूप में कार्य करने के आवेदनों पर कार्रवाई से संबंधित मुद्दों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया	पेटेंट, डिज़ाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम)
16.03.2026	क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा नोटिस जारी करने और धारा 12(8) के प्रयोग के संबंध में – प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया एक ही राज्य में नए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की स्थापना के कारण पंजीकृत कार्यालय को उसी राज्य के भीतर स्थानांतरित करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक की मंजूरी से कंपनियों को छूट देने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया अनिवार्य भौतिक प्रस्तुतिकरण के बिना ई-फाइलिंग के माध्यम से दाखिल किए गए आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए आरडी/आरओसी को निर्देश जारी करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने की प्रभावी तारीख के संबंध में धारा 14(1) के पहले परंतुक में संशोधन	एमसीए
18.03.2026	स्टाम्प शुल्क लगाने और उसकी वसूली के अधिकार-क्षेत्र के संबंध में स्पष्टीकरण और हस्तक्षेप की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया	डीओआर
18.03.2026	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बीईएन प्रपत्र दाखिल करने में देरी के लिए माफी योजना/ विलंब माफी शुरू करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	
30.03.2026	सीएसआर निधि प्राप्त करने के लिए पंजीकृत न्यासों के नाम में परिवर्तन/संशोधन की अनुमति देने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	एमसीए
30.03.2026	माननीय एनसीएलटी की विभिन्न पीठों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 और 252 तथा आईबीसी की धारा 59 के तहत मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया	

(iv) सुझाव

तिथि	विवरण	प्राधिकरण
18.08.2025	"केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025" पर आईसीएसआई के सुझाव	सीईआरसी
21.08.2025	"हरित ऋण प्रतिभूति के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष समीक्षक/प्रमाणक की नियुक्ति के संशोधित मानदंड" पर सेबी के परामर्श पत्र पर आईसीएसआई के सुझाव	सेबी
10.11.2025	निम्न पर आईसीएसआई के सुझाव: ● भारतीय रिजर्व बैंक (लघु वित्त बैंक – गवर्नेंस) निदेश, 2025; ● भारतीय रिजर्व बैंक (भुगतान बैंक – गवर्नेंस) निदेश, 2025; ● भारतीय रिजर्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – गवर्नेंस) निदेश, 2025; ● भारतीय रिजर्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – गवर्नेंस) निदेश; ● भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – गवर्नेंस) निदेश; ● भारतीय रिजर्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – गवर्नेंस) निदेश; ● भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं – गवर्नेंस) निदेश; ● भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – गवर्नेंस) निदेश; ● भारतीय रिजर्व बैंक (विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना) दिशानिर्देश, 2025	भा.रि.बैंक
29.01.2026	औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2025 के मसौदे पर आईसीएसआई के सुझाव	श्रम और रोजगार मंत्रालय
11.02.2026	सामाजिक सुरक्षा संहिता (केंद्रीय) नियम, 2025 के मसौदे पर आईसीएसआई के सुझाव	
13.02.2026	वेतन संहिता (केंद्रीय) नियम, 2025 के मसौदे पर आईसीएसआई के सुझाव	
13.02.2026	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (केंद्रीय) नियम, 2025 के मसौदे पर आईसीएसआई के सुझाव	
22.02.2026	आयकर नियम, 2026 के मसौदे पर आईसीएसआई के सुझाव	सीबीडीटी
27.02.2026	विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) संशोधन नियम, 2025 के मसौदे पर आईसीएसआई के सुझाव	आईपीएफ प्राधिकरण
30.03.2026	अधिमानी निर्गम और योग्य संस्थागत नियोजन के लिए विनियामक ढांचे पर आईसीएसआई के सुझाव	आईएफएससीए
30.03.2026	सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा अधिकार निर्गम के लिए विनियामक ढांचे पर आईसीएसआई के सुझाव	
30.03.2026	आईएफएससीए (प्रतिभूति बाजारों में बाजार दुरुपयोग का निषेध) विनियम, 2026 पर आईसीएसआई के सुझाव	

(v) आयकर विधेयक, 2025 की धारा 515(3)(ख) के तहत दी गई "लेखाकार" की परिभाषा में 'कंपनी सचिव' के पेशे को शामिल करने के लिए प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन

वित्त मंत्रालय	
02.07.2025	श्री हर्ष मल्होत्रा, माननीय राज्य मंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अन्य मंत्री	
02.07.2025	श्रीमती रक्षा निखिल खडसे, माननीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री
02.07.2025	श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, माननीय लोक सभा सदस्य
02.07.2025	श्री भुवनेश्वर कालिता, माननीय राज्य सभा सदस्य
04.07.2025	श्रीमती कमलजीत सहरावत, माननीय लोक सभा सदस्य
04.07.2025	श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्रालय
07.07.2025	श्री दिनेश मकवाना, माननीय लोक सभा सदस्य
07.07.2025	श्री शंकर लालवानी, माननीय लोक सभा सदस्य
10.07.2025	श्री बसवराज बोम्मई, माननीय लोक सभा सदस्य और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री
11.07.2025	श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
आयकर विधेयक, 2025 पर लोक सभा की प्रवर समिति के सदस्य	
27.05.2025	श्री सुधीर गुप्ता
03.07.2025	श्री राजू बिष्ट
04.07.2025	श्री भर्तृहरि महताब
07.07.2025	श्री एन. के. प्रेमचंद्रन

(च) छात्र वैश्विक पहल और विकास**(i) छात्र पंजीकरण**

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीएसईईटी, सीएस कार्यकारी कार्यक्रम और सीएस व्यावसायिक कार्यक्रम में पंजीकृत छात्रों की संख्या निम्नानुसार है:

सीएसईईटी रिमोट प्रक्टर मोड – 40565 पुनर्गठित (केन्द्र आधारित परीक्षा)–5519	46084
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम	31580
प्रोफेशनल प्रोग्राम	6935

(ii) कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सीएसईईटी)

सीएसईईटी (पुनर्गठित): संस्थान ने 16 दिसंबर, 2025 से रिमोट प्रक्टर मोड से केंद्र-आधारित परीक्षा प्रारूप में परिवर्तन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह परिवर्तन सीएस पेशे को उभरते कारपोरेट, तकनीकी और विनियामक विकास के अनुरूप बनाने के साथ-साथ भावी कंपनी सचिवों के लिए मजबूत आधार तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। नई संरचना के तहत पहला सत्र जून 2026 में आयोजित किया गया।

सीएसईईटी रिमोट प्रक्टर मोड: वर्ष 2025–26 के दौरान सीएसईईटी की रिमोट प्रक्टर मोड से परीक्षाएं चार बार आयोजित की गईं।

(iii) छात्र आउटरीच पहल**(क) कैरियर जागरूकता**

संस्थान ने पूरे देश के विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनेक करियर जागरूकता कार्यक्रम (सीएपी) आयोजित किए। संस्थान ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पूरे भारत में लगभग 128 करियर मेलों और प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।

कोर्स को लोकप्रिय बनाने और दूरदराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों से नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए, संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीएपी आयोजित करने पर अपना ध्यान बढ़ाया। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय के सहयोग से, संस्थान ने विभिन्न आर्मी पब्लिक स्कूलों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को इस पेशे के बारे में जानकारी दी जा सके। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओआर) तथा असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड (एसएसईबी) के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में भी करियर मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए गए।

	(क)		(ख)		(ग)	
	आयोजित सीएपी	उपस्थित छात्रों की संख्या	आयोजित करियर मेले	उपस्थित छात्रों की संख्या	आयोजित शिक्षक सम्मेलन	उपस्थित शिक्षकों की संख्या
ईआईआरसी	385	68258	20	2706	9	696
एनआईआरसी	541	102136	39	10051	13	727
एसआईआरसी	604	146701	37	337082	16	1077
डब्ल्यूआईआरसी	494	91663	32	11190	18	1100
कुल	2024	408758	138	361167	56	3600

(ख) कक्षा-कक्ष (क्लास रूम) शिक्षण

संस्थान अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और देशभर में स्थित शाखाओं (चैप्टरों) के नेटवर्क के माध्यम से सीएसईईटी, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्रामों के छात्रों के लिए कक्षा शिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, संस्थान के साथ अध्ययन केंद्र

के रूप में सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थानों को अपने-अपने क्षेत्रों में छात्रों के लिए कक्षा शिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(ग) नॉलेज आन डिमांड (केओडी)

नॉलेज आन डिमांड संस्थान की एक पहल है, जिसके अंतर्गत छात्रों को अपनी आवश्यकता के अनुसार महत्वपूर्ण विषयों पर रिकार्ड किए गए सत्र देखने और संस्थान के शिक्षण प्रबंधन प्रणाली मंच पर अपनी सुविधा के अनुसार आनलाइन अपने ज्ञान को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

(घ) आईसीएसआई मास्टर कक्षाएं

संस्थान जून/दिसंबर परीक्षा सत्र शुरू होने से पहले एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के छात्रों के लिए विशेष मास्टर कक्षाओं का आयोजन करता है।

(ङ) केंद्रीकृत सीएसईईटी कक्षाएं

संस्थान सीएसईईटी परीक्षा सत्रों की तैयारी कर रहे छात्रों की सहायता के लिए निःशुल्क केंद्रीकृत सीएसईईटी कक्षाएं आयोजित करता है।

(च) आनलाइन संदेह निवारण सत्र

परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, संस्थान ने जून और दिसंबर की कंपनी सचिव परीक्षा के सत्र से पहले एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के छात्रों के लिए आनलाइन संदेह निवारण सत्र आयोजित किए।

(iv) युवोत्सव

संस्थान ने अपने प्रमुख वार्षिक राष्ट्रीय छात्र महोत्सव, “युवोत्सव-2026” (कंपनी सचिव छात्रों का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन) का आयोजन 11-12 जनवरी, 2026 को चेन्नई में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर किया। वर्ष 2026 से युवोत्सव का प्रारूप विकेंद्रीकृत किया गया, जिसके तहत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और चैप्टर को चेन्नई में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ अपने-अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई। चार क्षेत्रीय कार्यालयों और 73 शाखाओं (चैप्टरों) में कुल 24 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 2,300 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन 12 जनवरी, 2026 को युवा मार्च और उसके बाद आधिकारिक पुरस्कार समारोह के साथ हुआ।

(v) विद्यार्थी माह

जुलाई माह को प्रत्येक वर्ष सभी आईसीएसआई क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं (चैप्टरों) में ‘छात्र माह’ के रूप में मनाया जाता है। पूरे माह के दौरान, संस्थान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, आनलाइन अभ्यास परीक्षाओं, क्रैश कोर्स, पुनरावृत्ति कक्षाओं, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास कार्यक्रमों, प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिताओं और जीवन कौशल सत्रों का आयोजन करता है, जिसका समापन विशेष करियर जागरूकता सप्ताह के साथ होता है। वर्ष 2026 से छात्र माह की गतिविधियों को पूरे वर्ष में विभाजित किया गया है और प्रत्येक चैप्टर पूरे वर्ष हर माह छात्र गतिविधियों का आयोजन करेगी।

(vi) पुरस्कार और छात्रवृत्ति— आईसीएसआई छात्र शिक्षा निधि ट्रस्ट

आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठी भूमि वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, संस्थान ने “आईसीएसआई छात्र शिक्षा निधि ट्रस्ट” की स्थापना की। इस ट्रस्ट के तहत पात्र छात्रों को एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के दोनों चरणों के लिए पंजीकरण, प्रवेश, ट्यूशन, परीक्षा और परीक्षा-पूर्व परीक्षा शुल्क से पूरी छूट दी जाती है। यह छूट जारी रखने के लिए छात्रों को निर्धारित शैक्षणिक प्रदर्शन मानकों को बनाए रखना आवश्यक है। वर्ष के दौरान, इस योजना से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 122 छात्रों और शैक्षणिक रूप से मेधावी वर्ग के 308 छात्रों को लाभ मिला।

माह	कुल आवेदन	आर्थिक पृष्ठीभूमि	अत्यधिक मेधावी	जारी कुल अनुदान (₹)
अप्रैल, 25	35	4	11	2,13,150
मई, 25	14	3	7	1,88,000
जून, 25	18	5	7	1,95,950
जुलाई, 25	59	9	15	4,40,700
अगस्त, 25	80	14	34	8,59,950
सितम्बर, 25	105	14	58	12,05,300
अक्टूबर, 25	65	10	30	6,46,000

नवम्बर, 25	56	08	27	5,60,200
दिसम्बर, 25	73	13	40	8,91,800
जनवरी, 26	65	18	22	5,04,650
फरवरी, 26	67	12	26	6,34,900
मार्च, 26	66	12	31	6,58,900
कुल	703	122	308	69,99,500

(vii) **शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)**

देशभर में शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और छात्रों के समग्र विकास में सहायता करने के लिए, आईसीएसआई ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ संस्थागत समझौते किए हैं। अपनी 'शैक्षणिक संपर्क' पहल के तहत, संस्थान ने 150 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 17 भारतीय प्रबंधन संस्थानों और 11 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के साथ रणनीतिक साझेदारियां शामिल हैं।

(viii) **अन्य पहलें**

(क) **ओलंपियाड**

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आईसीएसआई द्वारा निम्नलिखित कॉमर्स ओलंपियाड आयोजित किए गए:

- आईसीएसआई ने इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन के सहयोग से 29 नवंबर, 2025 को पूरे भारत के विद्यालयों में कक्षा XI और XII के छात्रों के लिए आईसीएसआई कॉमर्स ओलंपियाड आयोजित किया।
- आईसीएसआई ने मेसर्स हमिंगबर्ड एजुकेशन लिमिटेड के सहयोग से 09 दिसंबर, 2025 को पूरे भारत के विद्यालयों में कक्षा XI और XII के छात्रों के लिए आईसीएसआई कॉमर्स ओलंपियाड आयोजित किया।
- आईसीएसआई ने मेसर्स सिल्वरजोन फाउंडेशन लिमिटेड के सहयोग से 07 नवंबर, 2025 और 02 दिसंबर, 2025 को पूरे भारत के विद्यालयों में कक्षा XI और XII के छात्रों के लिए आईसीएसआई कॉमर्स ओलंपियाड आयोजित किया।

(ख) **राष्ट्रीय ऑनलाइन संविधान दिवस प्रश्नोत्तरी**

भारत सरकार के विधि कार्य विभाग की पहल के अनुरूप, संस्थान ने 26 नवंबर, 2025 को छात्रों के लिए "ऑनलाइन संविधान दिवस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य छात्रों में संविधान और उसकी विशेषताओं, विशेष रूप से भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों, के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

(ग) **समसामयिकी एवं सामान्य ज्ञान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी**

भारतभर के उच्चतर माध्यमिक और स्नातक छात्रों के लिए वार्षिक 'समसामयिक एवं सामान्य ज्ञान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी – 2025' आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य छात्रों के सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं और कॉरपोरेट अनुपालनों के प्रति जागरूकता के प्रारंभिक स्तर का आकलन करना था।

(घ) **अखिल भारतीय कंपनी कानून प्रश्नोत्तरी 2025**

छात्रों में अवधारणात्मक स्पष्टता और कॉरपोरेट कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, 08 नवंबर, 2025 को कोलकाता में अखिल भारतीय कंपनी कानून प्रश्नोत्तरी 2025 के राष्ट्रीय अंतिम चरण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

(ङ) **24वीं अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता 2025**

13 नवंबर, 2025 को गोवा में 24वीं अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता 2025 के राष्ट्रीय अंतिम चरण का आयोजन किया गया।

(च) **25वीं अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता 2025**

कॉरपोरेट लेखन कौशल को बेहतर बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के छात्रों के लिए 25वीं अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद द्वारा 16 जून, 2025 को किया गया।

(छ) 23वीं अखिल भारतीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025

23वीं अखिल भारतीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का राष्ट्रीय चरण 22 नवंबर, 2025 को कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर चयनित टीमों ने भाग लिया।

(ज) डिबेटिंग सोसाइटी

सार्वजनिक भाषण, व्यवस्थित तर्क और प्रभावशाली संचार कौशल को बढ़ावा देने के लिए, संस्थान ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और अधिकांश शाखाओं (चैप्टरों) में आईसीएसआई डिबेटिंग सोसायटी को सक्रिय किया।

(झ) भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, अग्निवीरों और बलिदानियों के परिवारों के लिए आईसीएसआई छूट/रियायत योजना

आईसीएसआई ने भारत सरकार की विभिन्न पहलों के अनुरूप भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, अग्निवीर कर्मियों और बलिदानियों के परिवारों को आईसीएसआई छूट/रियायत योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों को सीएस कार्यकारी कार्यक्रम में पंजीकरण के समय देय शुल्क से 100% रियायत दी जाती है, जबकि प्रशिक्षण के अन्य सभी शुल्क उनकी संबंधित श्रेणी के अनुसार पूर्ण रूप से लागू होते हैं:

- भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और सभी अर्धसैनिक बलों के बलिदानियों (जो सेवा के दौरान या तो युद्ध में हताहत होने या किसी अन्य कारण से वीरगति को प्राप्त हुए हैं) के वार्ड और विधवाएँ।
- भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और सभी अर्धसैनिक बलों (जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने वाले रक्षा कर्मी भी शामिल हैं) के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मी।
- भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और सभी अर्धसैनिक बलों (जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने वाले रक्षा कर्मी भी शामिल हैं) के सभी कर्मियों के वार्ड।
- वे अभ्यर्थी जो भारत सरकार की अग्निपथ योजना के अंतर्गत "अग्निवीर" के रूप में भर्ती हुए और चार साल पूरे करने के बाद (इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर) आवेदन करते हैं।

(ञ) वेबिनार श्रृंखला – भावी कंपनी सचिवों को सशक्त बनाने की आईसीएसआई की पहल

आईसीएसआई ने छात्रों के ज्ञान को फिर से सक्रिय करने, ताजा करने और निखारने के उद्देश्य से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की थी, जिसे छात्रों से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

(ट) उच्च योग्यता के आधार पर पेपरवार छूट

पूर्व शैक्षणिक उपलब्धियों को मान्यता देने और शैक्षणिक प्रगति को सुगम बनाने के लिए, संस्थान ने नई पाठ्यक्रम योजना, 2022 के तहत कंपनी सचिव कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए पेपरवार छूट शुरू की। निर्धारित उच्च शैक्षणिक योग्यताएं रखने वाले पात्र उम्मीदवारों को स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित विषयों में छूट प्रदान की गई। पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और संबंधित प्रावधानों से संबंधित विस्तृत निर्देश हितधारकों को उपलब्ध कराए गए और संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए गए।

(ठ) विदेशी परीक्षा केंद्र सहायता

संस्थान ने दुबई में स्थित विदेशी परीक्षा केंद्र के माध्यम से अपनी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम परीक्षाओं में वैश्विक स्तर पर शामिल होने की सुविधा जारी रखी। इस पहल से मध्य पूर्व और पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को भारत की यात्रा किए बिना परीक्षाओं में शामिल होने की सुविधा मिलती है, जिससे परीक्षा की पहुंच और सुविधा बढ़ती है।

दुबई केंद्र भारत के परीक्षा केंद्रों पर लागू समान मानकों, प्रक्रियाओं और परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार कार्य करता है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। विदेशी परीक्षा केंद्र का लगातार संचालन संस्थान की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय छात्र संख्या को सहयोग देने और कंपनी सचिव की योग्यता की वैश्विक पहचान को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(ड) नये पाठ्यक्रम पर जाना

शैक्षणिक प्रासंगिकता सुनिश्चित करने और बदलती पेशेवर तथा विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए, संस्थान ने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्रामों के लिए नई पाठ्यक्रम योजना, 2022 लागू की। छात्रों को इस बदलाव को आसानी से

अपनाने में सहायता देने के लिए व्यापक जागरूकता पहल की गई, जिनमें सामूहिक ई-मेल, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, संस्थान की वेबसाइट, सोशल मीडिया मंचों और छात्र पोर्टलों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना शामिल था। पात्रता मानदंड, विषयों के समायोजन, परीक्षा में लागू होने वाले प्रावधानों और बदलाव से संबंधित प्रावधानों के बारे में हितधारकों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

छात्रों को बदलाव की प्रक्रिया आसानी से पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए एसएमएसएच पोर्टल के माध्यम से एक समर्पित ऑनलाइन बदलाव सुविधा उपलब्ध कराई गई। मिश्रित माध्यम में ऑनलाइन केंद्रीकृत कक्षाओं के आयोजन से शैक्षणिक सहायता को और मजबूत किया गया।

(ढ) प्रतिलेख और शिक्षा सत्यापन

कंपनी सचिव की योग्यता को वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान मिलने के साथ, विदेशों में उच्च शिक्षा, पेशेवर अवसरों और आव्रजन के विकल्प तलाशने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थान ने उच्च शिक्षा, पेशेवर प्रमाणपत्रों और अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए आवेदनों में सहायता हेतु 209 ट्रांसक्रिप्ट जारी किए। इसके अतिरिक्त, नियोक्ताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी प्राधिकरणों और अधिकृत एजेंसियों से प्राप्त 80 शैक्षणिक सत्यापन अनुरोधों पर कार्रवाई की गई, जिससे शैक्षणिक योग्यताओं का समय पर और सही सत्यापन सुनिश्चित हुआ। ये सेवाएं छात्रों और सदस्यों की पेशेवर गतिशीलता में निरंतर सहायता कर रही हैं और साथ ही संस्थान की विश्वसनीयता तथा मान्यता को मजबूत कर रही हैं।

(ण) पुनः पंजीकरण के माध्यम से वेलकम बैक स्कीम

संस्थान ने “वेलकम बैक पुनः-पंजीकरण स्कीम” जारी रखी, जिसका उद्देश्य पात्र छात्रों को कंपनी सचिव बनने की अपनी यात्रा फिर से शुरू करने का अवसर प्रदान करना है। यह योजना उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए पंजीकरण नहीं कराया है और जिनकी पंजीकरण अवधि समाप्त हो गई है, जिसके कारण वे नए सिर से पंजीकरण के लिए पात्र नहीं रह गए हैं। इस योजना के तहत, ऐसे छात्रों को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम दोबारा किए बिना सीधे प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाती है, जिससे उनका महत्वपूर्ण समय बचता है और उनकी शैक्षणिक निरंतरता बनी रहती है।

(त) छात्र एमनेस्टी स्कीम 2025

पूर्व छात्रों को अपनी शैक्षणिक स्थिति नियमित करने और अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, संस्थान ने 01 दिसंबर, 2025 से छात्र एमनेस्टी स्कीम 2025 शुरू की। 01 दिसंबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक कुल 715 छात्रों ने इस योजना का सफलतापूर्वक लाभ उठाया। यह योजना उन पूर्व छात्रों को, जिनका पंजीकरण समाप्त हो चुका है और जो नए सिर से पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं, ₹5,000/- के मामूली शुल्क का भुगतान करके दोबारा नामांकन कराने, अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने और कंपनी सचिव बनने की योग्यता प्राप्त करने की दिशा में अपनी राह फिर से बनाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए, योजना की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त, 2026 तक कर दी गई।

(थ) एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पंजीकरण के लिए पात्रता में संशोधन

संस्थान ने कार्यकारी कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन किया है और इसके अनुसार, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं:

- (क) सीएसईईटी उत्तीर्ण उम्मीदवार
- (ख) सीएस फाउंडेशन उत्तीर्ण छात्र
- (ग) स्नातक और स्नातकोत्तर
- (घ) सीएमए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण छात्र
- (ङ) स्नातक कार्यक्रम (03 वर्ष) के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र – [अस्थायी पंजीकरण]
- (च) सीए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र
- (छ) किसी मान्यता प्राप्त इंटीग्रेटेड प्रोग्राम (05 वर्ष की अवधि) के 6वें सेमेस्टर को उत्तीर्ण करने वाले छात्र
- (ज) किसी मान्यता प्राप्त इंटीग्रेटेड प्रोग्राम (05 वर्ष की अवधि) के 6वें सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र – [अस्थायी पंजीकरण]

(द) आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (सामान्य अनारक्षित वर्ग) के लिए शुल्क में छूट

आईसीएसआई ने आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए शुल्क में छूट की सुविधा शुरू की है। इस शुल्क छूट श्रेणी के तहत, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को सीएस कोर्स के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पंजीकरण के समय शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। इस छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में तहसीलदार, उप-मंडल दंडाधिकारी (एसडीएम), जिला दंडाधिकारी (डीएम) या संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र शामिल हैं, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि छात्र के परिवार की आय ₹3,00,000/- से कम या उसके बराबर है।

(ix) अकादमिक पहलें

i. पाठ्यक्रम योजना 2022 के तहत अध्ययन सामग्री का अद्यतन (2025–2026 के लिए)

- पुनर्गठित सीएसआईटी अध्ययन सामग्री (दिसंबर 2025): उभरते कॉरपोरेट, तकनीकी और विनियामक विकास के अनुरूप बने रहने के लिए, संस्थान ने सीएसआईटी पाठ्यक्रम की व्यापक समीक्षा की। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप चार विषयों की अध्ययन सामग्री तैयार की गई।
- एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम की अध्ययन सामग्री: छात्रों को नवीनतम विकास से अवगत कराने और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देने के लिए, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (कुल 7 प्रश्नपत्र) और प्रोफेशनल प्रोग्राम (कुल 14 प्रश्नपत्र) की अध्ययन सामग्री को पूरी तरह से अद्यतन किया गया।

ii. 2022 आईसीएसआई पाठ्यक्रम योजना 2022 के तहत ऐच्छिक पेपर की शुरुआत

संबंधित विषयों का अधिक व्यापक और विशेष अध्ययन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संस्थान ने ८ प्रोफेशनल प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित ऐच्छिक पेपर शुरू किए। ये पेपर विशिष्ट क्षेत्रों में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं और छात्रों को समकालीन कॉरपोरेट, विनियामक और तकनीकी विकास के अनुरूप उन्नत दक्षताएं हासिल करने में सक्षम बनाते हैं।

(क) एडवांस्ड डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस (ऐच्छिक 4.5)

(ख) आईएफएससीए – रेगुलेशंस, लिस्टिंग एंड कंप्लायंस (ऐच्छिक 4.6)

iii. नमूना प्रश्नपत्र

संस्थान द्वारा सीएसआईटी पाठ्यक्रम की समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक समीक्षा किए जाने के बाद, संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रत्येक विषय के लिए नमूना प्रश्नपत्र तैयार किया गया और छात्रों को अद्यतन परीक्षा प्रारूप से परिचित कराने के लिए आईसीएसआई की वेबसाइट के शैक्षणिक पोर्टल पर अपलोड किया गया। इसके अलावा, नए शुरू किए गए ऐच्छिक पेपर के तहत 'आईएफएससीए – रेगुलेशंस, लिस्टिंग एंड कंप्लायंस' पेपर के लिए भी नमूना प्रश्नपत्र तैयार किया गया और छात्रों को परीक्षा पद्धति से परिचित कराने के लिए आईसीएसआई की वेबसाइट के शैक्षणिक पोर्टल पर अपलोड किया गया।

iv. मासिक अपडेट

छात्रों को वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, संस्थान ने हाल के विनियामक और अन्य विकासों को शामिल करते हुए मॉड्यूलवार और विषयवार मासिक अद्यतन जारी किए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्र व्यावसायिक, कानूनी और विनियामक वातावरण में होने वाले गतिशील बदलावों से लगातार अवगत रहें।

v. ई-पत्रिकाएं

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मासिक आधार पर जारी की गई ई-पत्रिकाएं 'छात्र कंपनी सचिव' और 'सीएसआईटी कम्प्यूनिक' थीं।

vi. गुजरात मेरीटाइम यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने गुजरात मेरीटाइम विश्वविद्यालय के सहयोग से 'मेरीटाइम रेगुलेशन एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन' प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य समुद्री कानून के व्यवहार, शिपिंग प्रबंधन, समुद्री बीमा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जटिल कानूनी व्यवस्था की समझ विकसित करना है। यह प्रोग्राम विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो समुद्री नियामक ढाँचों में उन्नत ज्ञान और दक्षता हासिल करना चाहते हैं, और इस विशेष क्षेत्र में अनुपालन पेशेवरों के रूप में भूमिका निभाने के लिए व्यक्तियों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

vii. आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने पूरे भारत के छात्रों के लिए स्वयं/स्वयं प्लस मंच पर कौशल-आधारित कोर्स उपलब्ध कराने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। इस सहयोग का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता को सुगम बनाना और प्रभावी शिक्षण संसाधनों के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देना है। लगभग 12 घंटे की अवधि वाला 'कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड ब्राफिटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स' कोर्स स्वयं प्लस पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया। यह कोर्स संस्थान के छात्रों सहित आम जनता के लिए खुला है।

(छ) प्रमुख कार्यक्रम**(i) 26वां राष्ट्रीय पेशेवर कंपनी सचिव सम्मेलन**

संस्थान ने 26वां राष्ट्रीय पेशेवर कंपनी सचिव सम्मेलन 14-15 जून, 2025 को विवांता गुवाहाटी में "डायनैमिक रेग्युलेटरी लैंडस्केपर्स सीएस/एक्सेलिंग स्ट्रैटेजीज" विषय पर आयोजित किया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, माननीय असम के राज्यपाल द्वारा किया गया। श्री भुवनेश्वर कालिता, माननीय राज्य सभा सदस्य और श्री दिलीप सैकिया, माननीय लोक सभा सदस्य ने भी विशेष अतिथि के रूप में सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से 400 प्रतिनिधियों ने प्रत्यक्ष रूप से और 3,000 प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया।

(ii) पीसीएस दिवस 2025

संस्थान ने 15 जून, 2025 को सीसीजीआरटी, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं के माध्यम से पीसीएस दिवस 2025 मनाया। इस अवसर पर "डायनैमिक रेग्युलेटरी लैंडस्केपर्स सीएस/एक्सेलिंग स्ट्रैटेजीज" विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सदस्यों को इस विषय से संबंधित उपयुक्त विषयों पर पैनल चर्चाओं, सेमिनारों, अध्ययन मंडल वार्ताओं, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से जोड़ा गया।

(iii) जीएसटी दिवस 2025

संस्थान प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को जागरूकता पैदा करने और 01 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू किए जाने का स्मरण करने के लिए जीएसटी दिवस मनाता है। संस्थान ने जुलाई, 2025 में क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं (चेप्टरों) के माध्यम से जीएसटी दिवस की 8वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर पैनल चर्चाओं, सेमिनारों और अध्ययन मंडल बैठकों के माध्यम से सदस्यों को समकालीन जीएसटी विषयों के बारे में जानकारी दी गई।

(iv) आईआईसीए उत्तर-पूर्व सम्मेलन 2025

संस्थान ने 11-12 जुलाई, 2025 को शिलांग में आयोजित आईआईसीए उत्तर-पूर्व सम्मेलन 2025 के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संस्थागत भागीदार के रूप में सहयोग किया। सम्मेलन का विषय 'विचार से निगमन तक' था। माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कौनराड के संगमा ने मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन का उद्घाटन किया। सीएस रणजीत पांडे, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई और सीएस आशीष गर्ग, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई ने सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

(v) आईपीएफ का 9वां स्थापना दिवस

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईपीएफ) ने आईसीएसआई और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर) के सहयोग से 08 सितंबर, 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में "क्लेमिंग द अनक्लेम्ड: अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ आइडल फाइनेंशियल एसेट्स इन इंडिया" विषय पर अपना 9वां स्थापना दिवस आयोजित किया। श्री संजीव सान्याल, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, भारत सरकार; श्रीमती अनीता शाह अकेला, सीईओ, आईपीएफ और संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार; लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य सिन्हा, महाप्रबंधक, आईपीएफ और श्री शोभित श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, आईपीएफ ने उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ाई।

(vi) आईसीएसआई का 57वां स्थापना दिवस

आईसीएसआई ने 04 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में "सुशासन की पटकथा, विकसित भारत का निर्माण" विषय पर अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। राज्य सभा के माननीय सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्री संजीव सान्याल

ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। आईसीएसआई ने इस अवसर पर संस्थान के पूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सचिवों को भी सम्मानित किया। व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं, वरिष्ठ कॉरपोरेट पेशेवरों, निदेशकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, आईसीएसआई के पूर्व अध्यक्षों और सचिवों, आईसीएसआई के सदस्यों, छात्रों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का आईसीएसआई के सोशल मीडिया माध्यमों पर सीधा प्रसारण भी किया गया।

(vii) 53वां राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन

संस्थान ने 31 अक्टूबर, 2025 से 02 नवंबर, 2025 तक होटल ग्रैंड हयात कोच्चि, बोलगट्टी, कोच्चि, केरल में 'प्रगतिशील, समावेशी और सतत भारत' विषय पर 53वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव अधिवेशन का आयोजन किया। अधिवेशन की शोभा मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, माननीय केरल के राज्यपाल; सम्मानित अतिथि श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, माननीय लोक सभा सदस्य और विशेष अतिथि श्री एम. पी. अहमद, अध्यक्ष, मालाबार समूह ने बढ़ाई। अधिवेशन में सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और पेशेवर समुदाय से लगभग 4,000 प्रतिनिधियों ने प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भाग लिया। अधिवेशन के दौरान छह तकनीकी सत्र और दो विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिनमें विनियामकों, कॉरपोरेट जगत के लीडर, उद्योग विशेषज्ञों आदि सहित प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया। संस्थान की परिषद के साथ सदस्यों के संवाद के लिए एक खुला सत्र भी आयोजित किया गया।

(viii) आईसीएसआई प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम

आईसीएसआई ने 14 मई, 2025 को आईसीएसआई मुख्यालय, नई दिल्ली में आईसीएसआई प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंत्रालय के विभिन्न विभागों के साथ 2023 बैच (14वीं पीसीपी) के भारतीय कॉरपोरेट कानून सेवा (आईसीएसआई) प्रशिक्षु अधिकारियों के ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत भारतीय कॉर्पोरेट लॉ सेवा अकादमी (आईसीएसआई) से प्राप्त संचार के अनुसरण में आयोजित किया गया।

(ix) 8वां आईसीएसआई लीडरशिप समिट – 2025

8वां आईसीएसआई लीडरशिप समिट – 2026 30 जनवरी से 01 फरवरी, 2026 तक जेपी ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिजॉर्ट, ग्रेटर नोएडा में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस समिट में आईसीएसआई के परिषद सदस्यों, चारों क्षेत्रीय परिषदों के सदस्यों, संस्थान की शाखाओं (चैप्टरों) के अध्यक्षों, संस्थान के वरिष्ठ प्रबंधन और अधिकारियों ने भाग लिया।

(ज) अंतरराष्ट्रीय पहचान, ब्रांड मजबूती और मीडिया में मौजूदगी

(i) अंतरराष्ट्रीय पहचान

(क) आईसीएसआई द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

आईसीएसआई मध्य-पूर्व सम्मेलन 2025, दुबई, यूएई

तिथि	24 – 26 अप्रैल, 2025
थीम	सुशासन: पूंजी बाजारों को सशक्त बनाना
मुख्य अतिथि	श्री राम नाथ कोविंद भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति
सम्मानित अतिथि	- श्री सतीश कुमार सिवन महावाणिज्य दूत, भारतीय महावाणिज्य दूतावास, दुबई - महामहिम डॉ. मारिया हनीफ अल कासिम आर्थिक नीति एवं अध्ययन विभाग की सहायक अवर सचिव, अर्थव्यवस्था मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात - माननीय मिर्जा हुसैन अल सईद निदेशक, महामहिम शेख हमदान बिन राशिद अल मकतूम कार्यालय - महामहिम डॉ. मोहम्मद सईद अल किंदी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इन्वेस्कोर और पूर्व पर्यावरण एवं जल मंत्री, संयुक्त अरब अमीरात
साझेदार	सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसईपीसी)
24 अप्रैल 2025 को दुबई फाइनेंशियल मार्केट (डीएफएम) का अध्ययन दौरा	

18वां अंतरराष्ट्रीय पेशेवर विकास और फेलोशिप कार्यक्रम (आईपीडीएफपी), श्रीलंका

तिथि	20-27 जून, 2025 26 जून, 2025 को कोलंबो, श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
थीम	इवोल्यूशन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस इन द डिजिटल एज
मुख्य अतिथि	श्री सथनाथन सुदर्शन, परिषद सदस्य, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड कॉरपोरेट सेक्रेटरीज

आईसीएसआई चौथा अंतराष्ट्रीय सम्मेलन

तिथि	03-04-05 सितंबर, 2025
थीम	एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, एन्हांसिंग गुड गवर्नेंस
मुख्य अतिथि	डॉ. एस. जानकीरमन, सिडनी में भारत के महावाणिज्यदूत
विशेष अतिथि	श्री के. राजारमन, अध्यक्ष, आईएफएससीए
विशेष सत्र	भारत के प्रथम आईएफएससी, गिफ्ट सिटी में व्यावसायिक अवसर
ज्ञान साझेदार	- सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) - ऑस्ट्रेलिया इंडिया चौबर ऑफ कॉमर्स (एआईसीसी)
अध्ययन दौरा	05 सितंबर, 2025 को यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, वोलोंगोंग परिसर में।
"भारत-ऑस्ट्रेलिया सुविधा केंद्र" शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा दोनों देशों की कंपनियों को एक-दूसरे के देशों में कार्यालय और सहायक कंपनियां स्थापित करने में सहायता करना है।	

आईसीएसआई ने सीएसआईए ग्लोबल गवर्नेंस अवॉर्ड्स 2026 की मेजबानी की

आईसीएसआई ने 27 फरवरी, 2026 को मुंबई (महाराष्ट्र) में कॉरपोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन लिमिटेड के लिए ग्लोबल गवर्नेंस अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन किया। वर्ष 2026 के इन पुरस्कारों में सीएसआईए के 12 सदस्य देशों में जिम्मेदार सुशासन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों और कॉरपोरेट संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों के माध्यम से उन व्यक्तियों और कॉरपोरेट संस्थाओं की उपलब्धियों का सम्मान किया गया जो विनियामक जटिलता, ईसीजी संबंधी जवाबदेही तथा डिजिटल बदलाव के दौर में सुशासन के भविष्य को सक्रिय रूप से आकार दे रहे हैं। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, पुरस्कार समारोह की शुरुआत ईसीजी तथा नैतिकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रौद्योगिकी विषयों पर दो पैनल चर्चाओं के साथ हुई।

विभिन्न देशों से 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने उपलब्धियों के इस उत्सव में भाग लिया, सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रेरित किया और उस मजबूत आधार को और सुदृढ़ किया, जिस पर वैश्विक व्यापार टिका हुआ है।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आइटीईसी) कार्यक्रम

आईसीएसआई ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत "कॉरपोरेट गवर्नेंस फॉर अ बेटर टुमोरो: एम्पावरिंग लीडर्स इन कंप्लायंस, रिस्क एंड सस्टेनेबिलिटी" विषय पर 14-25 जनवरी, 2026 तक आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, कोलकाता में 12 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। इस आवासीय कार्यक्रम में दुनिया भर के 16 देशों से कुल 18 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिष्ठित कंपनी सचिवों और विषय विशेषज्ञों ने ज्ञानवर्धक और उपयोगी सत्र आयोजित किए। कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) श्री आर. के. तिवारी के साथ संवाद करने का अवसर भी मिला।

(ख) अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों में आईसीएसआई की भागीदारी**आईओडी यूई ग्लोबल कन्वेंशन 2025**

थीम	बोर्ड्स इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड: इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ फॉर रेजिलिएन्स एंड सस्टेनेबिलिटी
तिथि	22-25 अप्रैल, 2025
स्थान	दुबई, यूई
संगठन	इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी)

केन्या के प्रमाणित सचिव संस्थान का 29वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

थीम	एथिकल लीडरशिप एंड गुड गवर्नेंस – रिस्टोरिंग ट्रस्ट, रिन्यूइंग मॉरल्स, सिव्योरिंग द फ्यूचर
तिथि	23–25 अप्रैल, 2025
स्थान	मोम्बासा, केन्या
संगठन	इंस्टिट्यूट ऑफ सर्टिफाइड सेक्रेटरीज़ ऑफ़ केन्या

कॉर्पोरेट अभिशासन पर ओईसीडी-एशिया गोलमेज सम्मेलन

थीम	कॉर्पोरेट गवर्नेंस
तिथि	27–28 नवंबर, 2025
स्थान	बैंकॉक, थाईलैंड
संगठन	इंस्टिट्यूट ऑफ़ डायरेक्टर्स (आईओडी)

आईसीएसआई मध्य-पूर्व (डीआईएफसी) एनपीआईओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम

कार्यक्रम	स्टडी सर्कल मीट
तिथि	29 मई, 2025
थीम	यूआई कॉर्पोरेट टैक्स
स्थान	अल मूसा टावर, दुबई

कार्यक्रम	आईसीएसआई मिडिल ईस्ट (डीआईएफसी) एनपीआईओ कॉन्फ्रेंस
तिथि	11 अक्टूबर, 2025
थीम	एआई एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस – इनसाइट्स फॉर द फ्यूचर
स्थान	विला रोटाना, शेख जायद रोड, दुबई

कार्यक्रम	आईसीएसआई मिडिल ईस्ट (डीआईएफसी) एनपीआईओ कॉन्फ्रेंस
तिथि	13 दिसंबर, 2025
थीम	गवर्नेंस बियॉन्ड बॉर्डर्स शोपिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट
मुख्य अतिथि	श्री अब्दुल्ला अल सालेह, अंडर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमी, यूआई
सम्मानित अतिथि	श्री बी.जी. कृष्णन, वाणिज्य-दूत (आर्थिक, व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा), भारतीय महावाणिज्य दूतावास, दुबई

(ग) आईसीएसआई अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार

साझेदार	तिथि	विषय
आईसीएसआई मध्य-पूर्व (डीआईएफसी) एनपीआईओ, दुबई	21.6.2025	अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो एंड एएमएल कंप्लायंस
आईसीएसआई मध्य-पूर्व (डीआईएफसी) एनपीआईओ	30.8.2025	ई-इनवॉइसिंग इन द यूआई – जर्नी टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी
आईसीएसआई मध्य-पूर्व (डीआईएफसी) एनपीआईओ	27.9.2025	फैमिली एसेट्स, प्रोटेक्शन एंड सक्सेशन प्लानिंग – डीआईएफसी स्ट्रक्चर्स
आईसीएसआई ओवरसीज़ सेंटर, यूके	13.11.2025	यूके न्यू रेग्युलेटरी रिव्वायरमेंट – डायरेक्टर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस
आईसीएसआई मध्य-पूर्व (डीआईएफसी) एनपीआईओ	21.02.2026	यूआई ई-इनवॉइसिंग – लीगल कंप्लायंस एस्पेक्ट्स
आईसीएसआई मध्य-पूर्व (डीआईएफसी) एनपीआईओ	14.03.2026	मेंटल हेल्थ – काम विदिन कैओस

आईसीएसआई ओवरसीज़ सेंटर, यूके	26.03.2026	नेविगेशन द यूके गवर्नर्स स्पेस – सीवी राइटिंग एंड इंटरव्यू टेक्नीक्स
आईसीएसआई मध्य-पूर्व (डीआईएफसी) एनपीआईओ	28.03.2026	न्यू यूई एएमएल लॉ

(घ) अंतर्राष्ट्रीय सिनर्जी

- आईसीएसआई ने सर्विसेज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसईपीसी) के साथ समझौता ज्ञापन किया: आईसीएसआई ने भारत की कॉरपोरेट सुशासन, अनुपालन और सचिवीय सलाहकार सेवाओं की क्षमता का लाभ उठाने के लिए एसईपीसी के साथ समझौता ज्ञापन किया। वैश्विक मानकों के अनुरूप अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किए गए इस समझौता ज्ञापन से आईसीएसआई के सदस्यों के लिए नए अवसर खुलने और उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, इससे संयुक्त अनुसंधान, संसाधन साझा करने और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
- आईओडी 2025 लंदन ग्लोबल कन्वेंशन: आईसीएसआई ने कॉरपोरेट सुशासन और सततता पर 04-07 नवंबर, 2025 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 2025 लंदन ग्लोबल कन्वेंशन में निदेशक संस्थान के साथ भागीदार के रूप में सहयोग किया।
- आईसीएसआई सदस्यों के लिए सीआईएमए के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (एसईपी) में नामांकन का विशेष अवसर: आईसीएसआई के सदस्य अब चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट (सीजीएमए) की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित उपाधि सीधे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में नामांकन करके प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम यूनाइटेड किंगडम के चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स (सीआईएमए) द्वारा संचालित किया जाता है और कुल 16 पेपरों में से केवल दो पेपर उत्तीर्ण करने होते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अनुभवी पेशेवरों को बाजार में होने वाले जटिल बदलावों से निपटने और रणनीतिक व्यावसायिक कौशल को अपनी पूरी क्षमता तक विकसित करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराता है। आईसीएसआई ने सितंबर 2025 में सीआईएमए के साथ आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि आईसीएसआई के सदस्यों को सीआईएमए की योग्यता प्राप्त करने के मार्ग उपलब्ध कराए जा सकें।
- सीएसआई में आईसीएसआई का प्रतिनिधित्व: सीएस धनंजय शुक्ला, आईसीएसआई के तत्काल पूर्व अध्यक्ष, को वर्ष 2026 के लिए कॉरपोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है। सीएसआई दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में 1,00,000 से अधिक कॉरपोरेट सचिवों और सुशासन पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है।
- आईसीजीएन निर्णायक मंडल: आईसीएसआई इंटरनेशनल कॉरपोरेट गवर्नर्स नेटवर्क ग्लोबल गवर्नर्स एंड स्टूवर्डशिप अवॉर्ड्स के निर्णायक मंडल के रूप में कार्य करता रहा है। इन पुरस्कारों के माध्यम से दुनिया भर में कॉरपोरेट सुशासन और निवेश संरक्षकता के क्षेत्र में व्यक्तियों और कंपनियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता और सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष, आईसीएसआई ने आईसीजीएन 2025 उपलब्धि पुरस्कारों और वैश्विक संरक्षकता प्रकटीकरण पुरस्कारों के निर्णायक मंडलों में स्वतंत्र निर्णायक के रूप में कार्य किया।

(ङ) आईसीएसआई में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

- केन्याई प्रतिनिधिमंडल: इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड सेक्रेटरीज, केन्या और केन्या अकाउंटेंट्स एंड सेक्रेटरीज नेशनल एग्जामिनेशंस बोर्ड (केएसएनईबी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 28 अक्टूबर, 2025 को आईसीएसआई मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान केन्या में कॉरपोरेट सुशासन को बढ़ाने की रणनीतियों, आपसी सहयोग के अवसरों तथा अपने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आईसीएसआई के कंपनी सचिव पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और परीक्षा ढांचे के मानकों के अनुरूप बनाने के विषय में चर्चा की गई।
- आईसीजीएन प्रतिनिधिमंडल: मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री जेन सिसन के नेतृत्व में आईसीजीएन के प्रतिनिधिमंडल ने 18 नवंबर, 2025 को आईसीएसआई मुख्यालय, दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान वैश्विक कॉरपोरेट सुशासन और सततता संबंधी नीतियों तथा ढांचे को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक योजना पर चर्चा की गई और उसे तैयार किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री जेन सिसन के नेतृत्व में आईसीजीएन के प्रतिनिधिमंडल ने 09 मार्च, 2026 को नई दिल्ली स्थित आईसीएसआई मुख्यालय का भी दौरा किया, ताकि संयुक्त अनुसंधान के क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और सुशासन, संरक्षकता तथा हितधारकों की सहभागिता में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके।

(ii) ब्रांड इक्विटी को बढ़ाना

(क) ब्रांड की दृश्यता और मीडिया पहुंच

आईसीएसआई ने प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सम्मेलन, मीडिया बातचीत, वेब पोर्टल और आईसीएसआई के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल मीडिया में पेशे से संबंधित सभी आईसीएसआई गतिविधियों, पहलों और विकास के कवरेज को सुनिश्चित करके ब्रांड आईसीएसआई के संवर्धन और वृद्धि के लिए विभिन्न ब्रांड बिल्डिंग पहल की है।

विवरण	संख्या
आईसीएसआई घटनाओं का प्रेस कवरेज, घोषणाएँ	Over 930
प्रेस कॉन्फ्रेंस	19
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवरेज और विशेष एपिसोड	24
ब्रांड प्रमोशन के लिए बनाए गए वीडियो की संख्या	16
आईसीएसआई पल्स – थिंक गवर्नेंस थिंक आईसीएसआई (पॉडकास्ट सीरीज)	10
रील्स	35

(ख) कंपनी सचिव के रूप में करियर पर करियर फीचर/लेख

भारत भर के प्रमुख समाचार पत्रों – प्रजावाणी, दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दिव्य मराठी, मलयाला मनोरमा, धरित्री, इंदौर समाचार, प्रभात खबर, राजस्थान पत्रिका, वीक मैगजीन, द टेलीग्राफ, रोजगार और निर्माण, बिजनेस स्टैंडर्ड, आईओडी बोर्ड स्टीवर्डशिप जर्नल, आज, जागरण जोश, एजुकेशन टाइम्स, करियर्स 360 पत्रिका और कॉम्पिटिशन रीफ्रेशर – में व्यापक पहुंच के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में “कंपनी सचिव के रूप में करियर” पर विशेष फीचर प्रकाशित किया गया है।

(ग) सोशल मीडिया में उपस्थिति

आईसीएसआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आईसीएसआई और सीएस प्रोफेशन को एक ब्रांड के रूप में महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है। आईसीएसआई कार्यक्रमों से संबंधित सभी घोषणाएँ और जानकारी आईसीएसआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, एक्स, लिंकडइन, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग 1100 पोस्ट के माध्यम से प्रसारित की गई हैं। आईसीएसआई वेबिनार, क्रैश, कोर्स चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल लेखों और अन्य ब्रांडिंग गतिविधियों के वीडियो आईसीएसआई यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जिससे पहुँच और प्रचार में वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के संदर्भ में संस्थान की पहुँच दर्शाती है:

सोशल मीडिया पोर्टल	फॉलोअर्स
फेसबुक https://www.facebook.com/ICSI	1,30,000
एक्स (पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था) https://twitter.com/icsi_cs	94,547
लिंकडइन https://www.linkedin.com/in/theicsi/	54980
इंस्टाग्राम https://www.instagram.com/theicsi/	78100
यू ट्यूब https://www.youtube.com/user/TheCsInstitute	97880
यू ट्यूब (छात्र) https://www.youtube.com/@icsiyoutubechannelforstude2052	30500
थ्रेड्स https://www.threads.net/@theicsi	11100
व्हाट्सएप https://www.whatsapp.com/channel/0029Va9qP1ID8SE69ZDQvW3F	98500

(घ) गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठकें

- श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, माननीय राज्यपाल, केरल
- श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, माननीय राज्यपाल, असम
- श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री
- श्री भूपेंद्र यादव, माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री

- श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
- श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री
- श्री जीतन राम मांझी, माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
- श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री
- श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, माननीय केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
- श्री चिराग पासवान, माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
- श्री हर्ष मल्होत्रा, माननीय राज्य मंत्री, कॉरपोरेट कार्य एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- श्री पंकज चौधरी, माननीय वित्त राज्य मंत्री
- श्रीमती रक्षा खडसे, माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री
- श्रीमती सावित्री ठाकुर, माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
- श्री रामनाथ ठाकुर, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
- श्री सतीश चंद्र दुबे, माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री
- श्री संजय सेठ, माननीय रक्षा राज्य मंत्री
- श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय लोक सभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री
- श्री बैजयंत जय पांडा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी एवं माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री शशि थरूर, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री सुधीर गुप्ता, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री फगन सिंह कुलस्ते, माननीय लोक सभा सदस्य
- डॉ. अमर सिंह, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री रामप्रीत मंडल, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री जगदीश शेठार, माननीय संसद सदस्य
- श्री गिरिधारी यादव, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री अरविंद सावंत, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री बी. वाई. राघवेंद्र, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री दग्गुमल्ला प्रसाद राव, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री कौशलेंद्र कुमार, माननीय लोक सभा सदस्य एवं आयकर विधेयक, 2025 की चयन समिति के सदस्य
- श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री रोडमल नागर, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री शंकर लालवानी, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्रीमती सुप्रिया सुले, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री सुरेश कश्यप, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री प्रदीप कुमार सिंह, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री राजेश वर्मा, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री मनोज तिवारी, माननीय लोक सभा सदस्य
- डॉ. भागवत किशनराव कराड, माननीय राज्य सभा सदस्य
- श्री उपेंद्र कुशवाहा, माननीय राज्य सभा सदस्य
- डॉ. भीम सिंह, माननीय राज्य सभा सदस्य
- डॉ. धर्मशिला गुप्ता, माननीय राज्य सभा सदस्य
- श्री दीपक प्रकाश, माननीय राज्य सभा सदस्य, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सह-प्रभारी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड
- श्री देवेश चंद्र ठाकुर, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री संजय जायसवाल, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री रामप्रीत मंडल, माननीय लोक सभा सदस्य
- श्री दिलेश्वर कामत, माननीय लोक सभा सदस्य

- श्री भूपेंद्र पटेल, माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात
- डॉ. प्रमोद सावंत, माननीय मुख्यमंत्री, गोवा
- श्री सुरेश प्रभु, पूर्व कैबिनेट मंत्री
- श्रीमती स्मृति जेड. ईरानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री
- डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड, माननीय भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
- डॉ. एस. जनकीरमन, सिडनी में भारत के महावाणिज्यदूत
- श्री रजनीश कुमार सिंह, विधान सभा सदस्य, बिहार सरकार

(झ) बुनियादी रूपरेखा

क. मुख्यालय स्तर पर परियोजनाएं

1. **सीसीजीआरटी—मानसेर परिसर:** सीसीजीआरटी परिसर का उद्घाटन किया गया और इसे 11 दिसंबर, 2025 से उपयोग में लाया गया।
2. **आईसीएसआई—मुख्यालय, नोएडा:** सी-36, सेक्टर-62, नोएडा स्थित संस्थान के भवन की अग्नि-निकास सीढ़ी की मरम्मत/संरचनात्मक मजबूती तथा बाहरी विकास कार्य प्रगति पर हैं।
3. **सीसीजीआरटी—मुंबई:** परिषद ने मौजूदा भवन को गिराकर सीसीजीआरटी, मुंबई के नए भवन के निर्माण को प्राथमिकता देने की मंजूरी दी है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

ख. क्षेत्रीय/शाखा (चैप्टर) कार्यालयों में प्रमुख परियोजनाएं

1. **हैदराबाद शाखा (चैप्टर) —** नए भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए भूमि पूजन/शिलान्यास समारोह 20 अप्रैल, 2025 को माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के कर-कमलों से आयोजित किया गया। 31 मार्च, 2026 तक पुराने भवन को गिराने के बाद हैदराबाद शाखा (चैप्टर) के नए भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है।
2. **रायपुर शाखा (चैप्टर) —** निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए भूमि पूजन/शिलान्यास समारोह 14 जनवरी, 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साहू के साथ किया। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3. **कानपुर शाखा (चैप्टर) —** कानपुर शाखा (चैप्टर) के भवन के निर्माण का कार्य 28 नवंबर, 2025 के समझौते के माध्यम से जमा कार्य आधार पर सरकारी एजेंसी मेसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को सौंपा गया। भूमि पूजन/शिलान्यास समारोह 17 जनवरी, 2026 को आयोजित किया गया और भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4. **लखनऊ शाखा (चैप्टर) —** लखनऊ शाखा (चैप्टर) के भवन के निर्माण का कार्य 28 नवंबर, 2025 के समझौते के माध्यम से जमा कार्य आधार पर सरकारी एजेंसी मेसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को सौंपा गया। भूमि पूजन/शिलान्यास समारोह 17 जनवरी, 2026 को आयोजित किया गया और भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
5. **कोच्चि शाखा (चैप्टर) (द्वितीय चरण) —** परिषद ने कोच्चि शाखा (चैप्टर) भवन की दूसरी मंजिल के विस्तार के लिए द्वितीय चरण को मंजूरी दी। डिजाइन को अंतिम रूप देने सहित द्वितीय चरण से संबंधित निर्माण—पूर्व गतिविधियां प्रगति पर हैं।

ग. अन्य स्थानों के लिए नए परिसर का अधिग्रहण/ जगह किराए पर लेना

1. **गांधीनगर गिफ्ट सिटी:** गांधीनगर (गिफ्ट सिटी) शाखा (चैप्टर) के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक—सिटी, गांधीनगर, गुजरात में 27 अगस्त, 2025 को लीज पर जगह लेकर कार्यालय परिसर स्थापित किया गया। इसके साथ ही आईसीएसआई गिफ्ट सिटी में भौतिक उपस्थिति स्थापित करने वाला पहला पेशेवर संस्थान बन गया।
2. **गुरुग्राम शाखा (चैप्टर):** संस्थान ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से भूमि की ई—नीलामी में भाग लिया और सफल बोलीदाता घोषित किया गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आवंटन के लिए आशय पत्र जारी किया गया।
3. संबंधित प्राधिकरणों को परिसर के आवंटन के लिए **अनुरोध पत्र प्रस्तुत किए गए:**

छत्रपति संभाजी नगर अहमदाबाद मदुरै श्रीनगर	आगरा नागपुर इंदौर गोवा	अमरावती जम्मू बरेली	गुरुग्राम विशाखापत्तनम जोधपुर
--	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

4. निम्नलिखित स्थानों पर रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से संपत्ति का चयन प्रक्रियाधीन है:

क) त्रिशूर — छांटी गई संपत्ति की उचित जाँच-पड़ताल के बाद रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से परिसर/संपत्ति का चयन किया गया है।

ख) नासिक — 31 मार्च, 2026 तक छांटी गई संपत्ति की उचित जाँच-पड़ताल पूरी कर ली गई थी।

ग) तिरुवनंतपुरम — रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से परिसर/संपत्ति की छंटवाई पहले ही कर ली गई है।

घ) पुणे — रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से परिसर/संपत्ति का चयन पहले ही कर लिया गया है और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद चयनित संपत्ति के अधिग्रहण की परियोजना लागत और वित्त व्यवस्था को परिषद ने मंजूरी दे दी है।

ङ) हुगली — रुचि की अभिव्यक्ति और उचित जाँच-पड़ताल के माध्यम से परिसर/संपत्ति का चयन पहले ही कर लिया गया है तथा चयनित परिसर/संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अन्य कानूनी कार्यवाही चल रही है।

च) कोझिकोड — रुचि की अभिव्यक्ति और उचित जाँच-पड़ताल के माध्यम से परिसर/संपत्ति का चयन पहले ही कर लिया गया है तथा चयनित परिसर/संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अन्य कानूनी कार्यवाही चल रही है।

छ) सूरत — रुचि की अभिव्यक्ति और उचित जाँच-पड़ताल के माध्यम से परिसर/संपत्ति का चयन पहले ही कर लिया गया है तथा चयनित परिसर/संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अन्य कानूनी कार्यवाही चल रही है।

ज) अहमदाबाद — रियायती दर पर भूखंड के आवंटन के लिए अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के साथ आगे की कार्यवाही की जा रही है।

झ) छत्रपति संभाजी नगर — रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से संपत्ति का चयन प्रक्रिया में है।

घ. निम्न हेतु पुराने परिसरों का निपटान:

ईआईआरओ — ईआईआरओ के पुराने परिसर के निपटान के लिए कोलकाता संस्करण के समाचार पत्रों (अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी) में निविदा सूचना जारी की गई।

(ज) विशिष्ट पहल

(i) त्वरित प्रतिक्रिया एवं समाधान टीम (क्यूआरआरटी):

त्वरित प्रतिक्रिया एवं समाधान टीम (क्यूआरआरटी) सदस्यों और छात्रों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करती है और प्रश्नों तथा शिकायतों का समय पर और बिना किसी परेशानी के समाधान सुनिश्चित करती है। क्यूआरआरटी ने आईसीएसआई सेवा चार्टर प्रकाशित किया है, जिसमें आईसीएसआई द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा (टीएटी) का विवरण दिया गया है।

क्यूआरआरटी एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से कार्य करती है, जिसमें टिकट संख्या, तारीख, हितधारक की जानकारी, संबंधित विषय, दिए गए समाधान और समाधान पूरा होने की तारीख जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती है।

(ii) मानव संसाधन

(क) कर्मचारी विकास

संस्थान के कर्मचारियों की क्षमताओं और कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा उन्हें हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने और उससे भी बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए, कर्मचारियों के निरंतर प्रशिक्षण तथा उनके ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के प्रयास किए गए। इसमें व्यवहार कौशल और पारस्परिक प्रभावशीलता, डिजिटल विपणन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बातचीत कौशल तथा वित्तीय और ईआरपी प्रणालियों जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। संस्थान अपने कार्यबल के

समग्र कल्याण पर भी विशेष ध्यान देता है। प्रमुख अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं के सहयोग से नियमित वेबिनार और स्वास्थ्य वार्ताएं आयोजित की गईं, जिनमें शारीरिक स्वास्थ्य, जीवनशैली प्रबंधन और निवारक देखभाल से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया।

(ख) स्पंदन, 2025

संस्थान ने 13 सितंबर, 2025 से 16 अक्टूबर, 2025 तक केवल आईसीएसआई कर्मचारियों के लिए "स्पंदन", एक भव्य खेल, कला और सांस्कृतिक उत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में टीम भावना, रचनात्मकता और कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं। खेल प्रतियोगिताओं में क्रिकेट टी10 श्रृंखला, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज और आर्म रेसलिंग शामिल थे, जबकि कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एकल गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य, पोस्टर निर्माण और रैंप वॉक शामिल थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य समापन 16 अक्टूबर, 2025 को नोएडा कार्यालय में आयोजित किया गया। स्पंदन 2025 को पूरे संस्थान के कर्मचारियों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। कर्मचारियों ने बहुत उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया, जिससे यह उत्सव शानदार रूप से सफल रहा और प्रतिभा तथा आपसी सौहार्द प्रदर्शित करने के लिए एक यादगार मंच बना।

(ग) महिला दिवस, 2026

08 मार्च, 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के हिस्से के रूप में और महिलाओं के सम्मान तथा महिला कर्मचारियों के अमूल्य योगदान की सराहना करने हेतु संस्थान ने पूरे भारत में स्थित आईसीएसआई के सभी कार्यालयों में सभी महिला कर्मचारियों को प्रशंसा स्वरूप उपहार प्रदान करके यह दिवस मनाया।

(घ) सेवा पुरस्कार

संस्थान ने उन कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए सेवा पुरस्कार समारोह आयोजित किए, जिन्होंने संस्थान में 15, 20, 25, 30 और 35 वर्षों की समर्पित सेवा पूरी की। 01 जुलाई, 2025 और उसके बाद 01 जनवरी, 2026 को सेवा पुरस्कार के लिए पात्र हुए कर्मचारियों को इन सेवा पुरस्कार समारोहों में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान की ओर से उनके बहुमूल्य योगदान के लिए आभार और सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्हें प्रशंसा पत्र, स्मृति-चिह्न और सेवा पुरस्कार प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

(ङ) भर्ती

आईसीएसआई की टीम को और मजबूत करने के लिए, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों की भर्ती की गई:

क्र.सं.	पद	भर्ती किए गए अधिकारियों की संख्या
1.	संयुक्त निदेशक	03
2.	उप निदेशक (अकादमिक)	02
3.	कार्यपालक सहायक	10

(च) कर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2026 तक संस्थान में कर्मियों की संख्या 372 थी, जिसमें 104 महिला कर्मचारी शामिल थीं, जो कुल जनशक्ति का 28% थी।

(छ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पोओएसएच)

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मामलों की रिपोर्ट

विवरण	मुख्यालय	एनआईआरओ और उसकी शाखाएं (चैप्टरों) आईसीएसआई—सीसीजीआरटी, मानेसर	ईआईआरओ और उसकी शाखाएं (चैप्टर), आईसीएसआई—सीसीजीआरटी, कोलकाता	डब्ल्यूआईआरओ और उसकी शाखाएं (चैप्टर), आईसीएसआई—सीसीजीआरटी, मुंबई	एसआईआरओ और उसकी शाखाएं (चैप्टर), आईसीएसआई—सीसीजीआरटी, हैदराबाद
प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निपटाई गई शिकायतों की संख्या	01	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
90 से अधिक दिनों से लंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

मामलों की संख्या					
यौन उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	01	01	01	01	01
नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान ने परिचालन कार्यकुशलता बढ़ाने, डिजिटल सुशासन को मजबूत करने, हितधारकों के लिए सेवाओं में सुधार करने और साइबर सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा। संस्थान ने अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं के स्वचालन, डिजिटल बदलाव, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, क्लाउड अपनाने और उन्नत प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन से संबंधित कई पहल कीं।

संस्थान ने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क बुनियादी ढांचे, सुरक्षा प्रणालियों और प्रबंधन सूचना प्रणालियों के निरंतर उन्नयन के माध्यम से अपने सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को और मजबूत किया। साइबर सुरक्षा, व्यावसायिक निरंतरता, क्लाउड में स्थानांतरण, हितधारकों की सुविधा और डेटा-आधारित निर्णय लेने पर विशेष जोर दिया गया।

सूचना सुरक्षा और तकनीकी नवाचार के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख पहल कीं:

- व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना: व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर) पहल में मौजूदा प्रक्रियाओं का अध्ययन और पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा क्षेत्र द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का सर्वेक्षण शामिल होगा। प्रक्रियाओं, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी आवश्यकताओं और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के इस विश्लेषण के आधार पर, बीपीआर के माध्यम से छात्रों, सदस्यों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए एकल साइन-ऑन एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू की जाएगी।
- ईआरपी, STIMULATE पोर्टल, प्लेसमेंट पोर्टल और अनुशासनात्मक पोर्टल सहित महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों के लिए सुरक्षा ऑडिट अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करना और उनका रखरखाव करना।
- व्यापक डेटा सेंटर सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा ऑडिट पूरा करना और ऑडिट की सिफारिशों को लागू करना।
- साइबर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करना।
- अनुशासनात्मक तंत्र सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग को एडब्ल्यू.एस. क्लाउड में स्थानांतरित करना, ताकि मापनीयता, उपलब्धता और सुरक्षा में सुधार किया जा सके।
- राउटर, इंटरनेट लीज लाइन (आईएलएल) की बैंडविड्थ सहित नेटवर्क बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणालियों के लिए एमपीएलएस से इंटरनेट लीज लाइन (आईएलएल) में स्थानांतरण करना।

(iv) परीक्षाएं

(क) परीक्षाओं का आयोजन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कंपनी सचिवों की एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम की परीक्षाएं क्रमशः जून और दिसंबर, 2025 सत्रों में पूरे भारत में 225 और 228 परीक्षा केंद्रों और दुबई स्थित एक विदेशी परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गईं। जून और दिसंबर, 2025 की परीक्षा सत्रों में परीक्षा में शामिल होने के लिए क्रमशः कुल 63,523 और 69,338 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया। वर्ष 2025-26 के दौरान परीक्षाओं के विभिन्न चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है:

परीक्षा का चरण	जून, 2025	दिसंबर, 2025
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम	2913	4015
प्रोफेशनल प्रोग्राम	2477	2271

परीक्षा केंद्रों के लिए शहरों की सूची परिशिष्ट-ग में दी गई है। परीक्षा परिणामों से संबंधित आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

कंपनी सचिव की परीक्षा – जून, 2025
परिणाम विश्लेषण

परीक्षा का चरण	अभ्यर्थियों की संख्या		
	नामांकित	उपस्थित हुए	उत्तीर्ण
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (पाठ्यक्रम-2017) *			
मॉड्यूल – I	2301	1662	494
मॉड्यूल – II	2932	2286	660
मॉड्यूल – III	2321	1719	491
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (पाठ्यक्रम-2022)**			
समूह – 1	29978	23575	3439
समूह – 2	25049	19114	4747
प्रोफेशनल प्रोग्राम (पाठ्यक्रम-2022)***			
समूह – 1	9546	8053	2026
समूह – 2	9047	7193	1897

* एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 572 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया, 438 अभ्यर्थियों ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (पाठ्यक्रम-2017) के सभी मॉड्यूल में उपस्थित हुए, जिनमें से 7 अभ्यर्थियों ने सभी मॉड्यूल उत्तीर्ण किए।

** एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 10158 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया, 8603 अभ्यर्थियों ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (पाठ्यक्रम-2022) के दोनों समूह में उपस्थित हुए, जिनमें से 918 अभ्यर्थियों ने दोनों समूह उत्तीर्ण किए।

*** प्रोफेशनल प्रोग्राम में 4860 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया, 4396 अभ्यर्थियों ने प्रोफेशनल प्रोग्राम (पाठ्यक्रम-2022) के दोनों समूह में उपस्थित हुए, जिनमें से 410 अभ्यर्थियों ने दोनों समूह उत्तीर्ण किए।

कंपनी सचिव की परीक्षा – दिसंबर, 2025

परिणाम विश्लेषण

परीक्षा का चरण	अभ्यर्थियों की संख्या		
	नामांकित	उपस्थित हुए	उत्तीर्ण
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (पाठ्यक्रम-2022) *			
समूह – 1	32620	25325	4571
समूह – 2	28154	21301	4744
प्रोफेशनल प्रोग्राम (पाठ्यक्रम-2022)**			
समूह – 1	14125	11622	3125
समूह – 2	13113	10156	2711

*एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 10973 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया, 9124 अभ्यर्थियों ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के दोनों समूह में उपस्थित हुए, जिनमें से 633 अभ्यर्थियों ने दोनों समूह उत्तीर्ण किए।

** प्रोफेशनल प्रोग्राम में 7701 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया, 6839 अभ्यर्थियों ने प्रोफेशनल प्रोग्राम के दोनों समूह में उपस्थित हुए, जिनमें से 703 अभ्यर्थियों ने दोनों समूह उत्तीर्ण किए।

(ख) कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सीएसईईटी) का आयोजन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीएसईईटी मई, 2025, जुलाई, 2025, नवंबर, 2025 और जनवरी, 2026 के महीनों में आयोजित किया गया था। सीएसईईटी को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है:

परीक्षा सत्र	अभ्यर्थियों की संख्या		
	नामांकित	उपस्थित हुए	उत्तीर्ण
मई 2025	8892	7532	4452
जुलाई 2025	12057	10991	6584
नवंबर 2025	15366	13701	8890
जनवरी 2026	9363	8840	6031

(ग) जून 2025 और दिसंबर 2025 परीक्षा सत्र के लिए नया परीक्षा केंद्र

दिसंबर 2025 के लिए शिवमोगा (कर्नाटक, 349) में एक नया परीक्षा केंद्र खोला गया।

(घ) अखिल भारतीय पुरस्कार

कंपनी सचिवों की परीक्षाओं में छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और उसे सम्मानित करने के लिए, संस्थान ने कई पुरस्कार शुरू किए हैं, जिनमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, राष्ट्रपति रजत पदक और पंडित नेहरू जन्म शताब्दी वार्षिक पुरस्कार शामिल हैं।

सत्र	पदक	प्राप्तकर्ता	केंद्र
जून, 2025	प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक	सुश्री भूमिका सिंह	मेरठ
	एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति रजत पदक	सुश्री भूमि विनोद मेहता	मुंबई
	पंडित नेहरू जन्म शताब्दी वार्षिक पुरस्कार	सुश्री भूमिका सिंह	मेरठ
दिसंबर 2024	प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक	सुश्रीयशी धरम मेहता	ठाणे
	एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति रजत पदक	सुश्री खुशबू कुंवर	उदयपुर
जून, 2025	प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक	सुश्री भूमि विनोद मेहता	मुंबई
	एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति रजत पदक	सुश्री तिथि बोहरा	जयपुर
	पंडित नेहरू जन्म शताब्दी वार्षिक पुरस्कार	सुश्री भूमि विनोद मेहता	मुंबई

मौजूदा अखिल भारतीय पुरस्कार योजनाओं, क्षेत्रीय और चैंप्टर पुरस्कार योजनाओं के साथ-साथ अन्य पुरस्कार विजेताओं का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

(ड) मेरिट प्रमाणपत्र/मेरिट छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता

जून, 2025 और दिसंबर, 2025 के परीक्षा सत्रों में आयोजित एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम की परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 25 सफल छात्रों को रैंक प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, जून, 2025 और दिसंबर, 2025 सत्र की परीक्षाओं में पहले ही प्रयास में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के सभी पेपर उत्तीर्ण करने वाले टॉपर्स को कंपनी सचिव पाठ्यक्रम के प्रोफेशनल प्रोग्राम हेतु आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार, मेरिट-सह-साधन सहायता योजना के अंतर्गत, पात्र उम्मीदवारों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि और सीएस परीक्षाओं के जून, 2025 सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। दिसंबर 2025 सत्र में इस योजना के लिए कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं पाया गया।

(v) प्रशिक्षण

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थान द्वारा छात्रों को लघु अवधि और दीर्घकालिक प्रशिक्षण से संबंधित सुविधा प्रदान करने के लिए कई पहल और गतिविधियाँ शुरू की गईं, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- **समाधान दिवस:** आईसीएसआई में पंजीकृत छात्रों की समस्याओं/शिकायतों का "मौके पर" समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, समाधान दिवस प्रत्येक महीने के दूसरे बुधवार को आयोजित किया जाता है। समाधान दिवस छात्रों के लिए आईसीएसआई के अधिकारियों से सीधे संवाद करने और आईसीएसआई छात्र प्रशिक्षण दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित विभिन्न प्रशिक्षणों से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान कराने का एक उपयोगी मंच है।
- **लघु अवधि प्रशिक्षण:**
 - (क) स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम (एसआईपी) की शुरुआत – 16 दिसंबर, 2025 या उसके बाद सीएसईईटी के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों के लिए पंजीकरण के 1 महीने के भीतर एक दिवसीय छात्र अभिमुखीकरण कार्यक्रम (एसआईपी) में भाग लेना आवश्यक है। एसआईपी को एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है, ताकि छात्रों को सीएस कोर्स की यात्रा के बारे में मार्गदर्शन दिया जा सके। एसआईपी में भाग लेना और इसे पूरा करना सीएसईईटी में नामांकन के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से एसआईपी को आईसीएसआई ई-लर्निंग शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) पोर्टल के माध्यम से लागू किया गया है।
 - (ख) तीन दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम (टीडीओपी): एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पंजीकरण कराने वाले छात्रों के लिए अपने पंजीकरण के तीन महीने के भीतर टीडीओपी पूरा करना अनिवार्य है।
- **सीएलडीपी करने के तरीके और माध्यम में संशोधन:** संस्थान ने 15 दिसंबर, 2025 से 30 दिनों के सीएलडीपी को करने के तरीके और माध्यम में संशोधन किया है। सीएलडीपी को निम्नलिखित क्रम में पूरा करना होगा:
 - सीएलडीपी चरण I – कक्षा माध्यम (गैर-आवासीय) में 15 दिनों का सीएलडीपी।
 - सीएलडीपी चरण II – कक्षा माध्यम (आवासीय) में 15 दिनों का सीएलडीपी।
- **सीएलडीपी पूरा करने पर एसोसिएट सदस्यता प्रदान करना:** सीएस छात्रों की सुविधा के लिए, संस्थान ने सीएलडीपी चरण-II (आवासीय) के अंतिम दिन समापन सत्र में एसोसिएट सदस्यता संख्या प्रदान करने की शुरुआत की है।
- **सीएलडीपी के वैकल्पिक माध्यम का दायरा बढ़ाया गया:** मौजूदा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने, पहुंच को आसान बनाने और छात्रों को सदस्यता प्राप्त करने के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए, आईसीएसआई ने कॉरपोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीएलडीपी) पूरा करने के लिए वैकल्पिक माध्यमों का दायरा और बढ़ाया है। पात्रता मानदंड संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध आईसीएसआई छात्र प्रशिक्षण दिशानिर्देश, 2024 में दिए गए हैं।

(vi) प्लेसमेंट

आईसीएसआई कंपनी सचिवों और सीएस प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करने वाली कंपनियों और फर्मों के लिए एक सुगम, समयबद्ध और दोनों पक्षों के लिए लाभकारी भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी समर्पित प्लेसमेंट और भर्ती सहायता पहलों के माध्यम से, संस्थान संगठनों को उनकी प्रतिभा संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता करने के साथ-साथ अपने सदस्यों और छात्रों को उपयुक्त करियर के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है। संस्थान का निरंतर प्रयास है कि वह अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सभी हितधारकों को सेवाएं प्रदान करे और ऐसा अनुकूल मंच तैयार करे, जो भर्ती करने वालों और करियर की तलाश कर रहे पेशेवरों के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा दे। इससे नियोक्ताओं और उम्मीदवारों, दोनों के लिए

लाभकारी एक मजबूत और समन्वित संबंध स्थापित होता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्लेसमेंट पोर्टल पर पंजीकरण और पोस्टिंग का विवरण निम्नलिखित है:

पंजीकृत उपयोगकर्ता			रक्तियों की कुल संख्या	
सदस्य	छात्र	कार्पोरेट	नियुक्ति	प्रशिक्षण
2,178	5,252	1,046	2,523	3,956

संस्थान के सदस्यों और छात्रों के लिए प्लेसमेंट के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु अनेक गतिविधियाँ शुरू की गईं। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कंपनी सचिवों और सीएस प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं को पूरा करना:** कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय / सीपीएसई / पीएसयू और अन्य सरकारी संस्थाओं के कार्यालयों से कंपनी सचिव, युवा पेशेवर और सीएस प्रशिक्षु के पदों के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए। इसके अनुसार, पात्र सदस्यों और छात्रों के बायोडेटा उन्हें भेजे गए।
- **आईसीएसआई एचआर कॉन्फ्लेव:** एचआर समुदाय को सीएस पेशे और कंपनी सचिवों की भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए, आईसीएसआई द्वारा 04 दिसंबर, 2025 को चेन्नई स्थित एसआईआरओ और 13 दिसंबर, 2025 को बेंगलुरु शाखा (चैप्टर) में एचआर कॉन्फ्लेव आयोजित किए गए।
- **आईसीएसआई पूर्व छात्र मिलन:** आईसीएसआई द्वारा 08 नवंबर, 2025 को बेंगलुरु शाखा (चैप्टर) और 21 नवंबर, 2025 को मुंबई स्थित डब्ल्यूआईआरओ में आईसीएसआई पूर्व छात्र मिलन आयोजित किए गए।
- **कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव:** संस्थान का कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम कॉरपोरेट्स को योग्य युवा और अनुभवी कंपनी सचिवों तथा छात्रों की प्रोफाइल देखने, उनकी क्षमताओं का आकलन करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है।
- **मेगा प्लेसमेंट ड्राइव:** आईसीएसआई ने जुलाई, 2025 के दौरान अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और आईसीएसआई सीसीजीआरटी में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-I, 2025 आयोजित किया। इस ड्राइव में विभिन्न भर्ती करने वाले संस्थानों (संगठनों और पीसीएस फर्मों सहित) तथा आईसीएसआई के रोजगार की तलाश कर रहे सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा, आईसीएसआई ने नवंबर, 2025 के दौरान अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और सीसीजीआरटी में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-II, 2025 आयोजित किया। मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-II, 2025 को पूरे भारत में नियोक्ताओं और सदस्यों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। कुल 74 नियोक्ताओं, जिनमें कॉरपोरेट्स, संगठन और पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस) फर्म शामिल थीं, ने इस ड्राइव के लिए पंजीकरण कराया। पूरे भारत से 133 से अधिक सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिससे कंपनी सचिव पेशे में प्रतिभाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में आईसीएसआई की भूमिका और मजबूत हुई।
- **स्टेप ऑन: कौशल संवर्धन कार्यशाला:** संस्थान ने 30-31 अगस्त, 2025 को आईसीएसआई हाउस, सेक्टर 62, नोएडा में स्टेप ऑन: कौशल संवर्धन कार्यशाला आयोजित की। करियर को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित विशेष एजेंसियों के सहयोग से तैयार किए गए इस विशेष कार्यक्रम को संचार, प्रस्तुति कौशल और साक्षात्कार की तैयारी के क्षेत्र के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा सोच-समझकर तैयार कर संचालित किया गया। यह कार्यक्रम करियर की शुरुआत करने वाले नेक्स्टजेन कंपनी सचिवों को अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाने, आत्मविश्वास विकसित करने और आज के बदलते रोजगार बाजार में एक अलग प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने का विशेष अवसर प्रदान करता है। 14 घंटे की इस कार्यशाला में विशेष एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण पेशेवर कौशलों अर्थात् संचार कौशल, प्रस्तुति कौशल, शिष्टाचार एवं व्यक्तित्व विकास तथा बातचीत एवं ग्राहक प्रबंधन को शामिल किया गया।
- **सीएस प्रशिक्षु ड्राइव:** सीएस प्रशिक्षु ड्राइव पूरे वर्ष पूरे भारत में संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालयों, सीसीजीआरटी और शाखाओं में भौतिक तथा वर्चुअल, दोनों माध्यमों से आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षु ड्राइव में देशभर के संगठनों, पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस) और अन्य फर्मों ने भाग लिया। इन संस्थाओं ने आईसीएसआई के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, सीसीजीआरटी और शाखाओं के माध्यम से अपनी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए पंजीकरण कराया। इन पहलों ने कंपनी सचिव बनने की आकांक्षा रखने वाले छात्रों को संभावित प्रशिक्षण संस्थाओं से जोड़ने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान किया, जिससे पेशेवर सीखने और करियर विकास के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिली।

(ट) सीसीजीआरटी

आईसीएसआई-
सीसीजीआरटी,
मुंबई

आईसीएसआई-
सीसीजीआरटी,
हैदराबाद

आईसीएसआई-
सीसीजीआरटी,
कोलकाता

आईसीएसआई-
सीसीजीआरटी,
मानेसर

आईसीएसआई-सीसीजीआरटी की स्थापना गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने और इस प्रकार संस्थान के छात्रों और सदस्यों के विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

(i) आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, मुंबई

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों/संगोष्ठियों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	तिथि	कार्यक्रम
1	26 अप्रैल, 2025	एनबीएफसी के अभिशासन, जोखिम और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं तथा सीएस की भूमिका पर कार्यशाला
2	24-25 मई, 2025	सेबी एलओडीआर के तहत अनुपालनों पर दो दिवसीय आवासीय/गैर-आवासीय कार्यशाला
3	21-22 जून, 2025	बौद्धिक संपदा अधिकारों पर दो दिवसीय आवासीय/गैर-आवासीय कार्यशाला
4	02-03 अगस्त, 2025	एसएमई लिस्टिंग पर दो दिवसीय आवासीय/गैर-आवासीय कार्यशाला
5	19-20 सितंबर, 2025	इंदौर शाखा (चैप्टर) के साथ संयुक्त रूप से उज्जैन में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध के लिए दो दिवसीय संयुक्त कार्यशाला
6	15-16 नवंबर, 2025	फेमा पर दो दिवसीय आवासीय/गैर-आवासीय कार्यशाला
7	27 नवंबर, 2025	आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, मुंबई ने एसोसिएशन साझेदार के रूप में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' पर आयोजित चौथे आईसीसी कॉन्क्लेव में भाग लिया
8	10-11 जनवरी, 2026	ईएसजी की बारीकियों पर दो दिवसीय आवासीय/गैर-आवासीय कार्यशाला
9	14-15 फरवरी, 2026	सीएस के लिए एआई पर दो दिवसीय आवासीय/गैर-आवासीय कार्यशाला
10	08 मार्च, 2026	पीओएसएच अधिनियम, 2013 पर गैर-आवासीय कार्यशाला
11	21-22 मार्च, 2026	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत नवीनतम संशोधनों पर दो दिवसीय आवासीय/गैर-आवासीय कार्यशाला

सीसीजीआरटी मुंबई की सदस्यों के लिए डिबेटिंग सोसाइटी की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	तिथि	विषय
1	05 अप्रैल, 2025	अपराधमुक्तीकरण: क्या यह कारोबार सुगमता को बढ़ावा देता है या कॉर्पोरेट अनुशासन के लिए खतरा है?
2	19 अप्रैल, 2025	स्वतंत्र निदेशक की स्वतंत्रता
3	17 मई, 2025	पेशे में एआई का उपयोग और इसका प्रभाव
4	07 जून, 2025	कानूनी सुरक्षा उपाय: क्या हमारे राष्ट्रीय डेटा संरक्षण कानून पर्याप्त रूप से मजबूत हैं?
5	28 जून, 2025	क्या ईएसजी अनुपालन प्रभाव दिखाने के बजाय केवल चेकलिस्ट पूरी करने तक सीमित हैं?
6	19 जुलाई, 2025	पीओएसएच: क्या यह केवल कागज पर अनुपालन है या उत्पादकता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है?
7	02 अगस्त, 2025	क्या स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया कॉर्पोरेट अभिशासन में उनके प्रभावी योगदान को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है?
8	20 सितंबर, 2025	शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण: कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए खतरा या कार्यकुशलता बढ़ाने वाला माध्यम?
9	11 अक्टूबर, 2025	सही 'जीवन-संतुलन' पाने की कोशिश एक मिथक है।
10	13 दिसंबर, 2025	कंपनी सचिव केवल अनुपालन अधिकारी हैं या बोर्ड के बिजनेस पार्टनर?
11	21 फरवरी, 2026	नियामकीय अनुपालन बनाम कारोबार सुगमता: क्या अनुपालन भारत में कॉर्पोरेट विकास में बाधा बन रहा है?

मेगा प्लेसमेंट ड्राइव: सदस्यों के लिए प्लेसमेंट के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से, संस्थान ने 19 जुलाई, 2025 को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-I और 07 नवंबर, 2025 को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-II का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन प्लेसमेंट ड्राइव ने प्रमुख संगठनों और कंपनी सचिव बनने के आकांक्षी उम्मीदवारों को जुड़ने के लिए एक सक्रिय मंच प्रदान किया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती की सुविधा मिली। इन पहलों में नियोक्ताओं और उम्मीदवारों, दोनों की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे संस्थान के सदस्यों और छात्रों के करियर विकास तथा रोजगार सृजन में सहायता करने के प्रयासों को और मजबूती मिली।

छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम: सीसीजीआरटी मुंबई ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 9 आवासीय कॉरपोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीएलडीपी) और 5 गैर-आवासीय सीएलडीपी आयोजित किए।

भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च के साथ समझौता ज्ञापन: सीसीजीआरटी मुंबई ने 27 मार्च, 2026 को भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च के साथ सहयोग की शुरुआत की, जो शैक्षणिक और पेशेवर विकास गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में एक सहयोगात्मक कदम है।

(ii) आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, हैदराबाद

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, हैदराबाद ने छात्रों, सदस्यों और अन्य पेशेवरों के लिए ऑनलाइन और कक्षा माध्यम से तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्यों के लिए पेशेवर विकास कार्यक्रम

सीसीजीआरटी हैदराबाद ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित पेशेवर विकास कार्यक्रम आयोजित किए:

क्र.सं.	तिथि	कार्यक्रम
1	18-19 अप्रैल, 2025	ईएसजी और बीआरएसआर पर दो दिवसीय शोध कॉन्क्लेव
2	16-17 मई, 2025	सेबी विनियमों पर दो दिवसीय शोध कॉन्क्लेव
3	11-12 जुलाई, 2025	"कॉरपोरेट कानूनों के अनुपालन प्रबंधन" पर दो दिवसीय आवासीय कार्यशाला
4	07-08 अगस्त, 2025	कॉरपोरेट फंडिंग – प्राइवेट इक्विटी और ऋण जुटाने पर दो दिवसीय आवासीय शोध कॉन्क्लेव
5	29-30 अगस्त, 2025	कॉरपोरेट पुनर्गठन की रणनीतियों और योजना प्रक्रिया पर दो दिवसीय कार्यशाला
6	13 अक्टूबर, 2025	एमसीए के वी3 पोर्टल के तहत वार्षिक फाइलिंग पर हैदराबाद शाखा (चैप्टर) के साथ संयुक्त रूप से सेमिनार
7	21 फरवरी, 2026	सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए निदेशक मंडल की बैठकों और उसकी शक्तियों पर कार्यशाला

छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम: रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीसीजीआरटी हैदराबाद ने 12 सीएलडीपी आयोजित किए।

सहयोगात्मक/संयुक्त कार्यक्रम: सीसीजीआरटी हैदराबाद ने 12 और 13 सितंबर, 2025 को एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के परिसर में एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के साथ संयुक्त रूप से कॉर्प कॉन-2025: पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन तथा दिवाला और शोध अक्षता संहिता पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में कुल 190 सदस्यों और छात्रों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे और समापन सत्र में तेलंगाना के माननीय राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा मुख्य अतिथि थे।

संवादात्मक सत्र: सीसीजीआरटी हैदराबाद ने 13 जून, 2025 को वार्षिक फाइलिंग और ई-फॉर्म शुरू किए जाने के संबंध में एमसीए उपयोगकर्ता जागरूकता सत्र पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया, जिसमें एमसीए की क्षेत्रीय निदेशक (एसईआर) सुश्री रिचा कुकरेजा और एमसीए के अन्य अधिकारियों ने सदस्यों के साथ संवाद किया। संवादात्मक सत्र में लगभग 160 सदस्यों ने भाग लिया।

आईआईसीए द्वारा आईबीसी के तहत अवसरों पर आउटरीच कार्यक्रम: 27 अप्रैल, 2026 को सीसीजीआरटी, हैदराबाद ने हैदराबाद शाखा के सहयोग से "दिवाला और शोध अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत अवसर" विषय पर आईआईसीए आउटरीच कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किया। कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह और आईआईसीए में सीआईबी के कोर्स निदेशक श्री सुधाकर शुक्ला सहित प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने आईबीसी व्यवस्था के तहत उभरते अवसरों और पेशेवर संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

मेगा प्लेसमेंट ड्राइव: सीसीजीआरटी हैदराबाद ने 01 जुलाई, 2025 को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-I और 12 नवंबर, 2025 को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-II का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन ड्राइव ने पेशेवरों को संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने और विभिन्न उद्योगों में करियर के विविध अवसर तलाशने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान किया।

(iii) आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, कोलकाता

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीसीजीआरटी कोलकाता ने निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए:

क्र.सं.	तिथि	कार्यक्रम
1.	26 अप्रैल, 2025	"कॉरपोरेट पुनर्गठन" पर शोध कॉन्वलेव
2.	12-13 जुलाई, 2025	कराधान (जीएसटी और प्रत्यक्ष कर) की मूल बातों और व्यावहारिक जानकारी पर 2 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम
3.	02-03 अगस्त, 2025	कॉरपोरेट कानूनों और सेबी विनियमों में नवीनतम संशोधनों और अपडेट पर 2 दिवसीय आवासीय सम्मेलन
4.	15 - 16 नवंबर, 2025	मध्यस्थता पर 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम (आईसीएसआई इंटरनेशनल एडीआर सेंटर और एडमास यूनिवर्सिटी के सहयोग से)
5.	15 नवंबर, 2025	कॉरपोरेट अभिशासन एवं सततता पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार (ईआईआरसी और केबीएसए के साथ संयुक्त रूप से)
6.	17 नवंबर, 2025	सांविधिक अनुपालनों, प्रकटीकरण, नियामकीय ढांचे से संबंधित मुद्दों तथा आईबीसी पर प्रशिक्षण कार्यशाला (डीपीई एवं आईआर, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ संयुक्त कार्यक्रम)
7.	22 - 23 नवंबर, 2025	आईसीएसआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड की बैठक
8.	1 - 3 दिसंबर, 2025	सीएंडएजी के ग्रुप ए और बी अधिकारियों के लिए "कंपनी अधिनियम, 2013" पर सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम
9.	16 - 18 दिसंबर, 2025	सीएंडएजी के ग्रुप ए और बी अधिकारियों के लिए "लेखा परीक्षा में कॉरपोरेट अभिशासन, अनुपालन और जोखिम कारक" पर सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम
10.	22 - 23 दिसंबर, 2025	पीयरलेस ग्रुप के सीएस और अनुपालन अधिकारियों के लिए "कॉरपोरेट अभिशासन, अनुपालन और नियामकीय ढांचा" विषय पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
11.	14 जनवरी - 25 जनवरी, 2026	भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में क्षमता निर्माण कार्यक्रम
12.	27 - 28 फरवरी, 2026	कॉरपोरेट पुनर्गठन पर 2 दिवसीय कार्यशाला (शैक्षणिक साझेदार - एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता और कॉरपोरेट साझेदार - आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप)
13.	14 - 15 मार्च, 2026	"भारत की दिवाला व्यवस्था" पर 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला

सीसीजीआरटी कोलकाता की डिबेटिंग सोसाइटी की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	तिथि	विषय
1.	05 अप्रैल, 2025	मानव जीवन में तनाव महत्वपूर्ण है (वर्चुअल)
2.	17 मई, 2025	युद्ध शांति का एक साधन है (वर्चुअल)
3.	14 अगस्त, 2025	टैरिफ नया हथियार है (वर्चुअल)
4.	24 सितंबर, 2025	सफलता से अधिक महत्वपूर्ण खुशी है (वर्चुअल)
5.	08 अक्टूबर, 2025	सख्त अनुपालन मानदंड कारोबार करने में सुगमता के लिए बाधा हैं (वर्चुअल)
6.	17 जनवरी, 2026	घर से काम करने से कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ती है (वर्चुअल)
7.	28 फरवरी, 2026	ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक कक्षा शिक्षण की जगह ले लेगी (वर्चुअल)
8.	14 मार्च, 2026	स्टार्ट-अप्स पर सूचीबद्ध कंपनियों के समान कॉरपोरेट अभिशासन मानक लागू नहीं होने चाहिए

छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम: रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, सीसीजीआरटी कोलकाता ने 11 आवासीय सीएलडीपी बैच (बैच 8 से 18) आयोजित किए।

(iv) आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, मानेसर

संस्थान की संस्थागत पहुंच को मजबूत करने तथा उच्च प्रभाव वाले शोध, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास के तहत, आईसीएसआई ने आईएमटी मानेसर, हरियाणा में अपना कॉरपोरेट अभिशासन, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीजीआरटी) का चौथा केंद्र शुरू किया। 11 दिसंबर, 2025 को उद्घाटित यह अत्याधुनिक केंद्र भारत इंक. में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उत्तरी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित, सीसीजीआरटी मानेसर एक प्रमुख इनक्यूबेशन और क्षमता निर्माण केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसे ऐसे उच्च क्षमता वाले पेशेवर नेतृत्वों को तैयार करने के लिए विकसित किया गया है, जो लगातार जटिल होते वैश्विक नियामकीय ढांचे को समझने और कारोबारी अनुपालनों को रणनीतिक कॉरपोरेट मूल्यों में बदलने में सक्षम हों। सीसीजीआरटी, मानेसर ने संस्थान के सदस्यों के लिए निम्नलिखित पेशेवर विकास कार्यक्रम आयोजित किए:

क्र.सं.	तिथि	कार्यक्रम
1	02 – 03 जनवरी, 2026	कॉरपोरेट पुनर्गठन पर पहली आवासीय क्षमता निर्माण कार्यशाला
2	13–14 फरवरी, 2026	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 पर दूसरी आवासीय क्षमता निर्माण कार्यशाला
3	21 फरवरी, 2026	निदेशक मंडल की बैठकों के व्यावहारिक पहलुओं पर पहली क्षमता निर्माण कार्यशाला
4	20–21 मार्च, 2026	सेबी विनियमों (एसएसटी, पीआईटी और आईसीडीआर) पर तीसरी आवासीय क्षमता निर्माण कार्यशाला

छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम: रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीसीजीआरटी मानेसर ने 9 आवासीय सीएलडीपी बैच (बैच 1 से 9) आयोजित किए।

(ठ) आईसीएसआई द्वारा प्रवर्तित कंपनियां

आईसीएसआई इंस्टिट्यूट ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स	आईसीएसआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गनाइजेशन	आईसीएसआई इंटरनेशनल एडीआर सेंटर
आईसीएसआई इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स	इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया	आईसीएसआई एनसीएलटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन

(i) आईसीएसआई इंस्टिट्यूट ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (आईसीएसआई-आईआईपी)

आईसीएसआई आईआईपी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ पंजीकृत एक अग्रणी नियामक है। आईसीएसआई आईआईपी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत है। आईसीएसआई आईआईपी को अन्य बातों के साथ-साथ इन्सॉल्वेंसी पेशेवर के रूप में अपने पंजीकृत सदस्यों के नामांकन, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन की निगरानी करने की शक्ति एवं प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अधिदेश में पेशेवर आचरण के मानक निर्धारित करना और जब भी आवश्यकता हो, अपने सदस्यों को अनुशासित करने की दिशा में उचित कदम उठाना शामिल है।

(क) इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों का नामांकन

आईसीएसआई आईआईपी के प्राथमिक कार्यों में से एक है इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों का नामांकन। कुल 1,238 पेशेवर सदस्य आईसीएसआई आईआईपी में नामांकित हैं।

(ख) सदस्यों के कार्य निष्पादन की निगरानी

आईसीएसआई आईआईपी इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों की निगरानी दो तरीकों से करता है, क) डेस्कटॉप मॉनिटरिंग और ख) निरीक्षण (नियमित निरीक्षण और घटना-आधारित निरीक्षण)।

(ग) गतिविधियां/कार्यक्रम

- पूर्व-पंजीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम: आईबीबीआई (इन्सॉल्वेंसी पेशेवर) विनियम, 2016 के विनियमन 5 (ख) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक पेशेवर सदस्य के रूप में अपना/अपने नामांकन के बाद एक इन्सॉल्वेंसी व्यावसायिक एजेंसी से अनिवार्य 50 घंटे के पंजीकरण पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम से गुजरने के बाद ही खुद को दिवाला पेशेवर (आईपी) के रूप में पंजीकृत करने के लिए पात्र हैं। आईसीएसआई आईआईपी ने अन्य इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसियों (आईपीए) के साथ संयुक्त रूप से 01 अप्रैल, 2025 से पंजीकरण पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम के तीन बैच आयोजित किए।
- एलआईटी यूपी – सीमित दिवाला परीक्षा की तैयारी के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) (इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स) विनियम, 2016 के विनियमन 5 के अनुसार, कोई व्यक्ति आईबीबीआई द्वारा आयोजित सीमित दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही दिवाला पेशेवर के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आईसीएसआई आईआईपी ने "एलआईटी यूपी" का एक बैच आयोजित किया, जो सीमित दिवाला परीक्षा की तैयारी के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था।

(घ) राष्ट्रीय सम्मेलन

आईसीएसआई आईआईपी ने 13 और 14 दिसंबर, 2025 को आईसीएसआई सीसीजीआरटी कोलकाता में दिवाला पेशेवर और पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया। कोलकाता में आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में 300 से अधिक दिवाला पेशेवर, पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं, कंपनी सचिवों और प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। माननीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो, प्रभारी मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्गठन, पश्चिम बंगाल सरकार, ने 'मुख्य अतिथि' के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सुश्री स्मिता पांडे, आईएस, प्रधान सचिव, सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्गठन विभाग और श्री विवेक गुप्ता, विधायक, पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा एवं पूर्व राज्यसभा सांसद, कार्यक्रम के विशेष अतिथि थे।

सम्मेलन में उच्च स्तरीय संवादात्मक पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञों, नियामकीय विशेषज्ञों और अनुभवी पेशेवरों ने एक साथ आकर आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की।

(ङ) अन्य कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आईसीएसआई आईआईपी ने 43 वर्कशॉप और 40 वेबिनार आयोजित किए।

(च) संयुक्त कार्यक्रम

क्र.सं.	विषय	तिथि
1.	आईबीबीआई, आईआईआईपीआई और आईपीए आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से आईपी के लिए भौतिक कार्यशाला	30 / 04 / 2025
2.	आईबीबीआई, आईआईआईपीआई और आईपीए आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से आईपी के लिए ऑनलाइन कार्यशाला	16 / 06 / 2025
3.	आईबीबीआई, आईआईआईपीआई और आईपीए आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से आईपी के लिए भौतिक कार्यशाला	20 / 06 / 2025
4.	आईबीबीआई, आईआईआईपीआई और आईपीए आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से आईपी के लिए ऑनलाइन कार्यशाला	03 / 07 / 2025
5.	आईबीबीआई, आईआईआईपीआई और आईपीए आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से आईपी के लिए ऑनलाइन कार्यशाला	10 / 07 / 2025
6.	आईसीएसआई ने आईसीएसआई आईआईपी के सहयोग से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया	19 / 08 / 2025
7.	आईसीएसआई आईआईपी ने आईबीबीआई, आईआईआईपी आईसीएआई और आईपीए आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से दिवाला पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया	31 / 10 / 2025 से 02 / 11 / 2025
8.	आईसीएसआई आईआईपी ने आईबीबीआई, आईआईआईपी आईसीएआई और आईपीए आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से दिवाला पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया	21 / 11 / 2025 से 23 / 11 / 2025
9.	आईसीएसआई आईआईपी ने आईबीबीआई, आईआईआईपी आईसीएआई और आईपीए आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से दिवाला पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया	12 / 12 / 2025 से 14 / 12 / 2025
10.	आईसीएसआई आईआईपी ने आईबीबीआई, आईआईआईपी आईसीएआई और आईपीए आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से दिवाला पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया	23 / 01 / 2026 से 25 / 01 / 2026
11.	आईसीएसआई सीसीजीआरटी कोलकाता ने आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की	14 / 03 / 2026 और 15 / 03 / 2026

(छ) गोलमेज

क्र.सं.	विषय	तिथि
1.	भूषण पावर एंड स्टील मामले में सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय	10 / 05 / 2025
2.	06 और 12 अगस्त, 2025 को जारी आईबीबीआई के चर्चा पत्र	14 / 08 / 2025
3.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025	01 / 11 / 2025
4.	06 नवंबर, 2025 को जारी आईबीबीआई का चर्चा पत्र	14 / 11 / 2025

5.	14 और 17 नवंबर, 2025 को जारी आईबीबीआई के चर्चा पत्र	24/11/2025
6.	16 फरवरी, 2026 को जारी आईबीबीआई का चर्चा पत्र	25/02/2026

(ज) राष्ट्रीय कॉन्क्लेव/आईपी कॉन्क्लेव

क्र.सं.	विषय	तिथि
1.	आईपी कॉन्क्लेव, मल्टीपर्पज हॉल, कमलादेवी कॉम्प्लेक्स, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली	09/05/2025
2.	आईसीएसआई के एसआईआरसी के हैदराबाद चौप्टर ने आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के सहयोग से आईसीएसआई नेशनल कॉन्क्लेव फॉर एनसीएलटी प्रैक्टिशनर्स-2025 आयोजित किया	29/11/2025
3.	आईसीएसआई के एसआईआरसी के बेंगलुरु चौप्टर ने आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के सहयोग से आईसीएसआई नेशनल कॉन्क्लेव फॉर एनसीएलटी प्रैक्टिशनर्स-2025 आयोजित किया	06/12/2025

(झ) पंजीकरण पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम (ऑनलाइन कोर्स)

क्र.सं.	विषय	तिथि
1.	पंजीकरण पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम का 67वां बैच	14/04/2025 - 20/04/2025
2.	पंजीकरण पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम का 68वां बैच	21/07/2025 - 27/07/2025
3.	पंजीकरण पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम का 69वां बैच	15/01/2026 - 21/01/2026

(ञ) एलआईटी यूपी (वर्चुअल कक्षा)

क्र.सं.	विषय	तिथि
1.	एलआईटी यूपी – सीमित दिवाला परीक्षा प्रशिक्षण । तैयारी के लिए वर्चुअल कक्षा	20/06/2022 - 22/06/2025

(ट) ज्ञान पहल

- **ई-जर्नल** : आईसीएसआई आईआईपी मासिक ई-जर्नल प्रकाशित करता है जिसमें नवीनतम घटनाओं, विषय विशेषज्ञों के साक्षात्कार, न्यायिक घोषणाओं, विभिन्न हितधारकों द्वारा लिखे गए लेखों, आईपी के लिए कोड और आचरण पर लिखने, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, अद्यतन नीति, वैश्विक क्षेत्र आदि शामिल होते हैं।
- **दैनिक ज्ञानार्जन चरण (डेली लर्निंग कर्व)**— आईसीएसआई आईआईपी सभी इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों, एनसीएलटी बेंच के सदस्यों, आईबीबीआई, अन्य पेशेवरों आदि को दैनिक आधार पर 'आईबीसी लर्निंग कर्व' प्रदान करता है। आईबीसी लर्निंग कर्व्स आईबीसी के अंतर्गत नवीनतम न्यायिक घोषणाओं पर आधारित हैं।
- **लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) पोर्टल**— आईसीएसआई आईआईपी ने पेशेवरों को अपने करियर के सभी क्षेत्रों के इन्सॉल्वेंसी कानून के बारे में अधिक जानने और अध्ययन करने में सक्षम बनाने के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। यह पोर्टल आईबीबीआई द्वारा अधिसूचित नवीनतम प्रारूप और पाठ्यक्रम के अनुसार सीमित इन्सॉल्वेंसी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीमित इन्सॉल्वेंसी परीक्षा पाठ्यक्रम और ई-मॉक परीक्षा को कवर करने वाले विशेषज्ञों द्वारा दिए गए ई-पुस्तकों, ऑनलाइन व्याख्यानों के माध्यम से सीखने में सहायता प्रदान करता है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को लिमिटेड इन्सॉल्वेंसी परीक्षाओं को प्रभावी ढंग से उत्तीर्ण करने में सक्षम बनाएगी।

(ठ) सर्टिफिकेट कोर्स

आईसीएसआई आईआईपी ने आईसीएसआई के साथ संयुक्त रूप से 'आईबीसी पर सर्टिफिकेट कोर्स – बैच 6' का आयोजन

19 अगस्त, 2025 से दिसंबर, 2025 तक किया। इस कोर्स के लिए लगभग 64 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया।

(ii) आईसीएसआई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन (आईसीएसआई आरवीओ)

आईसीएसआई आरवीओ संस्थान की एक धारा 8 कंपनी है। आईसीएसआई आरवीओ का उद्देश्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता एवं मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसार पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के पेशे को नामांकित, शिक्षित, प्रशिक्षित और बढ़ावा देना है।

(क) 50 घंटे के ऑनलाइन शैक्षिक पाठ्यक्रम

आईसीएसआई आरवीओ ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 09 बैचों में 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम आयोजित किए।

(ख) प्रमुख कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आईसीएसआई आरवीओ ने 12 निरंतर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए।

(ग) पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आयोजित अभ्यास प्रमाणपत्र (सीओपी) कार्यक्रम

क्र.सं.	तिथि	विषय
1.	07 मई, 2025	i. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आचार संहिता
		ii. पेशेवर नैतिकता
		iii. मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना
		iv. सॉफ्ट स्किल्स (क्लाइंट और सहकर्मियों के साथ कैसे संवाद करें)
2.	1 जुलाई, 2025	i. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आचार संहिता
		ii. पेशेवर नैतिकता
		iii. मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना
		iv. सॉफ्ट स्किल्स (क्लाइंट और सहकर्मियों के साथ कैसे संवाद करें)
3.	23 जुलाई, 2025	i. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आचार संहिता
		ii. पेशेवर नैतिकता
		iii. मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना
		iv. सॉफ्ट स्किल्स (क्लाइंट और सहकर्मियों के साथ कैसे संवाद करें)

(iii) आईसीएसआई अंतरराष्ट्रीय एडीआर केंद्र

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता और पंचाट को सुगम बनाने के उद्देश्य से, आईसीएसआई ने नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपना पहला आईसीएसआई अंतरराष्ट्रीय एडीआर केंद्र स्थापित किया। आईसीएसआई अंतरराष्ट्रीय एडीआर केंद्र का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, व्यक्तियों, कॉर्पोरेट्स, फर्मों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों (स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय) को सहायता और शिक्षा प्रदान करने हेतु मध्यस्थता और पंचाट सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) विधियों को बढ़ावा देना है।

आईसीएसआई आईएससी ने मध्यस्थों के रूप में पैनल में शामिल किए जाने के इच्छुक पेशेवरों से आवेदन आमंत्रित किए। कुल 53 पेशेवरों को आईसीएसआई इंटरनेशनल एडीआर सेंटर में मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल किया गया।

आईसीएसआई इंटरनेशनल एडीआर सेंटर ने आईसीएसआई-सीसीजीआरटी कोलकाता और एडमास यूनिवर्सिटी के सहयोग से 15 और 16 नवंबर, 2025 को मध्यस्थता पर 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया।

(iv) आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स (आईसीएसआई आईएसए)

आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स (आईसीएसआई-आईएसए) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 के तहत एक कंपनी है, जिसे आईसीएसआई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं को पंजीकृत करने, पैनल में शामिल करने के लिए मानदंड/नियम निर्धारित करने के साथ-साथ पंजीकृत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं के लिए पेशेवर आचरण के मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से निगमित किया गया है। आईसीएसआई-आईएसए ने उन सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं (एसआईए) का पैनल तैयार करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने अपेक्षित एनआईएसएम प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। आईसीएसआई-आईएसए ने 12 मई, 2023 से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, सेबी ने 27 मई, 2024 के परिपत्र, सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/0060 के माध्यम से आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स (आईसीएसआई-आईएसए) को आईसीएसआई-आईएसए के साथ पंजीकृत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं और सामाजिक प्रभाव आकलन संस्थाओं के लिए एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में निर्दिष्ट किया है।

(v) इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ इंडिया (आईजीपीआई)

इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया (पूर्व में आईसीएसआई गवर्नेंस रिसर्च एंड नॉलेज फाउंडेशन), आईसीएसआई द्वारा प्रवर्तित एक धारा 8 कंपनी है। यह कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 की तत्कालीन धारा 25 के तहत पंजीकृत थी, जिसे अब कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 के रूप में जाना जाता है।

इसका उद्देश्य है: "कॉर्पोरेट कानूनों, अभिशासन, प्रबंधन, व्यवसाय संधारणीयता और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, पूंजी और वित्तीय बाजारों, ऑडिटिंग, राजकोषीय और आर्थिक कानूनों एवं नीतियों, सूचना और नियंत्रण प्रणालियों तथा संबद्ध विषयों के क्षेत्र में शोध, प्रकाशन, प्रशिक्षण, शिक्षा या किसी अन्य माध्यम से, समान उद्देश्यों वाले या समान गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ सीधे या उनके सहयोग से ज्ञान का सृजन, प्रसार और प्रदान करना।"

(क) आईसीएसआई बोर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम

इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया ने आईसीएसआई के साथ मिलकर, आईसीएसआई बोर्ड मेंटरशिप कार्यक्रम के तत्वावधान में एक ऐसा मंच विकसित किया, जिसमें अनुभवी बोर्ड चेयर, स्वतंत्र निदेशक, नीति निर्माता, गवर्नेंस विशेषज्ञ, उद्योग जगत के नेता और अनुभवी पेशेवरों को एक मंच पर लाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान और भावी बोर्ड नेताओं को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण, वैश्विक गवर्नेंस प्रथाओं, रणनीतिक समझ और व्यावहारिक अनुभव से समृद्ध करना है।

वर्ष 2025-26 के दौरान, आईजीपीआई ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तीन (3) आईसीएसआई बोर्ड मेंटरशिप कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे क्षेत्रों का संतुलित प्रतिनिधित्व और समावेशी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

क्र.सं.	स्थान	क्षेत्र	तिथि
1	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	उत्तर	2 से 5 अप्रैल, 2025
2	कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल	पूर्व	18 से 21 सितंबर, 2025
3	जैसलमेर, राजस्थान	उत्तर-पश्चिम	8 से 11 जनवरी, 2026

इन कार्यक्रमों में देशभर के व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित नेताओं, वरिष्ठ कॉर्पोरेट पेशेवरों, कॉर्पोरेट निदेशकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। उनकी भागीदारी से सहकर्मी-आधारित सीखने (पीयर लर्निंग) के लिए एक समृद्ध मंच तैयार हुआ, जिससे गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला और कॉर्पोरेट जगत में उभरते रुझानों और चुनौतियों पर अधिक गहन संवाद को प्रोत्साहन मिला।

(ख) कॉर्पोरेट्स के लिए ऑनलाइन निदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईजीपीआई ने लचीले और प्रौद्योगिकी-सक्षम अधिगम के माध्यमों के जरिए कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित कौशल को बढ़ाने के लिए तीन (3) ऑनलाइन निदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है:

29 अप्रैल, 2025	एसएमई सूचीबद्ध कंपनियां, एनएसई के साथ संयुक्त रूप से	भौतिक (मुंबई, महाराष्ट्र)
4 नवंबर, 2025	सेंको लिमिटेड	ऑनलाइन
28 मार्च, 2026	सेंको गोल्ड लिमिटेड	ऑनलाइन

(vi) आईसीएसआई एनसीएलटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन

आईसीएसआई एनसीएलटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित एक धारा 8 कंपनी है, जो विशेष रूप से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष उपस्थित होने वाले पेशेवर कंपनी सचिवों के लिए है। एक गैर-लाभकारी, गैर-राजनीतिक और गैर-सरकारी संगठन के रूप में गठित, इस एसोसिएशन का उद्देश्य पेशेवर कंपनी सचिवों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अग्रणी संस्था के रूप में कार्य करना है। इसका मिशन समुदाय के भीतर व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देना और बनाए रखना तथा अपने सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना है।

यह एसोसिएशन कानूनी और कॉर्पोरेट शिक्षा के अवसर प्रदान करने, सेमिनार आयोजित करने, नेटवर्किंग और सौहार्द को बढ़ावा देने, और कार्यरत पेशेवरों के लिए कॉर्पोरेट कानूनी प्रणालियों में सार्थक योगदान देने के अवसर पैदा करने का प्रयास करता है।

(ड) समेकित लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु संस्थान के समेकित लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

(ढ) आईसीएसआई रणनीतिक कार्ययोजना (2026–2030)

संस्थान ने संस्थान की गतिविधियों की व्यापक समीक्षा करने और इसके विकास एवं बदलाव के लिए भविष्य की रूपरेखा सुझाने के लिए 'रणनीतिक समूह – आईसीएसआई एसेंड' का गठन किया। इस समूह को पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने, डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने, संगठन की कार्यक्षमता बढ़ाने, वैश्विक पहुंच का विस्तार करने और हितधारकों के साथ जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। व्यापक विचार-विमर्श और रणनीतिक विश्लेषण के माध्यम से, रणनीतिक समूह – आईसीएसआई एसेंड ने रणनीतिक कार्ययोजना (2026–2030) प्रस्तावित की, जिसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप उभरती चुनौतियों और अवसरों के लिए संस्थान और कंपनी सचिव पेशेवरों को तैयार करना है।

परिषद ने रणनीतिक समूह – आईसीएसआई एसेंड की सिफारिश के अनुसार संस्थान की रणनीतिक कार्ययोजना (2026–2030) को अपनाया। इसमें हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के आंतरिक संगठनात्मक पुनर्गठन और कार्यप्रणाली के पुनर्संरचना को भी शामिल किया गया है।

(ण) मुख्य गतिविधियाँ [अप्रैल 2026 – अगस्त 2026] – एक नज़र में

संस्थान द्वारा 01 अप्रैल, 2026 से अगस्त, 2026 तक की गई प्रमुख गतिविधियों को परिशिष्ट घ में दिया गया है।

(त) भावी परिदृश्य

“भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं।”

~ महात्मा गांधी

दुनिया अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है। आर्थिक पुनर्गठन, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, जलवायु से जुड़े जोखिम, तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति, निवेशकों की बदलती अपेक्षाएं और सतत विकास पर बढ़ता जोर, ये सभी मिलकर संस्थानों के काम करने और मूल्य सृजित करने के तरीके को नए रूप में परिभाषित कर रहे हैं। लगातार होते बदलाव के इस माहौल में, अभिशासन की समझ अनुपालन की मजबूरी से आगे बढ़कर एक रणनीतिक आवश्यकता बन गई है, जो मजबूत अर्थव्यवस्थाओं, भरोसेमंद संस्थानों और सतत उद्यमों की नींव के रूप में काम कर रही है।

यदि आने वाले दशकों में भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है, तो इंडिया इंक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरी दुनिया की नजर हम पर है कि हम अपने सपनों, विजन, लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस तरह हासिल करते हैं और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएन एसडीजी) तथा पर्यावरणीय सीमाओं के साथ अपना तालमेल किस प्रकार बनाए रखते हैं।

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने इन सभी पहलुओं के प्रति सदैव एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है—और नैतिक, पारदर्शी तथा भविष्य के लिए तत्पर संगठनों के निर्माण, संस्थागत विश्वसनीयता को प्रदर्शित करने एवं आर्थिक विकास व सामाजिक प्रगति में सहभागिता निभाने के प्रति दिन-प्रतिदिन अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

आने वाले वर्षों में ऐसे पेशेवरों की आवश्यकता होगी, जो इन लक्ष्यों से जुड़ी जटिलताओं को दक्षता और ईमानदारी के साथ समझते हुए आगे बढ़ने में सक्षम हों। भविष्य के अभिशासन पेशेवरों से अपेक्षा की जाएगी कि वह कानूनी और नियामकीय विशेषज्ञता के साथ डिजिटल जानकारी, रणनीतिक सोच, सरस्टेनेबिलिटी के प्रति जागरूकता और नेतृत्व क्षमता को भी साथ लेकर चले। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए, संस्थान अपने शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के ढांचे को लगातार बेहतर बनाता रहेगा, ताकि अपने सदस्यों और छात्रों को उभरते अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

यदि डिजिटल बदलाव पर जोर दिया जाए, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा ढांचे और डिजिटल गवर्नेंस तंत्र में तेजी से हो रही प्रगति कॉरपोरेट परिदृश्य को नए रूप में आकार दे रही है। इसी तरह, ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस) के पहलुओं पर भी लगातार बढ़ता जोर महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे व्यवसाय अपनी रणनीतिक निर्णय प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सततता दोनों को तेजी से शामिल कर रहे हैं, गवर्नेंस प्रोफेशनल्स संगठनों को जिम्मेदार तरीके से और दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने की दिशा में मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले विचार-विमर्श में संस्थान और पेशे की वैश्विक पहुंच केंद्र में है। यह केवल मान्यता हासिल करने की बात नहीं है, बल्कि अभिशासन के वैश्विक मार्गदर्शक बनने की बात है – रास्ता जानना, उस रास्ते पर चलना और दूसरों को रास्ता दिखाना। आगे बढ़ते हुए, हमारा उद्देश्य ऐसी साझेदारियों को बढ़ावा देना है, जो न केवल ज्ञान के आदान-प्रदान को सुगम बनाएं, बल्कि पेशेवर मानकों को भी बेहतर बनाएं और वैश्विक मंच पर भारत की अभिशासन क्षमताओं को प्रदर्शित करें।

जैसे-जैसे दुनिया बदल रही है और नए अवसर सामने आ रहे हैं, हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है। अच्छे गवर्नेंस को बढ़ावा देना, संस्थानों के जिम्मेदारी से संचालन के ढांचे को मजबूत करना और ऐसा भविष्य बनाने में योगदान देना, जो सभी के लिए मजबूत, समावेशी, सतत और समृद्ध हो।

भगवद्गीता के शब्दों में:

“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥”

(श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य जन भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे अपने कर्मों से जो आदर्श या प्रमाण स्थापित करते हैं, समस्त संसार उसी का अनुसरण करता है।)

इस शाश्वत सिद्धांत से मार्गदर्शन लेते हुए, संस्थान उत्कृष्टता की अपनी निरंतर खोज जारी रखेगा और अपने मिशन “अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन को बढ़ावा देने वाले उच्च क्षमता वाले पेशेवरों का विकास करना” के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार प्रतिभाओं को विकसित करने, अभिशासन की प्रथाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करने, निरंतर सीखने को बढ़ावा देने और हितधारकों के विश्वास को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

हमारा लक्ष्य केवल बदलाव के अनुरूप खुद को ढालना नहीं है, बल्कि ज्ञान, नैतिक नेतृत्व और अनुकरणीय पेशेवर कार्यशैली के माध्यम से बदलाव का नेतृत्व करना है।

(थ) आभार

**सह नावतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहे॥
(हम सबकी एक साथ रक्षा हो; हम सबका एक साथ पोषण हो;
हम सब पूरी ऊर्जा और उद्देश्य के साथ मिलकर कार्य करें।)**

~ तैत्तिरीय उपनिषद्

जब हम वर्ष 2025–26 के सफर पर नज़र डालते हैं, तो हम इसे बहुत विनम्रता और आभार के साथ देखते हैं। वर्ष के दौरान भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा हासिल की गई हर उपलब्धि हमारे हितधारकों द्वारा दिए गए अमूल्य सहयोग, प्रोत्साहन और विश्वास का प्रमाण है। पेशे और संस्थान में आपका अटूट विश्वास हमें उत्कृष्टता, सेवा और जिम्मेदारी के और ऊंचे मानक हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है।

सबसे पहले, हम भारत सरकार, और खास तौर पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देश के गवर्नेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में उनके लगातार मार्गदर्शन, सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए हम उनके आभारी हैं। हम माननीय मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ नीति-निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों से मिले प्रोत्साहन और रचनात्मक सहयोग की भी बहुत सराहना करते हैं; जिनकी दूरदर्शिता और समझ इस पेशे को और देश के निर्माण में इसके योगदान को लगातार समृद्ध कर रही है।

हम सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, एनएसई, बीएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल, सीईआरसी और अन्य संस्थानों सहित विभिन्न नियामकीय और वैधानिक प्राधिकरणों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मजबूत गवर्नेंस मानकों, निवेशकों के विश्वास, पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पेशे के साथ मिलकर काम किया है। तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में कंपनी सचिवों को अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने में उनके मार्गदर्शन और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

यदि अपने व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष के रूप में मिले सहयोग की बात करूं, तो मैं निर्णय लेने में परिषद और समितियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए कृतज्ञ हूँ; वहीं, परिषद के रूप में हम सामूहिक रूप से और कृतज्ञतापूर्वक बोर्डों, टास्क फोर्स, सलाहकार समूहों और अपीलीय प्राधिकरणों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हैं। उनकी समझ, अनुभव और अथक प्रयासों से ऐसी पहलों को आकार देने में मदद मिली है, जो संस्थान के विजन को आगे बढ़ाती हैं और हितधारकों तथा समाज के व्यापक हितों की सेवा करती हैं।

हमारी धारा 8 कंपनियां अपनी समर्पित पहलों के माध्यम से हर गुजरते दिन पेशेवर अवसरों के नए द्वार खोल रही हैं और इसके लिए मैं उनके शासी निकायों के प्रति अपनी हार्दिक सराहना एवं साधुवाद व्यक्त करता हूँ।

हम उद्योग जगत, कॉर्पोरेट्स, वित्तीय संस्थानों, वाणिज्य मंडलों, पेशेवर निकायों, शिक्षाविदों, शोध संस्थानों और नीति संबंधी थिंक टैंकों के नेतृत्वों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पूरे वर्ष हमारे साथ साझेदारी की। हमारे कार्यक्रमों, शोध पहलों और क्षमता निर्माण के प्रयासों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने विचारों के आदान-प्रदान को मजबूत किया और अभिशासन से जुड़े विचार-विमर्श को समृद्ध बनाया।

जैसे-जैसे अभिशासन का स्वरूप वैश्विक होता जा रहा है और आईसीएसआई अपने विजन “अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन को बढ़ावा देने में वैश्विक अग्रणी बनना” की दिशा में पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है, हम अंतरराष्ट्रीय अभिशासन निकायों, सचिवीय संघों, विदेशी दूतावासों, उच्चायोगों, महावाणिज्य दूतावासों और हमारे विदेशी केंद्रों के सहयोग के लिए कृतज्ञतापूर्वक उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारा निरंतर साथ मिलकर किया जा रहा प्रयास हमारी वैश्विक पहुंच को मजबूत कर रहा है और ऐसे सार्थक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिनका उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं से परे अभिशासन की प्रथाओं को आगे बढ़ाना है।

किसी भी संस्था की शक्ति और प्रगति—चाहे उसका उद्देश्य, आशय, संरचना और आकार कुछ भी हो—उसके लोगों के समर्पण में निहित होती है। टीम आईसीएसआई द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, निर्णयों के क्रियान्वयन में उनकी दृढ़ता और कार्यों में उनका उत्साह वास्तव में अनुकरणीय रहा है। पूरी परिषद की ओर से, मैं अपनी विभिन्न भूमिकाओं और क्षमताओं में सचिवालय, सीसीजीआरटी, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं (चैप्टरों), प्रबंध समितियों, प्रशिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों द्वारा हमें दिए गए समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी व्यावसायिकता, प्रतिबद्धता और अनवरत निष्ठा ने दृष्टिकोण को कार्यरूप देने तथा आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हम विशेष रूप से अपने सदस्यों और छात्रों के प्रति आभारी हैं, जो इस पेशे के सच्चे संवाहक (एंबेसडर) बने हुए हैं। वास्तव में यह आपकी त्रुटिहीन मूल्य-प्रणाली, उत्कृष्टता की निरंतर खोज और अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता ही है, जो इस पेशे के कद और विश्वसनीयता को निरंतर बढ़ा रही है। आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियाँ और सामूहिक प्रयास संस्थान को लगातार नवाचार करने, अपनी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और व्यावसायिक विकास के अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रेरित करते हैं।

हम उन पूर्व अध्यक्षों, परिषद सदस्यों, पदाधिकारियों और सभी प्रतिष्ठित पेशेवरों के योगदान को अत्यंत सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं, जिनके वर्षों के अथक प्रयासों ने एक मजबूत संस्थागत नींव तैयार की है, जिस पर हम आज भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

जैसे-जैसे हम तकनीकी बदलाव, सततता की बढ़ती जरूरतों और जवाबदेही तथा जिम्मेदारी से जुड़ी बदलती अपेक्षाओं के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सामूहिक सफलता सहयोग, विश्वास और साझा उद्देश्य पर निर्भर करती रहेगी। संस्थान हर उस हितधारक को महत्व देता है, जो बेहतर अभिशासन और जिम्मेदार नेतृत्व को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़ा है।

हमारी कहानी के हर सफल अध्याय के पीछे हमारे सभी हितधारकों का पूरा तंत्र है दृ एक ऐसा समुदाय जो बेहतरीन काम करने के लिए समर्पित है। हमारे सपनों पर भरोसा करने, हमारे कामों में साथ देने और हमारे दीर्घकालिक विजन के प्रति आपकी साझा प्रतिबद्धता के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि जेम्स सी. पेनी कहते हैं,

“विकास केवल संयोग से नहीं होता; यह कई ताकतों के एक साथ मिलकर काम करने का नतीजा होता है।”

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद हेतु और की ओर से

हस्ता/—

नई दिल्ली

तिथि: 29 अगस्त, 2026

सीएस पवन जी चांडक, अध्यक्ष, आईसीएसआई
[विज्ञापन-III/4/असा./338/2026-27]

परिशिष्ट—क

वर्ष – 2026 के लिए स्थायी, गैर-स्थायी समितियों और बोर्डों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद
1. कार्यकारी समिति		
1.	सीएस पवन जी चांडक	अध्यक्ष
2.	सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर	सदस्य
3.	श्री इंदर दीप सिंह धारीवाल	सदस्य (सरकारी नामिती)
4.	सीएस धनंजय शुक्ला	सदस्य
5.	सीएस बी नरसिम्हन	सदस्य
6.	सीएस मनोज कुमार पुरबे	सदस्य
7.	सीएस वेंकट रमण आर.	सदस्य
2. वित्त समिति		
1.	सीएस पवन जी चांडक	अध्यक्ष
2.	सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर	सदस्य
3.	सीएस आशीष करोड़िया	सदस्य
4.	सीएस मोहनकुमार ए.	सदस्य
5.	सीएस प्रवीण सोनी	सदस्य
6.	सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	सदस्य
7.	सीएस सुरेश पांडे	सदस्य
3. परीक्षा समिति		
1.	सीएस पवन जी चांडक	अध्यक्ष
2.	सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर	सदस्य
3.	सीएस बी नरसिम्हन	सदस्य
4.	सीएस एनपीएस चावला	सदस्य
5.	सीएस राजेश तारपारा	सदस्य
6.	सीएस रूपांजना डे	सदस्य
7.	सीएस सुरेश पांडे	सदस्य
4. वित्तीय सेवा समिति		
1.	सीएस आशीष करोड़िया	अध्यक्ष
2.	सीएस बी नरसिम्हन	सदस्य
3.	सीएस मनोज कुमार पुरबे	सदस्य
4.	सीएस मोहनकुमार ए.	सदस्य
5.	सीएस एनपीएस चावला	सदस्य
6.	सीएस राजेश तारपारा	सदस्य
7.	सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	सदस्य
5. कॉर्पोरेट कानून और अभिशासन समिति		
1.	सीएस मनीष गुप्ता	अध्यक्ष
2.	डॉ. अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य (सरकारी नामिती)
3.	सीएस धनंजय शुक्ला	सदस्य
4.	सीएस आशीष करोड़िया	सदस्य
5.	सीएस मनोज कुमार पुरबे	सदस्य
6.	सीएस राजेश तारपारा	सदस्य
7.	सीएस वेंकट रमण आर.	सदस्य
6. आईसीएसआई सीसीजीआरटी प्रबंधन समिति		
1.	सीएस धनंजय शुक्ला	अध्यक्ष
2.	सीएस मनीष गुप्ता	सदस्य

3.	सीएस आशीष करोड़िया	सदस्य
4.	सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	सदस्य
5.	सीएस वेंकट रमण आर.	सदस्य
7. केंद्रीकृत अवसंरचना समिति		
1.	सीएस धनंजय शुक्ला	अध्यक्ष
2.	सीएस मनीष गुप्ता	सदस्य
3.	सीएस आशीष करोड़िया	सदस्य
4.	सीएस राजेश तारपारा	सदस्य
5.	सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	सदस्य
6.	सीएस वेंकट रमण आर.	सदस्य
8. व्यावसायिक विकास समिति		
1.	सीएस वेंकट रमण आर.	अध्यक्ष
2.	श्री संजय शौरी	सदस्य (सरकारी नामिती)
3.	सीएस मनीष गुप्ता	सदस्य
4.	सीएस एनपीएस चावला	सदस्य
5.	सीएस प्रवीण सोनी	सदस्य
6.	सीएस राजेश तारपारा	सदस्य
7.	सीएस रूपांजना डे	सदस्य
8.	सीएस सुरेश पांडे	सदस्य
9. प्रशिक्षण और शैक्षिक सुविधा समिति		
1.	सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर	अध्यक्ष
2.	श्री बालामुरुगन डी.	सदस्य (सरकारी नामिती)
3.	सीएस धनंजय शुक्ला	सदस्य
4.	सीएस बी नरसिम्हन	सदस्य
5.	सीएस आशीष करोड़िया	सदस्य
6.	सीएस मनोज कुमार पुरबे	सदस्य
7.	सीएस मोहनकुमार ए.	सदस्य
8.	सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	सदस्य
10. पेशेवर कंपनी सचिव समिति		
1.	सीएस राजेश तारपारा	अध्यक्ष
2.	सीएस धनंजय शुक्ला	सदस्य
3.	सीएस बी नरसिम्हन	सदस्य
4.	सीएस आशीष करोड़िया	सदस्य
5.	सीएस मोहनकुमार ए.	सदस्य
6.	सीएस रूपांजना डे	सदस्य
7.	सीएस वेंकट रमण आर.	सदस्य
11. सूचना प्रौद्योगिकी समिति		
1.	सीएस मनोज कुमार पुरबे	अध्यक्ष
2.	सीएस धनंजय शुक्ला	सदस्य
3.	सीएस मोहनकुमार ए.	सदस्य
4.	सीएस एनपीएस चावला	सदस्य
5.	सीएस प्रवीण सोनी	सदस्य
6.	सीएस राजेश तारपारा	सदस्य
7.	सीएस रूपांजना डे	सदस्य
8.	सीएस वेंकट रमण आर.	सदस्य
12. प्लेसमेंट समिति		

1.	सीएस मोहनकुमार ए.	अध्यक्ष
2.	सीएस मनोज कुमार पुरबे	सदस्य
3.	सीएस एनपीएस चावला	सदस्य
4.	सीएस प्रवीण सोनी	सदस्य
5.	सीएस रूपांजना डे	सदस्य
6.	सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	सदस्य
7.	सीएस सुरेश पांडे	सदस्य
13. पेशेवर अनुसंधान समिति		
1.	सीएस रूपांजना डे	अध्यक्षा
2.	सीएस आशीष करोड़िया	सदस्य
3.	सीएस एनपीएस चावला	सदस्य
4.	सीएस राजेश तारपारा	सदस्य
5.	सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	सदस्य
14. प्रकाशन समिति		
1.	सीएस प्रवीण सोनी	अध्यक्ष
2.	डॉ. अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य (सरकारी नामिती)
3.	सीएस मनोज कुमार पुरबे	सदस्य
4.	सीएस मोहनकुमार ए.	सदस्य
5.	सीएस एनपीएस चावला	सदस्य
6.	सीएस रूपांजना डे	सदस्य
7.	सीएस सुरेश पांडे	सदस्य
15. अनुशासन बोर्ड		
1.	सीएस बी नरसिम्हन	पीठासीन अधिकारी
2.	सीएस वेंकट रमण आर.	सदस्य
3.	सीएस आशीष मोहन	सदस्य
16. अनुशासन समिति		
1.	सीएस पवन जी चांडक	पीठासीन अधिकारी
2.	श्री सुनील दाधे	सदस्य (सरकारी नामिती)
3.	श्री सुशील कुमार	सदस्य सदस्य (सरकारी नामिती)
4.	सीएस धनंजय शुक्ला	सदस्य
5.	सीएस मनीष गुप्ता	सदस्य
17. पीएमक्यू पाठ्यक्रम समिति		
1.	सीएस धनंजय शुक्ला	अध्यक्ष
2.	सीएस राजेश तारपारा	सदस्य
3.	सीएस मनोज कुमार पुरबे	सदस्य
4.	सीएस एनपीएस चावला	सदस्य
5.	सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	सदस्य
6.	सीएस आशीष करोड़िया	सदस्य
7.	सीएस वेंकट रमण आर.	सदस्य
18. सहकर्मी समीक्षा बोर्ड		
1.	सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	अध्यक्ष
2.	सीएस आशीष करोड़िया	सदस्य
3.	सीएस मनोज कुमार पुरबे	सदस्य
4.	सीएस मोहनकुमार ए.	सदस्य
5.	सीएस निसार अहमद	सदस्य
6.	सीएस प्रसाद तकलकर	सदस्य
7.	सीएस मनोज सोनी	सदस्य
19. संपादकीय सलाहकार बोर्ड		
1.	सीएस एनपीएस चावला	अध्यक्ष

2.	डॉ. अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य (सरकारी नामिती)
3.	सीएस पी. सी. अग्रवाल	सदस्य
4.	सीएस राजेश तारपारा	सदस्य
5.	सीएस रूपांजना डे	सदस्य
6.	सीएस (प्रोफेसर) अंजलि गुप्ता	सदस्य
7.	सीएस गौरव पिंगले	सदस्य
8.	सीएस सुधांशु सिंघल	सदस्य
9.	सीएस शीतल महामुनी	सदस्य
10.	सीएस बिमल जैन	सदस्य
11.	सीएस (डॉ.) डी. के. जैन	सदस्य
12.	सीएस राम ठक्कर	सदस्य
13.	सीएस नितिन सोमानी	सदस्य
14.	सीएस प्रणव कुमार	सदस्य
15.	सीएस (प्रोफेसर) रबी नारायण कार	सदस्य
16.	सीएस अभिजीत राणे	सदस्य
17.	सीएस (डॉ.) सुधींद्र पुट्टी	सदस्य
18.	सीएस रुद्र पांडे	सदस्य
19.	सीएस सचिन अग्रवाल	सदस्य
20. लेखा परीक्षा मानक बोर्ड		
1.	सीएस सुरेश पांडे	अध्यक्ष
2.	सीएस मनोज कुमार पुरबे	सदस्य
3.	सीएस विनीत के चौधरी	सदस्य
4.	सीएस अमित कौशल	सदस्य
5.	सीएस के वेंकट रमण	सदस्य
6.	सीएस राघवेंद्र जोशी	सदस्य
7.	सीएस रमाकांत पाठक	सदस्य
8.	सीएस विकास गेरा	सदस्य
9.	सीएस पवन कुमार रुस्तगी	सदस्य
10.	सीएस भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र	सदस्य
11.	सीएस कामित जैन	सदस्य
12.	सीएस राहुल जैन	सदस्य
13.	सीएस लोकेश ध्यानी	सदस्य
14.	सीएस राम प्रकाश पुंजानी	सदस्य
15.	सीएस रवि शर्मा	सदस्य
16.	सेबी के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार डांगेती मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), कॉरपोरेशन फाइनेंस विभाग – नीति कार्यक्षेत्र, सेबी	सदस्य
17.	बीएसई के प्रतिनिधि श्री विशाल झावेरी उप मुख्य नियामकीय अधिकारी, बीएसई	सदस्य
18.	एनएसई के प्रतिनिधि श्री आविष्कार नाइक वरिष्ठ उपाध्यक्ष – मध्यस्थता एवं शिकायत निवारण, सदस्य चूक आईएससी और यूसीआई	सदस्य
21. सचिवीय मानक बोर्ड		
1.	सीएस नागेंद्र डी राव	अध्यक्ष
2.	सीएस मनीष गुप्ता	सदस्य
3.	सीएस बी नरसिम्हन	सदस्य
4.	सीएस अजय जयसवाल	सदस्य

5.	सीएस अवनीश द्विवेदी	सदस्य
6.	सीएस कालिदास रामास्वामी	सदस्य
7.	सीएस कुलदीप रुचंदानी	सदस्य
8.	सीएस रवि कपूर	सदस्य
9.	सीएस ओम प्रकाश बागडिया	सदस्य
10.	सीएस प्रजोत तुंगारे	सदस्य
11.	सीएस रोहित अरोड़ा	सदस्य
12.	सीएस संजीव ग्रीवर	सदस्य
13.	सीएस सवित्री पारेख	सदस्य
14.	सीएस सुधाकर सारस्वतुला	सदस्य
15.	सीएस शिवकुमार	सदस्य
प्रतिनिधि सदस्यगण		
16.	नामिती - आईसीएमआई सीएमए अविजित गोस्वामी	सदस्य
17.	नामिती - आईसीआई सीए विशाल दोशी (एफसीए)	सदस्य
18.	नामिती - आईएफएससीए सीएस प्रदीप रामकृष्णन	सदस्य
19.	नामिती - बीएसई	सदस्य
20.	नामिती - सीआईआई सीएस मणिकण्ठ एजीएस	सदस्य
21.	नामिती - एनएसई सुश्री युक्ति शर्मा	सदस्य
22. एमएसएमई और स्टार्ट-अप बोर्ड		
1.	सीएस देवेन्द्र वी देशपांडे	अध्यक्ष
2.	सीएस राजीव बजाज	सदस्य
3.	सीएस (डॉ.) अजय गर्ग	सदस्य
4.	सीएस योगेन्द्र ओमप्रकाश शर्मा	सदस्य
5.	सीएस अजय संचेती	सदस्य
6.	सीएस अरुण मुल्गे	सदस्य
7.	सीए गौरव अरोड़ा	सदस्य
8.	श्री गौरव महानी	सदस्य
9.	सीएस प्रमोदकुमार रमेश लड्डा	सदस्य
10.	सीएस उज्जवल रमेशचंद्र निकम	सदस्य
11.	सीएस विकास रमेश अग्रवाल	सदस्य
12.	सीएस दीपक बंसल	सदस्य
13.	सीएस पद्मसिंह पाटिल	सदस्य
14.	सीएस सचिन खुराना	सदस्य
15.	सीएस आशिक ए एम	सदस्य
16.	सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	विशेष आमंत्रित
17.	सीएस वेंकट रमण आर.	विशेष आमंत्रित
23. ईएसजी और संधारणीयता बोर्ड		
1.	सीएस रंजीत पांडे	अध्यक्ष
2.	सीएस आशीष तिवारी	सदस्य
3.	सीएस परम्बिल देवासी विसेंट	सदस्य
4.	सीएस अनिल रुस्तगी	सदस्य

5.	सीएस राजेश सी. तारपारा	सदस्य
6.	सीएस अभिनव अग्रवाल	सदस्य
7.	सीएस रोहित गोखले	सदस्य
8.	सीएस भास्कर जोशी	सदस्य
9.	सीएस जे सुंदरेसन	सदस्य
10.	सीएस मंगल कुलकर्णी (सुश्री)	सदस्य
11.	सीएस पंकज चौरसिया	सदस्य
12.	सीएस चन्द्रशेखर चिंचोलकर	सदस्य
13.	सीएस सचिन मिश्रा	सदस्य
14.	सीएस शशि भूषण सिंह	सदस्य
15.	सीएस शुजाथ बिन अली	सदस्य
प्रतिनिधि:		
16.	एनएसई के नामिती डॉ. हरीश आहूजा	सदस्य
17.	एफआईसीसीआई के नामिती सीएस प्रमोद कुमार राय	सदस्य
18.	सीआईआई के नामिती सुश्री स्वाति तिवारी	सदस्य
19.	सीएस प्रदीप रामकृष्णन	सदस्य
20.	सीएस वेंकट रमण आर.	विशेष आमंत्रित
21.	सीएस के. एस. रविचंद्रन	विशेष आमंत्रित
24. अकादमिक बोर्ड		
1.	सीएस रंजीत पांडे	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर बिंदू एस रोनाल्ड	सदस्य
3.	डॉ. असीम कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	डॉ. शीतल झुनझुनवाला	सदस्य
5.	सीएस प्रदीप रामकृष्णन	सदस्य
6.	सीएस मकरंद जोशी	सदस्य
7.	सीएस हरीश कुमार	सदस्य
8.	डॉ. जीतेन्द्र मोहन भारद्वाज	सदस्य
9.	श्री बीजू वक्की	सदस्य
10.	सीएस द्वारकानाथ सी	पदेन
11.	सीएस आशीष मोहन	पदेन
प्रतिनिधि:		
12.	एमसीए के नामिती श्री घनश्याम साहू	सदस्य
13.	सीआईआई के नामिती सीएस पंकज तिवारी	सदस्य
14.	यूजीसी के नामिती डॉ. मंथा श्रीनिवासु	सदस्य
15.	एआईसीटीई के नामिती प्रोफेसर अनिल कुमार	सदस्य
16.	प्रो. (डॉ.) एम. अफशर आलम	विशेष आमंत्रित:
17.	सीएस लक्ष्मणन आर	विशेष आमंत्रित:
18.	सीएस शीतल जयवंत	विशेष आमंत्रित:

परिशिष्ट -ख

1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान आयोजित बैठकों और उपस्थिति का विवरण

नोट - * 01.04.25 से 31.03.26 के दौरान सदस्य द्वारा भाग लेने के लिए पात्र बैठकों की संख्या

1. परिषद की बैठकें		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस धनंजय शुक्ला	12	12
सीएस पवन जी चांडक	12	12
सीएस बी नरसिम्हन	12	11
सीएस मनीष गुप्ता	12	12
श्री बालामुरुगन डी.	12	1
श्री इंदर दीप सिंह धारीवाल	12	2
श्री मनीष गोस्वामी	12	0
श्री संजय शौरी	12	2
डॉ. अशोक कुमार मिश्रा	12	9
सीएस मोहनकुमार ए.	12	5
सीएस आशीष करोड़िया	12	12
सीएस द्वारकानाथ सी.	12	12
सीएस मनोज कुमार पुरबे	12	12
सीएस एन पी एस चावला	12	2
सीएस प्रवीण सोनी	12	11
सीएस वेंकट रमण आर.	12	11
सीएस राजेश तारपारा	12	12
सीएस रूपांजना डे	12	10
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	12	9
सीएस सुरेश पांडे	12	10
बैठकों की तारीख: 14.04.25, 15.06.25, 01.07.25, 25-26.07.25, 25.08.25, 10.11.25, 20-21.11.25, 27.12.25, 11.01.26, 19.01.26, 17-18.03.26, 27.03.26		
2. कार्यकारी समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस बी नरसिम्हन	7	6
सीएस धनंजय शुक्ला	7	7
श्री इंदर दीप सिंह धारीवाल	7	1
सीएस मनीष गुप्ता	5	5
सीएस द्वारकानाथ सी.	7	7
सीएस पवन जी चांडक	7	7
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	5	2
सीएस मनोज कुमार पुरबे	2	1
सीएस वेंकट रमण आर.	2	2
बैठकों की तारीख: 02.06.25, 16.07.25, 10.11.25, 19.11.25, 09.01.26, 06-07.03.26, 11.03.26		
3. वित्त समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस धनंजय शुक्ला	3	3
सीएस मोहनकुमार ए.	4	0
सीएस मनोज कुमार पुरबे	3	3
सीएस वेंकट रमण आर.	3	3

सीएस राजेश तारपारा	3	2
सीएस पवन जी चांडक	4	4
सीएस प्रवीण सोनी	4	2
सीएस द्वारकानाथ सी.	1	1
सीएस आशीष करोड़िया	1	1
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	1	0
सीएस सुरेश पांडे	1	1
बैठकों की तारीख: 16.07.25, 18.08.25, 13.01.26, 05.03.26		
4. परीक्षा समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस धनंजय शुक्ला	7	5
सीएस पवन जी चांडक	8	6
सीएस बी नरसिम्हन	8	5
सीएस आशीष करोड़िया	7	5
सीएस एन पी एस चावला	8	0
सीएस रूपांजना डे	8	5
सीएस सुरेश पांडे	8	4
सीएस द्वारकानाथ सी.	1	1
सीएस राजेश तारपारा	1	1
बैठकों की तारीख: 05.04.25, 13.05.25, 14.07.25, 14.08.25, 05.10.25, 18.11.25, 16.01.26, 18.02.26		
5. वित्तीय सेवा समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस बी नरसिम्हन	5	5
सीएस द्वारकानाथ सी.	3	3
सीएस आशीष करोड़िया	5	2
सीएस मनोज कुमार पुरबे	5	5
सीएस राजेश तारपारा	5	4
सीएस रूपांजना डे	3	2
सीएस सुरेश पांडे	3	2
सीएस मोहनकुमार ए.	2	0
सीएस एन पी एस चावला	2	0
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	2	1
बैठकों की तारीख: 03.06.25, 04.11.25, 15.01.26, 12.02.26, 13.03.26		
6. कॉर्पोरेट कानून और अभिशासन समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस मनीष गुप्ता	4	4
डॉ. अशोक कुमार मिश्रा	4	3
सीएस आशीष करोड़िया	4	3
सीएस द्वारकानाथ सी.	3	3
सीएस वेंकट रमण आर.	4	4
सीएस राजेश तारपारा	4	4
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	3	3

सीएस मोहनकुमार ए.	3	0
सीएस धनंजय शुक्ला	1	1
सीएस मनोज कुमार पुरबे	1	1
बैठकों की तारीख: 13.06.25, 26.08.25, 20.11.25, 17.03.26		
7. व्यावसायिक विकास समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस धनंजय शुक्ला	3	3
श्री संजय शौरी	5	0
सीएस बी नरसिम्हन	3	3
सीएस मनोज कुमार पुरबे	3	2
सीएस प्रवीण सोनी	5	5
सीएस वेंकट रमण आर.	5	5
सीएस राजेश तारपारा	5	5
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	3	1
सीएस मनीष गुप्ता	2	1
सीएस एन पी एस चावला	2	0
सीएस रूपांजना डे	2	2
सीएस सुरेश पांडे	2	1
बैठकों की तारीखें: 02.06.25, 30.07.25, 18.11.25, 18.02.26, 25.02.26		
8. प्रशिक्षण एवं शैक्षिक सुविधा समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस पवन जी चांडक	7	7
सीएस मनीष गुप्ता	7	6
सीएस मोहनकुमार ए.	10	2
सीएस आशीष करोड़िया	10	7
सीएस द्वारकानाथ सी.	10	9
सीएस सुरेश पांडे	7	6
श्री बालामुरुगन डी.	10	0
सीएस एन पी एस चावला	7	0
सीएस धनंजय शुक्ला	3	3
सीएस बी नरसिम्हन	3	3
सीएस मनोज कुमार पुरबे	3	2
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	3	0
बैठकों की तारीख: 30.04.25, 03.06.25, 17.07.25, 24.09.25, 03.10.25, 29.10.25, 17.11.25, 12.02.26, 05.03.26, 25.03.26		
9. पेशेवर कंपनी सचिव समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस प्रवीण सोनी	6	6
सीएस मनीष गुप्ता	6	4
सीएस द्वारकानाथ सी.	6	4
सीएस सुरेश पांडे	6	5
सीएस रूपांजना डे	7	5
सीएस मोहनकुमार ए.	7	0

सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	6	4
सीएस राजेश तारपारा	1	1
सीएस बी नरसिम्हन	1	1
सीएस वेंकट रमण आर.	1	1
सीएस धनंजय शुक्ला	1	1
सीएस आशीष करोड़िया	1	0
बैठकों की तारीख: 02.06.25, 16.07.25, 19.08.25, 22.09.25, 19.11.25, 26.12.25, 13.02.26		
10. सूचना प्रौद्योगिकी समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस मनोज कुमार पुरबे	5	5
सीएस मनीष गुप्ता	4	1
सीएस प्रवीण सोनी	5	5
सीएस वेंकट रमण आर.	5	4
सीएस राजेश तारपारा	5	5
सीएस रूपांजना डे	5	3
सीएस सुरेश पांडे	4	2
सीएस धनंजय शुक्ला	1	0
सीएस मोहनकुमार ए.	1	0
सीएस एन पी एस चावला	1	0
बैठकों की तारीख: 29.04.25, 08.08.25, 07.11.25, 24.12.25, 11.02.26		
11. चैप्टर विकास एवं समन्वय समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	4	4
सीएस मोहनकुमार ए.	4	0
सीएस आशीष करोड़िया	4	4
सीएस द्वारकानाथ सी.	4	4
सीएस एन पी एस चावला	4	0
सीएस वेंकट रमण आर.	4	4
सीएस सुरेश पांडे	4	2
बैठकों की तारीख: 31.07.25, 05.08.25, 09.10.25, 10.01.26		
12. पीएमक्यू पाठ्यक्रम समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस राजेश तारपारा	3	3
सीएस मोहनकुमार ए.	3	0
सीएस आशीष करोड़िया	3	3
सीएस एन पी एस चावला	3	1
सीएस वेंकट रमण आर.	3	3
सीएस प्रवीण सोनी	3	3
सीएस द्वारकानाथ सी.	3	2
बैठकों की तारीख: 01.07.25, 03.10.25, 19.12.25		
13. प्लेसमेंट समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति

सीएस सुरेश पांडे	2	2
सीएस मोहनकुमार ए.	2	1
सीएस मनोज कुमार पुरबे	2	0
सीएस एन पी एस चावला	2	0
सीएस प्रवीण सोनी	2	1
सीएस रूपांजना डे	2	1
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	2	2
बैठकों की तारीख: 08.05.25, 10.03.26		
14. आईसीएसआई—सीसीजीआरटी प्रबंधन समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस धनंजय शुक्ला	4	4
सीएस आशीष करोड़िया	4	4
सीएस मनीष गुप्ता	4	3
सीएस वेंकट रमण आर.	4	4
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	4	3
सीएस द्वारकानाथ सी.	3	3
बैठकों की तारीख: 04.06.25, 15.07.25, 24.12.25, 05.02.26		
15. विनियमन और चुनाव सुधार समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस द्वारकानाथ सी.	3	3
सीएस मनीष गुप्ता	3	2
सीएस आशीष करोड़िया	3	2
सीएस वेंकट रमण आर.	3	3
सीएस रूपांजना डे	3	1
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	3	1
सीएस सुरेश पांडे	3	2
बैठकों की तारीख: 09.06.25, 05.08.25, 15.10.25		
16. अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस रूपांजना डे	3	3
सीएस बी नरसिम्हन	3	3
सीएस मोहनकुमार ए.	3	0
सीएस आशीष करोड़िया	3	2
सीएस मनोज कुमार पुरबे	3	1
सीएस एन पी एस चावला	3	0
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	3	0
बैठकों की तारीख: 13.05.25, 23.07.25, 19.11.25		
17. केंद्रीकृत अवसंरचना समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस धनंजय शुक्ला	1	1
सीएस मनीष गुप्ता	1	1
सीएस आशीष करोड़िया	1	1
सीएस राजेश तारपारा	1	1
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	1	1
सीएस वेंकट रमण आर.	1	1

बैठक की तारीख: 05.02.26		
18. प्रकाशन समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस प्रवीण सोनी	1	1
डॉ. अशोक कुमार मिश्रा	1	1
सीएस मनोज कुमार पुरबे	1	0
सीएस मोहनकुमार ए.	1	0
सीएस एन पी एस चावला	1	0
सीएस रूपांजना डे	1	1
सीएस सुरेश पांडे	1	1
बैठक की तारीख: 12.02.26		
19. व्यावसायिक अनुसंधान समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस रूपांजना डे	1	1
सीएस आशीष करोड़िया	1	1
सीएस राजेश तारपारा	1	1
सीएस एन पी एस चावला	1	0
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	1	1
बैठक की तारीख: 16.03.26		
20. अनुशासन बोर्ड		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस बी नरसिम्हन	5	5
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	5	5
सीएस आशीष मोहन	5	5
बैठकों की तारीख: 22–23.04.25, 08–09.07.25, 19.08.25, 04.11.25, 29.01.26		
21. अनुशासन समिति		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस धनंजय शुक्ला	8	8
श्री सुशील कुमार	10	7
श्री सुनील दाधे	10	10
सीएस मनीष गुप्ता	10	10
सीएस द्वारकानाथ सी.	10	7
सीएस पवन जी चांडक	2	2
बैठकों की तारीख: 09.06.25, 10.06.25, 22.07.25, 25.09.25, 14.10.25, 16.12.25, 17.12.25, 13.01.26, 10.03.26, 11.03.26		
22. अकादमिक बोर्ड		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस रंजीत पांडे	3	3
डॉ. अलका मित्तल	2	1
डॉ. अनिल कुमार	2	2
डॉ. जीतेन्द्र मोहन भारद्वाज	3	3
सीएस मकरंद जोशी	3	3
डॉ. आर. वेंकट राव	2	1
डॉ. सलीना कुञ्जुप्पिल बशीर	2	2

सीएस संजीव ग्रोवर	2	1
सीएस पंकज तिवारी	2	1
प्रोफेसर बिंदू एस रोनाल्ड	1	1
डॉ. असीम कुमार मिश्रा	1	1
डॉ. शीतल झुनझुनवाला	1	1
सीएस प्रदीप रामकृष्णन	1	1
सीएस हरीश कुमार	1	1
श्री. बीजू वक्की	1	1
बैठकों की तारीख: 11.04.25, 05.07.25, 20.03.26		
23. लेखा परीक्षा मानक बोर्ड		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस विनीत के चौधरी	3	3
सीएस द्वारकानाथ सी.	3	1
सीएस मनोज कुमार पुरबे	3	2
सीएस प्रवीण सोनी	3	1
सीएस अमित कौशल	3	3
सीएस जी. वी. श्रीनिवास मूर्ति	3	3
सीएस जगदीश पात्रा	3	2
सीएस वेंकटरमण के.	3	3
सीएस कुलदीप दयाल दास रुचंदानी	3	2
सीएस कुमुदिनी दिनेश भालेराव	3	1
सीएस मनोज राजाराम हुरकट	3	3
सीएस पंकज विरमानी	3	2
सीएस रवि शर्मा	3	3
सीएस सचिन अग्रवाल	3	3
सीएस आलोक नारायण पांडे	3	2
श्री विशाल झावेरी	3	0
बैठकों की तारीख: 24.05.25, 04.07.25, 22–23.11.25		
24. संपादकीय सलाहकार बोर्ड		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस एन पी एस चावला	1	0
डॉ. अशोक कुमार मिश्रा	1	1
सीएस प्रवीण सोनी	1	1
सीएस राजेश तारपारा	1	0
सीएस रूपांजना डे	1	1
सीएस (प्रो.) अंजलि गुप्ता	1	1
सीएस अपूर्व कुमार	1	1
सीएस बिमल जैन	1	0
सीएस (डॉ.) डी.के. जैन	1	1
सीएस नितिन सोमानी	1	0
सीएस प्रणव कुमार	1	1
सीएस (प्रो.) रबी नारायण कर	1	1
सीएस शेख लतीफ	1	1

सीएस (डॉ.) सुधींद्र पुट्टी	1	1
सीएस सुशील कुमार कंडोई	1	1
बैठक की तारीख: 17.07.26		
25. ईएसजी और संधारणीयता बोर्ड		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस रंजीत पांडे	4	4
सीएस आशीष गर्ग	4	4
सीएस वेंकट रमण आर.	4	4
सीएस राजेश तारपारा	4	3
सीएस अभिनव अग्रवाल	4	3
सुश्री अरुणा सी. न्यूटन	3	2
सीएस भास्कर जोशी	4	2
सीएस जे सुंदरेसन	4	4
सीएस मंगल कुलकर्णी	4	4
सीएस पंकज चौरसिया	4	4
सीएस एस सुधाकर	4	3
सीएस सचिन मिश्रा	4	4
सीएस शशि भूषण सिंह	4	4
सीएस शुजाथ बिन अली	4	4
सीएस प्रदीप रामकृष्णन	4	2
श्री. राजेश कुमार डांगेटी	3	0
डॉ. हरीश आहूजा	4	0
सीएस प्रमोद कुमार राय	4	4
सुश्री स्वाति तिवारी	4	1
सीएस सचिन जैन	3	2
बैठकों की तारीख: 01.05.25, 19.07.25, 20–21.09.25, 16.01.26		
26. एमएसएमई और स्टार्टअप बोर्ड		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस राजीव बजाज	4	4
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	4	0
सीएस वेंकट रमण आर.	4	3
सीएस (डॉ.) अजय गर्ग	4	4
सीएस (डॉ.) अजय जयसवाल	4	4
सीएस अजय संचेती	4	4
सीएस अनिल रुस्तगी	4	3
विंग. कमांडर. एंथोनी अनीश (सेवानिवृत्त)	4	2
सीएस बाला नादर	4	3
सीएस देवेन्द्र सुहाग	4	1
सीएस गौरव अरोड़ा	4	3
श्री गौरव महानी	4	3
सीएस एल.एन. जोशी	4	3
सीएस एन बालासुब्रमण्यम	4	3
सीएस राजेश कुमार लूंबा	4	1

श्री. राजीव चावला	4	1
सीएस सचिन खुराना	4	2
सीएस योगेश खाकरे	4	2
बैठकों की तारीख: 23.04.25, 02.07.25, 01.10.25, 14.01.26		
27. सहकर्मी समीक्षा बोर्ड		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस मोहनकुमार ए.	3	3
सीएस आशीष करोड़िया	3	2
सीएस मनोज कुमार पुरबे	3	2
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	3	2
सीएस निसार अहमद	3	1
सीएस राम सहाय	3	3
सीएस वी. श्रीधरन	3	3
बैठकों की तारीख: 23.04.25, 28.07.25, 17.11.25		
28. पेशेवर कौशल संवर्धन बोर्ड		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस देवेन्द्र वी देशपांडे	3	3
सीएस एन पी एस चावला	3	0
सीएस संदीप कुमार केजरीवाल	3	0
सीएस सुरेश पांडे	3	1
सीएस बी. रेंगनाथन	3	2
सीएस जूड डिसूजा	3	2
सीएस महेश अनंत आठवले	3	3
सीएस पी. शिवकुमार	3	3
सीएस राघवेंद्र जोशी	3	3
सीएस रजत जैन	3	2
डॉ. सुनील केसवानी	3	3
सीएस उन्नति कनानी	3	2
सीएस विकास अग्रवाल	3	1
सीएस योगेश कुमार	3	2
बैठकों की तारीख: 01.05.25, 02.06.25, 04.09.25		
29 गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड		

नाम	आयोजित*	उपस्थिति
श्री राकेश मोहन	1	1
श्री ज्योति प्रकाश गदिया	1	1
सुश्री दीपना गोकुलराम	1	1
सीएस पवन जी चांडक	1	1
श्री प्रमोद कुमार राय	1	1
बैठक की तारीख: 12.11.25		
30. सचिवीय मानक बोर्ड		
नाम	आयोजित*	उपस्थिति
सीएस नागेंद्र डी. राव	2	2
सीएस मोहनकुमार ए.	2	0
सीएस प्रवीण सोनी	2	1
सीएस अजय जयसवाल	2	0
सीएस अवनीश द्विवेदी	2	1
सीएस बी. शनमुगसुंदरम	2	2
सीएस कालिदास रामास्वामी	2	1
सीएस मकरंद जोशी	2	2
सीएस पंकज टंडन	2	1
सीएस प्रजोत तुंगारे	2	2
सीएस रजनी कांत	2	1
सीएस रुद्र पांडे	2	1
सीएस संजीव ग्रोवर	2	1
सीएस सवित्री पारेख	2	2
सीएस सुधाकर सारस्वतुला	2	2
सीएमए अविजीत गोस्वामी	2	0
सीएस बाबू अब्राहम कल्लिवयालिल	2	0
श्री प्रदीप रामकृष्णन	2	2
सीएस मणिकंठा एजीएस	1	1
श्री विशाल भट्ट	1	1
बैठकों की तारीख: 03.05.25, 30—31.08.25		

परिशिष्ट -ग

परीक्षा केंद्रों की क्षेत्र-वार सूची (शहर) - सीएस परीक्षाएं

पूर्व		उत्तर			दक्षिण		पश्चिम				
1	आसनसोल	1	आगरा	43	लुधियाना	1	बेल्लारी	1	अहमदाबाद जोन-I	43	पुणे जोन-III
2	भागलपुर	2	अजमेर	44	मथुरा	2	बेलगावी	2	अहमदाबाद जोन-II	44	पुणे जोन-IV
3	भुवनेश्वर I	3	अलीगढ	45	मेरठ	3	बेंगलुरु जोन-I	3	अहमदाबाद जोन-III	45	रायपुर
4	भुवनेश्वर II	4	अलवर	46	मोदीनगर	4	बेंगलुरु जोन-II	4	अहमदाबाद जोन-IV	46	राजकोट
5	बोकारो	5	अम्बाला	47	मुरादाबाद	5	बेंगलुरु जोन-III	5	अहमदनगर	47	रतलाम
6	धनबाद	6	अमृतसर	48	मुजफ्फरनगर	6	बेंगलुरु जोन-IV	6	अकोला	48	सागर
7	गया	7	बरेली	49	नोएडा	7	चेन्नई जोन I	7	अमरावती	49	सतारा
8	गुवाहाटी	8	ब्यावर	50	पाली	8	चेन्नई जोन II	8	भायंदर	50	सोलापुर
9	हुगली	9	भीलवाड़ा	51	पानीपत	9	चेन्नई जोन III	9	भिलाई	51	सूरत
10	हावड़ा	10	भिवानी	52	पटियाला	10	चेन्नई जोन IV	10	भोपाल	52	ठाणे जोन-I
11	इंफाल	11	बीकानेर	53	प्रयागराज	11	चेन्नई जोन V	11	बिलासपुर	53	ठाणे जोन-II
12	जमशेदपुर	12	चंडीगढ़	54	रेवाड़ी	12	चेन्नई जोन VI	12	चंद्रपुर	54	ठाणे जोन-III
13	कोलकाता जोन I	13	चित्तौड़गढ़	55	रोहतक	13	चेन्नई जोन VII	13	छत्रपति संभाजीनगर	55	उज्जैन
14	कोलकाता जोन II	14	देहरादून	56	शिमला	14	कोयंबतूर	14	देवास	56	वडोदरा
15	कोलकाता जोन III	15	दिल्ली जोन I	57	सीकर	15	एर्नाकुलम	15	गांधीधाम	57	वापी
16	कोलकाता जोन IV	16	दिल्ली जोन II	58	सोनीपत	16	इरोड	16	गांधीनगर		
17	मुजफ्फरपुर	17	दिल्ली जोन III	59	श्रीनगर	17	गुंटूर-अमरावती	17	ग्वालियर		
18	पटना	18	दिल्ली जोन IV	60	उदयपुर	18	हुबली, धारवाड़	18	इंदौर		
19	रांची	19	दिल्ली जोन V	61	वाराणसी	19	हैदराबाद जोन I	19	जबलपुर		
20	राउरकेला	20	दिल्ली जोन VI	62	यमुनानगर	20	हैदराबाद जोन II	20	जलगांव		
21	संबलपुर	21	दिल्ली जोन VII			21	हैदराबाद जोन III	21	जामनगर		
22	सिलीगुड़ी	22	दिल्ली जोन VIII			22	कन्नूर	22	कटनी		
		23	फरीदाबाद			23	कोल्लम	23	कोल्हापुर		
		24	गाजियाबाद			24	कोट्टायम	24	लातूर		
		25	गोरखपुर			25	कोझिकोड	25	मिराज-सांगली		
		26	ग्रेटर नोएडा			26	मदुरै	26	मुंबई जोन-I		
		27	गुरुग्राम			27	मंगलुरु	27	मुंबई जोन-II		
		28	हल्द्वानी			28	मैसूर	28	मुंबई जोन-III		
		29	हिसार			29	नेल्लोर	29	मुंबई जोन-IV		
		30	जयपुर जोन I			30	पलक्कड़	30	मुंबई जोन-V		
		31	जयपुर जोन II			31	पुदुचेरी	31	मुंबई जोन-VI		
		32	जयपुर जोन III			32	सलेम	32	मुंबई जोन-VII		
		33	जयपुर जोन IV			33	शिमोगा	33	मुंबई जोन-VIII		
		34	जालंधर			34	सिरसी	34	नागपुर		
		35	जम्मू			35	तिरुवनंतपुरम	35	नांदेड़		
		36	झांसी			36	त्रिशूर	36	नासिक		
		37	झुंझुनूं			37	तिरुचिरापल्ली	37	नवी मुंबई जोन-I		
		38	जोधपुर			38	तिरुनेलवेली	38	नवी मुंबई जोन-II		
		39	कानपुर			39	तिरुपूर	39	पणजी		
		40	करनाल			40	उडुपी	40	पिंपरी-चिंचवाड़ा		
		41	कोटा			41	विजयवाड़ा	41	पुणे जोन-I		
		42	लखनऊ			42	विशाखापत्तनम	42	पुणे जोन-II		
विदेशी केंद्र: दुबई											

विदेशी केंद्र: दुबई

01 अप्रैल, 2026 से 31 अगस्त, 2026 तक संस्थान की प्रमुख गतिविधियाँ

01 अप्रैल 2026 से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान परिषद द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ की गईं और विषयों पर निर्णय लिए गए:

1. नए मान्यताएं:

- (क) आईएफएससीए: आईएफएससीए (सूचीबद्धता) विनियम, 2024 के अंतर्गत वरीयता निर्गम और क्यूआईपी के लिए पीसीएस को मान्यता।
- (ख) चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स (सीआईएमए) के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए सीएस पेशवरों को मान्यता।
- (ग) आईएजीईएस द्वारा निर्धारित स्वर्ण मानकों के अनुपालन के लिए प्रमाणन का कार्य पीसीएस द्वारा किया जाना।

2. परिषद की बैठकों में लिए गए प्रमुख निर्णय:

- (क) आईसीएसआई के क्षेत्रीय/शाखा (चैप्टर) कार्यालयों के नाम संबंधित क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा में तथा आईसीएसआई के अंग्रेजी नाम से पहले हिंदी नाम को आईसीएसआई के लोगो-शीर्षक के डिजाइन में शामिल करना।
- (ख) त्रिशूर शाखा (चैप्टर) और पुणे शाखा (चैप्टर) के लिए संपत्ति का अधिग्रहण तथा नासिक शाखा (चैप्टर) के लिए भूमि का अधिग्रहण।
- (ग) आगामी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं/कार्यों से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए जमा कार्य के आधार पर सरकारी एजेंसियों का सूचीबद्धकरण।
- (घ) आईसीएसआई सामाजिक प्रभाव आकलन मानक (आईसीएसआई एसआईएस) को सेबी को आगे प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया गया।
- (ङ) व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर) के माध्यम से छात्रों, सदस्यों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए एकल साइन-ऑन वाली एक समान और एकीकृत डिजिटल व्यवस्था लागू करना।
- (च) आईसीएसआई निर्वाचन-2026 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोजित करना, जिसमें मतदान केंद्र आधारित मतदान (क्षेत्र में कहीं से भी मतदान) और दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान (डाक मतपत्र की व्यवस्था के स्थान पर) की व्यवस्था होगी।
- (छ) कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल गवर्नेंस पर कार्यबल तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम और साइबर कानूनों पर कार्यबल का गठन।
- (ज) सीएसबीएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता की सीमा ₹10,00,000 से बढ़ाकर ₹15,00,000 की गई (शुल्क की सीमा में भी वृद्धि की गई)।

3. आयोजित कार्यक्रम:

- (क) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य (अंशकालिक) प्रोफेसर (डॉ.) गौरव वल्लभ की गरिमामयी उपस्थिति में 27वां राष्ट्रीय पेशवर कंपनी सचिव सम्मेलन 13-14 जून, 2026 को पुणे में आयोजित किया गया।
- (ख) पीसीएस दिवस, जीएसटी दिवस जैसे दिवस सभी सीसीसीआईआरटी, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा (चैप्टर) कार्यालयों में पूरे भारत में मनाए गए।
- (ग) सभी चार क्षेत्रों के लिए प्रथम द्विवार्षिक दीक्षांत समारोह गुवाहाटी (ईआईआरओ), अमृतसर (एनआईआरओ), अहमदाबाद (डब्ल्यूआईआरओ) और तिरुवनंतपुरम (एसआईआरओ) में आयोजित किए गए।
- (घ) अहमदाबाद में आईसीएसआई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सम्मेलन आयोजित किया गया।
- (ङ) इंदौर में आईसीएसआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन आयोजित किया गया।
- (च) मास्टर नॉलेज सीरीज 6.0 की शुरुआत की गई।

4. सामाजिक पहल / सहयोगात्मक गतिविधियां:

- (क) लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए धन जुटाने संबंधी सम्मेलन गुवाहाटी, आईसीएसआई नोएडा और मानेसर में आयोजित किए गए (यह सेबी की पहल थी, जिसे बीएसई और एआईबीआई के सहयोग से आयोजित किया गया)
- (ख) एसएसई पर पंजीकरण और सूचीबद्धता के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों के लिए आईसीएसआई जागरूकता कार्यक्रम (नाबार्ड के सहयोग से) भुवनेश्वर और बेंगलुरु में आयोजित किए गए।
- (ग) सदस्यों के लिए सॉफ्टवेयर संबंधी लाभ, ज्ञानवर्धन और स्वास्थ्य संबंधी लाभ उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

5. जारी किए गए प्रमुख प्रकाशन:

- (क) संशोधित गाइडेंस नोट ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस
- (ख) कॉरपोरेट गवर्नेंस: फ्रॉम कंप्लायंस टू एक्सीलेंस (वर्जन 5.0)
- (ग) हैंडबुक ऑन बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सरस्टेनेबिलिटी (वर्जन 4.0)

- (घ) गाइडेंस नोट ऑन एससीआर फॉर इनविट्स
- (ङ) गाइडेंस नोट ऑन एससीआर फॉर रीट्स
- (च) गाइडेंस नोट ऑन सिक्वोरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्युलेशंस, 2015 (संशोधित संस्करण, 2026)
- (छ) आईसीएसआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स (सीएसएस-1 से सीएसएस-4), संशोधित संस्करण, 2026/2026

6. वैश्विक उपस्थिति में वृद्धि:

- (क) 26 मई 2026 से 02 जून 2026 तक जापान में 19वां आईपीएफडीपी
- (ख) 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (मॉरीशस) 03 से 05 अगस्त 2026
- (ग) ऑनलाइन फ्रेंच भाषा कोर्स
- (घ) आईसीएसआई भारत-ऑस्ट्रेलिया सुविधा केंद्र
- (ङ) आईसीएसआई की सहभागिता में:
 - i. आईसीजीएन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन, एम्स्टर्डम (25-26 जून 2026)
 - ii. XX एनिवर्सरी इंटरनेशनल फोरम ऑन कॉरपोरेट गवर्नंस (मॉस्को, रूस) (09-10 जुलाई, 2026)

7. अवसंरचना विस्तार:

- (क) गुरुग्राम शाखा के लिए शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया
- (ख) आईसीएसआई हैदराबाद शाखा (चैप्टर) के नए परिसर का उद्घाटन किया गया

8. छात्र-संबंधी गतिविधियां:

- (क) पुनर्गठित सीएसआईटी के लिए पहली परीक्षाएं आयोजित की गईं।
- (ख) सीएलडीपी के दायरे में ऐसे छात्रों को शामिल किया गया, जिन्होंने प्रोफेशनल प्रोग्राम पांच वर्ष पहले उत्तीर्ण किया है और दीर्घकालिक व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है या उससे छूट प्राप्त है, साथ ही ऐसे छात्र जो विदेशों में निवास कर रहे हैं।
- (ग) हितधारकों से परामर्श के लिए नई पाठ्यचर्या 2027 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रश्नपत्रों की योजना, परीक्षा की पद्धति और मूल्यांकन का प्रारूप शामिल है।
- (घ) कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सीएसआईटी) में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत कक्षा 10वीं/मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण छात्रों को अनंतिम पंजीकरण की अनुमति दी गई।
- (ङ) अप्रत्याशित आपात स्थितियों का सामना कर रहे पंजीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आईसीएसआई छात्र कल्याण कोष (एसबीएफ) के गठन को मंजूरी दी गई।

ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 221-223 दीन दयाल मार्ग,
 नई दिल्ली-110002
 दूरभाष सं.: 011-23236958/59/60
 ई-मेल: tvandeca@gmail.com

एस. के. मित्तल एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 मित्तल हाउस,
 ई-29, साउथ एक्सटेंशन पार्ट - II
 नई दिल्ली - 110049
 दूरभाष सं.: 26258517/41640694
 फ़ैक्स: 26255204

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("आईसीएसआई") की परिषद के सदस्यों के लिए

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

मत

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 तक तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय खाता, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और

अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (बाद में "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसमें संस्थान की क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित रिटर्न / वित्तीय विवरण भी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर और लेखों पर टिप्पणियों तथा हमारी रिपोर्ट के प्रमुख मामलों और अन्य मामलों वाले पैराग्राफ में वर्णित मामलों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 ("अधिनियम") के तहत अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं:

- i. तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च 2026 तक संस्थान के मामलों की स्थिति;
- ii. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान के अधिशेष के आय और व्यय लेखा के मामले में, और
- iii. नकदी प्रवाह के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

मत का आधार

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए और आम तौर पर भारत में स्वीकृत अंकक्षण मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के संलग्न वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र इकाई हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो संलग्न वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इनके अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे संलग्न वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामला

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

जैसा कि टिप्पणी 29(2)(ख)(17) में संदर्भित किया गया है, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 16(1) के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के संबंध में लेखांकन मानक-18 के तहत अपेक्षित जानकारी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है और इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी अधिसूचना जारी किए जाने तक इसका प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं आया है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन और अभिशासन हेतु जो प्रभारी हैं उनका दायित्व

संस्थान का प्रबंधन कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 ("अधिनियम") के अनुसार इन संलग्न वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, लागू लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संस्थान का वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, इस जिम्मेदारी में संस्थान की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उपयुक्त कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

प्रबंधन संस्थान की एक चालू संस्था के रूप में वित्तीय विवरण तैयार करने तथा जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो परिचालन को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चालू संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन की जिम्मेदारी संस्थान की चालू संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करना, जहां लागू हो, चालू संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करना और लेखांकन के लिए चालू संस्था के आधार का उपयोग करना है, जब तक कि प्रबंधन का संस्थान को परिसमापित करने या उसका परिचालन बंद करने का इरादा न हो, अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी संस्थान की परिषद जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, इन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना और उन्हें निष्पादित करना तथा ऐसी पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के आधार के लिए पर्याप्त हो। धोखाधड़ी के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चलने का जोखिम, त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रणों को दरकिनारा करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं, लेकिन संस्थान के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू संस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है अथवा नहीं जिससे संस्थान की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर पर्याप्त संदेह पैदा हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करने या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण संस्थान एक चालू संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरण सहित स्वचलित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्वचलित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

महत्वपूर्णता वित्तीय वक्तव्यों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान अभिज्ञात करते हैं, को भी प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संप्रेषित करते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी लोगों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और हम उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में उनसे संवाद करते हैं जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में भी संसूचित करते हैं।

अन्य मामले

हमने चार क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनमें 76 चैप्टर शामिल हैं, के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जो संस्थान के वित्तीय विवरणों में शामिल हैं और जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष में कुल ₹86,94,86,268/- की संपत्तियां, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कुल ₹28,55,87,714/- का राजस्व और 31 मार्च, 2026 को ₹5,05,17,689/- की नकदी और नकदी समतुल्य दर्शाए गए हैं, जैसा कि वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

इन क्षेत्रीय कार्यालयों और चैप्टरों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई हैं, और जहां तक इन कार्यालयों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं आया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

इसके अतिरिक्त, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ख. हमारी राय में, बहियों/रिकॉर्डों की जांच और अन्य कार्यालयों से प्राप्त उचित विवरणियों से जहां तक प्रतीत होता है, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित लेखा-बहियां रखी गई हैं;

ग. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, आय और व्यय खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

घ. वित्तीय विवरण आईसीएसआई की वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के वित्तीय प्रभाव का प्रकटीकरण करते हैं (नोट 29(2)(ख)1 का संदर्भ लें)।

ङ. संस्थान के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ था।

च. हमारी राय में, तुलन पत्र, आय और व्यय खाता और नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000038N

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 001135N

(एम. पी. ठाकुर)
भागीदार
सदस्यता संख्या 052473
यूडीआईएन: 26052473एवाईजेएचपीई3822

(एस. मूर्ति)
भागीदार
सदस्यता संख्या 072290
यूडीआईएन: 26072290ओजेडएलएसीएन2598

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.08.2026

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.08.2026

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

31 मार्च, 2026 का तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	नोट सं	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
I. स्रोत और देयताएं			
(1) संचय एवं अधिशेष			
(क) संचय और अधिशेष	1	9,74,32,40,720	8,99,55,99,968
(ख) आबंटित निधियां	2	1,09,10,81,817	1,25,34,40,530
उप-योग		10,83,43,22,537	10,24,90,40,498
(2) गैर-चालू देयताएं			
(क) दीर्घ कालिक ऋण		-	-

(ख) दीर्घ कालिक देयताएं		39,000	35,500
(ग) दीर्घ कालिक प्रावधान		-	-
उप-योग		39,000	35,500
(3) चालू देयताएं			
(क) अल्प कालिक ऋण		-	-
(ख) विविध लेनदार	3	7,94,42,138	6,77,25,670
(ग) अन्य चालू देयताएं	4	28,01,49,327	25,12,27,421
(घ) अल्प कालिक प्रावधान	5	12,13,20,074	11,01,58,646
उप-योग		48,09,11,539	42,91,11,737
योग		11,31,52,73,076	10,67,81,87,734
II. संपत्तियां			
(1) गैर-चालू संपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	6		
(i) मूर्त संपत्तियां		1,91,60,57,481	1,72,40,47,300
(ii) अमूर्त संपत्तियां		55,46,425	86,85,601
(iii) प्रगति के अधीन पूंजी कार्य	7	20,32,94,394	23,52,59,224
उप-योग		2,12,48,98,301	1,96,79,92,125
(ख) गैर-चालू निवेश	8	5,99,74,90,420	5,40,59,07,254
(ग) अन्य गैर-चालू संपत्तियां	9	86,41,191	2,69,81,014
(घ) दीर्घ कालीन ऋण एवं अग्रिम		11,44,270	12,36,766
उप-योग		8,13,21,74,181	7,40,21,17,158
(2) चालू संपत्तियां			
(क) चालू निवेश	10	2,01,42,82,249	2,07,70,80,507
(ख) मालसूची	11	73,45,352	73,48,040
(ग) विविध देनदार	12	1,65,09,436	5,07,33,145
(घ) नकदी और नकदी समतुल्य	13	26,65,15,971	22,68,69,527
(ङ) अन्य चालू संपत्तियां	14	87,84,45,887	91,40,39,358
उप-योग		3,18,30,98,895	3,27,60,70,577
योग		11,31,52,73,076	10,67,81,87,734
लेखांकन नीतियाँ और लेखाओं से संबंधित अन्य टिप्पणियाँ	29		

ऊपर उल्लिखित टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

श्री प्रकाश
निदेशक (वित्त)

सीएस आशीष मोहन
सचिव

सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर
उपाध्यक्ष

सीएस पवन जी चांडक
अध्यक्ष

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 000038 N

(एम. पी. ठाकुर)
भागीदार
(सदस्यता संख्या 052473)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2026

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 001135N

(एस. मूर्ति)
भागीदार
(सदस्यता संख्या 072290)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2026

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	नोट सं	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
आय			
गतिविधियों से आय	15	1,73,93,52,326	1,46,69,28,651
निवेश पर ब्याज	16	54,20,37,312	54,67,23,993
अन्य आय	17	6,00,20,492	4,60,92,908
अन्य सेवाएं-आय	18	9,87,69,548	10,19,13,713
कुल आय		2,44,01,79,678	2,16,16,59,265
व्यय			
कर्मचारी हितकारी व्यय	19	65,73,73,751	69,56,80,657
अध्ययन सामग्री और अन्य / मौखिक शिक्षा व्यय		11,48,13,395	13,88,78,799
प्रकाशन और ब्रांडिंग व्यय		1,08,19,810	82,51,945
परीक्षा खर्च	20	20,31,17,791	21,91,09,932
यात्रा और वाहन व्यय	21	2,27,33,152	2,32,17,498
कार्यक्रम / सेमिनार खर्च	22	33,28,94,048	23,79,20,442
कैरियर जागरूकता और प्रोत्साहन व्यय		2,15,03,184	1,99,62,843
चार्टर्ड सचिव जर्नल और बुलेटिन		2,58,56,510	2,82,30,989
अवमूल्यन और परिशोधन	6	9,80,03,909	9,06,79,050
कानूनी सेवाएं	23	57,93,617	81,80,294
पेशेवर सेवाएं	24	1,48,34,157	79,09,854
बिजली और पानी		2,42,66,473	2,61,14,404
संचार व्यय	25	95,05,180	79,03,513
अन्य व्यय	26	18,59,59,787	16,62,06,079
अन्य सेवाएं-व्यय	27	9,77,91,632	10,15,06,923
कुल व्यय		1,82,52,66,396	1,77,97,53,222
अपवदीय और असाधारण मदों से पूर्व अधिशेष		61,49,13,282	38,19,06,043
अधिशेष में जोड़ें / (घटाएँ):			
अपवदीय मदें	28	2,68,37,803	5,28,70,250
असाधारण मदों से पूर्व अधिशेष		64,17,51,085	43,47,76,293
अधिशेष में जोड़ें / (घटाएँ):			
असाधारण मदें		-	-
असाधारण मदों के बाद अधिशेष		64,17,51,085	43,47,76,293
निधियों/आरक्षित निधियों में अंशदान:			
- प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहन निधि		1,64,02,700	1,49,10,893
- निर्धारित निधि पर ब्याज		10,62,96,603	10,90,51,664
- सीएस बेनेवोलेंट फंड		12,96,831	8,19,987
- भवन और प्रौद्योगिकी विकास निधि		-	20,00,000
अंशदान		12,39,96,134	12,67,82,544
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित किया गया निवल अधिशेष		51,77,54,951	30,79,93,749
कुल		64,17,51,085	43,47,76,293

लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	29
--	----

ऊपर उल्लिखित टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

श्री प्रकाश निदेशक (वित्त) श्रीएस आशीष मोहन सचिव सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर उपाध्यक्ष सीएस पवन जी चांडक अध्यक्ष

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 000038 N

(एम. पी. ठाकुर)
भागीदार
(सदस्यता संख्या 052473)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2026

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 001135N

(एस. मूर्ति)
भागीदार
(सदस्यता संख्या 072290)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2026

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपये में)

	2025-26	2024-25
परिचालन गतिविधि से नकदी प्रवाह		
पूर्व अवधि, असाधारण और अपवादीय मदों के बाद, आय एवं व्यय लेखा के अनुसार निवल अधिशेष	64,17,51,085	43,47,76,294
समायोजन:		
जोड़ें : अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	9,80,03,909	9,06,79,050
जोड़ें : अवकाश नकदीकरण पर बीमांकिक हानि	-	1,89,10,134
जोड़ें : संपत्तियों/स्टॉक की बिक्री पर हानि	35,72,081	2,01,438
गैर-नकद खर्चों के समायोजन के बाद परिचालन से नकदी प्रवाह	74,33,27,075	54,45,66,916
घटाएं : निवेश से आय	54,20,37,312	54,67,23,993
आस्तियों के निपटान पर अधिशेष	31,373	3,67,12,341
पूर्व अवधियों में उपयोग की गई निधियों से आस्तियों की खरीद से संबंधित समायोजन	16,22,483	62,60,400
पेंशन निधि पर बीमांकिक लाभ	2,36,68,938	99,29,364
अवकाश नकदीकरण पर बीमांकिक लाभ	93,42,695	-
ट्रस्ट/फंड के लिए अंशदान	12,96,831	57,79,99,632
कार्यशील पूंजी और निधि परिवर्तन से पूर्व परिचालन अधिशेष	16,53,27,443	(5,58,79,169)
चालू आस्तियों और वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)		
वस्तु सूची में (वृद्धि)/(कमी)	2,688	(31,32,148)
अशोध्य ऋणों के बाद शुद्ध देनदारों में (वृद्धि)/(कमी)	3,42,23,709	(43,68,776)
अन्य चालू आस्तियों में (वृद्धि)/(कमी)	5,92,62,409	1,51,30,524
दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/(कमी)	92,496	(1,00,130)
अन्य गैर चालू आस्तियों में (वृद्धि)/(कमी)	1,83,39,823	3,50,89,305
विविध लेनदारों में वृद्धि/(कमी)	1,17,16,468	(4,31,00,838)
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	2,89,21,906	5,23,14,400
अल्पावधि प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	1,11,61,428	5,20,68,183

गैर- वर्तमान देयताओं में वृद्धि / (कमी)	3,500		(8,500)	
कॉरपोरेट गवर्नंस फंड के लिए पुरस्कार में प्राप्तियां (उपयोग) (निवल)	(1,28,15,433)		(77,55,349)	
प्राप्तियां (उपयोग) कर्मचारी प्रशिक्षण निधि	(6,46,020)		(3,50,920)	
अवकाश नकदीकरण निधि से प्राप्तियां (उपयोग) / (हस्तांतरण)	(3,14,31,937)		(2,37,38,144)	
प्राप्तियां (उपयोग) बंदोबस्ती प्रोत्साहन पुरस्कार निधि	(4,94,878)		(3,01,292)	
प्राप्तियां (उपयोग) व्यावसायिक विकास निधि	1,34,21,694		44,97,036	
प्राप्तियां (उपयोग) निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन निधि	(1,64,48,323)	11,53,09,531	(1,49,10,893)	6,13,32,458
परिचालन गतिविधि से सृजित निवल नकदी		28,06,36,973		54,53,289
निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह				
निवेश से आय	54,20,37,312		54,67,23,993	
निवेश / म्यूचुअल फंडों के मोचन की बिक्री आय (गैर-चालू)	56,66,73,524		36,74,17,727	
निवेश / म्यूचुअल फंडों के मोचन की बिक्री आय (चालू)	1,96,12,85,688		61,71,70,225	
निवेश / म्यूचुअल फंड इकाइयों का अधिग्रहण (गैर-चालू)	(1,84,47,56,691)		(1,17,69,80,551)	
निवेश / म्यूचुअल फंड इकाइयों का अधिग्रहण (चालू)	(1,21,19,87,430)		(15,05,47,294)	
अचल संपत्तियों की बिक्री	35,45,607		3,89,00,453	
बंदोबस्ती प्रोत्साहन पुरस्कार निधि हेतु अंशदान	2,00,000		4,00,000	
अवसंरचना निधि हेतु अंशदान	-		20,00,000	
डब्ल्यूआईपी सहित अचल संपत्तियों का अधिग्रहण	(25,21,75,107)		(11,04,90,829)	
निवेश गतिविधि में प्रयुक्त निवल नकदी		(23,51,77,097)		13,45,93,724
वित्तीय गतिविधि से सृजित नकदी				
सामान्य रिजर्व और कॉर्पस दान में वृद्धि	60,08,411		7,10,790	
लाइब्रेरी रिजर्व (निवल) में वृद्धि / (कमी)	81,640		62,912	
आय एवं व्यय खाते (निवल) से विनियोग को छोड़कर बिल्डिंग रिजर्व में वृद्धि / (कमी)	-		(23,02,203)	
संपत्तियों के लिए क्षेत्रीय परिषदों / शाखाओं को / से अंशदान में (वृद्धि) / कमी / उपयोग	(2,67,98,288)		(4,28,70,083)	
अन्य रिजर्व और फंड (नेट) में वृद्धि / (कमी)	(36,29,194)		(38,230)	
पूंजी आरक्षित निधि में वृद्धि / (कमी)	1,85,24,000		1,34,70,000	
वित्तीय गतिविधि से सृजित निवल नकदी		(58,13,431)		(3,09,66,814)
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निवल नकदी प्रवाह (क)		3,96,46,445		10,90,80,199
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य (ख)		22,68,69,527		11,77,89,329
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		26,65,15,971		22,68,69,527

टिप्पणी:				
1	उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण एस-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके प्राप्त किया गया है।			
2	संलग्न नोट 1 से 29 तक नगदी प्रवाह विवरण का एक अभिन्न अंग है।			
3	नकद और नकद समतुल्य में शामिल हैं:			
क.	नकद, चेक / ड्राफ्ट / पोस्टल ऑर्डर और डाक टिकट	4,90,223		6,32,481
ख.	अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि			
	- बचत बैंक खातों में (सावधि का जमा सहित)	26,60,25,748		22,62,37,046
		26,65,15,971		22,68,69,527

कृते एवं संस्थान की ओर से

श्री प्रकाश
निदेशक (वित्त)

सीएस आशीष मोहन
सचिव

सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर
उपाध्यक्ष

सीएस पवन जी चांडक
अध्यक्ष

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 000038 N

(एम. पी. ठाकुर)
भागीदार
(सदस्यता संख्या 052473)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2026

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 001135N

(एस. मूर्ति)
भागीदार
(सदस्यता संख्या 072290)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2026

आरक्षित निधि एवं अधिशेष

नोट-1

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2026 को		31 मार्च 2025 को	
(1) आरक्षित पूंजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		16,34,53,040		14,99,83,040
जोड़ें: सदस्यों से प्रवेश शुल्क				
— सहयोगी सदस्य	1,63,34,000		1,17,12,000	
— साथी सदस्य	21,90,000	1,85,24,000	17,58,000	1,34,70,000
उप-योग (1)		18,19,77,040		16,34,53,040
(2) सामान्य आरक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		8,69,39,48,137		8,30,42,74,904
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन		32,01,681		7,63,821
जोड़ें: कॉर्पस दान		-		58,450
घटाएं: अंतरित दान		25,000		-
जोड़ें: अवसंरचना निधि से अंतरण		22,73,07,033		8,09,68,693
जोड़ें/घटाएं : अन्य रिजर्व में समायोजित/अंतरित		49,94,312		4,18,351
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन/उपयोग		-21,87,582		-5,29,832
		8,92,72,38,581		8,38,59,54,387
आय एवं व्यय लेखा से अधिशेष (व्यय से अधिक आय)		51,77,54,951		30,79,93,749
उप-योग (2)		9,44,49,93,531		8,69,39,48,136
(3) सामान्य आरक्षित निधि के अलावा, यदि कोई हो				
कार्यालय नवीनीकरण निधि - पिछली तुलन-पत्र के अनुसार		1,05,502		1,05,502
स्थिर आस्ति आरक्षित निधि - पिछली तुलन-पत्र के अनुसार		73,220		73,220
पुरस्कार वितरण निधि - पिछली तुलन-पत्र के अनुसार		1,82,465		1,82,465
उप-योग (3)		3,61,187		3,61,187
(4) लाइब्रेरी रिजर्व				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		32,41,746		31,78,832
जोड़ें: दान		41,672		30,375
जोड़ें: ब्याज		39,968		32,538
घटाएं: उपयोगिता		74,217		-

उप-योग (4)		33,97,603		32,41,745
(5) भवन रिजर्व				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		12,45,27,399		12,50,38,501
जोड़ें: दान		-		8,63,322
घटाएं: समायोजन/उपयोगिता		24,999		-13,74,424
उप-योग (5)		12,45,52,398		12,45,27,399
(6) इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		3,28,33,593		3,28,33,593
उप-योग (6)		3,28,33,593		3,28,33,593
(7) अन्य रिजर्व लेखा				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		82,358		82,358
उप-योग (7)		82,358		82,358
(8) अन्य रिजर्व				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		91,80,558		92,18,788
जोड़ें: रिजर्व से/(में) अंतरण		9,21,795		-
जोड़ें: ब्याज		1,33,431		1,00,430
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन/उपयोग		-46,84,420		-1,38,660
उप-योग (8)		55,51,364		91,80,558
(9) भूमि/भवन/अन्य संपत्तियों में/से अंशदान				
प्रारंभिक शेष : अंशदान-देयताएं		9,41,52,498		1,08,42,035
जोड़ें: संपत्तियों के लिए आरसी/चैप्टर से अंशदान		3,30,02,216		-1,95,56,057
घटाएं: संपत्तियों के लिए आरसी/चैप्टर को योगदान		-17,76,63,068		-2,33,14,026
उप-योग (9)		-5,05,08,354		-3,20,28,048
कुल : (1 से 9)		9,74,32,40,720		8,99,55,99,968

निर्धारित निधि

नोट-2

(राशि रुपये में)

विवरण	कॉर्पोरेट गवर्नंस फंड में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार		कर्मचारी प्रशिक्षण निधि		अवकाश नकदीकरण निधि		पुरस्कार प्रदान करने के लिए बंदोबस्ती निधि	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	18,87,43,525	18,22,30,637	1,11,54,588	1,06,66,245	23,94,44,563	20,67,53,541	1,19,87,209	1,10,59,871
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंशदान	-	-	-	-	-	-	2,00,000	4,00,000
सामान्य रिजर्व से अंतरण	-	-	-	-	-	1,89,10,134	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ें: ब्याज आवंटन	1,45,86,865	1,42,68,237	8,66,526	8,39,263	4,21,57,529	3,75,19,032	8,08,710	7,64,293
उप योग	20,33,30,390	19,64,98,874	1,20,21,114	1,15,05,508	28,16,02,092	26,31,82,707	1,29,95,919	1,22,24,164
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	1,28,15,433	77,55,349	6,46,020	3,50,920	4,07,74,632	2,37,38,144	4,94,878	3,01,292
वर्ष के अंत में शेष राशि	19,05,14,957	18,87,43,525	1,13,75,094	1,11,54,588	24,08,27,460	23,94,44,563	1,25,01,041	1,19,22,872

विवरण	प्रदर्शन से संबंधित प्रोत्साहन निधि		इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (भूमि एवं भवन निधि, एसआईआरसी की प्रौद्योगिकी विकास निधि सहित)		व्यावसायिक विकास निधि		कुल राशि	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	51,06,385	47,28,134	72,80,04,066	75,15,59,289	6,90,64,531	6,45,67,496	1,25,35,04,867	1,23,15,65,213
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंशदान	1,64,02,700	1,49,10,893	-	-	1,34,21,694	44,97,035	3,00,24,394	1,98,07,928
सामान्य रिजर्व से अंतरण	-	-	-	20,00,000	-	-	-	2,09,10,134
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ें: ब्याज आवंटन	4,06,686	3,78,251	4,72,32,559	5,54,13,470	-	-	10,60,58,875	10,91,82,546
उप योग	2,19,15,771	2,00,17,278	77,52,36,625	80,89,72,759	8,24,86,225	6,90,64,531	1,38,95,88,136	1,38,14,65,821
घटाएं: उपयोग पर जीआर में अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	1,64,48,323	1,49,10,893	22,73,27,033	-	-	-	29,85,06,319	4,70,56,598
घटाएं: भूमि एवं भवन के अधिग्रहण पर	-	-	-	8,09,68,693	-	-	-	8,09,68,693
वर्ष के अंत में शेष राशि	54,67,448	51,06,385	54,79,09,592	72,80,04,066	8,24,86,225	6,90,64,531	1,09,10,81,817	1,25,34,40,530

विविध लेनदार

नोट-3
(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
आपूर्तियां (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशियों सहित – नोट संख्या 29-2 (ख)-7 देखें)	3,63,95,337	1,19,53,168
सेवाएं और अन्य (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशियों सहित – नोट संख्या 29-2 (ख)-7 देखें)	4,30,46,801	5,54,08,622
आरओ/सी के माध्यम से पूंजी भुगतान (कैपेक्स)	-	3,63,880
कुल:	7,94,42,138	6,77,25,670

अन्य चालू देयताएं

नोट-4
(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
अग्रिम में प्राप्त शुल्क		
- छात्र से संबंधित शुल्क (परीक्षा शुल्क)	13,51,43,822	12,02,85,266
- सदस्यता शुल्क और अन्य	1,54,62,708	1,29,62,431
ट्रस्ट/निधियों/अन्य को देय (नए श्रम कानूनों के अनुसार निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी संबंधी देयता सहित [टिप्पणी संख्या 29-2 (ख) (6) देखें])*	7,58,24,960	5,88,99,287
प्रतिभूति जमा	1,06,66,449	1,02,64,552
प्रतिधारण राशि	2,34,35,690	3,49,04,938
संपत्ति कर देय	26,76,708	16,21,000
आय कर देय	91,20,097	35,16,721
जीएसटी देय	10,76,655	55,99,384
धरोहर राशि प्रतिदेय	37,42,000	16,22,750
अन्य देय	30,00,238	15,51,092
कुल:	28,01,49,327	25,12,27,421

* नए श्रम कानूनों के अनुसार निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तपोषित ग्रेच्युटी की देयता के रूप में ₹35,13,644/- शामिल हैं [टिप्पणी संख्या 29-2 (ख) (6) देखें]।

लघु अवधि के प्रावधान

नोट-5
(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
व्यय के लिए प्रावधान	12,13,20,074	11,01,58,646
कुल:	12,13,20,074	11,01,58,646

सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

नोट-6
(राशि रुपये में)

मदें	सकल ब्लॉक				मूल्यहास / हानि				निवल ब्लॉक	
	1.4.2025 को लागत	परिवर्धन	समायोजन/स्थानांतरण/बिक्री	31.3.2026 तक कुल लागत	1.4.2025 को मूल्य	वर्ष के लिए	समायोजन/स्थानांतरण/बिक्री	31.3.2026 तक कुल मूल्य	31.3.2026 को	31.3.2025 को
(i) मूर्त संपत्ति										
भूमि										
फ्रीहोल्ड	25,08,15,158	7,97,13,206	-	33,05,28,364	-	-	-	-	33,05,28,364	25,08,15,158
पट्टे पर दिया	30,24,50,802	-	-	30,24,50,802	3,32,09,713	32,51,451	-	3,64,61,164	26,59,89,638	26,92,41,089
इमारत	1,47,14,38,972	15,47,78,619	14,90,000	1,62,47,27,591	44,99,04,229	5,35,82,005	-	50,34,86,234	1,12,12,41,357	1,02,15,34,743
फर्नीचर एवं फिक्सचर @ &	17,37,67,878	85,33,311	78,23,621	17,44,77,568	10,11,28,932	92,81,931	1,30,03,735	9,74,07,128	7,70,70,439	7,26,38,945
कंप्यूटर सहायक उपकरण	12,05,24,166	64,46,109	62,90,873	12,06,79,402	9,81,05,894	1,01,17,597	59,01,245	10,23,22,246	1,83,57,157	2,24,18,273
शीतलन उपकरण	9,26,05,071	1,20,54,181	26,73,641	10,19,85,611	5,07,02,530	67,84,256	20,11,028	5,54,75,758	4,65,09,853	4,19,02,541
विद्युत उपकरण	6,94,21,534	69,05,425	33,44,308	7,29,82,651	4,59,43,709	38,59,748	24,86,742	4,73,16,715	2,56,65,936	2,34,77,825
कार्यालय मशीनें और संचार उपकरण	6,14,55,264	1,44,67,639	1,11,86,357	6,47,36,546	4,48,62,570	42,32,981	95,75,230	3,95,20,321	2,52,16,225	1,65,92,694
अन्य उपकरण @	1,50,44,032	7,35,390	9,44,442	1,48,34,980	1,00,10,510	7,95,514	11,07,447	96,98,577	51,36,403	50,33,522
पुस्तकालय पुस्तकें	67,49,437	25,12,659	6,88,715	85,73,381	67,40,585	24,87,697	6,90,083	85,38,199	35,183	8,852
वाहन	17,46,662	-	2,938	17,43,724	13,63,003	76,732	2,938	14,36,797	3,06,927	3,83,659
चालू वर्ष कुल (i)	2,56,60,18,976	28,61,46,539	3,44,44,895	2,81,77,20,620	84,19,71,675	9,44,69,912	3,47,78,448	90,16,63,139	1,91,60,57,481	1,72,40,47,300
पिछला वर्ष कुल	2,44,71,83,758	14,09,37,705	2,21,02,038	2,56,60,19,425	77,27,81,838	8,88,41,387	1,96,51,102	84,19,72,123	1,72,40,47,302	1,67,44,01,930
(ii) अमूर्त संपत्ति										
सॉफ्टवेयर एवं एप्लिकेशन	4,76,64,663	4,73,398	-25,489	4,81,04,098	3,89,79,063	35,33,997	-44,613	4,25,57,673	55,46,425	86,85,601
चालू वर्ष कुल (ii)	4,76,64,663	4,73,398	-25,489	4,81,04,098	3,89,79,063	35,33,997	-44,613	4,25,57,673	55,46,425	86,85,601
पिछला वर्ष कुल	3,80,37,835	96,79,669	-25,167	4,76,64,663	3,71,77,620	18,37,662	36,219	3,89,79,063	86,85,600	8,60,215
चालू वर्ष कुल (i+ii)	2,61,36,83,639	28,66,19,937	3,44,19,406	2,86,58,24,718	88,09,50,738	9,80,03,909	3,47,33,835	94,42,20,812	1,92,16,03,906	1,73,27,32,901
पिछला वर्ष कुल (i+ii)	2,48,52,21,593	15,06,17,374	2,20,76,871	2,61,36,84,088	80,99,59,458	9,06,79,050	1,96,87,321	88,09,51,186	1,73,27,32,902	1,67,52,62,145

@ इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्यालय द्वारा सीसीजीआरटी, कोलकाता को खरीदी/भुगतान की गई आस्तियों के संबंध में 01-04-2024 को किए गए समायोजन के माध्यम से ₹79,15,873/- का फर्नीचर और फिक्सचर तथा ₹4,02,109/- के अन्य उपकरण शामिल हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष के लिए फर्नीचर और फिक्सचर तथा अन्य उपकरणों पर क्रमशः ₹7,91,587/- और ₹60,316/- का मूल्यहास शामिल है, जिसकी कुल राशि ₹8,51,903/- है।

& इसमें बेंगलुरु शाखा से संबंधित वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूंजीकृत फर्नीचर और फिक्सचर (लागत ₹24,80,000/- और संचित मूल्यहास ₹16,22,483/-) का प्रत्यावर्तन भी शामिल है, जिसके संबंध में आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में कानूनी मामला लंबित है।

पूँजीगत कार्य – प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

नोट-7
(राशि रुपये में)

मर्दे	सकल ब्लॉक			
	1.4.2025 को लागत	परिवर्धन / समायोजन	पूँजीकरण / समायोजन साल के दौरान	31.3.2026 तक कुल लागत
क. मूर्त संपत्ति				
अधिग्रहण के तहत भूमि	9,17,21,119	3,88,91,994	7,97,13,206	5,08,99,907
भवन अधिग्रहण के तहत पूँजी अग्रिम [नोट सं. 29-2 (बी)- (16) का संदर्भ लें]	83,23,000	-	20,000	83,03,000
पूँजी नवीनीकरण / सुधार	13,52,15,105	18,84,35,039	17,95,58,657	14,40,91,487
चालू वर्ष कुल (क)	23,52,59,224	22,73,27,033	25,92,91,863	20,32,94,394
पिछला वर्ष कुल	26,91,25,370	8,09,68,693	11,48,34,838	23,52,59,225
ख. अमूर्त संपत्ति				
विकासाधीन सॉफ्टवेयर	-	-	-	-
चालू वर्ष कुल (ख)	-	-	-	-
पिछला वर्ष कुल	-	64,09,756	64,09,756	-
कुल योग चालू वर्ष	23,52,59,224	22,73,27,033	25,92,91,863	20,32,94,394
कुल योग पिछला वर्ष	26,91,25,370	8,73,78,449	12,12,44,594	23,52,59,224

गैर-चालू निवेश

नोट-8
(राशि रुपये में)

विवरण	1.4.2025 को लागत	परिवर्धन	परिपक्वता / मोचन / परिशोधन	चालू में अंतरण	31.03.2026 को
I. सरकारी प्रतिभूति में निवेश					
(i) भारत सरकार बचत बॉन्ड	10,58,000	-	-	-	10,58,000
उप-योग (I)	10,58,000	-	-	-	10,58,000
II. डिबेंचर / बॉन्ड में निवेश					
(i) 8.70% एलआईसी एचएसजी 2029	9,47,71,319		11,98,436		9,35,72,883
(ii) 7.99% एलआईसी एचएसजी 2029	12,62,98,023		10,03,055		12,52,94,968
(iii) 7.03% एनएचआई 2040	39,60,74,578		3,23,831		39,57,50,747
(iv) 7.05% एनएचआई 2041	38,89,86,481		1,26,208	-	38,88,60,273
(v) 7.14% एनएचआई 2040	37,33,63,241		20,582		37,33,42,659
(vi) 7.26% एनएचआई 2038	8,78,96,527		1,41,905		8,77,54,622
(vii) 7.48% एनएचआई 2040	25,69,23,681		3,97,776		25,65,25,905
(viii) 7.90% एपी एसडीएल 2033	24,72,86,718	-	2,79,803		24,70,06,915
(ix) 7.85% बिहार एसजीएस 2032	29,09,39,605	-	1,24,666		29,08,14,939
(x) एनएचआई 7.98% बॉन्ड 23.12.2049	10,71,777		2,991		10,68,786
(xi) एचडीएफसी 6.88% बॉन्ड 24.09.2031	9,94,000	-			9,94,000
(xii) एलआईसीएचएफएल 7.13% बॉन्ड 24.11.2031	19,87,000				19,87,000
(xiii) एनएचआई 6.99% बॉन्ड 28.05.2035	19,38,900	-			19,38,900
(xiv) 10.04% आईआरएफसी बॉन्ड	10,95,500	-			10,95,500
(xv) 7.48% आईआरएफसी बॉन्ड	19,72,500	-			19,72,500
(xvi) 8.27% एनएचआई बॉन्ड	10,35,300	-			10,35,300
(xvii) 8.35% आईआरएफसी बॉन्ड	20,99,200	-			20,99,200

(xviii)	8.79% आईआरआरसी बॉन्ड	10,72,600	-			10,72,600
(xix)	7% पीएफसी बॉन्ड 22.01.2031 (अंकित मूल्य 1000/-)	19,51,600				19,51,600
(xx)	7.54% आईआरएफसी बॉन्ड	10,29,000				10,29,000
उप-योग (II)		2,27,87,87,550	-	36,19,253	-	2,27,51,68,297
III	म्यूचुअल फंड में निवेश					
(i)	एसबीआई एमएफ डायरेक्ट-ग्रोथ	8,99,98,750	29,50,00,000	-	-	38,49,98,750
(ii)	केनरा रोबेको एमएफ डायरेक्ट-ग्रोथ	5,74,98,750	18,65,00,000	-	-	24,39,98,750
(iii)	यूटीआई एमएफ डायरेक्ट-ग्रोथ	4,24,99,750	3,00,00,000	-	-	7,24,99,750
उप-योग (III)		18,99,97,251	51,15,00,000	-	-	70,14,97,251
IV	अन्य गैर-चालू निवेश					
(क)	बैंकों में सावधि जमा					
(i)	केनरा	2,06,00,23,376	19,88,43,849	46,39,72,496	40,15,00,000	1,39,33,94,729
(ii)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सीबी)	22,97,43,698	11,94,45,606	2,27,86,776	-	32,64,02,527
(iii)	बी.ओ.बी	1,86,14,563	78,88,311	49,57,605	-	2,15,45,269
(iv)	भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)	30,69,66,716	1,59,85,763	4,49,002	28,50,00,000	3,75,03,477
(v)	पंजाब नेशनल बैंक	33,87,159	19,30,299	1,74,367	-	51,43,091
(vi)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	46,36,507	52,34,22,114	-	-	52,80,58,621
(vii)	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	24,56,535	7,604	4,92,155	-	19,71,984
(viii)	कर्नाटक बैंक	5,13,961	57,891	-	-	5,71,852
(ix)	इंडियन ओवरसीज बैंक	3,43,81,977	4,14,15,637	2,72,29,561	-	4,85,68,053
(x)	यस बैंक	2,50,000	40,00,000	-	-	42,50,000
(xi)	यूको बैंक	2,20,000	-	2,20,000	-	-
(xii)	आईडीबीआई बैंक	44,84,500	45,70,000	42,10,000	-	48,44,500
(xiii)	कॉर्पोरेशन बैंक	25,95,241				25,95,241
(xiv)	बैंक ऑफ इंडिया	-	14,98,819	11,28,819		3,70,000
(xv)	आईसीआईसीआई बैंक	4,00,000	-			4,00,000
उप-योग (क)		2,66,86,74,234	91,90,65,893	52,56,20,781	68,65,00,000	2,37,56,19,345
(ख)	बैंकों के अलावा अन्य संस्थानों में सावधि जमा					
(i)	टीटीडीएफसी लिमिटेड	56,875	-	-	-	56,875
(ii)	अन्य	52,10,878	40,76,97,647	56,16,321	-	40,72,92,204
(iii)	एलआईसी अवकाश नकदीकरण के साथ जमा राशि	9,81,15,685	64,93,151	3,18,17,169	-	7,27,91,667
उप-योग (ख)		10,33,83,438	41,41,90,798	3,74,33,490	-	48,01,40,746
(ग)	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)					
(i)	बैकबे एक्स. प्रीमि. सोसायटी लिमिटेड	1,000				1,000
(ii)	बैकबे एक्स. प्रीमि. सोसायटी लिमिटेड	5,781				5,781
(iii)	शेयरों में निवेश (आईसीएसआई-आईआईपी)	14,00,00,000				14,00,00,000
(iv)	शेयरों में निवेश (आईसीएसआई-आरवीओ)	2,00,00,000				2,00,00,000
(v)	शेयरों में निवेश (आईसीएसआई-एडीआर)	15,00,000	-			15,00,000
(vi)	शेयरों में निवेश (आईसीएसआई-आईएसए)	15,00,000	-			15,00,000
(vii)	शेयरों में निवेश (आईसीएसआई-एनसीएलटी)	10,00,000	-			10,00,000
उप-योग (ग)		16,40,06,781	-	-	-	16,40,06,781
उप-योग(क+ख+ग)=IV		2,93,60,64,453	1,33,32,56,691	56,30,54,271	68,65,00,000	3,01,97,66,872
योग (I+II+III+IV)		5,40,59,07,254	1,84,47,56,691	56,66,73,524	68,65,00,000	5,99,74,90,420

31 मार्च, 2026 को म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में शुद्ध बाजार मूल्य ₹67,87,63,051/- (पिछले वर्ष ₹22,67,22,378/-) है, जबकि निवेश की कुल लागत ₹69,99,97,250/- (पिछले वर्ष ₹18,99,97,250/-) है।

अन्य गैर – चालू परिसंपत्ति

नोट-9
(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
(i) सुरक्षित, वसूली योग्य माना गया		
(क) भूमि/भवन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं को दिए गए ऋण [नोट संख्या 29-2 (ख) (11) देखें]	5,00,000	19,40,000
(ख) भूमि/भवन की खरीद के लिए अग्रिम (क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं की ओर से)	-	1,69,08,252
(ii) प्रतिभूति जमा	81,41,191	81,32,762
कुल:	86,41,191	2,69,81,014

चालू निवेश

नोट-10
(राशि रुपये में)

विवरण	1.4.2025 को	परिवर्धन	परिपक्वता/मोचन / परिशोधन	गैर चालू निवेश से अंतरण	31.03.2026 को
I बॉन्ड/प्रतिभूति में निवेश					
(i) 8.70% आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.	5,00,06,307	-	5,00,06,307	-	-
उप-योग (I)	5,00,06,307	-	5,00,06,307	-	-
II अन्य चालू निवेश					
(क) बैंकों में सावधि जमा					
(i) इंडियन बैंक	3,14,69,107	17,20,153	42,41,250	-	2,89,48,010
(ii) बैंक ऑफ बड़ौदा	50,49,53,715	5,84,68,596	48,52,30,687	-	7,81,91,624
(iii) बैंक ऑफ इंडिया	14,98,819	-	14,98,819	-	-
(iv) केनरा बैंक	4,79,28,606	1,64,22,121	3,70,50,724	40,15,00,000	42,88,00,003
(v) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	21,32,644	1,08,92,91,783	-	-	1,09,14,24,427
(vi) आईसीआईसीआई बैंक	46,81,524	47,21,491	18,59,054	-	75,43,961
(vii) आईडीबीआई बैंक	10,44,342	14,94,826	10,44,342	-	14,94,826
(viii) इंडियन ओवरसीज बैंक	2,16,13,051	9,31,710	71,87,081	-	1,53,57,680
(ix) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)	43,46,259	12,05,241	-	-	55,51,500
(x) भारतीय स्टेट बैंक	3,77,96,729	2,96,16,281	1,57,84,549	28,50,00,000	33,66,28,461
(xi) यूको बैंक	74,52,438	45,44,538	75,81,790	-	44,15,186
(xii) कॉर्पोरेशन बैंक	79,96,900	2,59,863	-	-	82,56,763
(xiii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,00,72,10,066	33,10,827	1,00,28,51,085	-	76,69,808
उप-योग (II-क)	1,68,01,24,200	1,21,19,87,430	1,56,43,29,381	68,65,00,000	2,01,42,82,249
(ख) बैंकों के अलावा अन्य संस्थानों में सावधि जमा					
(i) पीएनबी एचएफएल	33,99,50,000	-	33,99,50,000	-	-
(ii) एलआईसी एचएफएल	70,00,000	-	70,00,000	-	-
उप-योग (II-ख)	34,69,50,000	-	34,69,50,000	-	-
उप-योग (II)	2,02,70,74,200	1,21,19,87,430	1,91,12,79,381	68,65,00,000	2,01,42,82,249
कुल (I+II)	2,07,70,80,507	1,21,19,87,430	1,96,12,85,688	68,65,00,000	2,01,42,82,249

माल सूची

नोट-11
(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्रकाशन और अध्ययन सामग्री	58,02,358	60,59,445
उपभोज्य, स्टोर और अन्य	15,42,994	12,88,595
कुल	73,45,352	73,48,040

विविध देनदार

नोट-12
(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
क) विविध देनदार		
सुरक्षित, अच्छे माने जाने वाले	3,46,846	3,02,347
असुरक्षित, अच्छे माने जाने वाले	1,31,131	2,61,181
संदिग्ध	59,96,147	59,96,147
घटाएं: संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	64,74,124 59,96,147	65,59,675 59,96,147
उप-योग (क)	4,77,977	5,63,528
ख) अन्य विविध देनदार		
सुरक्षित, अच्छे माने जाने वाले	3,20,200	2,48,072
असुरक्षित, अच्छे माने जाने वाले	1,56,18,859	4,99,21,545
संदिग्ध	92,400	3,00,000
घटाएं: संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	1,60,31,459 -	5,04,69,617 3,00,000
उप-योग (ख)	1,60,31,459	5,01,69,617
कुल (क+ख)	1,65,09,436	5,07,33,145

नकद और नकद के समतुल्य

नोट-13
(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
बैंकों में शेष राशि (मुख्यालय से संबंधित चालू वर्ष के ₹9,43,95,003/- और पिछले वर्ष के ₹10,49,52,324/- के लिंकड सावधि जमा सहित)	26,60,25,748	22,62,37,046
चेक/ड्राफ्ट/आईपीओ/स्टाम्प	29,443	8,103
हाथ में नकदी	4,60,780	6,24,378
कुल	26,65,15,971	22,68,69,527

अन्य चालू परिसंपत्तियां

नोट-14
(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
निवेश पर अर्जित ब्याज	64,67,11,591	71,65,30,807
पूर्व देय व्यय	1,09,27,303	96,58,176
प्रतिभूति जमा	44,86,863	35,20,327
जीएसटी आईटीसी	1,07,64,424	1,21,11,824
पिछले वर्ष तक देय आयकर प्रतिदेय	8,09,45,084	6,87,32,072
स्रोत पर कर कटौती चालू वर्ष	2,26,14,558	3,61,69,152
आईसीएसआई ट्रस्ट/निधियां	8,64,66,093	5,45,26,930
कर्मचारियों को अग्रिम	9,35,622	2,69,614
वसूली योग्य अन्य	45,74,353	87,57,894
पार्टियों के लिए अग्रिम	1,00,19,996	37,62,562
कुल:	87,84,45,887	91,40,39,358

गतिविधियों से आय

नोट-15
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए			
	31 मार्च 2026		31 मार्च 2025	
सदस्यों से आय				
वार्षिक शुल्क	16,83,09,468		16,38,35,580	
अन्य शुल्क	6,54,500	16,89,63,968	5,65,500	16,44,01,080
छात्रों से आय				
पंजीकरण शुल्क	17,61,19,825		13,84,60,125	
छूट शुल्क	3,48,58,000		3,17,03,750	
ओडीओपी पंजीकरण शुल्क	6,89,99,425		1,53,89,125	
शिक्षा शुल्क	55,29,94,818		50,14,90,550	
परीक्षा शुल्क	31,63,63,855		30,52,07,750	
मौखिक शिक्षा शुल्क	1,86,79,117		2,63,52,534	
अन्य शुल्क	4,80,94,504	1,21,61,09,544	1,98,44,548	1,03,84,48,383
प्रकाशनों की बिक्री				
छात्र	1,61,85,580		1,35,16,880	
सदस्य	27,51,925	1,89,37,505	22,09,302	1,57,26,182
कार्यक्रम / सेमिनार				
छात्र	21,33,72,585		8,66,55,112	
सदस्य	8,70,08,721	30,03,81,306	13,06,35,524	21,72,90,636
पाठ्यक्रम: पीएमक्यू/सर्टिफिकेट/क्रेडिट				
छात्र	39,69,000		26,88,500	
सदस्य	2,57,29,503		2,31,59,600	
अन्य	52,61,500	3,49,60,003	52,14,271	3,10,62,371
कुल		1,73,93,52,326		1,46,69,28,651

निवेश पर ब्याज

नोट-16
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
बैंकों में निवेश और जमा पर ब्याज	54,20,37,312	54,67,23,993
कुल	54,20,37,312	54,67,23,993

अन्य आय

नोट-17
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
जर्नल / बुलेटिन / न्यूजलेटर की सदस्यता	71,56,921	66,11,951
पेंशन ट्रस्ट/अवकाश नकदीकरण से संबंधित बीमांकिक लाभ		
(i) पेंशन ट्रस्ट	2,36,68,938	99,29,364
(ii) अवकाश नकदीकरण	93,42,695	-

दान — सामान्य	-	35,200
सीसीजीआरटी में सुविधा शुल्क	11,99,966	2,96,500
आईसीएसआई—आईआईपी / आरवीओ / आईएसए / एडीआर / आईजीपीआई से प्राप्तियां	98,79,811	87,33,852
आयकर रिफंड पर ब्याज	15,57,075	68,11,066
बेकार कागज की बिक्री	4,50,843	4,88,012
संपत्ति की बिक्री से अधिषेक (बिक्री पर हुए नुकसान को घटाने के बाद)	11,157	1,29,952
वसूलियां— अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से लगाया गया अर्थदंड	3,50,000	18,10,000
अन्य विविध आय / प्राप्तियां	64,03,086	1,12,47,011
कुल	6,00,20,492	4,60,92,908

अन्य सेवाएं—आय

नोट—18
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
एमसीए—सीआरसी मानेसर से प्राप्तियां	4,60,07,671	5,23,29,214
एमसीए—सीएससी मानेसर से प्राप्तियां	49,50,435	26,42,123
एमसीए—आईईपीएफए से प्राप्तियां	3,12,39,080	3,63,36,785
एमसीए—सी—पेस मानेसर से प्राप्तियां	1,08,47,656	61,46,071
एमसीए—सीपीसी मानेसर से प्राप्तियां	57,24,706	44,59,520
कुल	9,87,69,548	10,19,13,713

कर्मचारी लाभ व्यय

नोट—19
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए			
	31 मार्च 2026		31 मार्च 2025	
वेतन और भत्ते		-		
मुख्यालय और सीसीजीआरटी	41,28,61,475		40,72,76,825	
क्षेत्र / चैप्टर	15,12,93,273	56,41,54,748	14,27,56,289	55,00,33,114
के लिए अंशदान:				
भविष्य निधि	-			
मुख्यालय और सीसीजीआरटी	78,80,392		45,95,612	
क्षेत्र / चैप्टर	17,14,012	95,94,404	13,80,067	59,75,679
नई पेंशन योजना (पीएफआरडीए)	-			
मुख्यालय और सीसीजीआरटी	3,22,44,191		3,02,22,751	
क्षेत्र / चैप्टर	1,28,43,250	4,50,87,441	1,27,12,957	4,29,35,708
ग्रेच्युटी				
मुख्यालय और सीसीजीआरटी	85,55,853		3,90,02,071	
क्षेत्र / चैप्टर	36,66,794		1,56,23,974	
गैर-वित्तपोषित – निश्चित अवधि के कर्मचारी (नए श्रम कानूनों के अनुसार निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की देनदारी [टिप्पणी संख्या 29-2 (ख) (6) देखें])	11,93,621	1,34,16,268	-	5,46,26,045
अवकाश नकदीकरण निधि	-			
मुख्यालय और सीसीजीआरटी	21,601		1,36,01,901	
क्षेत्र / चैप्टर	-	21,601	54,13,519	1,90,15,420
कर्मचारी कल्याण				
मुख्यालय और सीसीजीआरटी	1,91,94,544		1,68,70,847	

क्षेत्र/चैप्टर	59,04,745	2,50,99,289	62,23,844	2,30,94,691
कुल		65,73,73,751		69,56,80,657

परीक्षा खर्च

नोट-20
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
पेपर सेटर/परीक्षकों को मानदेय	8,12,28,975	8,25,12,204
सामान्य प्रेक्षक	86,44,413	1,01,53,751
परीक्षा केंद्र	4,95,24,676	5,51,80,934
दस्तावेजों का प्रेषण	2,58,60,064	2,79,67,552
उत्तर पुस्तिका	63,91,940	41,09,218
प्रश्न पत्र	84,20,000	1,23,25,000
कार्यालय में उपयोग होने वाले फॉर्म, लिफाफे, कैनवास बैग आदि	2,53,797	3,32,876
पास प्रमाणपत्र	1,81,781	7,73,975
यात्रा	5,84,345	9,51,584
परीक्षा अभिलेख/डेटा का डिजिटलीकरण	1,30,19,674	1,54,20,031
परीक्षा में ई-प्रवेश पत्र/ई-परिणाम का प्रकाशन – सीएस परीक्षा	6,13,600	7,08,000
परीक्षा सीएसईईटी	74,45,514	72,89,523
परीक्षा अन्य	9,49,012	13,85,284
कुल	20,31,17,791	21,91,09,932

यात्रा और वाहन व्यय

नोट-21
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
यात्रा खर्च	2,18,55,405	2,22,75,425
वाहन व्यय	8,77,747	9,42,073
कुल	2,27,33,152	2,32,17,498

कार्यक्रम / संगोष्ठी व्यय

नोट-22
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
सदस्यों के कार्यक्रम / सेमिनार	17,25,94,121	16,11,44,705
छात्रों के कार्यक्रम / सेमिनार	16,02,99,928	7,67,75,738
कुल	33,28,94,048	23,79,20,442

कानूनी सेवाएं

नोट-23
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए			
	31 मार्च 2026		31 मार्च 2025	
कानूनी सेवाओं के लिए शुल्क	57,93,617	57,93,617	81,80,294	81,80,294
कुल	57,93,617		81,80,294	

व्यावसायिक सेवाएं

नोट-24
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए			
	31 मार्च 2026		31 मार्च 2025	
व्यावसायिक सेवाएँ – सलाहकार	1,23,65,460		60,74,409	

व्यावसायिक सेवाएँ — सलाहकारों के अलावा	24,68,697	1,48,34,157	18,35,445	79,09,854
कुल		1,48,34,157		79,09,854

संचार व्यय

नोट-25
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए			
	31 मार्च 2026		31 मार्च 2025	
— टेलीफोन / फ़ैक्स / ई-मेल / एसएमएस	48,62,519		49,32,431	
— कूरियर / डाक	46,42,661	95,05,180	29,71,081	79,03,513
कुल		95,05,180		79,03,513

अन्य व्यय

नोट-26
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए			
	31 मार्च 2026		31 मार्च 2025	
किराया, दरें और कर		2,19,31,796		1,85,63,911
लेखन सामग्री		74,73,429		88,07,147
बीमा		18,78,010		16,48,724
मरम्मत और रखरखाव				
— भवन	57,30,794		72,21,795	
— कंप्यूटर	98,55,557		97,15,986	
— अन्य परिसंपत्तियां	1,29,22,726		1,16,97,899	
— वाहन	4,79,726	2,89,88,803	6,27,618	2,92,63,298
कार्यालय का खर्चा		1,73,82,785		1,66,16,484
सुरक्षा और हाउसकीपिंग व्यय (नए श्रम कानूनों के अनुसार निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी संबंधी देयता सहित) [नोट संख्या 29-2 (ख) (6) देखें] *		3,61,71,645		3,47,57,798
समाचार पत्र और पत्रिकाएं		1,43,353		1,62,279
आईटी संबंधी व्यय		4,18,18,228		3,36,76,986
बैठक का खर्च		39,02,850		35,31,307
पैकिंग और प्रेषण		27,405		48,069
निर्वाचन व्यय		47,412		-
आस्तियों की बिक्री पर हानि (अधिशेष को घटाने के बाद)/ स्टॉक को बट्टे खाते में डालना		15,82,239		2,31,782
बैंक प्रभार		43,92,969		41,39,476
छात्र छात्रवृत्ति और पुरस्कार		44,656		2,51,870
सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
— पारिश्रमिक (खर्चों की प्रतिपूर्ति सहित)	22,05,940		21,48,029	
— अन्य प्रमाणन सेवाएँ	68,850	22,74,790	1,11,010	22,59,039
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क		24,93,174		19,15,523
अपीलीय प्राधिकरण में अंशदान		30,00,000		27,50,000
जीएसटी इनपुट रिवर्सल		4,20,519		1,16,889
बट्टे खाते में डाला गया दावा न किया जा सकने वाला जीएसटी क्रेडिट		48,389	1,51,000	1,51,000
भवन के उद्घाटन/शिलान्यास पर व्यय		-	7,14,762	7,14,762
विविध खर्च		6,32,854		18,20,834
अशोध ऋण		4,41,550		1,32,070
सब्सक्रिप्शन और सदस्यता शुल्क		2,33,750		-

जीएसटी/टीडीएस पर विलंब शुल्क/ब्याज		17,890		14,844
बट्टे खाते में डाली गई टीडीएस/आयकर वसूली योग्य राशि		14,798		61,251
सीसीजीआरटी, मानेसर व्यय #		48,42,955		-
आईआईपी/आरवीओ/आईएसए/एडीआर/आईजीपीआई से संबंधित व्यय		57,53,538		45,70,736
कुल		18,59,59,787		16,62,06,079

* इसमें नए श्रम कानूनों के अनुसार निश्चित अवधि के कर्मचारियों (सुरक्षा और हाउसकीपिंग कर्मचारियों) के लिए गैर-वित्तपोषित ग्रच्युटी की देयता के रूप में ₹5,17,870/- शामिल हैं [नोट संख्या 29-2 (ख) (6) देखें]।

#इसमें सीसीजीआरटी-मानेसर के संचालन और रखरखाव के लिए परिचालन शुरू करने, सुरक्षा सेवाओं, हाउसकीपिंग, बिजली आदि से संबंधित व्यय शामिल हैं।

अन्य सेवाएं-व्यय

नोट-27
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
सीआरसी मानेसर व्यय	4,55,52,151	5,24,13,359
सीएससी मानेसर व्यय	49,01,420	26,15,964
एमसीए-आईआईपीएफ व्यय	3,09,29,783	3,59,77,017
सी-पेस मानेसर व्यय	1,07,40,253	60,85,217
सीपीसी मानेसर व्यय	56,68,025	44,15,366
कुल	9,77,91,632	10,15,06,923

अपवादीय मदें

नोट-28
(राशि रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
अपवादीय मदों में शामिल हैं:		
आय		
(i) पिछली अवधि की आय	1,23,741	83,03,216
(ii) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते में वापस लिया जाना	4,23,20,366	1,27,73,917
(iii) परिसंपत्ति (भवन) के निपटान पर अधिशेष	-	3,64,74,048
उप-योग (क)	4,24,44,107	5,75,51,181
व्यय		
(i) पिछली अवधि के व्यय	4,51,494	45,87,834
(ii) विक्रेताओं/पूर्व कर्मचारियों के साथ मुकदमेबाजी का निपटान	1,13,42,599	-
(iii) परिसंपत्तियों/स्टॉक के निपटान पर हानि	20,10,058	93,097
(iv) कर्मचारी लाभ व्यय (नए श्रम कानूनों के अनुसार निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रच्युटी संबंधी देयता सहित) [नोट संख्या 29-2 (ख) (6) देखें]	18,02,153	-
उप-योग (ख)	1,56,06,304	46,80,931
कुल (क) - (ख)	2,68,37,803	5,28,70,250

नोट-29

1. सामान्य सूचना

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("संस्थान अथवा आईसीएसआई") जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्राप्त गारंटी द्वारा कंपनी लिमिटेड के रूप में 4 अक्टूबर, 1968 को भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निगमित किया गया था, भारत में कंपनी सचिवों के पेशे को विकसित और विनियमित करने के लिए भारत में मान्यता प्राप्त पेशेवर निकाय है। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय पेशेवर निकाय है।

तत्पश्चात्, संस्थान को वैधानिक निकाय के रूप में परिवर्तित करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने संसद में एक विधेयक पेश किया और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 पारित किया गया, जिसके अनुसार भारत में कंपनी सचिवों के पेशे को विनियमित करने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1981 के प्रभाव से संस्थान को “भारतीय कंपनी सचिव संस्थान” के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उक्त अधिनियम के अनुसार, संस्थान के कार्यों के प्रबंधन का दायित्व संस्थान की परिषद को सौंपा गया है।

इस उद्देश्य के लिए, परिषद ने मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में एक-एक करके 4 क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और मानेसर में 4 कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र तथा पूरे भारत में 76 चौप्टर (7 उभरते हुए चौप्टर सहित) स्थापित किए हैं।

संस्थान कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। यह संस्थान कंपनी सचिव (सीएस) पाठ्यक्रम के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है और सीएस सदस्यों के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और लेखाओं पर टिप्पणियां

(क) लेखांकन नीति

1. वित्तीय विवरणों तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति और कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं तथा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (इंडियन जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा न कहा गया हो, सभी आय और व्यय की प्रोद्भन के आधार पर गणना की जाती है। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां संस्थान द्वारा लागू की गई नीतियों के अनुरूप हैं और पिछले वर्ष में उपयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं, जब तक अन्यथा न कहा गया हो।

2. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएं करनी पड़ती हैं, जो वित्तीय विवरण की तारीख पर रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं की राशियों, रिपोर्ट की गई आय और व्यय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम ज्ञात/वास्तविक होते हैं।

3. चालू और गैर-चालू के वर्गीकरण का आधार

तुलन पत्र में परिसंपत्ति और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब इसके सामान्य परिचालन चक्र में बिक्री के लिए प्राप्त होने की उम्मीद है, या बिक्री के लिए अभिप्रेत है; या यह मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है; या इसकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, या यह नकद या नकदी के समतुल्य है जब तक कि इसे विनिमय करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयता को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब इसके सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है; या यह मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है; या इसकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाने की उम्मीद है; या संस्थान के पास कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक परिचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद और नकदी के समतुल्य में उनकी प्राप्ति के बीच का

समय है।

4. राजस्व की मान्यता

क. प्रवेश शुल्क किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में प्रवेश दिए जाने के समय लिया जाता है और इसे सीधे "आरक्षित पूंजी निधि" में जमा किया जाता है।

ख. सदस्यों से प्राप्त शुल्क (वस्तु एवं सेवा कर को घटाने के बाद) का लेखा नकदी आधार पर किया जाता है; हालांकि, अग्रिम रूप से प्राप्त शुल्क को देयता के रूप में आगे ले जाया जाता है।

ग. छात्रों से प्राप्त शुल्क को नकदी आधार पर मान्यता दी जाती है।

घ. परीक्षा शुल्क को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है।

ङ. प्रकाशनों और अन्य संबंधित वस्तुओं की बिक्री से होने वाली आय को तब मान्यता दी जाती है, जब संपत्ति से जुड़े जोखिम और लाभ खरीदार को हस्तांतरित हो जाते हैं, जो सामान्यतः वस्तुओं की सुपुर्गर्गी के साथ होता है।

च. निवेश से आय

- i) निवेश पर लाभांश को प्राप्ति के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ii) ब्याज वाली प्रतिभूतियों और सावधि जमाओं पर आय को समयानुपातिक आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें बकाया राशि और बीमांकिक आधार पर लागू दरों को ध्यान में रखा जाता है।

छ. कार्यक्रमों/सेमिनारों से संबंधित आय/व्यय की प्राप्ति को आय एवं व्यय लेखा में उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

ज. दान —

- (i) दानदाताओं से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान/दान की उन राशियों को, जिनके लिए दानदाताओं ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि इन्हें मूलनिधि का हिस्सा बनाया जाए, कॉर्पस फंड में जमा किया जाता है।
- (ii) विशेष रूप से प्राप्त दान को संबंधित विशिष्ट निधि खाते में जमा किया जाता है।
- (iii) अन्य दानों को आय के रूप में माना जाता है।

5. निवेश—

क. निवेशों को शुरु में लागत पर दर्ज किया जाता है और लागत में ब्रोकरेज, शुल्क और ड्यूटी जैसे अधिग्रहण संबंधी व्यय शामिल होते हैं। खरीद के समय भुगतान किए गए उपार्जित ब्याज को प्राप्त ब्याज के विरुद्ध समंजन किया जाता है।

ख. म्यूचुअल फंड सहित दीर्घकालिक निवेशों को अधिग्रहण संबंधी खर्चों सहित लागत पर रखा जाता है और मूल्य में होने वाली ऐसी कमी, जो अस्थायी न हो, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है।

ग. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर रखा जाता है।

घ. प्रीमियम पर खरीदे गए निवेशों को अंकित मूल्य पर तुलन पत्र में डाला जाता है और प्रीमियम की राशि को निवेश की शेष अवधि में आनुपातिक रूप से परिशोधित किया जाता है।

6. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) / मूल्यह्रास और परिशोधन—

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तब मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि उस मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ संस्थान को प्राप्त होंगे और उस मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में किसी भी व्यापार छूट और रिबेट को घटाने के बाद का खरीद मूल्य तथा परिसंपत्ति को उसके निर्धारित उपयोग के लिए तैयार करने पर सीधे होने वाला व्यय शामिल होता है। पात्र संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित अन्य आकस्मिक व्यय, जो परिसंपत्ति को उसके निर्धारित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक किए गए हों, को भी पूंजीकृत किया जाता है।

ख. भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है।

- ग. अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि आस्ति से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे और आस्ति की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत में किसी भी व्यापार छूट और रिबेट को घटाने के बाद का खरीद मूल्य, आस्ति को उसके निर्धारित उपयोग के लिए तैयार करने पर सीधे होने वाला व्यय तथा पात्र आस्तियों के अधिग्रहण से संबंधित अन्य आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं, जो आस्ति को उसके निर्धारित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक किए गए हैं। अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्णता के बाद किए गए बाद के व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय से उस आस्ति से प्राप्त होने वाले भविष्य के लाभ उसके पहले से आकलित प्रदर्शन के स्तर से बढ़ जाते हों।
- घ. स्थायी पट्टे के साथ-साथ 99 से अधिक वर्षों के लिए पट्टे पर प्राप्त भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में माना जाता है। 99 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए पट्टे पर अधिग्रहित भूमि को लीजहोल्ड भूमि के रूप में माना जाता है।
- ङ. फ्रीहोल्ड भूमि लागत पर दर्शाई जाती है। पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क सहित भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि पर लीजहोल्ड भूमि का उल्लेख किया जाता है। लीजहोल्ड भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।
- च. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास संबंधित आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर परिषद द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर अवलिखित मूल्य पद्धति से प्रदान किया जाता है:

मद	%
भवन	5
फर्नीचर व फिक्सचर	10
लिफ्ट/एयर कंडीशनर/अन्य उपकरण	15
वाहन	20
कंप्यूटर और मोबाइल	40

- छ. अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि पर मूल्यह्रास मासिक आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है। बिक्री के वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं लिया जाता है।
- ज. 5,000 रु या उससे कम रुपये की लागत वाली अचल परिसंपत्तियों का खरीद वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।
- झ. पुस्तकालय की पुस्तकों का खरीद वर्ष में 100% की दर से मूल्यह्रास किया जाता है।
- ञ. अमूर्त परिसंपत्ति (सॉफ्टवेयर) को तीन साल की अवधि में समान रूप से सीधी रेखा विधि के अनुसार मूल्यह्रासित किया जाता है।
- ट. किसी परिसंपत्ति की बिक्री/निपटान/पहचान से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और संबंधित वर्ष के आय और व्यय खाते के विवरण में पहचाना जाता है।

7. माल सूची

कागजात, उपभोग्य सामग्रियों, प्रकाशनों, अध्ययन सामग्री आदि की सूची का मूल्यांकन लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत फीफो के आधार पर निर्धारित की जाती है। हालाँकि 1 वर्ष से अधिक पुराने माल का मूल्यांकन धीमी गति से चलने वाले/गैर-चालित/अप्रचलित पर विचार करते हुए केवल 1 रुपए पर किया जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं के स्टॉक को खरीद वर्ष में आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है और वर्ष के अंत में शून्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेनदेन

- क. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख के अनुसार प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि पर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर दर्ज किया जाता है।
- ख. सभी आय और व्यय का औसत दर पर रूपान्तरण किया जाता है। सभी मौद्रिक सम्पत्तियों/दायित्वों का रूपान्तरण वर्ष के अंत की दरों पर किया जाता है जबकि गैर-मौद्रिक सम्पत्तियों को लेन-देन की तिथि की दर पर लगाया जाता है।

ग. विनिमय दर अंतर के कारण सभी आय या व्ययों को, आय और व्यय लेखा खाते में पहचाना जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

क. संस्थान द्वारा बनाए गए भविष्य निधि ट्रस्ट में अंशदान/राष्ट्रीय पेंशन योजना (पीएफआरडीए) में अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

परिभाषित लाभ योजना

क. ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट में अंशदान एलआईसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और एएस-15 (संशोधित) के अनुसार व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख. पेंशन निधि ट्रस्ट में योगदान बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और एएस-15 (संशोधित) के अनुसार व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग. अवकाश नकदीकरण का प्रावधान एलआईसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और एएस-15 (संशोधित) के अनुसार व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

10. नकदी एवं नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जिसमें बैंक खाते से जुड़ी फ्लेक्सी जमा राशि शामिल है, जो मूल्य में परिवर्तन के एक अमहत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

11. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को लेखा मानकों-3 “नकदी प्रवाह विवरण” में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिससे गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों के लिए कर से पहले अधिशेष/(घाटा) को समायोजित किया जाता है और पिछले या भविष्य के नकदी के किसी भी आस्थगित या प्रोद्भवन रसीदें या भुगतान को संस्थान के संचालन, निवेश और वित्त गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर अलग किया जाता है।

12. चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम

चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिमों को तुलन पत्र में इस धारणा से दर्शाया गया है कि गतिविधि के सामान्य क्रम में वसूली पर, मूल्य दिखाए गए कुल राशि के बराबर होगा।

प्रबंधन की राय में तीन साल से अधिक समय से बकाया और वसूली के लिए संदिग्ध विविध देनदारों और अग्रिमों को बही खातों में शुद्ध प्रावधानों के लिए प्रदान किया गया है।

13. प्रावधान

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब किसी उद्यम पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। कर्मचारी कल्याण जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और पेंशन के अलावा प्रावधानों को इसके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और तुलन पत्र की तारीख पर दायित्वों को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

14. क्षेत्रीय कार्यालयों और चैप्टरों के प्रकाशनों की बिक्री पर व्यय और सब्सिडी की अनुदान / प्रतिपूर्ति

वार्षिक अनुदान, व्यय की प्रतिपूर्ति और क्षेत्रीय कार्यालयों और चैप्टरों के प्रकाशनों की बिक्री पर सब्सिडी का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।

15. स्वीकृत निधियों/संस्थाओं/संगठनों को अंशदान/अनुदान

आईसीएसआई स्टूडेंट्स एजुकेशन फंड ट्रस्ट, आईसीएसआई नेशनल अवार्ड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस, आईसीएसआई एम्प्लॉइज

मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन ट्रस्ट, कंपनी सेक्रेटरीज बनेवोलेंट फंड, आईसीएसआई एम्प्लॉइज बनेवोलेंट फंड, परफॉर्मेंस से संबंधित इंसेंटिव फंड, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के आधार पर परिषद द्वारा समय-समय पर स्वीकृत राशि का आवंटन/योगदान किया जाता है।

16. आबंटन/आरक्षित निधियों और अधिशेष तथा निर्धारित निधि में अंतरण

क. वर्ष के दौरान भवन एवं अन्य विशिष्ट निधि के लिए प्राप्त संग्रह दानधराशि को सीधे सामान्य आरक्षित/विशिष्ट निधि में रखा जाता है।

ख. निर्धारित प्रयोजन के लिए रखी गई निधियों के निवेश से होने वाली आय संबंधित निर्धारित निधियों में 8% वार्षिक की दर से प्रारंभिक और अंतिम शेष राशि के औसत पर आवंटित की जाती है तथा उसमें से उपयोग की गई राशि को ऐसी निधियों में डेबिट किया जाता है।

17. “बयाना राशि जमा, प्रतिधारण राशि, प्रतिभूति जमा और पुराने चेक” के शीर्ष के तहत पुरानी बकाया राशि

बयाना राशि जमा, प्रतिधारण राशि, प्रतिभूति जमा और वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया चेक के तहत तीन साल से अधिक के लिए बकाया निर्विवाद राशि को बड़े खाते में डाला जा रहा है और वर्ष के लिए आय के रूप में मान्यता दी गई है। बड़े खाते में डाली गई राशि में से किसी भी बाद के दावे का भुगतान दावे के वर्ष में किया जाएगा और तदनुसार वर्ष के लिए व्यय के रूप में दर्ज किया जाएगा।

(ख) लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

(क) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए संस्थान के खिलाफ दावा:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2024–25
1	निर्धारण वर्ष 2021–22 के लिए एसीआईटी द्वारा आयकर की मांग उठाई गई है, जिसके विरुद्ध सीआईटी (ए) के समक्ष अपील लंबित है। इसके संबंध में ₹72,55,653/- का टीडीएस रोककर रखा गया है।	90,90,74,526/-	शून्य
2	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के उप आयुक्त द्वारा 30 दिसंबर, 2025 के आदेश के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर की मांग उठाई गई है, जिसके विरुद्ध आयुक्त-अपील, (ए-II) के समक्ष अपील लंबित है। इस मामले में सुनवाई हो चुकी है और आदेश की प्रतीक्षा है।	52,70,040/-	शून्य
3	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के उप आयुक्त द्वारा 29 जून, 2025 के आदेश के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर की मांग उठाई गई है, जिसके विरुद्ध आयुक्त-अपील, (ए-II) के समक्ष अपील लंबित है। सुनवाई की प्रतीक्षा है।	5,66,58,342/-	शून्य
4	संपत्ति कर संबंधी मामला	35,531/-	35,531/-
5	टीजीआईआईसीएल से मांग	1,36,73,413/-	1,36,73,413/-
6	विवादित विक्रेता दावे	23,11,515/-	1,19,74,515/-
7	अन्य – पूर्ण एवं अंतिम निपटान के विरुद्ध दावे	89,729/-	89,729/-
	कुल	98,71,13,096/-	2,57,73,188/-

(ख) आयकर प्राधिकारियों के साथ समायोजन के लिए लंबित टीआरएसीईएस चूक की राशि ₹8,800/- है (पिछला वर्ष ₹74,590/-)।

2. संस्थान के छात्रों के लिए निर्मित, संचालन और स्थानांतरण (बीओटी) आधार पर ई-लर्निंग के लिए संस्थान और मैसर्स गुरुकुल ऑनलाइन लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (जीओएलएस) के बीच एक समझौता किया गया था। समझौता 13.09.2015 को समाप्त हो गया। जीओएलएस जुलाई, 2015 से संस्थान को लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहा और आईसीएसआई को पोर्टल स्थानांतरित करने में भी विफल रहा। दोनों पक्षों ने मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.03.2017 के द्वारा पक्षों को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

संस्थान ने 43,24,920/- रुपये अपने देय के लिए और 2,00,00,000/- रुपये के नुकसान के लिए अपने दावे का विवरण दाखिल किया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र ने माननीय न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता को दिल्ली मध्यस्थता परिषद का एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। जीओएलएस ने लगभग 32.00 करोड़ रुपये का अपना काउंटर दावा भी दायर किया है और संस्थान के दावे का जवाब दिया है।

न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता, एकमात्र मध्यस्थ ने दिनांक 23.01.2021 के रिवाइड के माध्यम से जीओएलएस के प्रति दावे को खारिज कर दिया और आईसीएसआई के पक्ष में और जीओएलएस के खिलाफ कुल रु 1,00,89,479/- 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ तथारिवाई राशि पर 22.05.2017 से 23.01.2021 तक, रिवाइड की तारीख से 30 दिनों के भीतर देय और उसके बाद 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ जीओएलएस के "आईसीएसआई ऑनलाइन" पोर्टल को पूरे डेटा बेस और सामग्री के साथ आईसीएसआई को 15 दिनों के भीतर स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है। हालांकि, जीओएलएस ने एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिए गए उक्त पंचाट का अनुपालन नहीं किया है।

मैसर्स गुरुकुल ऑनलाइन लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (जीओएलएस) ने वर्ष 2021 में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत 23.01.2021 के मध्यस्थता पंचाट के विरुद्ध याचिका दायर की थी। उक्त मध्यस्थता पंचाट के माध्यम से एकमात्र मध्यस्थ न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता ने (जीओएलएस) के प्रति-दावे को खारिज करते हुए आईसीएसआई के पक्ष में पंचाट दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30.09.2026 है।

इसके अलावा, इस बीच, संस्थान ने वर्ष 2021 में पुरस्कार धारक (आईसीएसआई) के पक्ष में दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, नई दिल्ली के एकमात्र मध्यस्थ न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम.एल. मेहता द्वारा 23.01.2021 को दिए गए मध्यस्थता पंचाट के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए निष्पादन याचिका दायर की थी। उक्त निष्पादन याचिका का निपटारा 12 मई, 2026 के आदेश द्वारा इस स्वतंत्रता के साथ किया गया कि संबंधित न्यायालय, अर्थात् उस उच्च न्यायालय के समक्ष उचित निष्पादन याचिका दायर की जा सकती है, जिसके पास उस स्थान पर अधिकारिता है जहां इसकी आस्तियां स्थित हैं।

तदनुसार, संस्थान द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष निष्पादन याचिका दायर की गई है और यह वर्तमान में बंबई उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में आपत्तियों के अधीन है। आपत्तियों को दूर किया जा रहा है और सितंबर, 2026 में सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।

3. पूंजी प्रतिबद्धताएं और अन्य प्रतिबद्धताएं

- पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अग्रिम राशियों को घटाने के बाद अनुमानित राशि 31.03.2026 को ₹32,08,97,773/- है (पिछला वर्ष ₹18,63,89,221/-)।
- संस्थान के सामान्य कामकाज में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित अन्य प्रतिबद्धताओं की अनुमानित राशि अत्यधिक विवरण देने से बचने के लिए प्रकट नहीं की गई है।

4. प्रबंधन का मत है कि वर्ष के दौरान सक्रिय उपयोग से हटाई गई/त्यागी गई और बड़े खाते में डाली गई परिसंपत्तियों को छोड़कर, वर्ष के अंत में अन्य किसी परिसंपत्ति के लिए लेखांकन मानक-28 में परिकल्पित अतिरिक्त हानि के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

5. कर्मचारी लाभ

लेखा मानक-15 में परिभाषित 'कर्मचारी लाभ' का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:-

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना जैसे भविष्य निधि/ राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) में नियोक्ता का अंशदान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रभारित किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि 'आईसीएसआई कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट' द्वारा प्रशासित है। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) का प्रबंधन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना**(i) ग्रेज्युटी**

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित नियोक्ता ग्रेज्युटी फंड योजना एक 'परिभाषित लाभ योजना' है। दायित्व का वर्तमान मूल्य एलआईसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। दायित्व का वर्तमान मूल्य एलआईसी द्वारा लेखा मानक-15 में परिभाषित प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्रेज्युटी प्लान का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

विवरण	25-26	24-25	23-24	22-23	21-22
(I) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:					
वर्ष की शुरुआत में वर्तमान मूल्य	2,679	2,173	2,050	1,549	-
ब्याज लागत	194	158	149	112	-
चालू सेवा लागत	123	99	96	95	-
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(42)	398	(20)	296	-
भुगतान किए गए लाभ	(220)	(148)	(101)	(2)	-
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	2,734	2,679	2,173	2,050	-
(II) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:					
वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,217	2,233	1,944	1,694	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित/वास्तविक प्रतिलाभ	160	136	142	125	-
अंशदान	3	-	256	251	-
भुगतान किए गए लाभ	(220)	(148)	(101)	(117)	-
निधि प्रबंधन शुल्क	-	(4)	(8)	(8)	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,159	2,217	2,233	1,944	-
(III) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त धनराशि:					
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,734	2,679	2,173	2,050	-
वर्ष के अंत में योजनागत सम्पत्तियों का उचित मूल्य	2,159	2,217	2,233	1,944	-
वित्त पोषित स्थिति	(575)	(463)	60	(106)	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति/(देयता)	(575)	(463)	60	(106)	-
(IV) आय और व्यय लेखा में मान्यता प्राप्त व्यय:					
वर्तमान सेवा लागत	123	99	96	95	-
ब्याज लागत	194	158	149	112	-
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	(160)	(136)	(142)	(125)	-
निधि प्रबंधन प्रभार	-	4	8	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	(42)	398	(20)	296	-
चिन्हित (लाभ)/हानि	115	522	90	378	-
जोड़ें:- वर्तमान दायित्व पर उपलब्ध प्रारंभिक अतिरिक्त/घाटे की राशि/योजना/निधिकृत परिसंपत्ति	-	(60)	(150)	(392)	-
निवल (लाभ)/हानि	115	463	(60)	(13)	-
(V) वित्त पोषित निवेश विवरण:					
निवेश ब्यौरा: भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 100% वित्त पोषित	2,159	2,217	2,233	1,944	-
(VI) बीमांकिक अनुमान:					
छूट की दर	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%	-
भविष्य वेतन वृद्धि	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	-
योजनागत संपत्तियों पर रिटर्न	7.63%	7.68%	6.78%	7.01%	-

(ii) पेंशन

‘पेंशन’ का प्रबंधन ‘आईसीएसआई कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट’ नामक एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और पेंशन लाभ योजना की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन लेखांकन मानक-15 के अनुसार पी.यू.सी. पद्धति का पालन करते हुए किया गया है। पेंशन निधि का विवरण निम्नानुसार है:-

	(रुपये लाख में)				
विवरण	25-26	24-25	23-24	22-23	21-22
(I) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:					
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	5,432	5,376	5,301	7,175	7,119
ब्याज लागत	380	387	399	517	463
चालू सेवा लागत	38	42	45	47	117
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(229)	(101)	(103)	(837)	(278)
भुगतान किए गए लाभ	(287)	(272)	(266)	(1,601)	(245)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	5,335	5,432	5,376	5,301	7,175
(II) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:					
वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,956	5,801	5,632	6,602	6,356
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित/वास्तविक प्रतिलाभ	459	472	395	462	477
भुगतान किए गए लाभ	(287)	(272)	(266)	(1,601)	(245)
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(33)	(44)	39	168	15
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,095	5,956	5,801	5,632	6,602
(III) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त धनराशि:					
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,335	5,432	5,376	5,301	7,175
वर्ष के अंत में योजनागत सम्पत्तियों का उचित मूल्य	6,095	5,956	5,801	5,632	6,602
वित्त पोषित स्थिति	761	524	425	331	(572)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति/(देयता)	761	524	425	Nil	(572)
(IV) आय और व्यय लेखा में मान्यता प्राप्त व्यय:					
वर्तमान सेवा लागत	38	42	45	47	117
ब्याज लागत	380	387	399	517	463
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	(459)	(472)	(395)	(462)	(477)
निधि प्रबंधन प्रभार	(196)	(56)	(142)	(1,005)	(293)
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(237)	(99)	(94)	(904)	(190)
जोड़ें:- वर्तमान दायित्व पर उपलब्ध प्रारंभिक अतिरिक्त/घाटे की राशि/योजना/निधिकृत परिसंपत्ति	-		(331)	331	-
निवल (लाभ)/हानि	(237)	(99)	(425)	(572)	(190)
(V) वित्त पोषित निवेश विवरण:					
निधि निवेश ब्योरा	केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बॉन्ड, अनुसूचित बैंकों में सावधि जमाएं और म्यूचुअल फंड।				
(VI) बीमांकिक अनुमान:					
छूट की दर	7.25%	7.00%	7.20%	7.50%	7.20%
भविष्य वेतन वृद्धि	10.00%	11.00%	11.00%	8.50%	8.50%
योजनागत संपत्तियों पर प्रतिलाभ	7.70%	7.70%	8.13%	7.00%	7.00%

(iii) अवकाश नकदीकरण

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित अवकाश नकदीकरण फंड योजना एक ‘परिभाषित लाभ योजना’ है। दायित्व का वर्तमान मूल्य एलआईसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। दायित्व का वर्तमान मूल्य एलआईसी द्वारा लेखा मानक-15 में परिभाषित प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अवकाश नकदीकरण का ब्योरा निम्नानुसार है:-

	(रुपये लाख में)				
विवरण	25-26	24-25	23-24	22-23	21-22
(I) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:					
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2,394	2,068	1,541	1,592	1,484

ब्याज लागत	174	150	169	115	104
पिछला सेवा लागत	-	-	796	-	-
चालू सेवा लागत	248	225	169	90	90
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(89)	190	(7)	(95)	168
भुगतान किए गए लाभ	(318)	(238)	(601)	(161)	(254)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	2,408	2,394	2,068	1,541	1,592
(II) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:					
वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	981	1,144	1,294	1,143	1,242
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित/वास्तविक प्रतिलाभ	61	77	74	83	80
अंशदान	4	-	381	325	75
भुगतान किए गए लाभ	(318)	(238)	(601)	(251)	(254)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-
निधि प्रबंधन शुल्क	-	(2)	(4)	(5)	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	728	981	1,144	1,294	1,143
(III) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त धनराशि:					
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,408	2,394	2,068	1,541	1,592
वर्ष के अंत में योजनागत सम्पत्तियों का उचित मूल्य	728	981	1,144	1,294	1,143
वित्त पोषित स्थिति	(1,680)	(1,413)	(924)	(247)	(449)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति/(देयता)	-	-	-	(247)	(449)
(IV) आय और व्यय लेखा में मान्यता प्राप्त व्यय:					
वर्तमान सेवा लागत	248	225	169	90	90
ब्याज लागत	174	150	169	115	104
योजनागत परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	(61)	(77)	(74)	(83)	(80)
पिछला सेवा लागत	-	-	796	-	-
निधि प्रबंधन प्रभार	-	2	4	-	168
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(89)	190	(7)	(95)	282
चिन्हित (लाभ)/हानि	271	490	1,058	27	-
घटाएं:- निर्धारित निधि पर आबंटित प्रतिलाभ	(422)	(375)	(338)	-	-
जोड़ें:- वर्तमान दायित्व पर उपलब्ध प्रारंभिक अतिरिक्त/घाटे की राशि/योजना/निधिकृत परिसंपत्ति	-	(0)	(796)	(27)	(52)
निवल (लाभ)/हानि	(150)	115	(76)	-	230
(V) वित्त पोषित निवेश विवरण:					
निवेश ब्यौरा: भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 100% वित्त पोषित	728	981	1,144	1,294	1,143
(VI) बीमांकिक अनुमान:					
छूट की दर	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%	7.00%
भविष्य वेतन वृद्धि	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	8.50%
योजनागत संपत्तियों पर प्रतिलाभ	7.63%	7.68%	6.78%	7.01%	7.00%

निश्चित अवधि के कर्मचारियों (एफटीई) के कर्मचारी लाभ व्यय (गैर-वित्तपोषित)–

6. 21 नवंबर, 2025 को भारत सरकार ने मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 ('श्रम संहिताएं') के प्रावधानों को अधिसूचित किया, जो मौजूदा उनतीस श्रम कानूनों को एक एकीकृत ढांचे में समाहित करती हैं और सेवाकाल तथा सेवोत्तर अवधि के दौरान कर्मचारियों के लाभों को नियंत्रित करती हैं। श्रम संहिताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, मजदूरी की एक समान परिभाषा और अवकाश से संबंधित लाभों में वृद्धि सहित कई बदलाव किए गए हैं।

संस्थान ने कर्मचारी लाभों के लिए मजदूरी की परिभाषा का पुनर्मूल्यांकन किया है। इन बदलावों के वित्तीय प्रभाव के कारण, लेखांकन मानक-15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक द्वारा निर्धारित ग्रेज्युटी देयता में कुल ₹35,13,644/- की वृद्धि हुई है [नोट-4 का संदर्भ लें]। इसमें श्रम संहिता लागू होने के कारण पिछले सेवा व्यय के रूप में ₹18,02,153/- [नोट-28 का संदर्भ लें] और चालू सेवा व्यय के रूप में ₹17,11,491/- की वृद्धि शामिल है [₹11,93,621/- के लिए नोट-19 और ₹5,17,870/- के लिए नोट-26 का संदर्भ लें]। संस्थान श्रम संहिताओं से संबंधित घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रहा है और निश्चित अवधि के कर्मचारियों (एफटीई) के कर्मचारी लाभ व्यय (गैर-वित्तपोषित) से संबंधित देयता के मापन पर पड़ने

वाले किसी भी प्रभाव का आकलन करेगा। संस्थान पर लागू नियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा।

बीमांकिक की रिपोर्ट के अनुसार उपदान देयता (गैर-वित्तपोषित) का विवरण निम्नानुसार है:—

(रुपये लाख में)

विवरण	25-26	24-25
(I) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:		
वर्ष की शुरुआत में वर्तमान मूल्य	-	-
पिछला सेवा लागत	18.02	-
चालू सेवा लागत	17.11	-
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-	-
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	35.14	-
(II) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित/वास्तविक प्रतिलाभ	-	-
अंशदान	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
(III) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त धनराशि:		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	35.14	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति/(देयता)	(35.14)	-
(IV) आय और व्यय लेखा में मान्यता प्राप्त व्यय:		
पिछला सेवा लागत	18.02	-
वर्तमान सेवा लागत	17.11	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
चिन्हित (लाभ)/हानि	-	-
निवल (लाभ)/हानि	35.14	-
(V) बीमांकिक अनुमान:		
छूट की दर	7.25%	-

7. लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय राशियों से संबंधित प्रकटीकरण, संस्थान के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
(क) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष राशि:		
मूलधन	132.01	81.42
ब्याज	-	-
कुल	132.01	81.42
(ख) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ-साथ लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।	-	-
(ग) भुगतान करने में हुई देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि, जिसका भुगतान वर्ष के दौरान किया गया है, लेकिन निर्धारित दिन के बाद किया गया है, इसमें लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल नहीं किया गया है।	-	-
(घ) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित और भुगतान न की गई ब्याज की राशि।	-	-

(ड) आगामी वर्षों में भी देय और भुगतान योग्य शेष अतिरिक्त ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक ऊपर उल्लिखित ब्याज की देय राशियों का वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता, ताकि लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय को अस्वीकार किया जा सके।	-	-
---	---	---

8. संस्थान ने वर्ष के अंत में विभिन्न पक्षों/विक्रेताओं को उनकी शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र भेजे हैं। कुछ पक्षों से पुष्टि प्राप्त होना अभी बाकी है।
9. संस्थान मुख्य रूप से भारत में और एक ही भौगोलिक खंड में कार्य करता है, क्योंकि पूरे भारत की आर्थिक परिस्थितियां समान हैं। इसके अलावा, संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी सचिव के पेशे का विकास करना है। अतः खंड रिपोर्टिंग से संबंधित लेखांकन मानक-17 के अर्थ के अनुसार, इसके सभी परिचालन केवल एक ही खंड के अंतर्गत आते हैं।
10. प्रकाशनों और अन्य मदों के अंतिम भंडार के मूल्यांकन का लेखा संस्थान द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाता है। यह मूल्यांकन मुख्यालय/कॉरपोरेट गवर्नंस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों/क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं में वर्ष के अंत में किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर किया जाता है और आवश्यक समायोजन लेखा बहियों में किया जाता है।
11. 31 मार्च, 2026 को क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं को दिए गए भवन ऋण की बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है [नोट 9(i) (क) का संदर्भ लें]:

(राशि रुपए में)			
क्र.सं.	स्थान	31.3.2026 को	31.3.2025 को
1	फरीदाबाद चैप्टर	5,00,000	5,00,000
2	कोल्हापुर चैप्टर	--	14,40,000
	कुल	5,00,000	19,40,000

12. आय कर —

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत किया गया है और आयकर अधिनियम की धारा 11/12 के तहत आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है।

(ii) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए 14 दिसंबर, 2022 की धारा 143(1) के अंतर्गत जारी सूचना के माध्यम से सीपीसी ने ₹81,99,10,138/- (ब्याज सहित) की मांग उठाई, क्योंकि अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत ₹1,20,00,31,900/- की छूट का लाभ स्वीकार नहीं किया गया था। हालांकि, सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर करने के बाद, धारा 11(2) के अंतर्गत ₹1,10,94,73,718/- की राशि स्वीकार की गई और इस प्रकार ₹9,05,58,182/- की वृद्धि तक सीमित कर दिया गया। सीआईटी (ए) के आदेश से असंतुष्ट होकर, संस्थान ने माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली के समक्ष अपील दायर की।

माननीय आईटीएटी, दिल्ली ने 27 मार्च, 2024 के आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को दावे का आवश्यक सत्यापन करने और निर्धारण आदेश में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया। तदनुसार, सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल छूट 2(1), दिल्ली ने 21 जुलाई, 2025 को धारा 254 सहपठित धारा 143(1) के अंतर्गत आदेश द्वारा माननीय आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते हुए ₹9,05,58,182/- की राहत प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध निर्धारणीय आय शून्य हो गई। हालांकि, ₹72,55,653/- की देय स्रोत पर कर कटौती की वापसी का कोई प्रभाव नहीं दिया गया।

इसके अलावा, सीआईटी ने दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के दौरान निवेश संबंधी विवरण सहित अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज मांगे, जिसके लिए संस्थान द्वारा विभिन्न उत्तर प्रस्तुत किए गए। इसके बाद, सीआईटी द्वारा 31 मार्च, 2026 को धारा 254 सहपठित धारा 143(1) के अंतर्गत ई-हस्ताक्षरित आदेश पारित किया गया और अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत ₹1,20,00,31,900/- की छूट का लाभ स्वीकार न किए जाने के कारण मांग उठाई गई तथा पूरी छूट राशि को आय मानते हुए ब्याज सहित ₹90,90,74,526/- की मांग की गई।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर, संस्थान ने मांग को समाप्त करने के लिए 28 अप्रैल, 2026 को सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। उक्त अपील पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।

(iii) निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, सीपीसी ने 7 मार्च, 2023 को धारा 143(1) के अंतर्गत जारी सूचना के माध्यम से विवरणी में दर्शाई गई आय के आधार पर निर्धारण पूरा किया और ब्याज सहित ₹6,37,96,900/- की रिफंड प्रदान

की/प्राप्त हुई।

तत्पश्चात्, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148क(1) के अंतर्गत एसीआईटी, सर्कल छूट 2(1), दिल्ली द्वारा 27 मार्च, 2026 को जारी सूचना के माध्यम से अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण की कार्यवाही शुरू की गई। उक्त 27 मार्च, 2026 की धारा 147 के अंतर्गत जारी सूचना के संबंध में संस्थान ने 20 जून, 2026 को ई-कार्यवाही के माध्यम से उत्तर दाखिल किया है।

(iv) निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, सीपीसी ने 13 नवंबर, 2024 को धारा 143(1) के अंतर्गत जारी सूचना के माध्यम से विवरणी में दर्शाई गई आय के आधार पर निर्धारण पूरा किया और ब्याज सहित ₹6,68,09,430/- की रिफंड प्रदान की/प्राप्त हुई।

तत्पश्चात्, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148क(1) के अंतर्गत एसीआईटी, सर्कल छूट 2(1), दिल्ली द्वारा 27 मार्च, 2026 को जारी सूचना के माध्यम से अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण की कार्यवाही शुरू की गई। उक्त 27 मार्च, 2026 की धारा 147 के अंतर्गत जारी सूचना के संबंध में संस्थान ने 24 जून, 2026 को ई-कार्यवाही के माध्यम से उत्तर दाखिल किया है।

(v) निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए, सीपीसी ने 17 अप्रैल, 2025 को धारा 143(1) के अंतर्गत जारी सूचना के माध्यम से विवरणी में दर्शाई गई आय के आधार पर निर्धारण पूरा किया। आयकर विवरणी के अनुसार ₹6,15,23,106/- की वापसी देय थी, जिसके विरुद्ध ₹2,55,12,170/- की स्रोत पर कर कटौती की वापसी प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप जमा राशि में अंतर के कारण ₹3,75,68,016/- की वापसी कम प्राप्त हुई।

जमा राशि में अंतर के संबंध में संस्थान ने 16 जनवरी, 2026 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दाखिल किया था। इसके बाद, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148क(1) के अंतर्गत एसीआईटी, सर्कल छूट 2(1), दिल्ली द्वारा 27 मार्च, 2026 को जारी सूचना के माध्यम से अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण की कार्यवाही शुरू की गई। उक्त 27 मार्च, 2026 की धारा 147 के अंतर्गत जारी सूचना के संबंध में संस्थान ने 24 जून, 2026 को ई-कार्यवाही के माध्यम से उत्तर दाखिल किया है।

13

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) -

(i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के उप आयुक्त ने 30 दिसंबर, 2025 के आदेश द्वारा सीजीएसटी/यूपीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत ₹52.70 लाख (₹15.95 लाख कर, ₹20.80 लाख ब्याज और ₹15.95 लाख जुर्माना शामिल) की मांग उठाई है। यह मांग जीएसटीआर-9 की तालिका 5(ग) में दर्शाई गई प्रायोजन आय पर वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान न किए जाने के कारण उठाई गई है। संस्थान ने वस्तु एवं सेवा कर विवरणियों में दर्शाई गई राशियों के संबंध में विस्तृत उत्तर, मिलान विवरण और संबंधित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। हालांकि, विभाग द्वारा मांग की पुष्टि कर दी गई। संस्थान ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत 27 मार्च, 2026 को प्रथम अपर आयुक्त (अपील-II), नोएडा, उत्तर प्रदेश के समक्ष अपील दायर की है। अपील पर 4 जुलाई को सुनवाई हो चुकी है और आदेश की प्रतीक्षा है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के संबंध में, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के उप आयुक्त ने 27 दिसंबर, 2025 के आदेश द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत संस्थान के विरुद्ध ₹566.58 लाख (₹303.80 लाख कर, ₹232.40 लाख ब्याज और ₹30.38 लाख जुर्माना शामिल) की मांग उठाई है। यह मांग रिवर्स चार्ज तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत लेनदेन, जमा/नामे परिवर्तियों, इनपुट कर प्रत्यय के मिलान तथा वस्तु एवं सेवा कर विवरणियों (जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी) में रिपोर्टिंग से संबंधित अंतरों के आधार पर उठाई गई है। संस्थान ने मांग को समाप्त करने के अनुरोध के साथ सहायक दस्तावेजों सहित विस्तृत मिलान विवरण प्रस्तुत किए थे; हालांकि, निर्णयन प्राधिकारी द्वारा मांग की पुष्टि कर दी गई।

उक्त आदेश के विरुद्ध 25 मार्च, 2026 को आयुक्त (अपील-II), नोएडा, उत्तर प्रदेश के समक्ष अपील दायर की गई थी और उसे स्वीकार कर लिया गया है। 4 मई, 2026 को निर्धारित सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई की तारीख की प्रतीक्षा है।

14.

संस्थान ने आई.पी.-उपप्ल, हैदराबाद में कुल 4918 वर्ग मीटर (1.215 एकड़) क्षेत्र के आवंटन के लिए भूमि की लागत के रूप में आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड (अब तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड) को ₹2,88,56,250/- की राशि का भुगतान किया है, जिसमें से:

- (i) प्रथम चरण में 3140 वर्ग मीटर के लिए विक्रय का करार निष्पादित और पंजीकृत किया जा चुका है;
- (ii) द्वितीय चरण में 912 वर्ग मीटर के लिए पूरक विक्रय करार निष्पादित और पंजीकृत किया जा चुका है; और
- (iii) तृतीय चरण में 866 वर्ग मीटर के लिए विक्रय करार का निष्पादन और कब्जा दिया जाना अभी बाकी है।

तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड से विक्रय विलेख के निष्पादन का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, उष्ण औद्योगिक संघ द्वारा निर्माण कार्य पर अंतरिम रोक लगाने के लिए 18-10-2014 को वाद याचिका संख्या 31594/2014 तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने 24-08-2015 के आदेश द्वारा संस्थान के पक्ष में हटा दिया था। अंततः, न्यायालय ने 15 मार्च, 2024 के आदेश द्वारा उक्त वाद याचिका खारिज कर दी।

प्रथम चरण में आवंटित भूमि के लिए विक्रय विलेख के निष्पादन के संबंध में संस्थान द्वारा टीजीआईआईसीएल से संपर्क किए जाने पर, तेलंगाना इंडस्ट्रियल अवसंरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसके प्रत्युत्तर में 20 जुलाई, 2024 को पत्र जारी कर प्रथम चरण की भूमि के विक्रय विलेख के निष्पादन में हुई देरी के लिए ₹1,15,87,638/- की राशि, प्रत्येक विलंबित वर्ष के लिए 3% की दर से विलंब माफी शुल्क/प्रक्रिया शुल्क तथा ₹20,85,775/- का 18% वस्तु एवं सेवा कर, अर्थात् कुल ₹1,36,73,413/- के भुगतान की मांग की।

15.

इसके अलावा, परिषद ने ₹1,36,73,413/- की जुर्माना राशि तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड को 'आपत्ति के साथ' जमा करने की स्वीकृति दी है। यदि आपत्ति के साथ जमा की जाने वाली जुर्माना राशि उपर्युक्त राशि से कम है, तो यह स्वीकृति ऐसी कम राशि तक ही सीमित मानी जाएगी।

संस्थान ने इंदौर में बहुमंजिला भवन "द ग्रेस" (पूर्व नाम - नासा) की पांचवीं मंजिल के एक हिस्से को कुल ₹3,21,00,000/- के प्रतिफल पर खरीदने के लिए 31.03.2015 को विक्रय करार किया था और सहमत कुल प्रतिफल की आंशिक राशि के रूप में ₹80,25,000/- का भुगतान किया गया था। उक्त विक्रय करार की शर्तों के अनुसार, श्री सिराजुद्दीन मलिक एवं अन्य (प्रतिवादियों) को विक्रय करार की तारीख से चार महीने (15 दिनों की अतिरिक्त अवधि सहित) के भीतर एमपीएफसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र और इंदौर नगर निगम से अधिभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना था। प्रतिवादियों द्वारा 31.03.2015 के विक्रय करार की शर्तों के अनुसार एमपीएफसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र और अधिभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में विफल रहने के कारण विक्रय विलेख का निष्पादन नहीं हो सका। इस संबंध में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण सहित कुल ₹83,03,000/- का व्यय हुआ है। यह राशि पूंजीगत कार्य प्रगति पर के रूप में दर्शाई और रखी गई है, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

संस्थान ने 31.03.2015 के विक्रय करार के विशिष्ट निष्पादन के लिए श्री सिराजुद्दीन मलिक, सुश्री सलमा, श्री मुर्तुजा मलिक और मैसर्स कबीर रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे "प्रतिवादी" कहा गया है) के विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय, इंदौर के समक्ष घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया था।

27.09.2025 को न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे 60 दिनों के भीतर संस्थान को ₹80,25,000/- (अस्सी लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) की कुल बयाना राशि का भुगतान करें। इसके साथ ₹50,72,240/- का ब्याज भी देय है, जो करार के निष्पादन की तारीख अर्थात् 31.03.2015 से वाद दायर करने की तारीख तक 12% वार्षिक की दर से और वाद दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6% वार्षिक की दर से गणना किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादियों को करार के निष्पादन से पहले किए गए पंजीकरण व्यय, पेशेवर सेवा शुल्क और कानूनी राय तथा करार रद्द किए जाने के लिए मुआवजे के रूप में संस्थान को ₹6,28,800/- (छह लाख अठ्ठाईस हजार आठ सौ रुपये मात्र) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। उपर्युक्त के अनुसार कुल देय राशि ₹1,37,26,040/- है।

उक्त आदेश का अनुपालन करने में प्रतिवादियों के विफल रहने के कारण संस्थान द्वारा निष्पादन याचिका दायर की गई है। 15.07.2026 को निर्धारित समय के भीतर डिक्री की राशि जमा नहीं किए जाने के कारण, विद्वान निष्पादन न्यायालय ने निर्णय-देनदार के विरुद्ध वसूली वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 27.09.2026 है।

इसके अलावा, प्रतिवादियों ने 27.09.2025 के उक्त आदेश/निर्णय को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर खंडपीठ) के समक्ष चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने ₹6,28,800/- की राशि तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है और उक्त राशि के संबंध में विचारण न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई की तारीख 09.09.2026 तक रोक लगा दी है (अपील की प्रति अभी तक संस्थान को प्राप्त नहीं हुई है)।

इसके अतिरिक्त, 4 जुलाई, 2017 को मैसर्स कबीर रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के श्री सिराजुद्दीन मलिक, श्रीमती सलमा और श्री मुर्तुजा मलिक के विरुद्ध 31.03.2015 के विक्रय करार के संबंध में धोखाधड़ी और छल करने के लिए भारतीय दंड

16.

17. संहिता की धारा 420, 416, 120—बी, 323, 294 और 506 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी (आपराधिक), इंदौर की अदालत में एक आपराधिक शिकायत (आपराधिक वाद— विचारण संख्या 3135/2017— आईसीएसआई बनाम सिराजुद्दीन मलिक एवं अन्य) भी दायर की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 18.09.2026 है।
- 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान के वित्तीय विवरण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार मौजूदा प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
18. कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 16(1) (समय—समय पर यथा संशोधित) के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के संबंध में लेखांकन मानक—18 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी अधिसूचना जारी किए जाने तक इसका प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।
19. क्षेत्रीय कार्यालयों की संबंधित शाखाओं के साथ परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित अंतर—इकाई शेष के मामले में, 31 मार्च, 2026 को ₹3,52,573/— की राशि (यह राशि वर्ष के अंत से पहले क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चैप्टरों को देय शुद्ध राशि है, जो कार्यक्रमों आदि के अधिशेष में शाखाओं के हिस्से के संबंध में थी और जिसे चैप्टरों द्वारा शामिल नहीं किया गया था) को संस्थान के लेखा बहियों के एकीकरण में शामिल किया गया है।

विदेशी मुद्रा में अर्जित आय और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	मुद्रा	वित्तीय वर्ष 2025—26		वित्तीय वर्ष 2024—25	
		विदेशी मुद्रा	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा	भारतीय मुद्रा
क. विदेशी मुद्रा में आय					
प्रतिनिधि शुल्क	एसजीडी	--	--	500	29,292
अंतरराष्ट्रीय मामले और सम्मेलन	यूएसडी	13565	12,07,487	--	--
कुल आईएनआर			12,07,487		29,292
ख. विदेशी मुद्रा में व्यय					
सदस्यता शुल्क	जीबीपी	675	86,820	2,970	3,21,614
	यूएसडी	--	--	1,5000	13,13,452
अंतरराष्ट्रीय मामले और सम्मेलन	ईडी	54,032	13,06,892	75,189	17,92,821
	यूडी	31,045	18,17,084	3,679	2,11,879
	एसजीडी	--	--	2,500	1,60,217
दुबई परीक्षा केंद्र	ईडी	18,024	4,67,403	19,562	4,83,991
पीएमक्यू परीक्षा	ईडी	5,250	1,47,217	--	--
कुल आईएनआर			38,25,416		42,83,974

20. पिछले वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्मित किया गया है।

कृते एवं संस्थान के परिषद् की ओर से

श्री प्रकाश
निदेशक (वित्त)

सीएस आशीष मोहन
सचिव

सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर
उपाध्यक्ष

सीएस पवन जी चांडक
अध्यक्ष

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000038N

(एम. पी. ठाकुर)
भागीदार
(सदस्यता संख्या 052473)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2026

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001135N

(एस. मूर्ति)
भागीदार
(सदस्यता संख्या 072290)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2026

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2026

REPORT OF THE COUNCIL

F. No. 104/46/Accts. -1.—

(A) INTRODUCTION

In terms of the requirements of sub-section (5B) of Section 18 of the Company Secretaries Act, 1980, the Council of The Institute of Company Secretaries of India (ICSI/the Institute) is pleased to present its 46th Annual Report and Audited Statements of consolidated accounts along with the Auditors' Report thereon for the Financial Year ended 31 March, 2026.

President and Vice-President

CS Pawan G. Chandak and CS Dwarakanath Chennur were elected by the Council as the President and Vice-President of the Institute respectively, w.e.f. 19 January, 2026.

Council Meetings

The Council held 12 Meetings during the Financial Year 2025-26.

Composition of Committees

The composition of various Standing, Non-Standing Committees and Boards is given at [Annexure-A](#). Details of Meetings held and attended by the Members of Council and Committees / Boards are placed at [Annexure-B](#).

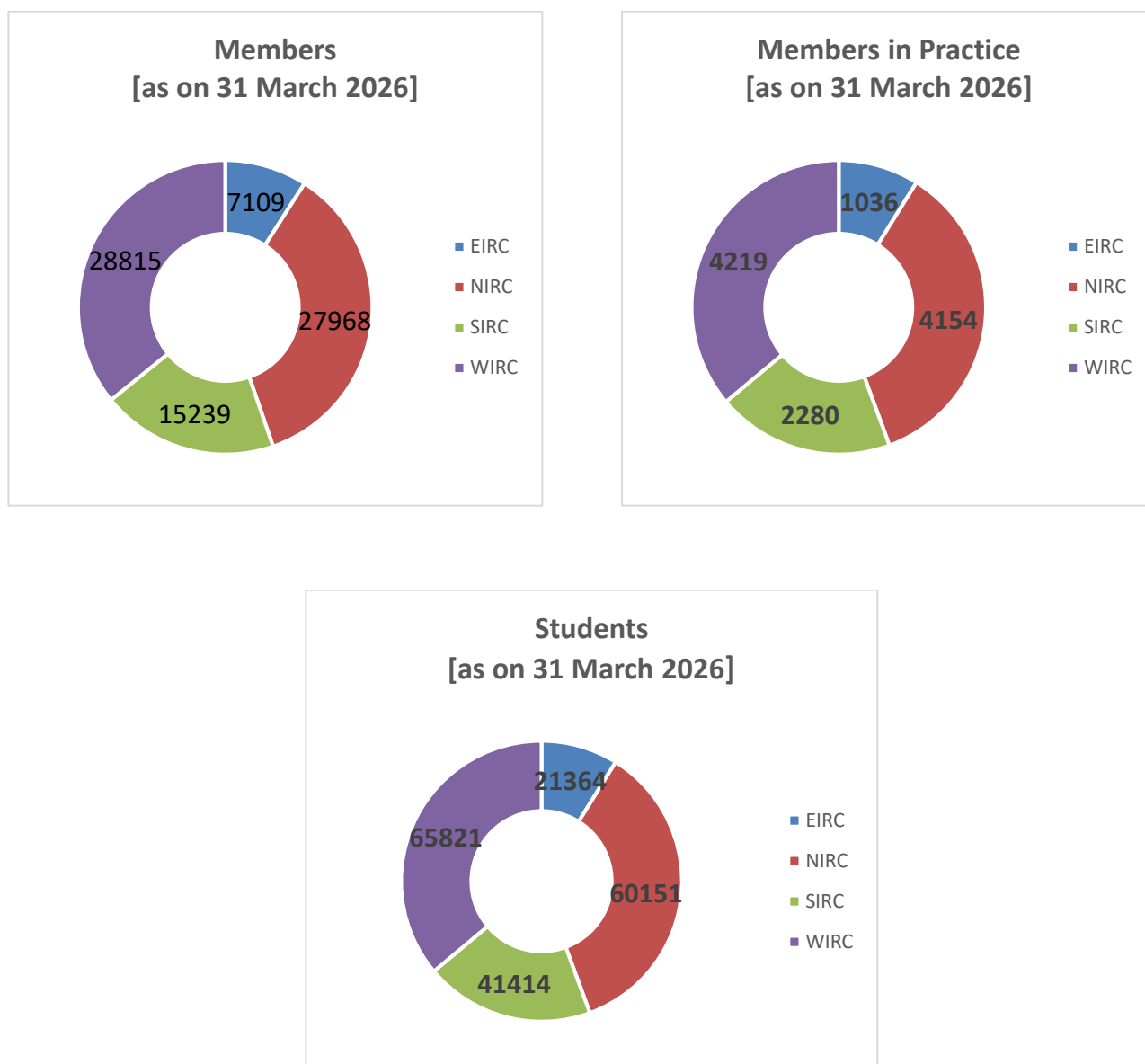
Statistics at a glance

The region-wise statistics of Members and students for the period under Report are as follows:

MEMBERS					
As on	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC	Total
31.03.2026	7109	27968	15239	28815	79131
31.03.2025	7009	26998	14132	26969	75108

MEMBERS IN PRACTICE					
As on	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC	Total
31.03.2026	1036	4154	2280	4219	11689
31.03.2025	1023	4101	2210	4140	11474

STUDENTS OF REGULAR PROGRAMME					
As on	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC	Total
31.03.2026	21364	60151	41414	65821	188750
31.03.2025	20613	57630	40611	64574	183428



(B) FACILITATING EXCELLENCE IN CORPORATE GOVERNANCE

Institutions are increasingly judged not by their policies, but by their principles. ICSI's vision of governance reflects this shift - one that goes beyond compliance to embed foresight, accountability, and stakeholder trust into everyday decision-making. Company Secretaries are central to this evolution, shaping boardroom judgment, identifying risk early, and aligning profitability with purpose. Through this year's initiatives and engagements, ICSI has reinforced a simple but powerful idea: governance is not a rulebook to be followed; it is a discipline to be lived.

(i) 25th ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance, 2025

ICSI instituted the "ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance" in 2001, with the aim of fostering a culture of good governance across the Indian corporate sector. Over more than two decades, these awards have earned wide recognition among corporations and professionals as a benchmark for governance excellence and a meaningful catalyst for raising standards across the industry.

The selection process for the ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance follows a rigorous and comprehensive evaluation framework. An Expert Group, comprising eminent professionals from industry and practice, is constituted annually for each award category. This group provides guidance on framing the evaluation methodology and designing the assessment questionnaire. Following the analysis of responses based on the Expert Group's questionnaire,

the findings are presented to a distinguished Jury for final selection. The Jury consists of experts from various fields and is typically chaired by a former Chief Justice of India, ensuring the highest standards of integrity and expertise in the selection process.

The 25th edition of the ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance was held in New Delhi on 19th December 2025. The ceremony was graced by Dr. Raj Bhushan Choudhary, Hon'ble Minister of State for Jal Shakti, Government of India, as the Chief Guest. The Guest of Honour was Padma Shri Smt. P. T. Usha, Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha) and President, Indian Olympic Association, and the Keynote Speaker and Special Guest was Shri Tuhin Kanta Pandey, Chairman, Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Award winners for the year 2025 are as follows:

25 th ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance	Listed Segment • The Indian Hotels Company Limited (Large Category) • Uno Minda Limited (Medium Category) • Greaves Cotton Limited (Emerging Category)
	Unlisted Segment • Ageas Federal Life Insurance Company Limited (Medium Category) • Interise Investment Managers Private Limited (Emerging Category)
10 th ICSI CSR Excellence Awards	• The Tata Power Company Limited (Large Category) • TP Southern Odisha Distribution Limited (Medium Category) • ICRA Limited (Small & Emerging Category)
7 th ICSI Best Secretarial Audit Report Award	CS P. Eswaramoorthy (for Secretarial Audit Report issued to Pricol Limited)
5 th ICSI Best PCS Firm Award	S. C. Sharada & Associates, Company Secretaries
4 th ICSI Business Responsibility and Sustainability Awards	• Polycab India Limited (Non-Service Sector) • L&T Finance Limited (Service Sector)
25 th ICSI Lifetime Achievement Award	Mr. R. C. Bhargava, Chairman, Maruti Suzuki India Limited

(ii) Secretarial Standards

In line with its ongoing vision of strengthening transparency and accountability in corporate governance, the ICSI has played a pivotal role in the formulation and promotion of the Secretarial Standards. These Standards, which establish benchmarks for board processes and corporate disclosures, hold the distinction of being the first of their kind globally to be accorded statutory recognition under the Companies Act, 2013. They continue to function as vital instruments of governance, fostering procedural consistency and greater transparency across corporate entities. The Institute remains committed to sustaining and periodically reviewing these Standards, ensuring their continued alignment with emerging best practices and regulatory requirements.

Pursuant to Regulation 105A of the Company Secretaries Regulations, 1982 the Institute has constituted the Secretarial Standards Boards (SSB) and the details of its members are provided in **Annexure A**.

(iii) Quality Review Board

The Quality Review Board (QRB), constituted by the Central Government under Section 29A of the Company Secretaries Act, 1980, is entrusted with the responsibility of making recommendations to the Council of the Institute on the quality of services rendered by its Members, reviewing such services, and guiding Members towards enhancing service quality and ensuring compliance with applicable statutory and regulatory requirements. The Board comprises a chairperson, along with two Members nominated by the Central Government and two Members nominated by the Council of the Institute.

(iv) Peer Review Board

Peer Review contemplates examination of systems and approach of a Practice Unit by other Members of the Institute with the objective of identifying the areas for improvement. The focus lies on continuing quality improvement in an atmosphere of openness and mutual trust. A total of 1400 Peer Review exercises were completed during the period under Report, and accordingly Certificates were issued to the Practice Units. Three Training Programmes for the empanelment of Peer Reviewers were organised during the period under report at Nagpur on 05 April 2025, Chennai on 10 May 2025, and Bengaluru on 23 August 2025.

(v) Centre for Corporate Governance, Research and Training (CCGRTs)

The Institute currently operates four CCGRTs, located in Mumbai, Hyderabad, Kolkata, and Manesar, with the Centre at Manesar having been inaugurated and made operational in December, 2025. A detailed account of the programmes and initiatives undertaken by the CCGRTs during the year is presented in Section K of this Report.

(vi) ICSI Initiatives on ESG and Sustainability

The ICSI has undertaken a range of initiatives in the area of ESG and Sustainability, with a focus on tracking emerging trends and global developments, encouraging corporates to adopt sustainability measures through the active involvement of Company Secretaries, and identifying new opportunities for CS professionals within the sustainability space. These initiatives are aimed at deepening the awareness and knowledge of professional fraternity and other stakeholders, thereby facilitating the effective implementation of sustainability measures. The major ESG and Sustainability initiatives undertaken by the ICSI during the year under Report are set out below:

(a) Stakeholder Engagement Toolkit on ESG

With a view to strengthening the ESG governance ecosystem, the Institute released the Stakeholder Engagement Toolkit on ESG at the 53rd National Convention of Company Secretaries held on 31 October - 02 November, 2025. The Stakeholder Engagement Toolkit on ESG is a practically oriented structured resource that outlines suitable engagement practices for different kinds of stakeholders as well as principles to be followed while planning and executing stakeholder engagement activities. The Toolkit highlights best practices to be observed during stakeholder engagement to facilitate effective communication and engagement with varied class of stakeholders.

(b) ICSI Principles on Climate Change Governance

Reaffirming its commitment to promoting sound governance practices, the Institute has developed the ICSI Principles on Climate Change Governance (IPCG), which were released at the 53rd National Convention of Company Secretaries held on 31 October - 02 November, 2025. The ICSI Principles on Climate Change Governance reinforce the commitment of entities, their Boards and Senior leadership, to embed climate resilience into their core business strategy, risk management, performance metrics and accountability structures. By adopting these Principles, entities can demonstrate corporate stewardship on climate governance.

(c) ICSI Communique - ESG Catalyst and ESG Corner

The “ESG Catalyst” is a bi-monthly initiative launched by the ICSI to build awareness about ESG amongst the professionals by sharing key ESG term, write-up, promising practices and latest developments in ESG domain. In addition, a dedicated section titled ‘ESG Corner’ has been introduced in the Chartered Secretary Journal comprising latest news, insights and updates on ESG.

(d) ICSI ESG Mission LiFE Messages

As part of its commitment to sustainability advocacy, the ICSI disseminates environment-friendly tips and short, impactful messages on ESG to sensitize professionals and other stakeholders. These messages are aimed at encouraging the adoption of sustainable practices in daily and professional conduct, in alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Government of India's LiFE (Lifestyle for Environment) Mission.

(vii) ICSI Initiatives on PMLA (Prevention of Money Laundering Act, 2002)

AML & CFT Guidelines for Professionals with Certificates of Practice from ICAI, ICSI and ICMAI are effective from 19 June, 2023, whereby ICSI has been designated as Self-regulatory Body (SRB) for the Company Secretary professionals. Following are the major activities conducted by the ICSI (SRB) during the period under Report:

- Monthly bulk mailers of PMLA flyer to practicing members.
- Bulk SMS to Practicing Members on monthly basis.
- Dedicated webinars conducted for sensitization of PMLA and AML/CFT guidelines under EEE 5.0
- PMLA Portal comprising:

- FAQs on "AML & CFT Guidelines for Professionals with Certificate of Practice from ICAI, ICSI and ICMAI
- List of individuals, designated as terrorist, under UAPA, 1967
- Links to Documents related to Targeted Financial Sanctions Related to Terror Financing and Proliferation Financing
- Social Media creatives at regular intervals on ICSI Social Media Channel
- Dedicated email ID **pmla@icsi.edu** for PMLA related queries

Registration of Reporting Entities: Reporting Entities are required to register themselves with ICSI through its 'registration portal', which is available on STIMULATE. ICSI also has in place, the PMLA Portal, wherein all notifications and the FATF Grey & Black list can be accessed by the Members.

(C) FACILITATION AND STANDARDIZATION

(i) Major Strategic Partnerships

(a) The Chamber of Commerce and Industry

The Institute has entered into an MoU with the Cochin Chamber of Commerce and Industry in order to conduct Joint Professional Development workshops, seminars, continuing education and training programmes for students, practicing professionals and corporate executives on themes of topical and professional interest and to hold several other activities/projects mutually and severally beneficial to the parties.

(b) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA)

A Memorandum of Understanding was signed with the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) during the IICA North-East Conclave 2025 held on 11-12 July, 2025 at Shillong, *inter alia* covering, launching courses, programmes for building capacities in terms of employability of youth in the North-Eastern Region and other areas of mutual interest reflecting joint efforts of both the Institutes.

(c) Symbiosis Skills & Professional University, Pune

The Institute has entered into an MoU with Symbiosis Skills & Professional University, Pune with the objective of upskilling Students, Staff and Members of the Institute in emerging areas such as RegTech, FinTech and other technology-driven domains. The collaboration seeks to promote learning, skill development, professional training and capacity building through various educational and training initiatives, thereby enabling stakeholders to remain abreast of evolving technological advancements and industry requirements.

(d) Bharath Cloud (BCDC Cloud Centers Pvt. Ltd.)

The Institute has entered into an MoU with Bharath Cloud (BCDC Cloud Centers Pvt. Ltd.) to facilitate members by providing access to secure cloud-based digital solutions and AI-integrated compliance tools. Under this collaboration, members shall be entitled to special subscription packages, free training programmes and dedicated support services. The partnership aims to strengthen professional excellence, digital transformation and compliance management through enterprise-grade security and advanced technological solutions.

(e) TSS Consultancy Services Pvt. Ltd. (Screenzaa)

The Institute has entered into an MoU with TSS Consultancy Services Pvt. Ltd. (Screenzaa) to facilitate members by providing access to advanced compliance screening and monitoring solutions. The platform offers complimentary compliance checks, special discounted pricing, dedicated support and assured confidentiality. It enables professionals to undertake due diligence and regulatory compliance through sanctions screening, adverse media monitoring, suspicious transaction reporting and other compliance management tools.

(f) ICSI Industry / Institutional Outreach Programme

The Institute launched a significant initiative empowering its Regional and Chapter Offices across India to independently initiate and enter into MoU with Industry Associations, Chambers of Commerce and similar allied bodies within their respective regional jurisdictions. Underpinned by a structured approval process with Headquarter oversight, strict data protection protocols and annual impact reporting, the framework ensures transparency, accountability and consistency across all Region and Chapter-level partnerships. Through these collaborations, Members and Students stand to benefit from joint professional development programmes,

seminars, conferences, workshops and sector-specific training tailored to their evolving needs along with CPE Credits for eligible jointly organised programmes, subject to the ICSI guidelines.

(g) India International Exchange (IFSC) Limited

The ICSI and India International Exchange (IFSC) Limited (India INX) inked an MoU on 26 February, 2026 to collaborate and mutually work to develop GIFT-IFSC as a Global Listing Centre by creating awareness about the opportunities available for Company Secretaries in GIFT IFSC.

(h) Indian Association of Gold Excellence and Standards

The ICSI has inked MoU with Indian Association of Gold Excellence and Standards (IAGES) on 15 January, 2026, in New Delhi. The MoU will provide leverage to ICSI-registered Practising Company Secretaries (PCS) firms by giving them access to IAGES' Value Chain Partners in the Indian Gold Industry who have expressed interest in undergoing assessment for IAGES accreditation. PCS firms will have an opportunity to empanel themselves with IAGES as external agency to conduct assessment of the IAGES' Value Chain Partner across India. The criteria were revised to include Sole Proprietorships in the eligible entities. Furthermore, the minimum requirement of average annual financial turnover over the last 3 consecutive financial years has been revised to ₹50 lakhs from the earlier threshold of ₹1 crore.

(ii) eCSIN (Employee Company Secretaries Identification Number) Amnesty Scheme, 2025

The Institute launched the eCSIN Amnesty Scheme, 2025 effective from 01 April, 2025 to 15 April, 2025, which was extended upto 20 April, 2025. All active eCSINs generated from the effective date of the eCSIN Guidelines i.e., 01 October, 2019 upto the validity of the Amnesty Scheme i.e., 20 April, 2025 were covered under the Amnesty Scheme.

(i) UDIN (Unique Document Identification Number) Amnesty Scheme, 2025

The Institute launched the UDIN Amnesty Scheme, 2025 valid from 01 April, 2025 to 15 April, 2025, which was extended upto 20 April, 2025. All UDINs generated from 19 April, 2024 upto the closure of the Scheme i.e., 20 April, 2025 were eligible to avail benefit under the Amnesty Scheme.

(ii) ICSI (Management and Development of Company Secretaries in Practice) Guidelines, 2023

The ICSI (Management and Development of Company Secretaries in Practice) Guidelines, 2023 were issued by the Institute w.e.f. 15 December, 2023. The Guidelines were amended by the Council in its 321st (Special) Meeting held on 25 August, 2025, in order to bring procedural clarity in certain matters.

(iii) Revamping of PCS Portal

The PCS Portal on the website of the Institute has been revamped in order to bring uniformity, clarity and streamline various information / guidance / guidelines available for the benefit of Company Secretaries in Practice.

(iv) Suggestive monthly themes for Regional and Chapter Offices

The Institute introduced suggestive monthly themes for Regional and Chapter Offices with the prescribed theme to be incorporated in at least one programme of the month, either as the main theme or as a sub-theme. This initiative ensures thematic consistency and provides members with structured professional enrichment. Such suggestive monthly themes are also being incorporated in the Chartered Secretary Journal to promote standardization and provide a unified focus for professional development of members.

(vii) Company Secretaries Benevolent Fund (CSBF)

CSBF is a society registered with the Registrar of Societies, New Delhi under the Societies Registration Act, 1860. It was established by the Institute in the year 1976 to create a security umbrella and provide a safety net to the Company Secretaries who are Members of the CSBF and their dependent family members in times of

distress. During the period under report, a total of 1611 Members were admitted to CSBF. As on 31 March, 2026, there were 19026 life Members of CSBF.

A Special Drive for CSBF Life Membership was launched from 18 January, 2026 till 30 June, 2026 at a discounted fee of Rs.9,000/-. The Members who took membership of the CSBF during Special Drive were also provided with complimentary publications of the ICSI.

(D) CAPACITY BUILDING & KNOWLEDGE UPDATION FOR MEMBERS

(i) Capacity Building Series

Capacity Building Series (webinar mode) is an initiative of the Institute for knowledge upgradation and skill enhancement of the Members on various topics to equip them with theoretical and practical insights to take-up professional opportunities in areas which are less explored. The webinar series focus upon (i) Basic concepts & legal aspects relating to the topic (ii) Opportunities for Company Secretaries in that area and (iii) Skill-set required for taking up the opportunities.

(ii) Study Circles

ICSI has been creating knowledge upgradation avenues for Members by promoting the formation of Study Circles across the country. During the period under Report, the following Study Circles were formed/renewed:

Regional Council	Name	Formation/ Renewal
SIRC	Hubli-Dharwad Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
NIRC	Dwarka Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	Rewari Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	Greater Noida West Study Circle of ICSI	Formation for F/Y 2025-26
	Rohini Study Circle of ICSI	Formation for F/Y 2025-26
WIRC	Mahindra (Corporate) Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	H T Parekh Marg (Corporate) Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	Jamnagar Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	Makarand M Joshi & Co. (Corporate) Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	Sangli Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	Reliance Industries (Corporate) Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	L&T (Corporate) Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	Bhilai Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	Santacruz Study Circle of ICSI	Formation for F/Y 2025-26
	JSW Group (Corporate) Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	Mahindra (Corporate) Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2026-27
	Kandivali Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2026-27
	Aditya Birla Group (Corporate) Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2026-27
	H T Parekh Marg (Corporate) Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2026-27
EIRC	Madhya Kolkata Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26
	Tollygunge Study Circle of ICSI	Renewal for F/Y 2025-26

(iii) Knowledge on Demand

Knowledge on Demand (KoD) is an initiative of the Institute providing online facility to Members to explore the recorded sessions delivered by subject experts on important topics and update their knowledge at their convenience 24x7 on the LMS Platform of the Institute.

(iv) Major Publications**(a) Model Governance Code for Meetings of Gram Panchayats**

The Institute released the Model Governance Code for Meetings of Gram Panchayats in 2017 as a social initiative to standardize practices for convening panchayat meetings. Recognizing that different states operate with varied deadlines and procedures, the Code has been updated to provide a unified document that harmonizes all schedules. The updated Code was released on 19th April, 2025. This comprehensive Code represents a significant advancement in strengthening Indian local self-governance. It aims to standardize procedures for Gram Panchayat meetings while enhancing operational efficiency, accountability, and transparency. By improving village-level governance processes, the Code facilitates better policy implementation, promotes rural development initiatives, and builds greater public confidence in local self-government institutions.

(b) Corporate Governance – From Compliance to Excellence (Handbook on Best Practices), Version 4.0

The fourth edition of Corporate Governance – From Compliance to Excellence (Handbook on Best Practices), is based on extensive analysis of governance mechanisms employed by companies participating in the 24th edition of the ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance Awards. The publication examines and highlights best practices across six critical areas: board effectiveness, transparency and disclosure, risk management, stakeholder value enhancement, sustainability and workplace innovation, offering valuable insights and practical guidance to stakeholders in the corporate governance ecosystem to help them achieve excellence beyond mere compliance.

(c) Decoding ESG: FAQs on ESG and Sustainability

The publication serves as a compendium of various terminologies and concepts used in ESG & Sustainability domain. The structure of the publication follows a question-and-answer format, covering a wide range of themes such as blue economy, green washing and other important ESG and sustainability concepts to equip the readers with a foundational understanding of the ESG and sustainability landscape.

(d) Handbook on Business Responsibility and Sustainability, Version 3.0

The third edition of Handbook on Business Responsibility and Sustainability navigates the ways in which companies can successfully manage their transition to a more responsible and sustainable way of doing business. It compiles the legislative journey both in India and internationally, observed practices among shortlisted companies during the Awards evaluation process and step-by-step guidance for corporates to prepare their BRS Report.

(e) Model Governance Code for Meetings of Zila Parishad

The Model Governance Code for Meetings of Zila Parishad embodies the Zila Parishad's integrative role in governance, recognizing varied development needs across communities while pursuing the singular goal of collective prosperity and well-being. Since the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 institutionalized the three-tier Panchayati Raj system, the Zila Parishad has served as the apex body of rural governance, bridging state policy with community aspirations. This Model Governance Code standardizes meeting procedures and strengthens accountability and transparency, enabling better policy execution and more effective rural development.

(f) Model Governance Code for Meetings of Panchayat Samiti

The Code reinforces the constitutional role of the Panchayat Samiti as the crucial intermediate tier between village and district administration. The Code provides best practices for conducting efficient, transparent and inclusive meetings, promoting structured deliberations, effective planning, citizen engagement and accountable decision-making, thereby empowering Panchayat Samitis to fulfil their mandate of promoting economic development, social justice and equitable public service delivery.

(g) Stakeholder Engagement Toolkit on ESG

Stakeholder Engagement Toolkit on ESG is a practical oriented structured resource that guides users through the process of identifying, involving and collaborating with stakeholders in different scenarios. The Toolkit highlights key best practices to be observed during stakeholder engagement to facilitate effective communication and engagement with varied class of stakeholders.

(h) ICSI Principles on Climate Change Governance

The publication reinforces the commitment of entities, their Boards and Senior leadership, to embed climate resilience into their core business strategy, risk management, performance metrics and accountability structures. By adopting these Principles, entities can demonstrate corporate stewardship on climate governance. The principles are universal in nature and are free from jurisdictional bias, which makes them adoptable by any entity across the globe.

(i) Guidance Note on Meetings of Board of Directors (GN-1)

The Secretarial Standard on Meetings of the Board of Directors (SS-1), issued by the ICSI under Section 118(10) of the Companies Act, 2013, has significantly contributed to strengthening corporate governance since its introduction in July 2015. SS-1 was revised in 2017 and again in 2024 to reflect evolving practices. To facilitate effective compliance with SS-1, the ICSI had issued a Guidance Note on Meetings of the Board of Directors, which has been periodically updated in line with revisions to SS-1 to ensure consistency with the Companies Act.

(j) Guidance Note on General Meetings (GN-2)

The Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), issued by the ICSI under Section 118(10) of the Companies Act, 2013, has significantly contributed to strengthening corporate governance since its introduction in July 2015. SS-2 was revised in 2017 and again in 2024 to reflect evolving practices. To facilitate effective compliance with SS-2, the ICSI had issued a Guidance Note on General Meetings, which has been periodically updated in line with revisions to SS-2 to ensure consistency with the Companies Act.

(k) MSME Ready Reckoner 2.0

It is a practical guide for MSMEs in India, which provides clear details on legal frameworks, compliance rules, and operational guidelines for small businesses. The updated 2.0 edition reflects recent government policy changes and new initiatives for the sector. It serves as an essential reference tool for Company Secretaries and professionals handling business compliance.

(l) Navigating Labour Codes: A Handbook

The New Labour Codes, framed and enacted in 2019, made a breakthrough in the legislative arena, by bringing together similar legislations, giving greater benefits and reliefs to the labour section of the society. This publication complements the fruition of the enforcement of these Laws, attempting to provide better clarity on various matters engulfed and encased within these Codes.

(m) Guidance Note on Third Party Assurance (BRSR Core)

The Guidance Note on Third Party Assurance (BRSR Core) has been formulated to serve as a practical guide for assurance providers, reporting entities and other stakeholders. It outlines practical approaches to planning, executing, and reporting on assurance engagements of BRSR Core disclosures, including guidance on assessing data quality, evaluating internal controls over sustainability information, applying materiality considerations in the ESG context and avoidance of greenwashing risks.

(n) Handbook on Internal Audit

The Handbook provides a comprehensive, instructional, and standardized guide for the internal audit process. It equips professionals with systematic methodologies and best practices to evaluate corporate governance, risk management, and internal controls effectively. This essential manual helps ensure strict compliance with statutory requirements while driving organizational efficiency and financial integrity.

(o) Handbook on Consumer Protection Law

The Publication encompasses various crucial dimensions of consumer protection such as genesis of consumer protection; legislative milestones in the forms of Consumer Protection Act, 1986 and 2019 and their ramifications; significance of consumer education; regulatory bodies ensuring safeguarding and enforcement of consumer rights like Central Consumer Protection Authority (CCPA); global scenario of consumer protection and so on, to sensitize the corporate world at large, consumers, governance professionals, pertinent regulatory bodies, media, academicians, researchers, industries, chambers of commerce, research firms especially conducting research on consumers related rights, students etc.

(p) Handbook on Anti-Corruption Laws

The publication titled, “Handbook on Anti-Corruption Laws” focusing on crucial aspects like historical perspectives of corruption, regulatory framework for controlling anti-bribery / anti-corruption practices, whistle blower mechanism, anti-bribery policy, international institutional practices for anti-bribery / anti-corruption, landmark cases on anti-bribery etc. aims to create massive awareness and provide deep insights regarding anti-bribery and corruption among industries, government bodies, chambers of commerce, governance professionals, professionals of other bodies, academicians and researchers, students and others.

(q) Handbook on SME IPO - Process & Listing

In light of the tremendous significance MSME sector holds in Indian economy, the Institute has brought out a research-based publication titled, “Handbook on SME IPO- Process & Listing” emphasizing on various key facets such as the genesis of SME listing; functioning of SME; value addition by SME in emerging economy; regulatory and legal framework governing SME’s IPO listing (ICDR Regulations); pre-listing preparation, due diligence etc.

(r) Handbook on Corporate Restructuring

The Publication “Handbook on Corporate Restructuring” makes an endeavour to throw light on various vital dimensions of corporate restructuring such as types of restructuring, demerger, spin-offs, corporate debt restructuring, valuation in restructuring, regulatory framework governing restructuring etc.

(s) Registered Valuer’s Toolkit

The Registered Valuers’ Toolkit aims to equip both aspiring and practicing Registered Valuers with the essential knowledge, regulatory frameworks, practical tools, and ethical guidance required for carrying out valuation assignments with competence and integrity. From valuation methodologies to reporting formats, from legal provisions to illustrative case studies, the material endeavours to provide a balanced blend of theoretical understanding and practical application. The Publication is ideal for valuation practitioners, financial analysts, and corporate advisors, and is the ‘go-to resource’ for achieving valuation excellence.

(v) Major Webinars**(a) Webinars organised by Headquarters**

S. No.	Topic	Date
1	Next-Generation GST Reforms (Recommendations of the 56 th Meeting of the GST Council)	11 September, 2025
2	Labour Codes (Overview and Way Forward)	29 November, 2025

(b) Joint Webinars/Seminars

S. No.	Particulars	Date
Joint Programmes with PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI)		
1.	Institutional Partner in the Seminar on ‘Blending AI for Effective ESG & Compliance – Attaining Excellence in Sustainability & CSR Reporting’ organized at New Delhi.	02 May, 2025
2.	Institutional Partner in the Seminar on ‘IEPF, Corporate Exits & Investors Protection’ at New Delhi.	18 July, 2025
3.	Institutional Partner in the Seminar on ‘SEBI (LODR) & PIT Regulations: Strengthening Corporate Governance & Safeguarding Investors’ organized at New Delhi	19 September, 2025
4.	Institutional Partner in the Seminar on ‘Corporate Restructuring: Efficient Corporate Structures with Evolving Legal & Governance Framework’ organized at New Delhi.	28 November, 2025
5.	Institutional Partner in the ‘Symposium on Competition Law’ organized at New Delhi.	12 December, 2025

Joint Programme with IIM Bangalore		
6.	Academic Partner in the IIMB-CCGS Corporate Governance & Sustainability Conclave 2025 on the theme 'Navigating the Future of Corporate Governance: Accountability & Innovation' organised at Bengaluru.	04 July, 2025
Joint Programme with Women's Collective Forum (WCF)		
7.	Institutional Partner with the Women's Collective Forum (WCF) for the SPARK – The 100K Collective, an initiative to empower women-led SMEs with early-stage legal clarity, compliance literacy, and enterprise governance through masterclasses.	24 September, 2025
ICSI – Educators' Outreach Programme		
8.	Educators' Outreach Programme comprising the Vice Chancellors/ Principals/ Deans/ Professors, etc. from reputed Government and Private Universities/ Colleges/ Institutions located in the Delhi NCR.	15 January, 2026

(c) **EEE 5.0 – Master Knowledge Series:** The Institute launched the EEE (Enable, Evaluate, Excel) Webinar Series since the year 2017 to help its members refresh, enhance, and update their knowledge of corporate and sectoral laws. The second, third and fourth editions of this capacity building initiative were launched in 2021, 2023 and 2024 respectively. Keeping the same intent & the enthusiastic response to its previous editions, the ICSI has launched next phase of this webinar series under the aegis of EEE 5.0 - Master Knowledge Series. 37 sessions under aegis of EEE 5.0 Master Knowledge series were conducted.

(d) **MCA User Awareness Sessions:** MCA in collaboration with ICSI conducts regular User Awareness Sessions and Open House Sessions for resolution of the stakeholder's issues on MCA -21 V3 and other important technical aspects.

(vi) **Key Initiatives**

(a) **MSME & Startup Connect 2025:** The ICSI MSME & Startup Connect 2025 is an initiative by the MSME & Startup Board held from June to July 2025 to observe MSME Day, with a theme "MSMEs & Start-ups: Empowering Growth", accelerating success on self-sustained basis. The programme follows a standard, uniform structure across India and aims to create opportunities for governance professionals in areas relevant to MSMEs and startups, and further facilitate capacity building for Company Secretaries, corporate advisors, and entrepreneurs, in order to build a compliant, sustainable, and capital-ready business ecosystem.

(b) **National Conclave on NCLT Practitioners :** The National Conclave on NCLT Practitioners grew out of the ICSI NCLT & NCLAT Taskforce – 2025. ICSI Regional Offices and Chapters organized these events across India in the regions of NCLT Benches using a standard format and a self-sustaining financial model. Technical or Financial members from the NCLT Bench of the respective region attended conclave as Guest of Honour for the programmes. Held under the theme "NCLT/NCLAT: Complete Corporate Jurisdiction for Dispute Resolution," the sub-themes covered the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the Companies Act, 2013, with a focus on connecting statutory law to courtroom practice. The main purpose of the conclave is to equip Practicing Company Secretaries with actionable litigation capabilities directly aligned with current National Company Law Tribunal frameworks.

(c) **Startup Week :** The Institute celebrated Startup Week 2026 in January 2026 under the core theme "Transforming Start-up Ecosystem: Creating a Digitally Empowered Nation." ICSI Regional Offices and Chapters across India, hosted specialized programmes from 12-22 January, 2026. Topics covered funding options, compliances, investment opportunities, shareholder and share purchase agreements, valuation, intellectual property rights, debt recovery, and financial restructuring to enhance the professional opportunities for the Company Secretaries and to strengthen India's startup ecosystem.

(d) **National Programme on Internal Audit :** The National Programme on Internal Audit was on held 10 January 2026. The programme was conducted as a part of an initiative of the ICSI Task Force on Internal Audit 2025, which was constituted to explore and strengthen the role of Company Secretaries in Internal Audit and in fostering robust governance frameworks. The programme was organized under the theme 'Internal Audit: A Framework for Enhanced Stewardship' and aimed to highlight the importance of internal audit in promoting transparency, accountability, risk management, and effective corporate governance.

(e) **National Seminar for Regions :** During the period under Report, the Institute organised a series of regional seminars aimed at fostering dialogue and deliberation on emerging economic opportunities and sectoral growth across the country. As part of this initiative, the "Aspirational East" seminar was held on 12 September, 2025 at Patna, themed on "National Seminar on Startups, FPO and Agri-Business," focusing on the growth prospects of

startups, Farmer Producer Organisations and agri-business. This was followed by the "Emerging South – Growth Beyond Metros" seminar held on 17 January, 2026 at Mysuru, themed "Digital Horizons – Impact on IT, MSMEs, Startups, Foods & Textiles Sector," which deliberated on the transformative impact of digitalisation on key sectors driving growth beyond metropolitan centres. On the same day, the "Magnificent West" seminar was organised at Pune, themed "Empowerment Through 3Is: Innovation, Inclusion and Impact," highlighting the role of innovation, inclusion and impact-driven strategies in economic empowerment. These seminars provided valuable platforms for stakeholders to exchange ideas, explore emerging opportunities, and strengthen the Institute's engagement with the wider economy.

- (f) **Capacity Building Programme on Direct Tax** : The Institute organised a 'Capacity Building Programme on Direct Tax' for Members and students of ICSI free of charge. The programme was organised from 10 July, 2025 to 29 August, 2025. The programme was organised in virtual mode, and a total of 30 hours' training was provided by subject experts on different dimensions of Direct Tax.
- (g) **Capital Markets Week 2025** : To commemorate Capital Markets Week 2025, the Institute organised a series of programmes across the country aimed at deliberating on developments and emerging trends in the capital markets ecosystem. The Western India Regional Office (WIRO) hosted its programme on 18 December, 2025 at Mumbai, while the Northern India Regional Office (NIRO) organised its programme on the same date at Delhi. This was followed by the programme organised by the Southern India Regional Office (SIRO) on 19 December, 2025 at Chennai, and the Eastern India Regional Office (EIRO) programme held on 10 January, 2026 at Kolkata. The programmes were graced by eminent dignitaries from regulatory bodies and industry, whose insights enriched the discussions and added significant value to the proceedings. These initiatives reflect the Institute's continued endeavour to engage with stakeholders and promote awareness on capital market regulations and practices among professionals and industry participants.
- (h) **ICSI National Sustainability Conference 2025** : ICSI National Sustainability Conference 2025 was organised on 26-27 July, 2025 at Udaipur, Rajasthan on the theme "Fostering Sustainability Towards a Resilient Future". The Conference was inaugurated in the august presence of Dr. Prem Chand Bairwa, Hon'ble Deputy Chief Minister of Rajasthan, Chief Guest and Prof. (Dr.) Gourav Vallabh, Member, Economic Advisory Council to the Prime Minister, Special Guest. The conference also witnessed the presence of Dr. Manna Lal Rawat, Member of Parliament (Lok Sabha) from the Udaipur constituency.

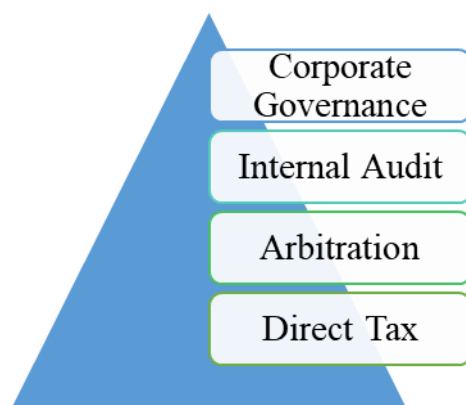
(vii) **Courses**

- (a) **ICSI Certificate Courses for IFSCs launched at GSMC 2.0** : The ICSI launched following three specialized courses designed for aspiring professionals, compliance officers, and legal experts seeking to build a distinguished career within the IFSC framework at the GSMC 2.0 on 26 February, 2026.
- Regulatory framework for Capital Market Intermediaries in IFSC course provides a concise understanding of the regulatory ecosystem, covering essential compliance, operations, and risk management.
 - Regulatory framework for Fund Management in IFSC: AIFs and Retail Scheme offers a comprehensive overview of AIFs and retail schemes, building practical expertise in valuation and financial modelling.
 - Corporate Governance in IFSC course utilizes immersive workshops and case studies to develop strategic leadership skills for IFSC intermediaries.
- (b) **ICSI Online Crash Courses** : The Institute has launched online crash courses on varied topics with a view to assist the Members in gaining a comprehensive knowledge of various laws and develop the requisite skills and expertise for application of such laws. During the period under report, Crash Course were organised on the following topics:

Interpretation of Statutes with reference to Company Law	Related Party Transactions	Artificial Intelligence and IT Tools	Decoding Financial Statements	A to Z of NBFC Compliances
--	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

(c) **ICSI Post Membership Qualification (PMQ) Courses**

The Institute has conducted PMQ Courses for the Members in the following disciplines:



(d) ICSI Certificate Courses

With a view to provide insight and promote better understanding, Certificate Courses in the following areas were conducted:

Regulatory Framework for Fund Management in IFSC: AIFs and Retail Schemes
Certificate Course on Regulatory framework for Capital Market Intermediaries in IFSC
Forensic Audit
Commercial Contract Management
GST
Professional Reboot: Women in Company Secretarial Role
POSH
FEMA
IPR
UAE Business Manager
Securities Laws
Independent Director
Certified CSR Professionals
ESG
IFSCA
Corporate Restructuring
Valuation of Securities / Financial Assets
IBC

(viii) Chartered Secretary Journal

The Chartered Secretary Journal is the most coveted Flagship Journal of the Institute which was launched in the year 1971. This ISSN publication has more than one lakh readers nationally and globally. It is widely circulated amongst Industry professionals, Academia, Ministries, Government bodies, and other professionals in hard copy and online mode, with awareness created through social media handles of ICSI. The Journal is also listed on Magzter, one of the professional online platforms for listing Journals.

Every month, the Journal publishes theme-based articles. Each issue has a dedicated segment on research, where research-oriented articles with focus on legal, & conceptual research, and application of research methods are published. The Global Connect section covers articles of international relevance.

The Journal inter-alia covers features on 'Legal World, which carries updates on recent judgments, and 'From the Government', where relevant Government orders/ circulars are published.

The Institute's monthly initiatives are highlighted through 'Activity Highlights' where Institute's innovative approach towards various professional areas as well as efforts for various recognitions and opportunities are published to apprise the Members.

There is a special section on 'Beyond Governance' with interesting Legal Case Studies, Crossword and a Book Review. The Miscellaneous Corner captures recent trends and Government initiatives in corporate governance and other emerging areas, such as Ethics, GST, ESG, MSME, AI and Gist of ROC and RD Adjudication orders, covering national and global perspective.

In order to create more awareness about the maritime sector amongst the professional fraternity, the Journal has a dedicated "Maritime Corner" under Miscellaneous Corner section comprising key terms and developments in the maritime industry.

As a new initiative, QR codes have been placed at the end of each article. Scanning these QR codes, allows readers to directly access the audio version of articles on the ICSI YouTube Channel. It gives ease of access to the readers by providing an option to listen to the articles/contents of the Journal.

Chartered Secretary Collector's Series: The Chartered Secretary Collector's Series, is an attempt of the Institute towards collating the pearls of wisdom spread over the various editions and volumes of the Chartered Secretary Journal across years and bringing them within the bindings of a single publication. The fifth edition under the title 'Direct Taxes and GST' was released in June, 2025.

(E) RECOGNITIONS, REPRESENTATIONS AND SUGGESTIONS

(i) IFSCA authorises Practising Company Secretaries to Certify Compliance of Preferential Issues

The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) vide circular no. F. No. IFSCA-PLNP/16/2024-Capital Markets dated 22 April, 2026 has authorised Practising Company Secretaries to certify that any preferential issue proposed by an issuer has been carried out in accordance with the requirements specified under the circular on the Framework for Preferential Issues and Qualified Institutions Placement under the IFSCA (Listing) Regulations, 2024.

(ii) Adoption of ICSI Stewardship Principles for IFSC Entities

IFSCA vide circular dated 23 October, 2025 has introduced a Framework on Stewardship Code in IFSC to enhance investor protection and promote robust corporate governance. The IFSCA has recognized the 'ICSI Guiding Principles on Stewardship' issued by the Institute as a Stewardship Code, which may be adopted by Fund Management Entities and Institutional Investors in the IFSC, undertaking investment activities.

(iii) Major Representations

Date	Particulars	Authority
05.05.2025	Request to include the qualification of Company Secretary for recruitment of specialist cadre officers in public sector banks	IBA
06.06.2025	Request for modification in layout of e-form MGT-8	MCA
06.06.2025	Request for organizing MCA User Awareness Sessions (on launch of Annual Filing Forms on MCA-21 V3) in Bengaluru and Delhi	
06.06.2025	Request for modification in format of Certificate of Incorporation in the case of conversion of an entity into Company under section 366 of Companies Act, 2013	
06.06.2025	Request for introduction of Company Law and LLP Law Settlement Scheme, 2025 (CL & LLSS-2025)	
18.07.2025	Request for allowing condonation in case of delayed filing of e-Form MR-2	
01.09.2025	Request for relaxation in the requirement of mobile OTP verification at the time of DIR-3 KYC for Foreign Directors	
12.09.2025	Request for extension of time limit for holding AGMs through VC or OAVM and EGMs through VC or OAVM or transacting items through postal ballot - Reg.	
23.09.2025	Request for inclusion of Company Secretaries as eligible professionals for certification of shareholding and other non- financial certifications	
30.09.2025	Functioning of MCA- 21 V3 Portal - Issues and Challenges faced by stakeholders	
15.10.2025	Request for Extension of Timeline for filing of Annual E-forms under the Companies Act, 2013	
10.11.2025	Request for introduction for "Company Law and LLP Law Settlement Scheme 2025"	
22.12.2025	Functioning of MCA-21 V3 Portal -Issues and Challenges faced by stakeholders	
01.08.2025	Request for a clarification w.r.t relaxation from the applicability of Regulation 36 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015	SEBI
27.08.2025	Request to recognize the profession of Company Secretary under the Central	CERC

	Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021	
26.09.2025	Request to process applications of Company Secretaries to act as Trade Marks Agent under the Trade Marks Act, 1999 and Rules made thereunder	Dept. of Commerce, Ministry of Commerce and Industry
12.11.2025	Request to authorise Company Secretary in Practice to appear under Section 16 (4) and Section 32 of the FEMA 1999	RBI
19.02.2026	Representation on issues in processing of applications of Company Secretaries in Practice to act as Trade Marks Agent under the Trade Marks Act, 1999 and Rules made thereunder	Controller General of Patents, Designs & Trade Marks (CGPDTM)
16.03.2026	Issuance of notices by Regional Directors and application of Section 12(8) – Request for adherence to principles of natural justice	MCA
	Exempt companies from approval of Regional Director for shifting of Registered Office within same state on account of establishment of new ROCs within same state	
	Issuance of instructions to RDs/ROCs for processing applications filed through e-Filing without mandatory physical submission	
	Modification in first proviso to Section 14(1) regarding effective date of conversion of private company into public company	
18.03.2026	Representation seeking clarification and intervention regarding jurisdiction for levy and collection of Stamp Duty	DoR
18.03.2026	Request for Introduction of Amnesty Scheme / Condonation for Delay in Filing of BEN Forms under the Companies Act, 2013	MCA
30.03.2026	Allowing Change / Modification in the Name of Trusts Registered for Receiving CSR Funds	
30.03.2026	Prioritised listing of matters u/s 230-232 & 252 of Companies Act, 2013 and Sections 59 under IBC at various Benches of Hon'ble NCLT	

(iv) Suggestions

Date	Particulars	Authority
18.08.2025	Suggestions of ICSI on the “Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) (First Amendment) Regulations, 2025	CERC
21.08.2025	Suggestions of ICSI on the SEBI Consultation paper on “Revised Norms for appointment of an independent third-party reviewer/ certifier for green debt security”	SEBI
10.11.2025	Suggestions of ICSI on: • RBI (Small Finance Banks – Governance) Directions, 2025; • RBI (Payments Banks – Governance) Directions, 2025; • RBI (Local Area Banks – Governance) Directions, 2025; • RBI (Regional Rural Banks – Governance) Directions; • RBI (Urban Co-operative Banks – Governance) Directions; • RBI (Rural Co-operative Banks – Governance) Directions; • RBI (All India Financial Institutions – Governance) Directions; • RBI (Non-Banking Financial Companies – Governance) Directions; • RBI (Setting Up of Wholly Owned Subsidiaries by Foreign Banks) Guidelines, 2025	RBI
29.01.2026	Suggestions of ICSI on Draft Industrial Relations (Central) Rules, 2025	Ministry of Labour and Employment
11.02.2026	Suggestions of ICSI on Draft Code on Social Security (Central) Rules, 2025	
13.02.2026	Suggestions of ICSI on Draft Code on Wages (Central) Rules, 2025	
13.02.2026	Suggestions of ICSI on Draft Occupational, Health & Safety (Central) Rules, 2025	
22.02.2026	Suggestions of ICSI on Draft Income-Tax Rules, 2026	CBDT
27.02.2026	Suggestions of ICSI on Draft IEPFA (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2025	IEPF Authority
30.03.2026	Suggestions of ICSI on Regulatory Framework for the Preferential Issues & QIPs	IFSCA
30.03.2026	Suggestions of ICSI on Regulatory Framework for Rights Issue by Listed Entities	
30.03.2026	Suggestions of ICSI on IFSCA (Prohibition of Market Abuse in Securities Markets) Regulations, 2026	

(v) **Representations submitted for seeking inclusion of the profession of 'Company Secretary' in the definition of "Accountant" given under Section 515(3)(b) of The Income-Tax Bill, 2025**

MINISTRY OF FINANCE	
02.07.2025	Shri Harsh Malhotra, Hon'ble Minister of State, Ministry of Corporate Affairs
OTHER MINISTERS	
02.07.2025	Smt. Raksha Nikhil Khadse, Hon'ble Youth Affairs and Sports Minister of State
02.07.2025	Shri Krishna Prasad Tenneti, Hon'ble Member of Lok Sabha
02.07.2025	Shri Bhubaneswar Kalita, Hon'ble Member of Rajya Sabha
04.07.2025	Smt. Kamaljeet Sehrawat, Hon'ble Member of Lok Sabha
04.07.2025	Shri Amit Shah, Hon'ble Union Minister, Ministry of Home Affairs
07.07.2025	Shri Dinesh Makwana, Hon'ble Member of Lok Sabha
07.07.2025	Shri Shankar Lalwani, Hon'ble Member of Lok Sabha
10.07.2025	Mr. Basavaraj Bommai, Hon'ble Member of Lok Sabha and former CM of Karnataka
11.07.2025	Shri. Pralhad Joshi, Hon'ble Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
MEMBERS OF THE SELECT COMMITTEE OF LOK SABHA ON INCOME TAX BILL, 2025	
27.05.2025	Shri Sudheer Gupta
03.07.2025	Shri Raju Bista
04.07.2025	Shri Bhartruhari Mahtab
07.07.2025	Shri N K Premachandran

(F) STUDENTS, ACADEMIC INITIATIVES AND DEVELOPMENTS

(i) Student Registration

During the period under Report, the number of students registered in CSEET, CS Executive Programme and CS Professional Programme are as follows:

CSEET	
Remote Proctor Mode – 40565	46084
Restructured (Centre Based Examination)-5519	
Executive Programme	31580
Professional Programme	6935

(ii) Company Secretary Executive Entrance Test (CSEET)

CSEET (Restructured): The Institute has taken a major step in transitioning from remote proctored mode to a Centre-Based Examination format from 16 December, 2025. This transition is designed to align the CS profession with emerging corporate, technological, and regulatory developments, while strengthening the foundation for future Company Secretaries. The first session under the new structure was conducted in June 2026.

CSEET Remote Proctored mode: The CSEET Remote Proctored mode tests were conducted four times during the year 2025-26.

(iii) Student Outreach Initiatives

(a) Career Awareness

The Institute organized numerous Career Awareness Programmes (CAPs) across the country at various schools and universities. The Institute also participated in approximately 128 career fairs and exhibitions across India during the period.

To popularize the course and attract fresh talent from remote and rural areas, the Institute expanded its focus on organizing CAPs in rural areas. Furthermore, with the support of the Ministry of Defence, the Institute conducted extensive awareness programmes across various Army Public Schools to sensitize students, parents, and teachers about the profession. Career guidance sessions were also conducted at Higher Secondary Government Schools under the Directorate of Education (DoE), Government of NCT of Delhi, and the Assam State School Education Board (ASSEB).

	A		B		C	
	CAP Conducted	No of Students Attended	Career Fair Conducted	No of Students Attended	Teacher's Conference Conducted	No. of Teachers attended
EIRC	385	68258	20	2706	9	696
NIRC	541	102136	39	10051	13	727
SIRC	604	146701	37	337082	16	1077
WIRC	494	91663	32	11190	18	1100
Total	2024	408758	128	361167	56	3600

(b) Class- Room Teaching(CRT)

The Institute provides Classroom Teaching classes for students of the CSEET, Executive and Professional Programmes through its network of Regional Offices and Chapters nationwide. Additionally, academic institutions empanelled with the Institute as Study Centres are authorized to provide classroom teaching facilities to students in their respective vicinity.

(c) Knowledge on Demand (KOD)

Knowledge on Demand is an initiative of the Institute, providing students with the facility to explore recorded sessions on important topics as per their requirement and update their knowledge at their convenience online on the Institute's LMS platform.

(d) ICSI Master Classes

The Institute organizes specialized Master Classes for Executive and Professional Programme students prior to the commencement of June/December Exam session.

(e) Centralised CSEET Classes

The Institute conducts free Centralized CSEET Classes to support students preparing for the CSEET examination sessions.

(f) Online Doubt Clearing Sessions

To enhance examination readiness, the Institute organized online doubt-clearing sessions for Executive and Professional Programme students ahead of June and December CS examination session

(iv) Yuvotsav

The Institute celebrated its flagship annual national student festival, "YUVOTSAV-2026" (the 26th National Conference of Student Company Secretaries), in Chennai on 11-12 January, 2026, marking the birth anniversary of Swami Vivekananda. Beginning in 2026, the format of Yuvotsav was decentralized, allowing each Regional Office and Chapter to host localized events concurrently with the mega event in Chennai. A total of 24 competitions were organized across four Regional Offices and Seventy-Three Chapters, drawing participation from approximately 2,300 students. The event concluded on 12 January, 2026, with a Youth March followed by the official award ceremony.

(v) Student Month

The month of July is observed annually as 'Student Month' across all ICSI Regional Offices and Chapters. Throughout the month, the Institute hosts quiz contests, online mock tests, crash courses, revision classes, soft skills development programmes, PowerPoint competitions, and life skills sessions, culminating in a dedicated Career Awareness Week. From the year 2026, the Student Month activities have been apportioned across the year and each chapter will be organizing student activities every month throughout the year.

(vi) Awards & Scholarships: ICSI Students Education Fund Trust

To encourage meritorious students from economically weaker backgrounds, the Institute established the 'ICSI Students Education Fund Trust'. Under this Trust, eligible students receive full exemptions from registration, admission, tuition, examination, and pre-examination test fees for both the Executive and Professional Programme stages. Continued exemptions are contingent upon maintaining academic performance standards. During the year,

122 students under the Economically Backward Category and 308 students under the Academically Bright Category benefited from the scheme.

Month	Total Applications	Economically Background	Highly Meritorious	Total Grant released (Rs.)
Apr, 25	35	4	11	2,13,150
May, 25	14	3	7	1,88,000
Jun, 25	18	5	7	1,95,950
Jul, 25	59	9	15	4,40,700
Aug, 25	80	14	34	8,59,950
Sep, 25	105	14	58	12,05,300
Oct, 25	65	10	30	6,46,000
Nov, 25	56	08	27	5,60,200
Dec, 25	73	13	40	8,91,800
Jan, 26	65	18	22	5,04,650
Feb, 26	67	12	26	6,34,900
Mar, 26	66	12	31	6,58,900
Total	703	122	308	69,99,500

(vii) Memorandum of Understanding (MoUs) for Academic Collaboration

To drive nationwide academic excellence and support holistic development, ICSI has entered into institutional agreements with various universities and academic bodies. As part of its 'Academic Connect' initiative, the Institute has signed 150 MoUs, which include strategic partnerships with 17 Indian Institutes of Management (IIMs) and 11 National Law Universities (NLUs).

(viii) Other Initiatives

(a) Olympiads

The following Commerce Olympiads were conducted by ICSI during the period under Report:

- ICSI in association with the International Olympiad Foundation (IOF), conducted the ICSI Commerce Olympiad for students of Classes XI and XII in schools across India on 29 November, 2025.
- ICSI in association with M/s Hummingbird Education Limited, conducted Commerce Olympiad for students of Classes XI and XII in schools across India, on 09 December, 2025.
- ICSI in association with M/s Silverzone Foundation Limited, conducted Commerce Olympiad for students of Classes XI and XII in schools across India, on 07 November, 2025 and 02 December, 2025.

(b) National Online Constitution Day Quiz

In line with the initiative of Department of Legal Affairs, Government of India, the Institute celebrated the "Online Constitution Day Quiz Competition" for students on 26 November, 2025 to create awareness amongst them about the Constitution and its special features, particularly the Fundamental Duties, as enshrined in the Constitution of India.

(c) Online Quiz on Current Affairs and General Knowledge

The Annual 'Online Quiz on Current Affairs & General Knowledge – 2025' was held for senior secondary and undergraduate students across India to evaluate baseline general knowledge, current events, and awareness of the corporate compliances.

(d) All India Company Law Quiz 2025

Designed to enhance conceptual clarity and corporate law visibility among students, the final national round of the All-India Company Law Quiz 2025 was held on 08 November, 2025, in Kolkata.

(e) 24th All India Debate Competition 2025

The national final round of the 24th All India Debate Competition 2025 was organized on 13 November, 2025 at Goa.

(f) 25th All India Essay Writing Competition 2025

To improve corporate writing skills, the 25th All India Essay Writing Competition for Executive and Professional Programme students was hosted by NIRC on 16 June, 2025.

(g) 23rd All India Moot Court Competition 2025

The national round of the 23rd All India Moot Court Competition was held on 22 November, 2025, at Kolkata, featuring qualified regional teams.

(h) Debating Society

To foster public speaking, structured reasoning, and persuasive communication skills, the Institute operationalized the ICSI Debating Society across all Regional Offices and the majority of Chapters during the period under Report.

(i) ICSI Waiver/ Concession Scheme for Indian armed forces, paramilitary forces, Agniveers and families of Martyrs

The ICSI in alignment with the various initiatives of the Government of India launched the ICSI Waiver scheme for Indian armed forces, paramilitary forces, Agniveers and families of Martyrs. Under the scheme, 100% concession is given to the following categories in full fee payable at the time of Registration in CS Executive Programme, while all other fees, including those for trainings being applicable in full as per their respective category:

- Wards and widows of martyrs (who have died during service; either during battle casualty or due to any other reason) of Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy and all para-military forces.
- In Service/ Retired personnel of Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy and all paramilitary forces (including defence personnel who have taken retirement under short service commission).
- Wards of all personnel of Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy and all paramilitary forces (including wards of defence personnel who have taken retirement under short service commission).
- Candidates who are inducted as “Agniveer” under AGNEEPATH Scheme of the Government of India after completing four years under the Scheme (upon submission of documentary evidence for the same).

(j) Webinar Series – An ICSI Initiative to empower aspiring Company Secretaries

The ICSI, with the intent of reviving, refreshing and sharpening the knowledge base of students, had launched a Webinar Series, which has received an overwhelming response from students.

(k) Paper wise exemption on the basis of higher qualifications

In recognition of prior academic achievements and to facilitate academic progression, the Institute introduced paper-wise exemptions for students enrolling in the Company Secretaryship Course under the New Syllabus, 2022. Eligible candidates possessing specified higher academic qualifications were granted exemptions in designated subjects in accordance with the approved guidelines. Detailed instructions regarding eligibility criteria, application procedures, and related provisions were communicated to stakeholders and made available on the Institute's website.

(l) Overseas Examination Centre Support

The Institute continued to facilitate global access to its Executive and Professional Programme Examinations through an overseas examination centre located in Dubai. This initiative enables students residing in the Middle East and neighbouring regions to appear in the examinations without the need to travel to India, thereby enhancing accessibility and convenience.

The Dubai Centre operates in accordance with the same standards, procedures, and examination schedules applicable to centres within India, ensuring uniformity and integrity in the examination process. The continued operation of the overseas examination centre reflects the Institute's commitment to supporting its growing international student community and strengthening the global recognition of the Company Secretary qualification.

(m) Switchover to New Syllabus

To ensure academic relevance and alignment with evolving professional and regulatory requirements, the Institute implemented the New Syllabus, 2022 for the Executive and Professional Programmes. Comprehensive outreach initiatives were undertaken to facilitate a smooth transition for students, including dissemination of information through bulk e-mails, Frequently Asked Questions (FAQs), the Institute's website, social media platforms, and student portals. Detailed guidance regarding eligibility criteria, subject mapping, examination applicability, and transition provisions were provided to stakeholders.

A dedicated online switchover facility was made available through SMASH Portal, enabling students to complete the transition process seamlessly. Academic support was further strengthened through the conduct of hybrid-mode Online Centralised Classes.

(n) Transcripts & Education Verification

With the growing global recognition of the Company Secretary qualification, an increasing number of students are pursuing higher education, professional opportunities, and immigration pathways abroad. During the period under report, the Institute issued 209 transcripts to support applications for higher studies, professional certifications, and international opportunities. In addition, 80 education verification requests received from employers, public sector undertakings, government authorities, and authorised agencies were processed, ensuring timely and accurate verification of academic credentials. These services continue to support the professional mobility of students and members while reinforcing the credibility and recognition of the Institute.

(o) Welcome Back Scheme via Re-Registration

The Institute continued the "Welcome Back" Re-Registration Scheme with the objective of providing eligible students an opportunity to resume their journey towards becoming Company Secretaries. The Scheme is designed for students who have successfully completed the Executive Programme but have not registered for the Professional Programme and whose registration period has expired, rendering them ineligible for *de novo* registration. Under the Scheme, such students are permitted to register directly for the Professional Programme without repeating the Executive Programme, thereby saving valuable time and preserving academic continuity.

(p) Student Amnesty Scheme 2025

With a view to providing former students an opportunity to regularize their academic status and continue their studies, the Institute introduced the Student Amnesty Scheme 2025 with effect from 01 December, 2025. A total of 715 students successfully availed this Scheme from 01 December, 2025 to 31 March, 2026. The scheme provides a valuable opportunity for former students, whose registrations have expired and who are not eligible for Registration De Novo to re-enrol and resume their studies and rebuild their pathway towards qualifying as Company Secretaries by paying a nominal fee of ₹5,000/-. In view of the encouraging response, the duration of the Scheme got extended to 31 August, 2026.

(q) Revision in Eligibility to register for Executive Programme

The Institute has revised the eligibility criteria for registration into the Executive Programme, and accordingly, the persons eligible for registration to Executive Programme are as follows:

- CSEET qualified candidates
- CS Foundation pass students

- Graduates and Post-Graduates
- CMA Final Pass students
- Students appearing in the final year or final semester of undergraduate programmes (03 years)- [Provisional Registration]
- CA Intermediate Pass students
- Students who have passed the 6th semester of any recognized integrated programme (05 years' duration)
- Students who are appearing in the 6th semester of any recognized integrated programme (05 years' duration) [Provisional Registration].

(r) Fee concession for Economically Backward Students (General Unreserved)

The ICSI has introduced Fee Concession for Economically Backward Students. Under this Fee Concession category, Economically Backward Students will get a 50% concession at the time of registration into the Executive Programme of the Company Secretaryship Course. The documents required to avail this concession are an EWS Certificate issued by Tehsildar, Sub-Divisional Magistrate (SDM), District Magistrate (DM), or any other competent authority authorised by the respective State Government & an Income certificate stating that the family income of the student should be less than or equal to Rs. 3,00,000/-.

(ix) Academic Initiatives

i. Updation of Study Material under Syllabus 2022 (For 2025-2026)

- Restructured CSEET Study Material (December 2025): To remain aligned with emerging corporate, technological, and regulatory developments, the Institute undertook a comprehensive review of the CSEET syllabus. The Study Material of four subjects was prepared in alignment with the revised syllabus.
- Study material for Executive Programme and Professional Programme: To keep students abreast of the latest developments and to support their preparation for the upcoming examinations, the study material of Executive Programme (Total of 7 papers) and Professional Programme (Total of 14 papers) were thoroughly updated.

ii. Introduction of Elective Papers under ICSI Syllabus 2022

With a view to ensure more comprehensive and specialized study of the respective subjects, the Institute introduced following elective papers under the Professional Programme. These papers provide in-depth knowledge in niche areas, and equip students with advanced competencies aligned to contemporary corporate, regulatory, and technological developments.

- a) Advanced Direct Tax Laws and Practice (Elective 4.5)
- b) IFSCA- Regulations, Listing and Compliances (Elective 4.6)

iii. Sample Question Papers

As the Institute undertook a comprehensive review of the CSEET syllabus to align it with contemporary requirement, sample question paper for each subject was prepared in line with the revised syllabus, and uploaded on ICSI website under Academic Portal to familiarize the students with the updated exam pattern. Also, as part of the newly introduced elective paper, sample question paper for the paper 'IFSCA- Regulations, Listing and Compliances' was prepared and uploaded on ICSI website under Academic Portal to familiarize students with the examination methodology.

iv. Monthly Updates

In order to educate the students on real time basis, the Institute brought out module wise subject wise monthly updates covering recent regulatory and other developments. This ensures that the students remain continuously informed of dynamic changes in the business, legal and regulatory environment.

v. E-Journals

The e-journals released on monthly basis during the period under Report were Student Company Secretary and CSEET Communique.

vi. Memorandum of Understanding with Gujarat Maritime University

The Institute in association with Gujarat Maritime University (GMU) introduced 'MBA in Maritime Regulations and Compliance Management'. The program aims to navigate the complex legal landscape of maritime law practice, shipping management, marine insurance and international trade. The program is specifically structured for those who are aiming to cultivate advanced knowledge and competencies in maritime regulatory frameworks, with a focus on preparing individuals for roles as compliance professionals in the specialized field.

vii. Memorandum of Understanding with IIT Madras

The Institute entered into an MoU with IIT Madras to provide skills-based courses on SWAYAM/SWAYAM plus platform for students across India. The objective of this collaboration is to facilitate the availability of quality education and foster skill development through effective learning resources. A course on 'Commercial Contract Management and Drafting of Contracts' with approximate 12 Hours of duration was onboarded at SWAYAM Plus portal. The Course is open for public at large including students of the Institute.

(G) MAJOR PROGRAMMES**(i) 26th National Conference of Practicing Company Secretaries**

The Institute organized its 26th National Conference of Practicing Company Secretaries on 14-15 June, 2025 at Vivanta Guwahati on the theme "Dynamic Regulatory Landscape: CS@Excelling Strategies". The Conference was inaugurated by the Chief Guest, Shri Lakshman Prasad Acharya, Hon'ble Governor of Assam. Shri Bhubaneswar Kalita, Hon'ble Member of Rajya Sabha and Shri Dilip Saikia, Hon'ble Member of Lok Sabha also graced the Conference as Special Guests. The Conference witnessed the presence of 400 delegates in person and 3,000 delegates connected virtually from different parts of the country.

(ii) PCS Day 2025

The Institute celebrated PCS Day 2025 on 15 June, 2025 through CCGRTs, Regional Offices and Chapters by organising various programmes on the theme "Dynamic Regulatory Landscape: CS@Excelling Strategies". The members were engaged through panel discussions, seminars, study circle talks, workshops, etc. on the topics befitting the theme.

(iii) GST Day 2025

The Institute celebrates GST Day every year on 01 July in order to create awareness and commemorate the introduction of GST on 01 July, 2017. The Institute celebrated the 8th anniversary of GST Day in July, 2025 through Regional and Chapter offices to sensitise members on contemporary GST topics through panel discussions, seminars and study circle meetings.

(iv) IICA North-East Conclave 2025

The Institute joined hands as institutional partner with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for the IICA North East Conclave 2025 held on 11-12 July, 2025 at Shillong. The theme of the Conclave was 'Ideation to Incorporation'. Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Union Minister of Finance & Corporate Affairs and Shri Conrad K. Sangma, Hon'ble Chief Minister of Meghalaya inaugurated the Conclave as the Chief Guest and Guest of Honour. CS Ranjeet Pandey, Former President, ICSI and CS Ashish Garg, Former President, ICSI represented the Institute at various sessions of the Conclave.

(v) 9th Foundation Day of IEPFA

The Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) organized its 9th Foundation Day in collaboration with the ICSI and National Council of Applied Economic Research (NCAER) on 08 September, 2025 at the India International Centre, New Delhi on the theme "*Claiming the Unclaimed: Unlocking the Potential of Idle Financial Assets in India*". Shri Sanjeev Sanyal, Member of the Prime Minister's Economic Advisory Council, Government of India; Smt. Anita Shah Akella, CEO, IEPFA and Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Government of India; Lt. Col. Aditya Sinha, General Manager, IEPFA & Shri Shobhit Srivastava, General Manager, IEPFA graced the Inaugural Session.

(vi) 57th Foundation Day of ICSI

The ICSI celebrated its 57th Foundation Day on 04 October, 2025, in New Delhi, on the theme ‘Scripting Good Governance, Shaping Viksit Bharat’. Dr. Sudhanshu Trivedi, Hon’ble Member, Rajya Sabha & National Spokesperson of Bharatiya Janata Party, graced the occasion as the Chief Guest and Shri Sanjeev Sanyal, Member, Prime Minister’s Economic Advisory Council, was the Keynote Speaker. The ICSI also felicitated Former Presidents, Vice-Presidents and Secretaries of the Institute on the occasion. Leaders from trade and industry, Senior Corporate Professionals, Directors, Senior Government Officials, Former Presidents and Secretaries of the ICSI, ICSI members, students and employees attended the event, which was also telecasted live on the ICSI Social Media handles.

(vii) 53rd National Convention of Company Secretaries

The Institute organised its 53rd National Convention of Company Secretaries on 31 October, 2025 - 02 November, 2025 on the theme ‘Progressive, Inclusive and Sustainable Bharat’ at Hotel Grand Hyatt Kochi, Bolgatty, Kochi, Kerala. The Convention was graced by Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, Hon’ble Governor of Kerala, Chief Guest, Shri N. K. Premachandran, Hon’ble Member of Lok Sabha, Guest of Honour and Shri M. P. Ahammad, Chairman, Malabar Group, Special Guest. The Convention was attended by around 4,000 delegates from Government, industry, academia and professional fraternity in both physical and virtual mode. Six Technical Sessions and Two Special Sessions were organised during the Convention, which witnessed the presence of eminent speakers comprising Regulators, corporate leaders, industry experts, etc. An Open House session was also organised for interaction of the members with the Council of the Institute.

(viii) One Day Programme for ICLS Officers Trainees

The ICSI organised a One Day Training Programme for Indian Corporate Law Service (ICLS) Officers Trainees at the ICSI Headquarters, New Delhi on 14 May, 2025, pursuant to Indian Corporate Law Service Academy (ICLSA), Ministry of Corporate Affairs communication regarding On-the-Job Training of Indian Corporate Law Service (ICLS) Officer Trainees of 2023 Batch (14th PCP), with various arms of the Ministry in the National Capital Region.

(ix) 8th ICSI Leadership Summit – 2026

The 8th ICSI Leadership Summit - 2026 was successfully organized at Jaypee Greens Golf & Spa Resort, Greater Noida from 30 January - 01 February, 2026. The Summit was attended by the Council Members, the ICSI, Members of the Four Regional Councils, Chairmen of the Chapters of the Institute, Senior Management and officials of the Institute.

(H) INTERNATIONAL FOOTPRINT, BRAND ENHANCEMENT & MEDIA VISIBILITY**(i) INTERNATIONAL FOOTPRINT****(a) International Conferences hosted by the ICSI****ICSI Middle East Conference 2025, Dubai, UAE**

Date	24 – 26 April, 2025
Theme	Good Governance: Empowering Capital Markets
Chief Guest	Shri Ram Nath Kovind Hon’ble Former President of India
Guests of Honour	- Mr. Satish Kumar Sivan, Consul General, Consulate General of India, Dubai - H.E. Dr. Maria Hanif Al Qassim, Assistant Undersecretary of Economic Policies & Studies, Ministry of Economy, UAE - H.E. Mirza Hussain Al Sayegh, Director, Office of H.H. Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum - H.E. Dr. Mohammed Saeed Al Kindi, Senior Vice President, Invescore and Former Minister for Environment & Water, UAE
Partners	Services Export Promotion Council (SEPC)
Study Tour of the Dubai Financial Market (DFM) on 24 April, 2025	

18th International Professional Development & Fellowship Programme (IPDFP) in Sri Lanka

Date	20-27 June, 2025 International Conference was held on 26 June, 2025 in Colombo, Sri Lanka
Theme	Evolution of Corporate Governance in the Digital Age
Special Guest	Mr. Sathananthan Sudarshan, Council Member, Institute of Chartered Corporate Secretaries.

ICSI 4th International Conference

Date	3-4-5 September, 2025
Theme	Embracing Innovation, Enhancing Good Governance
Chief Guest	Dr. S. Janakiraman, Consul General of India in Sydney
Special Guest	Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA
Special Session	Business Opportunities in India's maiden IFSC at GIFT City
Knowledge Partners	- Services Export Promotion Council (SEPC) - Australia India Chamber of Commerce (AICC)
Study Tour	At University of Wollongong, Wollongong Campus on 05 September, 2025
Launched "India–Australia Facilitation Centre" to boost bilateral trade & investments, and help companies of both countries establish offices & subsidiaries across them.	

ICSI Hosts CSIA Global Governance Awards 2026

ICSI organised the Global Governance Awards for Corporate Secretaries International Association (CSIA) Limited, in Mumbai (Maharashtra) on 27 February, 2026. The 2026 Awards honoured the trailblazers of responsible governance across CSIA's twelve member countries, celebrating individuals and corporates that are actively shaping the future of governance in an era defined by regulatory complexity, ESG accountability, and digital transformation. Building on the momentum, the Award Ceremony began with two panel discussions on ESG & Ethics and AI & Technology.

More than 150 delegates from different countries witnessed the celebration of achievements, inspiring commitment to governance and reinforcing the foundation on which global commerce stands.

Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme

The ICSI organized a 12-day Capacity Building Programme on "*Corporate Governance for a Better Tomorrow: Empowering Leaders in Compliance, Risk & Sustainability*" under the auspices of the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme of the Ministry of External Affairs, Government of India, from 14–25 January, 2026 at the ICSI-CCGRT, Kolkata. A total of 18 delegates from 16 countries across the globe participated in this residential programme. Renowned Company Secretaries and subject-matter experts from various parts of the country conducted engaging and insightful sessions. As part of the programme, participants had the opportunity to interact with Shri R. K. Tiwari, Regional Director (Eastern Region), Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

(b) ICSI's participation in International Conferences**IOD UAE Global Convention 2025**

Theme	Boards in a Rapidly Changing World: Innovative Strategies for Resilience and Sustainability
Date	22-25 April, 2025
Location	Dubai, UAE
Organization	Institute of Directors (IOD)

29th Annual International Conference of Institute of Certified Secretaries of Kenya

Theme	Ethical Leadership & Good Governance - Restoring Trust, Renewing Morals, Securing the Future
Date	23-25 April, 2025
Location	Mombasa, Kenya
Organization	Institute of Certified Secretaries of Kenya

OECD-Asia Roundtable on Corporate Governance

Theme	Corporate Governance
Date	27-28 November, 2025
Location	Bangkok, Thailand
Organization	Institute of Directors (IOD)

Programmes hosted by ICSI Middle East (DIFC) NPIO

Programme	Study Circle Meet
Date	29 May, 2025
Theme	UAE Corporate Tax
Venue	Al Moosa Tower, Dubai

Programme	ICSI Middle East (DIFC) NPIO Conference
Date	11 October, 2025
Theme	AI & Corporate Excellence – Insights for the Future
Venue	Villa Rotana, Sheikh Zayed Road, Dubai

Programme	ICSI Middle East (DIFC) NPIO Conference
Date	13 December, 2025
Theme	Governance Beyond Borders: Shaping Global Standards from the Middle East
Chief Guest	Mr. Abdulla Al Saleh, Under Secretary, Ministry of Economy, UAE
Guest of Honour	Mr. B.G. Krishanan, Consul (Economic, Trade, Commerce & Education), Consulate General of India, Dubai

(c) ICSI International Webinars

In association with	Date	Topic
ICSI Middle East (DIFC) NPIO, Dubai	21.6.2025	Understanding Crypto and AML compliance
ICSI Middle East (DIFC) NPIO, Dubai	30.8.2025	E-Invoicing in the UAE- Journey towards Digital Economy
ICSI Middle East (DIFC) NPIO, Dubai	27.9.2025	Family Assets, Protection & Succession Planning- DIFC Structures
ICSI Overseas Centre, UK	13.11.2025	UK new regulatory requirement- Director Identity Verification Process
ICSI Middle East (DIFC) NPIO, Dubai	21.02.2026	UAE E-invoicing- Legal Compliance Aspects
ICSI Middle East (DIFC) NPIO, Dubai	14.03.2026	Mental Health - Calm Within Chaos
ICSI Overseas Centre, UK	26.03.2026	Navigating the UK Governance Space – CV Writing and Interview Techniques
ICSI Middle East (DIFC) NPIO, Dubai	28.03.2026	New UAE AML Law

(d) International Synergy

- **ICSI inks MoU with Services Exports Promotion Council (SEPC):** ICSI entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with SEPC to leverage India's strength in Corporate Governance, Compliance, and Secretarial Advisory Services. Aimed at providing customized training programmes to meet global standards, the MoU seeks to open new avenues for ICSI members and give them an access to the global markets, besides facilitating joint research, resource sharing and collaboration in international events.
- **IOD 2025 London Global Convention:** ICSI partnered with the Institute of Directors (IOD) for 2025 London Global Convention on Corporate Governance and Sustainability, held on 04-07 November, 2025, in London, United Kingdom.
- **Special Opportunity for ICSI Members to enrol in CIMA's Senior Executive Programme (SEP):** The ICSI members can now attain the globally acclaimed Chartered Global Management Accountant (CGMA) designation by directly enrolling in the Senior Executive Programme (SEP) offered by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), UK and clearing just two papers out of a total of sixteen papers. The Senior

Executive Programme equips experienced professionals with the tools to navigate complex market changes and develop strategic business skills to their fullest potential. ICSI signed a Letter of Intent (LoI) with the CIMA in September 2025 to offer ICSI members pathways to gain the CIMA qualification.

- **Representation of ICSI in CSIA:** CS Dhananjay Shukla, Immediate Former President, ICSI has been unanimously elected as the Vice President of Corporate Secretaries International Association (CSIA), for the year 2026. CSIA represents more than 1,00,000 Corporate Secretaries and Governance Professionals in over 100 countries in the world.
- **ICGN Jury:** The ICSI has been serving as the jury for the International Corporate Governance Network Global Governance and Stewardship Awards, that recognize and honour exceptional accomplishments of individuals as well as companies across the globe in Corporate Governance and Investment Stewardship. This year, the ICSI served as an independent judge on the judging panels for ICGN 2025 Achievement Awards and the Global Stewardship Disclosure Awards.

(e) Visit of International Delegations to ICSI

- **Kenyan Delegation:** A delegation from Institute of Certified Secretaries, Kenya and from Kenya Accountants and Secretaries National Examinations Board (KASNEB) visited the ICSI Headquarters, New Delhi on 28 October, 2025, to discuss strategies for enhancing Corporate Governance in Kenya, identifying opportunities for mutual collaboration and for benchmarking CS Course, Training and Examination framework of the ICSI, for strengthening their own syllabus, training and examination process.
- **ICGN Delegation:** ICGN delegation led by CEO Ms. Jen Sisson, visited the ICSI Headquarters, Delhi on 18 November, 2025 to discuss & devise a collaborative plan for enhancing global Corporate Governance & Sustainability policies and framework. ICGN delegation led by CEO Ms. Jen Sisson, visited the ICSI Headquarters in New Delhi on 09 March, 2026 to explore areas of joint research and develop a roadmap for best practices in good governance, stewardship, and stakeholder engagement.

(ii) ENHANCING BRAND EQUITY

(a) Brand Visibility and Media Outreach

The ICSI has undertaken various image building initiatives to promote and enhance the brand ICSI by ensuring coverage of all the ICSI Events, initiatives and developments related to the profession in the Print/ Electronic/Digital Media through Press Releases, Press Conferences, Media Interactions, Web Portals and Social Media Handles of the ICSI.

Particulars	Number
Press Coverage of ICSI events, announcements	Over 930
Press Conferences	19
Coverage in Electronic Media and Special Episodes	24
Number of Videos Created for Brand Promotion	16
ICSI Pulse – Think Governance Think ICSI (Podcast Series)	10
Reels	35

(b) Career Feature/ Articles on Career as a Company Secretary

Special Feature on “Career as a Company Secretary” has been published in regional languages for wider reach in leading Newspapers/ Journals across India – Prajavaani, Divya Bhaskar, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran, Divya Marathi, Malayala Manorama, Dharitri, Indore Samachar, Prabhat Khabar, Rajasthan Patrika, Week Magazine, The Telegraph, Rozgar aur Nirman, Business Standard, IOD Board Stewardship Journal, Aaj, Jagran Josh, Education Times, Careers360 Magazine, Competition Refresher.

(c) Social Media Presence

ICSI Social Media Platforms have significantly strengthened ICSI & the CS Profession as a brand. All announcements and information related to ICSI Events has been disseminated through around 1100 posts on ICSI Social Media Platforms, viz., Facebook, X, LinkedIn, Instagram, Threads and WhatsApp. Videos of ICSI Webinars, Crash Courses, Chartered Secretary Journal Articles and other branding activities were uploaded on ICSI YouTube Channel, ensuring increased reach and publicity. The table as placed hereunder depicts the reach of the Institute in terms of followers on social media:

Social Media Portals	Followers
Facebook https://www.facebook.com/ICSI	1,30,000
X (earlier Known as Twitter) https://twitter.com/icsi_cs	94,547
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/theicsi/	54980
Instagram https://www.instagram.com/theicsi/	78100
YouTube https://www.youtube.com/user/TheCsInstitute	97880
YouTube (Students) https://www.youtube.com/@icsiyoutubechannelforstude2052	30500
Threads https://www.threads.net/@theicsi	11100
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va9qP1lD8SE69ZDQvW3F	98500

(d) Meeting with Major Dignitaries

- Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, Hon'ble Governor of Kerala
- Shri Lakshman Prasad Acharya, Hon'ble Governor of Assam
- Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of Finance & Corporate Affairs
- Shri Bhupender Yadav, Hon'ble Minister for Environment, Forest & Climate Change
- Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Minister of Ports, Shipping & Waterways
- Shri Gajendra Singh Shekhawat, Hon'ble Minister of Culture and Tourism
- Shri Jitan Ram Manjhi, Hon'ble Minister of Micro, Small and Medium Enterprises
- Shri G Kishan Reddy, Hon'ble Union Minister for Coal and Mines
- Shri Jyotiraditya M. Scindia, Hon'ble Union Minister for Communication and Development of the North Eastern Region
- Shri Chirag Paswan, Hon'ble Minister of Food Processing Industries
- Shri Harsh Malhotra, MoS for Corporate Affairs & Ministry of Road, Transport & Highways
- Shri Pankaj Chaudhary, Hon'ble MoS for Finance
- Smt. Raksha Khadse, Hon'ble MoS for Youth Affairs & Sports
- Smt. Savitri Thakur, Hon'ble MoS for Women and Child Development
- Shri Ramnath Thakur, Hon'ble Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare
- Shri Satish Chandra Dubey, Hon'ble Minister of State for Coal and Mines
- Shri Sanjay Seth, Hon'ble Minister of State for Defence
- Shri Ravi Shankar Prasad, Hon'ble Member, Lok Sabha & Former Union Minister
- Shri Baijayant Jay Panda, National Vice President, BJP & Hon'ble Member of Lok Sabha
- Shri Shashi Tharoor, Member of Parliament, Lok Sabha
- Shri Sudhir Gupta, Hon'ble Member of Parliament
- Shri Faggan Singh Kulaste, Member of Parliament, Lok Sabha
- Dr. Amar Singh, Hon'ble Member of Lok Sabha
- Shri Rampreet Mandal, Hon'ble Member of Lok Sabha
- Shri Jagdish Shettar, Hon'ble Member of Parliament
- Shri Giridhari Yadav, Hon'ble Member, Lok Sabha
- Shri Arvind Sawant, Hon'ble Member of Lok Sabha
- Shri B. Y. Raghavendra, Hon'ble Member of Lok Sabha
- Shri Daggumalla Prasada Rao, Hon'ble Member of Lok Sabha
- Shri Kaushalendra Kumar, Hon'ble Member of Lok Sabha & Select Committee Member, Income-Tax Bill, 2025
- Shri Krishna Prasad Tenneti, Hon'ble Member of Lok Sabha
- Shri Rodmal Nagar, Hon'ble Member of Lok Sabha

- Shri Shankar Lalwani, Hon'ble Member of Lok Sabha
- Smt. Supriya Sule, Hon'ble Member of Lok Sabha
- Shri Suresh Kashyap, Hon'ble Member of Lok Sabha
- Shri Vishweshwar Hegde Kageri, Hon'ble Member of Lok Sabha
- Shri Pradeep Kumar Singh, Hon'ble Member, Lok Sabha
- Shri Rajesh Verma, Hon'ble Member, Lok Sabha
- Shri Manoj Tiwari, Hon'ble Member, Lok Sabha
- Dr. Bhagwat Kishanrao Karad, Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha
- Shri Upendra Kushwaha, Hon'ble Member, Rajya Sabha
- Dr. Bhim Singh, Hon'ble Member, Rajya Sabha
- Dr. Dharmshila Gupta, Hon'ble Member, Rajya Sabha
- Shri Deepak Prakash, Hon'ble Member, Rajyasabha, Co In-charge, BJP Bihar & Ex State President, BJP Jharkhand
- Shri Devesh Chandra Thakur, Hon'ble Member, Lok Sabha
- Shri Sanjay Jaiswal, Hon'ble Member, Lok Sabha
- Shri Rampreet Mandal, Hon'ble Member, Lok Sabha
- Shri Dileshwar Kamait, Hon'ble Member, Lok Sabha
- Shri Bhupendra Patel, Hon'ble Chief Minister of Gujarat
- Dr. Pramod Sawant, Hon'ble Chief Minister, Goa
- Shri Suresh Prabhu, Former Cabinet Minister
- Smt. Smriti Z. Irani, Former Cabinet Minister
- Dr. Justice D Y Chandrachud, Hon'ble Former Chief Justice of India
- Dr. S. Janakiraman, Consul General of India in Sydney
- Shri Rajnish Kumar Singh, Member of Legislative Assembly, Government of Bihar

(I) INFRASTRUCTURE

A. Projects at Headquarters (HQs) level

1. **CCGRT-Manesar premises:** CCGRT Premises was inaugurated and put-to-use w.e.f. 11 December, 2025.
2. **ICSI-HQ Noida:** Repairing / Structural strengthening of fire escape staircase and external development work of Institute's building at C-36, Sector – 62, Noida in progress.
3. **CCGRT-Mumbai:** The Council has approved for fixing of priority for Construction of New Building of CCGRT, Mumbai by demolishing the existing building. The proposals for the execution of project received from various Govt. agencies.

B. Major Projects at Regional/Chapter Offices

1. **Hyderabad Chapter** – Bhoomi Puja / Foundation Stone Laying Ceremony for commencement of the construction work of Hyderabad Chapter's new building done on 20 April, 2025 at the hands of Shri G Kishan Reddy, Hon'ble Union Minister for Coal and Mines. As on 31 March, 2026, the construction work for Hyderabad new building after demolition of old building is nearing completion.
2. **Raipur Chapter-** The Bhoomi Puja / Foundation Stone laying ceremony for the commencement of construction work was done on 14 January, 2026 by Shri Arun Sao, Hon'ble Deputy Chief Minister, Government of Chhattisgarh along with Shri Nand Kumar Sahu, Chairman, Raipur Development Authority. The construction work is in progress.
3. **Kanpur Chapter-** The work for construction of building for Kanpur Chapter was awarded to M/s NBCC (India) Limited vide Agreement dated 28 November, 2025 on deposit work basis. The Bhoomi Puja / Foundation Stone laying ceremony was held on 17 January, 2026, and the construction work of the building is in progress.
4. **Lucknow Chapter-** The work for construction of building for Lucknow Chapter was awarded to M/s NBCC (India) Limited vide Agreement dated 28 November, 2025 on deposit work basis. The Bhoomi Puja / Foundation Stone laying ceremony was held on 17 January, 2026, and the construction work of the building is in progress.

5. **Kochi Chapter (2nd Phase)**- The Council approved the extension of 2nd floor of Kochi Chapter building in 2nd phase. Pre-construction activities including finalisation of design etc. for 2nd phase is in progress.

C. Acquisition of New Premises/Hiring of space for other locations

1. **Gandhinagar GIFT City:** An office premises for Gandhinagar (GIFT City) Chapter was established by hiring of space on lease at Gujarat International Finance Tec-City, Gandhinagar, Gujarat on 27 August, 2025, thereby making ICSI, the first professional Institute to establish its physical presence in GIFT City.
2. **Gurugram Chapter:** The Institute participated in the e-auction of land from Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP) and was declared as the successful bidder. The Letter of Intent for allotment of land was given by HSVP.
3. **Request letters** submitted to respective Authorities for allotment of the following Chapters:

Chhatrapati Sambhaji Nagar Ahmedabad Madurai Srinagar	Agra Nagpur Indore Goa	Amaravati Jammu Bareilly	Gurugram Visakhapatnam Jodhpur
--	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

4. **Property selection** under process through Expression of Interest (EoI) at following locations:
 - a) **Thrissur** – Selection of the premises/ property has been done through Expression of Interest (EoI) after due diligence of the shortlisted property.
 - b) **Nashik** – As on 31 March, 2026, the due diligence of the shortlisted property was completed.
 - c) **Thiruvananthapuram** – Shortlisting of the premises/ property has been done through Expression of Interest (EoI).
 - d) **Pune** - Selection of the premises/ property has been done through Expression of Interest (EoI) and after following due process The project cost and means of finance for acquisition of selected property was approved by the Council.
 - e) **Hooghly**- Selection of the premises/ property has been done through Expression of Interest (EoI) and due diligence, and other legal works are in process to acquire the selected premises/ property.
 - f) **Kozhikode**- Selection of the premises/ property has been done through Expression of Interest (EoI) and due diligence, and other legal works are in process to acquire the selected premises/ property.
 - g) **Surat** - Selection of the premises/ property has been done through Expression of Interest (EoI) and due diligence, and other legal works are in process to acquire the selected premises/ property.
 - h) **Ahmedabad** - Follow up with the Ahmedabad Urban Development Authority for the allotment of plot at concessional rate.
 - i) **Chhatrapati Sambhaji Nagar** - The selection of property through Expression of Interest (EoI) is in progress.

D. Disposal of old premises in process for:

EIRO Office Building- Tender notice was issued for disposal of the EIRO's old premises in newspapers (English; Bengali and Hindi), Kolkata editions.

(J) SPECIFIC INITIATIVES**(i) QUICK RESPONSE & RESOLUTION TEAM (QRRT)**

The Quick Response & Resolution Team (QRRT) functions as a single point of contact for members and students, facilitating timely and hassle-free resolution of queries and grievances. QRRT has published the ICSI Service Charter with details of the Turnaround Time (TAT) for various services provided by the ICSI.

QRRT operates through a robust Management Information System (MIS) that captures critical details such as ticket number, date, stakeholder information, concern area, resolution provided, and closure date.

(ii) HUMAN RESOURCES**(a) Employee Development**

In order to enhance the capabilities & effectiveness of the employees of the Institute to meet and exceed the expectation of stakeholders and to provide efficient services, efforts have been made for continuous training and updation of knowledge & skills of the employees, covering areas such as soft skills and interpersonal effectiveness, digital marketing, artificial intelligence, negotiation skills, and financial and ERP systems. The Institute also places significant focus on the holistic well-being of its workforce. Regular webinars and health talks were organised in association with leading hospitals and healthcare foundations, covering a wide range of topics relating to physical health, lifestyle management and preventive care.

(b) Spandan, 2025

The Institute successfully organized “SPANDAN”, a mega Sports, Arts & Cultural Fest exclusively for ICSI employees, from 13 September, 2025 to 16 October, 2025. The event featured a wide range of sports and cultural activities aimed at fostering teamwork, creativity, and employee engagement. Sports competitions included the Cricket T10 Series, Badminton, Table Tennis, Carom, Chess, and Arm Wrestling, while arts and cultural events comprised Solo Singing, Solo Dance, Group Dance, Poster Making, and Ramp Walk. The Grand Finale for the cultural events was held at the Noida Office on 16 October, 2025. SPANDAN 2025 received an overwhelming response from employees across the Institute, who participated with great enthusiasm and spirit, making the festival a resounding success and a memorable platform for showcasing talent and camaraderie.

(c) Women’s Day, 2026

As part of the International Women’s Day Celebration on 08 March, 2026 and to celebrate Womanhood and to appreciate the immense contribution of women employees; the Institute celebrated the same by presenting a gift as a token of appreciation to all women employees on this occasion, across all ICSI offices on pan India level.

(d) Service Award

The Institute organized Service Award Functions to recognize and honor employees who completed 15, 20, 25, 30, and 35 years of dedicated service to the Institute. Employees who became eligible for the awards as on 01 July, 2025 and subsequently as on 01 January, 2026 were felicitated during the Service Award Functions, wherein, they were presented with Appreciation Letters, Mementoes, and Service Award Certificates as tokens of the Institute’s gratitude and recognition of their valuable contributions.

(e) Recruitment

In order to further strengthen the ICSI team, the following officials were recruited during the period under Report:

S. No.	Post	No. of officials recruited
1.	Joint Directors	03
2.	Deputy Director (Academics)	02
3.	Executive Assistant	10

(f) Employee Strength

As on 31 March, 2026, the manpower strength of the Institute stood at 372 including 104 female employees which comprised 28% of the total manpower strength.

(g) Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

Report of Cases under The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 for the Financial Year 2025-2026

Description	Headquarters	NIRO and its Chapters, ICSI-CCGRT, Manesar	EIRO and its Chapters, ICSI-CCGRT, Kolkata	WIRO and its Chapters, ICSI-CCGRT, Mumbai	SIRO and its Chapters, ICSI-CCGRT, Hyderabad
Number of complaints of sexual harassment received	01	Nil	Nil	Nil	Nil
Number of complaints disposed of	01	NA	NA	NA	NA
Number of cases pending for more than ninety days	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Number of workshops or against sexual harassment carried out	01	01	01	01	01
Nature of action taken by the employer	NA	NA	NA	NA	NA

(iii) INFORMATION TECHNOLOGY

The Institute continued its commitment towards leveraging Information Technology for enhancing operational efficiency, strengthening digital governance, improving stakeholder services, and ensuring cybersecurity compliance during the period under Report. The Institute undertook several initiatives aimed at process automation, digital transformation, infrastructure modernization, cloud adoption, and implementation of advanced technologies to support the Institute's strategic objectives.

The Institute further strengthened its IT ecosystem through continuous upgradation of hardware, software, network infrastructure, security systems, and management information systems. Special emphasis was laid on cybersecurity, business continuity, cloud migration, stakeholder convenience, and data-driven decision-making.

Recognizing the growing importance of information security and technological innovation, the Institute undertook the following major initiatives during the year:

- Business Process Reengineering: The Business Process Reengineering (BPR) initiative shall include a study of the existing processes and a survey of best practices adopted by professional educational institutions and the education sector internationally. Based on this analysis of processes, IT requirements, and global best practices implementation of a Single Sign-on Integrated Software System for Students, Members, Employees and other Stakeholders through BPR.
- Acquisition and maintenance of Security Audit Compliance Certificates for critical applications including ERP, STIMULATE Portal, Placement Portal and Disciplinary Portal.
- Completion of comprehensive Data Centre IT Infrastructure Audit and implementation of audit recommendations.
- Enhanced cybersecurity measures.
- Migration of the Disciplinary Mechanism Software Application to AWS Cloud for improved scalability, availability and security.
- Upgradation of network infrastructure including routers, Internet Lease Line (ILL) bandwidth and migration from MPLS to ILL for Video Conferencing systems.

(iv) EXAMINATIONS**(a) Conduct of Examinations**

During the period under Report, Company Secretaries Examinations for Executive Programme and Professional Programme were held at 225 and 228 Examination Centres respectively all over India and one overseas Examination Centre at Dubai in June and December 2025 sessions of Examinations respectively. A total number of 63523 and 69338 candidates sought enrolment for appearing in June and December, 2025 sessions of Examinations respectively. The number of candidates who successfully completed the various stages of Examinations during the year 2025-26 is mentioned hereunder:

Stage of Examination	June, 2025	December, 2025
Executive Programme	2913	4015
Professional Programme	2477	2271

The list of cities for examination centres is given in [Annexure-C](#). The statistics relating to Examination Results are mentioned hereunder:

COMPANY SECRETARIES' EXAMINATION - JUNE, 2025			
RESULT ANALYSIS			
Stage of Examination	Number of Candidates		
	Enrolled	Appeared	Pass
<i>Professional programme (syllabus 2017) *</i>			
Module – I	2301	1662	494
Module – II	2932	2286	660
Module – III	2321	1719	491
<i>Executive Programme (Syllabus 2022) **</i>			
Group – 1	29978	23575	3439
Group – 2	25049	19114	4747
<i>Professional Programme (Syllabus 2022) ***</i>			
Group – 1	9546	8053	2026
Group – 2	9047	7193	1897
* 572 Candidates enrolled; 438 Candidates appeared for Professional programme (Syllabus 2017)- All Modules, out of which 7 candidates passed All modules.			
** 10158 Candidates enrolled; 8603 Candidates appeared for Executive Programme (Syllabus 2022)- Both Groups, out of which 918 candidates passed for Both Groups.			
*** 4860 Candidates enrolled; 4396 Candidates appeared for Professional Programme (Syllabus 2022)- Both Groups, out of which 410 candidates passed for Both Groups.			
COMPANY SECRETARIES' EXAMINATION - DECEMBER, 2025			
RESULT ANALYSIS			
Stage of Examination	Number of Candidates		
	Enrolled	Appeared	Pass
<i>Executive Programme (Syllabus 2022) *</i>			
Group – 1	32620	25325	4571
Group – 2	28154	21301	4744
<i>Professional Programme (Syllabus 2022) **</i>			
Group – 1	14125	11622	3125
Group – 2	13113	10156	2711

* 10973 Candidates enrolled, 9124 Candidates appeared for Executive programme-Both Groups, out of which 633 candidates passed Both Groups.			
** 7701 Candidates enrolled, 6839 Candidates appeared for Professional Programme- Both Groups, out of which 703 candidates passed for Both Groups.			

(b) Company Secretary Executive Entrance Test (CSEET)

During the period under Report, CSEET was held in the months of May 2025, July 2025, November 2025 and January 2026. The number of Candidates who successfully completed CSEET is mentioned as under.

Examination Session	Number of Candidates		
	Enrolled	Appeared	Passed
May 2025	8892	7532	4452
July 2025	12057	10991	6584
November 2025	15366	13701	8890
January 2026	9363	8840	6031

(c) New Examination Centre for June 2025 and December 2025 session of Examination

A new Examination Centre was opened at Shimoga (Karnataka,349) for December 2025.

(d) All India Prize Awards

In order to inspire and recognize the brilliant performance of students in Company Secretaries Examinations, the Institute has instituted a number of Awards including President's Gold Medal, President's Silver Medal and Pt. Nehru Birth Centenary Annual Award.

Session	Medal	Recipient	Centre
June, 2024	President's Gold Medal for Professional Programme	Ms. Bhumika Singh	Meerut
	President's Silver Medal for Executive Programme	Ms. Bhumi Vinod Mehta	Mumbai
	Pt. Nehru Birth Centenary Annual Award	Ms. Bhumika Singh	Meerut
December, 2024	President's Gold Medal for Professional Programme	Ms. Yashee Dharam Mehta	Thane
	President's Silver Medal for Executive Programme	Ms. Khushboo Kunwar	Udaipur
June, 2025	President's Gold Medal for Professional Programme	Ms. Bhumi Vinod Mehta	Mumbai
	President's Silver Medal for Executive Programme	Ms. Tithi Bohra	Jaipur
	Pt. Nehru Birth Centenary Annual Award	Ms. Bhumi Vinod Mehta	Mumbai

The particulars of other prize Award Winners along with existing All-India Prize Schemes, Regional and Chapter Prize Schemes are hosted on the Institute's website.

(e) Merit Certificates/ Merit Scholarships/ Financial Assistance

Rank Certificates were awarded to 25 top-ranked successful students in Executive Programme and Professional Programme Examinations held in June, 2025 and December, 2025 sessions of Examinations. Pursuant to Merit Scholarship Scheme, Scholarships were awarded to the toppers qualifying all papers of Executive Programme in the first attempt in June, 2025 and December, 2025 session of Examination for pursuing further studies for the Professional Programme of Company Secretaryship course. Likewise, under the Merit-cum-Means Assistance Scheme, financial assistance was granted to eligible candidates considering their economic background and meritorious performance in June, 2025 session of Examination. No candidate was found eligible for the scheme in December 2025 session.

(v) TRAINING

During the period under Report, numerous initiatives and activities were undertaken by the Institute to facilitate the students pertaining to Short Term and Long-Term trainings, as mentioned hereunder:

- **Samadhan Diwas:** With an objective to provide “on-the-spot” resolution to issues/grievances of students registered with ICSI, Samadhan Diwas is being organised on the second Wednesday of each month. Samadhan Diwas serves as an engaging platform for students to communicate directly with ICSI officials to address their concern regarding various trainings as prescribed under ICSI Student Training Guidelines.
- **Short Term Trainings:**
 - (a) Introduction of Student Induction Programme (SIP): The students registering for the CSEET on or after 16 December, 2025, are required to undergo one day Student Induction Program (SIP) within 1 month of their registration. SIP has been introduced as one day orientation programme to guide students about the journey in CS course. Attending and completing SIP is a pre-requisite for enrolling in the CSEET examination. Further, SIP in online mode has been implemented through ICSI e-learning LMS Portal.
 - (b) Three Days Orientation Programme (TDOP): The students registering in the Executive Programme are required to mandatorily complete their TDOP within three months of their registration.
- **Revision in the manner and mode of undergoing CLDP:** The Institute has revised the manner and mode of undergoing 30 days CLDP w.e.f. 15th December, 2025. CLDP has to be completed in the following order:
 - CLDP Phase I- 15 days CLDP in Classroom Mode (Non-Residential)
 - CLDP Phase II- 15 days CLDP in Classroom Mode (Residential)
- **Awarding of the Associate Membership upon completion of CLDP:** To facilitate CS Students the Institute has introduced the awarding of Associate Membership number on the last day of CLDP Phase – II (Residential) at the valedictory session.
- **Expanded the purview of Alternate Mode of CLDP:** To effectively address the existing challenges while enhancing accessibility and creating greater opportunities for students to attain membership, the ICSI has further expanded the scope of alternative pathways for the completion of the Corporate Leadership Development Programme (CLDP). The eligibility criteria is available under the ICSI Student Training Guidelines, 2024 on the website of the Institute.

(vi) PLACEMENT

The ICSI remains committed to facilitating a seamless, time-bound, and mutually beneficial recruitment process for companies and firms seeking to hire Company Secretaries and CS Trainees. Through its dedicated placement and recruitment support initiatives, the Institute strives to assist organizations in meeting their talent requirements efficiently while enabling its members and students to secure suitable career opportunities. It is the Institute’s constant endeavour to serve all stakeholders to the best of its capacity by creating a conducive platform that fosters meaningful engagement between recruiters and aspiring professionals, thereby establishing a strong and synergistic connection that benefits both employers and candidates. The Registrations and Postings at Placement Portal during the period under Report is as follows:

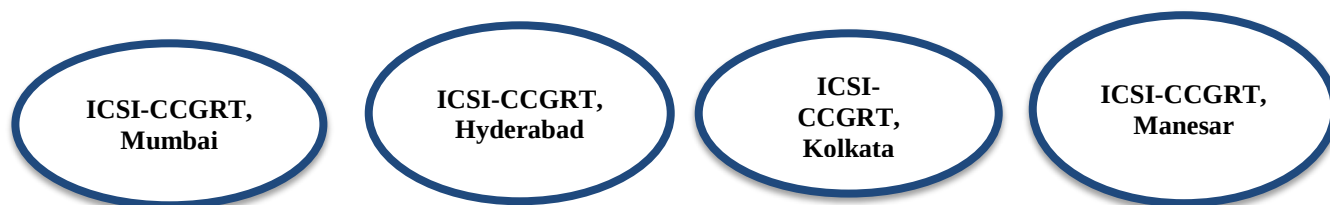
Registered Users			Total No. of Vacancies	
Members	Students	Corporates	Jobs	Trainings
2,178	5,252	1,046	2,523	3,956

Numerous activities were undertaken to ensure increase in Placement opportunities for the Members and Students of the Institute. Major initiatives include the following:

- **Handling requirements for Company Secretaries and CS Trainees at various Government Offices:** Requests were received from offices of the Ministry of Corporate Affairs/ CPSE/ PSUs and other Government entities regarding the position of Company Secretary, Young Professionals and CS Trainee. Resumes of eligible Members and Students were sent to them accordingly.
- **ICSI HR Conclaves:** HR Conclaves were organised by ICSI at Chennai, SIRO on 04th December, 2025 and Bengaluru Chapter on 13th December, 2025 to make the HR community aware about CS Profession and role of Company Secretaries.
- **ICSI Alumni Meets:** ICSI Alumni Meets were organised by ICSI at Bengaluru Chapter on 08th November, 2025 and Mumbai, WIRO on 21st November, 2025.

- **Campus Placement Drives:** The Campus Placement Programme of the Institute provides a unique opportunity to Corporates to peruse the profiles of qualified young and experienced Company Secretaries and Students, assess their capabilities and select suitable Candidates as per their requirements.
- **Mega Placement Drives:** The ICSI conducted the Mega Placement Drive – I, 2025 at its Regional Offices and ICSI CCGRTs during the month of July, 2025. The drive witnessed the active participation of various recruiters (including Organisations and PCS firms) and job seeking Members of the ICSI. Further, the ICSI conducted the Mega Placement Drive – II, 2025 at its Regional Offices and CCGRTs during the month of November, 2025. The Mega Placement Drive – II, 2025 received an encouraging response from Recruiters and Members across India. A total of 74 recruiters, comprising of Corporates, Organizations and Practising Company Secretary (PCS) firms, registered for the drive. More than 133 Members participated on pan-India basis, reaffirming the role of ICSI as a significant platform for connecting talent with employment opportunities in the Company Secretary profession.
- **STEP ON: Skill Enhancement Workshop:** The Institute organized STEP ON: Skill Enhancement Workshop on 30 - 31 August, 2025, at ICSI House, Sector 62, NOIDA. In collaboration with specialized agencies dedicated to career acceleration, this exclusive programme has been designed thoughtfully and delivered by industry experts in Communication, Presentation Skills, and Interview Preparedness. It offers a unique opportunity for aspiring NextGen Company Secretaries to enhance their professional competencies, build confidence and gain a distinct competitive advantage in today's dynamic job market. The 14 hours workshop was a focused learning programme covering the following high-impact Professional Skills by specialised agencies, viz., Communication Skills, Presentation Skills, Etiquette & Grooming and Negotiation & Client Handling.
- **CS Trainee Drives:** CS Trainee Drives were conducted throughout the year on a pan-India basis in both physical and virtual modes across the Regional Offices, CCGRTs, and Chapters of the Institute. The Trainee Drives attracted participation from organizations, Practising Company Secretaries (PCS), and other firms from across the country, which registered their training requirements through various ICSI Regional Offices, CCGRTs and Chapters. These initiatives provided a valuable platform for connecting aspiring Company Secretaries with prospective training Organizations, thereby facilitating Professional Learning and Career Development Opportunities.

(K) CCGRTs



The ICSI-CCGRTs are set up with the objective of fostering quality research, thereby nurturing the growth and development of Students and Members of the Institute.

(i) ICSI-CCGRT, Mumbai

The details of various Programmes / seminars organised during the period under Report are mentioned hereunder:

S. No.	Date	Programme
1	26 April, 2025	Workshop on the NBFCs Governance, Risk & Compliance Requirements and Role of CS
2	24-25 May, 2025	Two-Days Residential/Non-Residential Workshop on Compliances under SEBI LODR
3	21-22 June, 2025	Two-Days Residential/Non-Residential Workshop on Intellectual Property Rights
4	02-03 August, 2025	Two-Days Residential/Non-Residential Workshop on SME Listing
5	19-20 September, 2025	Two Days Joint Workshop on Research on Critical Issues under the Companies Act, 2013 at Ujjain jointly with Indore chapter
6	15-16 November, 2025	Two days Residential/Non-Residential Workshop on FEMA
7	27 November, 2025	ICSI-CCGRT, Mumbai as Association Partner with Indian Chamber of Commerce participated in 4th ICC Conclave on the 'National Pension System'
8	10-11 January, 2026	Two-Days Residential/Non-Residential Workshop on Intricacies of ESG
9	14-15 February, 2026	Two-Days Residential/Non-Residential Workshop on AI for CS
10	08 March, 2026	Non-Residential Workshop on PoSH Act, 2013
11	21-22 March, 2026	Two-Days Residential/Non-Residential Workshop on Latest Amendments under Companies Act, 2013

The details of activities of Debating Society of CCGRT Mumbai for Members are as follows:

S. No	Date	Topic
1	05 April, 2025	Decriminalisation: A Boost for Ease of Doing Business or Threat to Corporate Discipline?
2	19 April, 2025	Independence of Independent Director
3	17 May, 2025	AI usage in the profession and its impact
4	07 June, 2025	Legal Safeguards: are our national Data protection laws robust enough?
5	28 June, 2025	Are ESG Compliances more about fulfilling checklists than demonstrating impact?
6	19 July, 2025	POSH a mere compliance on paper or having positive impact on productivity
7	02 August, 2025	Is the onboarding process for Independent Directors sufficient to ensure their effective contribution to corporate governance?
8	20 September, 2025	Hostile takeovers-a threat to Corporate Governance or a catalyst for efficiency?
9	11 October, 2025	The pursuit of perfect 'life-balance' is a myth.
10	13 December, 2025	Company Secretaries are only compliance officers or Business partners to the Board
11	21 February, 2026	Regulatory Compliance vs. Ease of Business: Is Compliance Hindering Corporate Growth in India?

Mega Placement Drives: To enhance placement opportunities for Members, the Institute successfully organized Mega Placement Drive-I on 19 July, 2025 and Mega Placement Drive-II on 07 November, 2025. These placement drives provided a dynamic platform for leading organizations and aspiring Company Secretaries to connect, facilitating recruitment across diverse sectors. The initiatives witnessed active participation from recruiters and candidates alike, further strengthening the Institute's efforts to support career advancement and employment generation for its members and students.

Student Training Programmes: CCGRT Mumbai organised 9 Residential Corporate Leadership Development Programmes (CLDP) and 05 Non-Residential CLDPs during the period under Report.

MoU with Bharati Vidyapeeth Institute of Management Studies and Research: CCGRT Mumbai initiated collaboration with Bharti Vidyapeeth Institute of Management Studies and Research on 27 March, 2026, marking a collaborative step towards strengthening academic and professional development activities.

(ii) ICSI-CCGRT, Hyderabad

The ICSI-CCGRT, Hyderabad organized various programmes for students, Members and other professionals through Online and Classroom mode, and in collaboration with prestigious Institutions during the period under Report, as mentioned hereunder:

Professional Development Programmes for Members

CCGRT Hyderabad conducted the following Professional Development Programmes during the period under Report:

S. No.	Date	Programme
1	18-19 April, 2025	Two-day Research Conclave on ESG & BRSR
2	16-17 May, 2025	Two Days Research Conclave on SEBI Regulations
3	11-12 July, 2025	Two Days Residential Workshop on "Compliance Management on Corporate Laws
4	07-08 August, 2025	Two Days Residential Research Conclave on Corporate Funding - Private Equity and Debt Raising
5	29-30 August, 2025	Two Days Workshop on Corporate Restructuring Strategies and Planning Process
6	13 October, 2025	Seminar on Annual Fillings Under V3 Portal of MCA Jointly with Hyderabad Chapter
7	21 February, 2026	Workshop on Meetings of Board of Directors and its powers for Listed and Unlisted Companies

Student Training Programmes: During the period under Report, CCGRT Hyderabad conducted 12 CLDPs.

Collaborative / Joint Programmes: CCGRT Hyderabad conducted CORP CON-2025: A National Conference on Environmental, Social & Governance and Insolvency and Bankruptcy Code, jointly with NALSAR University of Law, Hyderabad on 12 & 13 September, 2025 at NALSAR University Campus. A total of 190 Members and students participated in the Conference. For the Inaugural Session, Shri Gyaneshwar Kumar Singh, Director General and CEO of the Indian Institute of Corporate Affairs served as the Chief Guest, and for the Valedictory Session, Hon'ble Governor of Telangana Sri Jishnu Dev Varma served as the Chief Guest.

Interactive Session: CCGRT Hyderabad conducted Interactive Session - MCA User Awareness Session on the launch of Annual Filing, E-Forms on 13 June, 2025, wherein Ms. Richa Kukreja, Regional Director (SER), MCA and other officials from MCA interacted with the Members. Around 160 Members participated in the Interactive Session.

IICA Outreach Programme on Opportunities under IBC: On 27 April, 2026, CCGRT, Hyderabad, in association with the Hyderabad Chapter, jointly organized an IICA Outreach Programme on "Opportunities under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)". The programme featured distinguished speakers, including Mr. Gyaneshwar Kumar Singh, Director General & CEO, Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), and Mr. Sudhakar Shukla, Course Director for the CIB, IICA, who shared valuable insights on emerging opportunities and professional prospects under the IBC framework.

Mega Placement Drives: CCGRT Hyderabad successfully organized Mega Placement Drive-I on 01 July, 2025 and Mega Placement Drive-II on 12 November, 2025, providing a valuable platform for professionals to connect with prospective employers and explore diverse career opportunities across industries.

(iii) ICSI-CCGRT, Kolkata

During the period under Report, CCGRT Kolkata organized the following events:

S. No.	Date	Programme
1.	26 April, 2025	Research Conclave on "Corporate Restructuring"
2.	12-13 July, 2025	2 Days Residential Programme on Fundamentals and Practical Insight into Taxation (GST and Direct Taxes)
3.	02-03 August, 2025	2 Days Residential Conference on Latest Amendments and Updates in Corporate Laws and SEBI Regulations
4.	15-16 November, 2025	2 Days Orientation Programme on Arbitration (in association with ICSI International ADR Centre and ADAMAS University)
5.	15 November, 2025	One Day National Seminar on Corporate Governance and Sustainability (jointly with EIRC and KBSAA)
6.	17 November, 2025	Training Workshop on Statutory Compliances, Disclosure, Regulatory Framework issues along with IBC (joint programme with DPE & IR, Govt of West Bengal)
7.	22-23 November, 2025	Meeting of ICSI Auditing Standards Board
8.	1-3 December, 2025	Collaborative Training Programme for the Group A and B officers of C&AG on "Companies Act 2013"
9.	16-18 December, 2025	Collaborative Training Programme for the Group A and B officers of C&AG on "Corporate Governance, Compliance and Risk factors in Audit"
10.	22-23 December, 2025	Capacity Building Programme on the topic "Corporate Governance, Compliance and Regulatory Framework" for the CS and Compliance Officers of Peerless Group
11.	14-25 January, 2026	Capacity Building Programme under Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme under the aegis of the Ministry of External Affairs, Govt. of India
12.	27-28 February, 2026	2 Days Workshop on Corporate Restructuring (Academic Partner- Amity University Kolkata and Corporate Partner – RP-Sanjeev Goenka Group)
13.	14-15 March, 2026	2 Days Capacity Building Workshop on "India's Insolvency Framework"

The details of activities of Debating Society of CCGRT Kolkata are as follows:

S. No.	Date	Topic
1.	5 April, 2025	Stress in human life is important (Virtual)
2.	17 May, 2025	War is a means to peace (Virtual)
3.	14 August, 2025	Tariff is the new Weapon (Virtual)
4.	24 September, 2025	Happiness is more important than success (Virtual)

5.	8 October, 2025	Stringent Compliance norms are a hurdle to ease of doing business (Virtual)
6.	17 January, 2026	Work From Home Increases Productivity among Employees (Virtual)
7.	28 February, 2026	Online Education will replace the Traditional Classroom Teaching (Virtual)
8.	14 March, 2026	Start-ups should not be subjected to the same Corporate Governance standards as Listed Companies

Student Training Programmes: During the period under Report, CCGRT Kolkata, organized 11 Residential CLDP Batches (Batch 8 to 18).

(iv) ICSI-CCGRT, Manesar

In its continuous endeavour to strengthen its institutional footprint and drive high-impact research, training, and consultancy, the ICSI proudly commissioned its 4th Centre for Corporate Governance, Research and Training at IMT Manesar, Haryana. Inaugurated on 11 December, 2025, this state-of-the-art facility stands as a testament to the Institute's unwavering commitment to fostering trust, transparency, and accountability across India Inc. Positioned strategically in the Northern Region, CCGRT Manesar acts as a premier incubation and capability-building hub. It is engineered to develop high-calibre professional leaders capable of navigating increasingly complex global regulatory frameworks and transforming business compliances into strategic corporate values. CCGRT, Manesar organised the following Professional Development Programmes for Members of the Institute:

S. No.	Date(s)	Programme
1	02-03 January, 2026	1st Residential Capacity Building Workshop on Corporate Restructuring
2	13-14 February, 2026	2nd Residential Capacity Building Workshop on SEBI(LODR) Regulations, 2015
3	21 February, 2026	1st Capacity Building Workshop on Practical Aspects of Board Meetings
4	20-21 March, 2026	3rd Residential Capacity Building Workshop on SEBI Regulations (SAST, PIT & ICDR)

Student Training Programmes: During the year under Report, CCGRT Manesar organised 9 Residential CLDP Batches (Batch 1 to 9).

(L) COMPANIES PROMOTED BY ICSI

ICSI Institute of Insolvency Professionals	ICSI Registered Valuers Organisation	ICSI International ADR Centre
ICSI Institute of Social Auditors	Institute of Governance Professionals of India	ICSI NCLT Practitioners Association

(i) ICSI Institute of Insolvency Professionals (ICSI-IIP)

ICSI IIP is a frontline regulator registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. ICSI IIP is registered under section 8 of the Companies Act, 2013. ICSI IIP has been vested with the power and authority *inter-alia* to enroll, educate, train and monitor the performance of its registered Members as an Insolvency Professional. Its mandate includes laying down standards of professional conduct and taking appropriate steps to ensure adherence of such standards.

(a) Enrollment of Insolvency Professionals

One of the primary functions of ICSI IIP is enrollment of Insolvency Professionals. ICSI IIP has a total of 1,238 active professional Members.

(b) Monitoring of Performance of Members

The ICSI IIP carries out monitoring of Insolvency Professionals in two ways, i.e., a) Desktop Monitoring and b) Inspection (includes routine inspection and event-based inspection).

(c) Events / Programmes

- Pre-Registration Educational Courses: Pursuant to Regulation 5(b) of the IBBI (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, individuals are eligible to register themselves as Insolvency Professionals (IP) only after undergoing the mandatory 50 hours Pre-Registration Educational Course from an Insolvency Professional Agency after his/her enrolment as a Professional Member. ICSI IIP, jointly with the other Insolvency Professional Agencies conducted three batches of pre-registration educational courses since 01 April, 2025.
- LIT UP- 3 days Training Programme for preparation of Limited Insolvency Examination: Pursuant to Regulation 5 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, an individual is eligible for registration as an Insolvency Professional only after passing Limited Insolvency Examination conducted by IBBI. During the period under review, ICSI IIP organized One batch of “LIT UPs” - 3 days training programme for preparation of Limited Insolvency Examination.

(d) National Convention

ICSI IIP has successfully organised the 03rd National Convention of Insolvency Professionals & Registered Valuers on 13th & 14th December, 2025 at ICSI CCGRT Kolkata. The city of Kolkata witnessed a landmark gathering as over 300 Insolvency Professionals, Registered Valuers, Company Secretaries, and key stakeholders came together for the 03rd National Convention of Insolvency Professionals and Registered Valuers. Hon'ble Minister Shri Babul Supriyo, Minister In-Charge, Information Technology & Electronics and Public Enterprises & Industrial Reconstruction, Government of West Bengal graced the occasion as 'Chief Guest'. Ms. Smita Pandey, IAS, Principal Secretary, Department of Public Enterprises & Industrial Reconstruction and Shri Vivek Gupta, MLA, West Bengal State Legislative Assembly and Former Rajya Sabha MP were the Special Guests of the event.

The convention facilitated a series of high-level interactive panel discussions, bringing together judicial minds, regulatory experts, and veteran practitioners to dissect the future of the IBC ecosystem.

- (e) Other Programmes:** During the period under review, ICSI IIP organised 43 workshops and 40 webinars.

(f) Joint Programmes

S. No.	Topic	Date
1.	Physical Workshop for IPs jointly with IBBI, IIPI and IPA ICAI	30/04/2025
2.	Online Workshop for IPs jointly with IBBI, IIPI and IPA ICAI	16/06/2025
3.	Physical Workshop for IPs jointly with IBBI, IIPI and IPA ICAI	20/06/2025
4.	Online Workshop for IPs jointly with IBBI, IIPI and IPA ICAI	03/07/2025
5.	Online Workshop for IPs jointly with IBBI, IIPI and IPA ICAI	10/07/2025
6.	ICSI in association with ICSI IIP organises Certificate Course on Insolvency & Bankruptcy Code, 2016	19/08/2025
7.	ICSI IIP jointly with IBBI, IIPI ICAI and IPA ICAI conducted Training for insolvency professionals	31/10/2025 to 02/11/2025
8.	ICSI IIP jointly with IBBI, IIPI ICAI and IPA ICAI conducted Training for insolvency professionals	21/11/2025 to 23/11/2025
9.	ICSI IIP jointly with IBBI, IIPI ICAI and IPA ICAI conducted Training for insolvency professionals	12/12/2025 to 14/12/2025
10.	ICSI IIP jointly with IBBI, IIPI ICAI and IPA ICAI conducted Training for insolvency professionals	23/01/2026 to 25/01/2026
11.	ICSI CCGRT Kolkata in association with ICSI Institute of Insolvency Professionals organises Capacity Building Workshop	14/03/2026 and 15/03/2026

(g) Roundtables

S.No.	Topic	Date
1.	Recent Supreme Court Judgement in Bhushan Power and Steel Case	10/05/2025
2.	IBBI Discussion Papers dated 6th & 12th August, 2025	14/08/2025
3.	Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2025	01/11/2025
4.	IBBI Discussion Paper dated 6th November, 2025	14/11/2025

5.	IBBI Discussion Paper dated 14th&17th November, 2025	24/11/2025
6.	IBBI Discussion Paper dated 16th February, 2026	25/02/2026

(h) National Conclave/ IP Conclave

S.No.	Topic	Date
1.	IP Conclave at Multipurpose Hall, Kamaladevi Complex, India International Centre, New Delhi.	09/05/2025
2.	ICSI Hyderabad Chapter of SIRC in association with ICSI Institute of Insolvency Professionals organises ICSI National Conclave for NCLT Practitioners-2025	29/11/2025
3.	ICSI Bengaluru Chapter of SIRC in association with ICSI Institute of Insolvency Professionals organises ICSI National Conclave for NCLT Practitioners-2025	06/12/2025

(i) Pre-Registration Education Course (online course)

S.No.	Topic	Date
1.	67th Batch Pre-Registration Education Course	14/04/2025 to 20/04/2025
2.	68th Batch Pre-Registration Education Course	21/07/2025 to 27/07/2025
3.	69th Batch Pre-Registration Education Course	15/01/2026 to 21/01/2026

(j) LIT UP (Virtual Classroom)

S.No.	Topic	Date
1.	LIT UP - Limited Insolvency Examination Training Preparatory Virtual Classroom	20/06/2025 to 22/06/2025

(k) Knowledge Initiatives

- **E-Journal:** ICSI IIP brings out bi-monthly e-journal which inter alia captures initiatives undertaken by ICSI IIP, latest amendments, success stories of Insolvency Professionals, judicial pronouncements, articles written by different stakeholders, write up on code and conduct for IPs, FAQs, policy updates, global arena, games corner, case studies etc.
- **Daily Learning Curves:** ICSI IIP provides 'IBC Learning Curve' on a daily basis to all the Insolvency professionals, Members of NCLT benches, IBBI, other professionals etc. IBC Learning Curves are based on the latest judicial pronouncements under IBC.
- **Learning Management System (LMS) Portal:** ICSI IIP has created a user-friendly online platform to enable professionals from all spheres of their careers to learn and study more about Insolvency Law. This Portal delivers assistance in learning by way of e-books, online lectures delivered by experts covering the Limited Insolvency Exam Syllabus and e-mock exam for aspirants preparing for Limited Insolvency Examination as per the latest format and Syllabus notified by IBBI. This feature enables the users to pass the Limited Insolvency Examinations effectively.

(l) Certificate Courses

ICSI IIP jointly with ICSI organised a 'Certificate Course on IBC- Batch 6' from 19th August 2025 to December 2025. Around 64 participants have registered for the course.

(ii) ICSI Registered Valuers Organisation (ICSI RVO)

ICSI RVO is a section 8 company of the Institute. ICSI RVO intends to enrol, educate, train and promote the profession of Registered Valuers as per the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.

(a) Online 50 Hours of Educational Courses

ICSI RVO conducted 50 Hours of Educational Courses in 09 Batches during the period under Report.

(b) Major Programmes:

During the period under review, ICSI RVO organised 12 Continuous Professional Educational Programmes (CPE).

(c) Certificate of Practice (CoP) Programme conducted for Registered Valuers

Sl. No.	Date	Topic
1.	07 th May, 2025	i. Code of Conduct for Registered Valuers
		ii. Professional Ethics
		i. Drafting Valuation Report
		ii. Soft Skills (How to communicate with the clients and peers)
2.	1 st July, 2025	i. Code of Conduct for Registered Valuers
		ii. Professional Ethics
		i. Drafting Valuation Report
		ii. Soft Skills (How to communicate with the clients and peers)
3.	23 rd July, 2025	i. Code of Conduct for Registered Valuers
		ii. Professional Ethics
		i. Drafting Valuation Report
		ii. Soft Skills (How to communicate with the clients and peers)

(iii) ICSI International ADR Centre

With the intent to facilitate Arbitration and Mediation at National and International level, the ICSI established its first ICSI International ADR Centre at Noida (U.P.). The objective of the ICSI International ADR Centre is to promote Alternate Dispute Resolution (ADR) methods including Mediation and Arbitration to assist and educate all sections of Society, Individuals, Corporates, Firms, Institutions and Establishments (Local or International).

The ICSI IAC invited applications from professionals interested in being empanelled as Arbitrators. A total of 53 professionals has been empanelled as Arbitrator at ICSI International ADR Centre.

The ICSI International ADR Centre in association with ICSI-CCGRT Kolkata and ADAMAS University organised 2 Days Orientation Programme on Arbitration on 15 and 16 November, 2025.

(iv) ICSI Institute of Social Auditors (ICSI ISA)

The ICSI Institute of Social Auditors (ICSI-ISA) is a Section 8 Company under the Companies Act, 2013 incorporated by ICSI with the objective to register Social Impact Assessors, lay down criteria/ norms for empanelment as well as standards of professional conduct for the registered Social Impact Assessors. The ICSI-ISA commenced the empanelment of Social Impact Assessors (SIAs) who have obtained the requisite NISM Certification. The ICSI-ISA commenced the empanelment of Social Impact Assessors from 12 May, 2023. Further, SEBI vide circular, SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/0060 dated 27 May, 2024 has specified the ICSI Institute of Social Auditors (ICSI-ISA) as a Self-Regulatory Organization (SRO) for the Social Impact Assessors and Social Impact Assessment Entities registered with ICSI-ISA.

(v) Institute of Governance Professionals of India (IGPI)

The Institute of Governance Professionals of India (Formerly ICSI Governance Research and Knowledge Foundation), Section 8 Company, promoted by ICSI, is a company promoted by ICSI, which is registered under the erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956 (now section 8 under the Companies Act, 2013).

Its object is "to generate, spread and impart knowledge, directly or in association with person(s) having similar objects or engaged in similar activities, in the area of corporate laws, governance, management, business sustainability and corporate social responsibility, capital and financial markets, auditing, fiscal and economic laws and policies, information and control systems and allied disciplines through research, publications, training, education or in any other manner."

(a) ICSI Board Mentorship Programmes

The Institute of Governance Professionals of India along with ICSI developed a platform under the aegis of ICSI Board Mentorship Programme, to bring together accomplished Board Chairs, Independent Directors, policymakers, governance experts, industry leaders, and seasoned professionals under one roof. The programme aims to equip present and aspiring

Board leaders with forward-looking perspectives, global governance practices, strategic insights, and practical wisdom.

During the period 2025-26, IGPI organised three (3) ICSI Board Mentorship Programmes across diverse regions of India, ensuring balanced regional representation and inclusive participation.

S. No.	Location	Region	Dates
1	Srinagar, Jammu & Kashmir	North	2 to 5 April, 2025
2	Kalimpong, West Bengal	East	18 to 21 September, 2025
3	Jaisalmer, Rajasthan	North-West	8 to 11 January, 2026

These programmes were attended by esteemed leaders from trade and industry, senior corporate professionals, corporate directors, and senior government officials from across the country. Their participation created a rich platform for peer learning, enabling an exchange of governance best practices and fostering deeper dialogue on emerging trends and challenges in the corporate landscape.

(b) Online Directors' Training Programmes for Corporates

IGPI also conducted three (3) online Directors' Training Programmes to enhance corporate governance skills through flexible and technology-enabled learning modes. The Programme details are as follows:

29 April, 2025	SME Listed Companies jointly with NSE	Physical (Mumbai, Maharashtra)
4 November, 2025	SENCO Limited	Online
28 March, 2026	Senco Gold Limited	Online

(vi) ICSI NCLT Practitioners Association

The ICSI NCLT Practitioners Association is a Section 8 Company, established under the Companies Act, 2013, specifically for Practicing Company Secretaries who appear before the National Company Law Tribunal (NCLT). Formed as a non-profit, non-political, and non-governmental organization, the association aims to serve as a leading body representing the interests of Practicing Company Secretaries. Its mission is to promote and uphold the highest standards of professionalism within the community and safeguard the rights and privileges of its members.

The association seeks to offer opportunities for legal and corporate education, organize seminars, foster networking and camaraderie, and create avenues for making meaningful contributions to the corporate legal systems for practicing professionals.

(M) AUDITED STATEMENTS OF CONSOLIDATED ACCOUNTS

The Audited statements of the Consolidated Accounts of the Institute along with the Auditors' Report for the financial year ended 31 March, 2026 form part of this Report.

(N) ICSI STRATEGIC ACTION PLAN (2026-2030)

The Institute constituted 'Strategic Group – ICSI Ascend' to undertake a comprehensive review of the Institute's activities and recommend a futuristic roadmap for its growth and transformation. The group was entrusted with developing a strategic action plan to modernize professional education and training, enhance digital service delivery, improve organizational efficiency, expand global outreach, and reinforce stakeholder engagement. Through extensive consultations and strategic analysis, Strategic Group-ICSI Ascend proposed a Strategic Action Plan (2026-2030) aimed at preparing the Institute and the Company Secretaries professionals for emerging challenges and opportunities aligning with the national vision of Viksit Bharat 2047.

The Council adopted the Strategic Action Plan (2026-2030) of the Institute, as recommended by the Strategic Group-ICSI Ascend which includes the internal organisational re-structuring and re-alignment of the Institute, for better service delivery to stakeholders.

(O) MAJOR ACTIVITIES [April 2026- August 2026]- AT A GLANCE

The major activities undertaken by the Institute from 01 April, 2026 to August, 2026 are placed at **Annexure D**.

(P) FUTURE OUTLOOK

"The future depends on what you do today."
~ Mahatma Gandhi

The world is witnessing an era of unprecedented transformation. Economic realignments, geopolitical uncertainties, climate-related risks, rapid technological advancements, evolving investor expectations, and the growing emphasis on sustainable development are collectively redefining the way institutions function and create value. In this environment of continual change, the imaging of governance has shifted from a compliance compulsion to a strategic imperative, serving as the foundation upon which resilient economies, trusted institutions, and sustainable enterprises are being built.

If India is being envisioned as a global super power in the upcoming decades, the India Inc. has a solid role to play in this. The eyes of the entire world are upon us – as to how we achieve our dreams, our vision, our goals and our objectives – and while we do that how do we go about aligning with the UN SDGs or the environmental limits.

The Institute of Company Secretaries of India has always held a sensitized approach towards all these facets – and has day-in day-out extended its full-fledged commitment towards building ethical, transparent, and future-ready organizations, portraying institutional credibility and partnering in economic development and societal progress.

The years to follow will demand professionals who are capable of navigating the complexities entailing these goals with competence and integrity. The Governance Professional of tomorrow will be expected to combine legal and regulatory expertise with digital literacy, strategic thinking, sustainability consciousness, and leadership acumen. Recognizing this transformation, the Institute shall continue to enrich its education, training, and capacity-building frameworks to equip its members and students for emerging opportunities and challenges.

If the digital transformation is to be emphasized upon, the rapid advancement of Artificial Intelligence, data analytics, cybersecurity frameworks, and digital governance mechanisms is reshaping the corporate landscape. Equally significant is the growing emphasis on the aspects of ESG. As businesses increasingly integrate both AI and sustainability into their strategic decisions, Governance Professionals will play a critical role in guiding organizations towards responsible and long-term value creation.

In a futuristic brainstorming, the Global outreach of the Institute as well as the profession occupies centre-stage. It is not about gaining recognitions alone, but to be the global torchbearers of governance – to know the way, to go the way and to show the way. Going forward, the intent is to foster partnerships which will not only facilitate knowledge exchange, but also enhance professional standards, and showcase India's governance capabilities on the global stage.

As the world evolves and new opportunities emerge, our commitment remains unwavering: to advance the cause of good governance, strengthen the stewardship framework of institutions, and contribute to building a future that is resilient, inclusive, sustainable, and prosperous for all.

In the words of the Bhagavad Gita:

"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥"

(Whatever a great person does, others follow.

Whatever standards they set by their actions, the world follows.)

Guided by this timeless principle, the Institute shall continue its pursuit of excellence, and living by its mission "to develop high calibre professionals facilitating good corporate governance", focus on nurturing future-ready talent, encouraging innovation in governance practices, promoting continuous learning, and strengthening stakeholder trust.

The goal is not merely to respond to change but to lead transformation through knowledge, through ethical leadership and through exemplary professionalism.

(Q) ACKNOWLEDGEMENTS

सह नावतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै॥

(May we be protected together; may we be nourished together; may we work together with great energy and purpose.)

~ Taaittiriya Upanishad

As we reflect upon the journey of the year 2025-26, we do so with a deep sense of humility and gratitude. Every milestone achieved by the Institute of Company Secretaries of India during the year is a testament to the invaluable support, encouragement, and confidence extended by our stakeholders. Your unwavering faith in the profession and the Institute continues to inspire us to strive for higher standards of excellence, service, and stewardship.

At the outset, we express our sincere gratitude to the Government of India, particularly the Ministry of Corporate Affairs, for its continued guidance, support, and commitment towards strengthening the governance ecosystem of the country. We deeply appreciate the encouragement and constructive engagement extended by the Hon'ble Ministers, Members of Parliament, senior policymakers, and government officials whose vision and insights continue to enrich the profession and its contribution to nation-building.

We also place on record our appreciation to various regulatory and statutory authorities including SEBI, RBI, IBBI, IRDAI, PFRDA, IFSCA, NCLT, NCLAT, NSE, BSE, NSDL, CDSL, CERC and other institutions that have worked closely with the profession to promote robust governance standards, investor confidence, transparency, and regulatory compliance. Their guidance and collaboration have played a significant role in enabling Company Secretaries to effectively discharge their responsibilities in a rapidly evolving business environment.

If in my individual capacity as the President, I am gratified with the support extended by the Council and the committees in decision making; as a Council, we collectively and gratefully acknowledge the invaluable contributions of the Boards, Task Forces, Advisory Groups, Appellate Authorities. Through their wisdom, experience, and tireless efforts, they have helped shape initiatives that advance the Institute's vision and serve the larger interests of stakeholders and society.

Our section 8 companies with their dedicated pathways are opening new doors of professional opportunity with each passing day and for that I wholeheartedly extend my commendations and appreciations to their Governing Bodies.

Our sincere appreciation to the leaders of industry, corporates, financial institutions, chambers of commerce, professional bodies, academia, research institutions, and policy thinktanks who have partnered with us throughout the year. Their active participation in our programmes, research initiatives, and capacity-building efforts has strengthened the exchange of ideas and enriched the governance discourse.

As governance increasingly assumes a global dimension and the ICSI marches zealously towards the achievement of its vision "to be a global leader in promoting good corporate governance", we acknowledge with gratitude the support of International Governance bodies, Secretarial Associations, Foreign Embassies, High Commissions, Consulate Generals, and our Overseas Centres. Our continued engagement together is strengthening our global outreach and facilitated meaningful collaborations aimed at advancing governance practices beyond geographical boundaries.

The strength and progress of each entity – irrespective of its objective, intent, structure and size lies in the dedication of its people. The commitment portrayed by the Team ICSI, their steadfastness in implementation of decisions and the zeal in actions has indeed been par exemplary. On behalf of the entire Council, I acknowledge the support extended to us by the Secretariat, CCGRTs, Regional Offices, Chapters, Managing Committees, Trainers & Resource persons in their various roles and capacities. Their professionalism, commitment, and perseverance have been instrumental in translating vision into action and aspirations into achievements.

We are especially grateful to our members and students, who remain the true ambassadors of the profession. It is indeed your impeccable value system, your pursuit of excellence, and commitment to upholding the highest standards of governance that continue to enhance the stature and credibility of this profession. Your individual achievements and collective efforts inspire the Institute to continuously innovate, strengthen its services, and expand opportunities for professional growth.

With great reverence we acknowledge the contributions of Former Presidents, Council Members, Office Bearers, and all the distinguished professionals whose untiring efforts over the years have laid strong institutional foundation upon which we continue to build.

As we move forward in an era marked by technological transformation, sustainability imperatives, and evolving expectations of accountability and stewardship, our collective success will continue to depend upon collaboration, trust, and shared purpose. The Institute values every stakeholder who has joined us in our endeavour to promote sound governance and responsible leadership.

Behind every successful chapter of our story stands our entire ecosystem of stakeholders – a community dedicated to excellence. Thank you for your trust in our dreams, your support in our actions and your shared commitment to our long-term vision. For as James C. Penney says,

"Growth is never by mere chance; it is the result of forces working together."

For and on behalf of the Council of
The Institute of Company Secretaries of India

Sd/-

New Delhi

Date: 29 August, 2026

CS PAWAN G. CHANDAK, President (ICSI)

[ADVT.-III/4/Exty./338/2026-27]

ANNEXURE-A

LIST OF STANDING, NON-STANDING COMMITTEES AND BOARDS FOR THE YEAR – 2026

S. No.	Name	Position
1. Executive Committee		
1.	CS Pawan G. Chandak	Chairman
2.	CS Dwarakanath Chennur	Member
3.	Shri Inder Deep Singh Dhariwal	Member (Govt. Nominee)
4.	CS Dhananjay Shukla	Member
5.	CS B. Narasimhan	Member
6.	CS Manoj Kumar Purbey	Member
7.	CS Venkata Ramana R.	Member
2. Finance Committee		
1.	CS Pawan G. Chandak	Chairman
2.	CS Dwarakanath Chennur	Member
3.	CS Ashish Karodia	Member
4.	CS Mohankumar A.	Member
5.	CS Praveen Soni	Member
6.	CS Sandip Kumar Kejriwal	Member
7.	CS Suresh Pandey	Member
3. Examination Committee		
1.	CS Pawan G. Chandak	Chairman
2.	CS Dwarakanath Chennur	Member
3.	CS B. Narasimhan	Member
4.	CS NPS Chawla	Member
5.	CS Rajesh Tarpara	Member
6.	CS Rupanjana De	Member
7.	CS Suresh Pandey	Member
4. Financial Services Committee		
1.	CS Ashish Karodia	Chairman
2.	CS B. Narasimhan	Member
3.	CS Manoj Kumar Purbey	Member
4.	CS Mohankumar A.	Member
5.	CS NPS Chawla	Member
6.	CS Rajesh Tarpara	Member
7.	CS Sandip Kumar Kejriwal	Member
5. Corporate Laws & Governance Committee		
1.	CS Manish Gupta	Chairman
2.	Dr. Ashok Kumar Mishra	Member (Govt. Nominee)

3.	CS Dhananjay Shukla	Member
4.	CS Ashish Karodia	Member
5.	CS Manoj Kumar Purbey	Member
6.	CS Rajesh Tarpara	Member
7.	CS Venkata Ramana R.	Member
6. ICSI CCGRT Management Committee		
1.	CS Dhananjay Shukla	Chairman
2.	CS Manish Gupta	Member
3.	CS Ashish Karodia	Member
4.	CS Sandip Kumar Kejriwal	Member
5.	CS Venkata Ramana R	Member
7. Centralized Infrastructure Committee		
1.	CS Dhananjay Shukla	Chairman
2.	CS Manish Gupta	Member
3.	CS Ashish Karodia	Member
4.	CS Rajesh Tarpara	Member
5.	CS Sandip Kumar Kejriwal	Member
6.	CS Venkata Ramana R.	Member
8. Professional Development Committee		
1.	CS Venkata Ramana R.	Chairman
2.	Shri Sanjay Shorey	Member (Govt. Nominee)
3.	CS Manish Gupta	Member
4.	CS NPS Chawla	Member
5.	CS Praveen Soni	Member
6.	CS Rajesh Tarpara	Member
7.	CS Rupanjana De	Member
8.	CS Suresh Pandey	Member
9. Training & Educational Facilities Committee		
1.	CS Dwarakanath Chennur	Chairman
2.	Shri Balamurugan D.	Member (Govt. Nominee)
3.	CS Dhananjay Shukla	Member
4.	CS B. Narasimhan	Member
5.	CS Ashish Karodia	Member
6.	CS Manoj Kumar Purbey	Member
7.	CS Mohankumar A.	Member
8.	CS Sandip Kumar Kejriwal	Member
10. Practicing Company Secretaries Committee		

1.	CS Rajesh Tarpara	Chairman
2.	CS Dhananjay Shukla	Member
3.	CS B. Narasimhan	Member
4.	CS Ashish Karodia	Member
5.	CS Mohankumar A.	Member
6.	CS Rupanjana De	Member
7.	CS Venkata Ramana R.	Member
11. Information Technology Committee		
1.	CS Manoj Kumar Purbey	Chairman
2.	CS Dhananjay Shukla	Member
3.	CS Mohankumar A.	Member
4.	CS NPS Chawla	Member
5.	CS Praveen Soni	Member
6.	CS Rajesh Tarpara	Member
7.	CS Rupanjana De	Member
8.	CS Venkata Ramana R.	Member
12. Placement Committee		
1.	CS Mohankumar A.	Chairman
2.	CS Manoj Kumar Purbey	Member
3.	CS NPS Chawla	Member
4.	CS Praveen Soni	Member
5.	CS Rupanjana De	Member
6.	CS Sandip Kumar Kejriwal	Member
7.	CS Suresh Pandey	Member
13. Professional Research Committee		
1.	CS Rupanjana De	Chairperson
2.	CS Ashish Karodia	Member
3.	CS NPS Chawla	Member
4.	CS Rajesh Tarpara	Member
5.	CS Sandip Kumar Kejriwal	Member
14. Publication Committee		
1.	CS Praveen Soni	Chairman
2.	Dr. Ashok Kumar Mishra	Member (Govt. Nominee)
3.	CS Manoj Kumar Purbey	Member
4.	CS Mohankumar A.	Member
5.	CS NPS Chawla	Member
6.	CS Rupanjana De	Member
7.	CS Suresh Pandey	Member
15. Board of Discipline		
1.	CS B. Narasimhan	Presiding Officer
2.	CS Venkata Ramana R.	Member
3.	CS Asish Mohan	Member
16. Disciplinary Committee		
1.	CS Pawan G. Chandak	Presiding Officer
2.	Shri Sunil Dadhe	Member (Govt. Nominee)
3.	Shri Sushil Kumar	Member (Govt. Nominee)
4.	CS Dhananjay Shukla	Member
5.	CS Manish Gupta	Member
17. PMQ Course Committee		

1.	CS Dhananjay Shukla	Chairman
2.	CS Rajesh Tarpara	Member
3.	CS Manoj Kumar Purbey	Member
4.	CS NPS Chawla	Member
5.	CS Sandip Kumar Kejriwal	Member
6.	CS Ashish Karodia	Member
7.	CS Venkata Ramana R.	Member
18. Peer Review Board		
1.	CS Sandip Kumar Kejriwal	Chairman
2.	CS Ashish Karodia	Member
3.	CS Manoj Kumar Purbey	Member
4.	CS Mohankumar A.	Member
5.	CS Nesar Ahmad	Member
6.	CS Prasad Takalkar	Member
7.	CS Manoj Soni	Member
19. Editorial Advisory Board		
1.	CS NPS Chawla	Chairman
2.	Dr. Ashok Kumar Mishra	Member (Govt. Nominee)
3.	CS P C Agarwal	Member
4.	CS Rajesh Tarpara	Member
5.	CS Rupanjana De	Member
6.	CS (Prof.) Anjali Gupta	Member
7.	CS Gaurav Pingle	Member
8.	CS Sudhanshu Singhal	Member
9.	CS Sheetal Mahamuni	Member
10.	CS Bimal Jain	Member
11.	CS (Dr.) D.K. Jain	Member
12.	CS Ram Thakkar	Member
13.	CS Nitin Somani	Member
14.	CS Pranav Kumar	Member
15.	CS (Prof.) Rabi Narayan Kar	Member
16.	CS Abhijit Rane	Member
17.	CS (Dr.) Sudheendhra Putty	Member
18.	CS Rudra Pandey	Member
19.	CS Sachin Agarwal	Member
20. Auditing Standards Board		
1.	CS Suresh Pandey	Chairman
2.	CS Manoj Kumar Purbey	Member
3.	CS Vineet Kumar Chaudhary	Member
4.	CS Amit Kaushal	Member
5.	CS K Venkata Raman	Member
6.	CS Raghavendra Joshi	Member
7.	CS Ramakant Pathak	Member
8.	CS Vikas Gera	Member
9.	CS Pawan Kumar Rustagi	Member
10.	CS Bhuwneshwar Prasad Mishra	Member
11.	CS Kamit Jain	Member
12.	CS Rahul Jain	Member
13.	CS Lokesh Dhyan	Member
14.	CS Ram Prakash Punjani	Member
15.	CS Ravi Sharma	Member
16.	Representatives of SEBI Shri Rajesh Kumar Dangeti.	Member

	Chief General Manager (CGM), Corporation Finance Department-Policy Vertical, SEBI	
17.	Representatives of BSE Mr. Vishal Jhaveri, Deputy Chief Regulatory Officer, BSE	Member
18.	Representatives of NSE Shri. Avishkar Naik Senior Vice President - Arbitration & Grievance Redressal, Member Default ISC and UCI	Member
21. Secretarial Standards Board		
1.	CS Nagendra D Rao	Chairman
2.	CS Manish Gupta	Member
3.	CS B Narasimhan	Member
4.	CS Ajay Jaiswal	Member
5.	CS Awanish Dwivedi	Member
6.	CS Kalidas Ramaswamy	Member
7.	CS Kuldeep Ruchandani	Member
8.	CS Ravi Kapoor	Member
9.	CS Om Prakash Bagdia	Member
10.	CS Prajot Tungare	Member
11.	CS Rohit Arora	Member
12.	CS Sanjeev Grover	Member
13.	CS Savithri Parekh	Member
14.	CS Sudhakar Saraswatula	Member
15.	CS Sivakumar	Member
Representative Members		
16.	Nominee – ICAI CMA Avijit Goswami	Member
17.	Nominee -ICAI CA Vishal Doshi (FCA)	Member
18.	Nominee – IFSCA CS Pradeep Ramakrishnan	Member
19.	Nominee – BSE	Member
20.	Nominee – CII CS Manikantha AGS	Member
21.	Nominee – NSE Ms. Yukti Sharma	Member
22. MSME and Start-Up Board		
1.	CS Devendra V Deshpande	Chairman
2.	CS Rajiv Bajaj	Member
3.	CS (Dr.) Ajay Garg	Member
4.	CS Yogendra Omprakash Sharma	Member
5.	CS Ajay Sancheti	Member
6.	CS Arun Mulge	Member
7.	CA Gaurav Arora	Member
8.	Mr. Gaurav Mahani	Member
9.	CS Pramodkumar Ramesh Ladda	Member
10.	CS Ujwal Rameshchandra Nikam	Member
11.	CS Vikas Ramesh Agarwal	Member
12.	CS Deepak Bansal	Member
13.	CS Padmasinh Patil	Member

14.	CS Sachin Khurana	Member
15.	CS Ashique A M	Member
16.	CS Sandip Kumar Kejriwal	Special Invitee
17.	CS Venkata Ramana R	Special Invitee
23. ESG and Sustainability Board		
1.	CS Ranjeet Pandey	Chairman
2.	CS Ashish Tiwari	Member
3.	CS Parambil Devassy Vincent	Member
4.	CS Anil Rustgi	Member
5.	CS Rajesh C. Tarpara	Member
6.	CS Abhinav Agarwal	Member
7.	CS Rohit Gokhale	Member
8.	CS Bhasker Joshi	Member
9.	CS J Sundharesan	Member
10.	CS Mangal Kulkarni (Ms.)	Member
11.	CS Pankaj Chourasia	Member
12.	Dr. Chandrashekhar Chincholkar	Member
13.	CS Sachin Mishra	Member
14.	CS Shashi Bhushan Singh	Member
15.	CS Shujath Bin Ali	Member
Representatives from:		
16.	Nominee of NSE Dr. Harish Ahuja	Member
17.	Nominee of FICCI CS Pramod Kumar Rai	Member
18.	Nominee of CII Ms. Swati Tewari	Member
19.	CS Pradeep Ramakrishnan	Member
20.	CS Venkata Ramana R.	Special Invitee
21.	CS K. S. Ravichandran	Special Invitee
24. Academic Board		
1.	CS Ranjeet Pandey	Chairman
2.	Prof. Bindu S Ronald	Member
3.	Dr. Asim Kr. Mishra	Member
4.	Dr. Shital Jhunjhunwala	Member
5.	CS Pradeep Ramakrishnan	Member
6.	CS Makarand Joshi	Member
7.	CS Harish Kumar	Member
8.	Dr Jitendra Mohan Bhardwaj	Member
9.	Shri Biju Varkkey	Member
10.	CS Dwarakanath C	Ex-officio
11.	CS Asish Mohan	Ex-officio
Representatives from:		
12.	Nominee of MCA Sh. Ghanshyam Sahu	Member
13.	Nominee of CII CS Pankaj Tewari	Member
14.	Nominee of UGC Dr. Mantha Srinivasu	Member
15.	Nominee of AICTE Prof. Anil Kumar	Member
16.	Prof. (Dr.) M. Afshar Alam	Special Invitee:
17.	CS Lakshmanan R	Special Invitee:
18.	CS Sheetal Jaywant	Special Invitee:

ANNEXURE-B

**DETAILS OF MEETINGS HELD AND ATTENDANCE FOR THE PERIOD
01 APRIL, 2025 TO 31 MARCH, 2026**

Note - * No. of meetings eligible to be attended by the member during the period 01.04.25 to 31.03.26

1. Council Meetings		
Name	Held*	Attended
CS Dhananjay Shukla	12	12
CS Pawan G. Chandak	12	12
CS B. Narasimhan	12	11
CS Manish Gupta	12	12
Sh. Balamurugan D.	12	1
Sh. Inder Deep Singh Dhariwal	12	2
Sh. Manish Goswami	12	0
Sh. Sanjay Shorey	12	2
Dr. Ashok Kumar Mishra	12	9
CS Mohankumar A.	12	5
CS Ashish Karodia	12	12
CS Dwarakanath C.	12	12
CS Manoj Kumar Purbey	12	12
CS N P S Chawla	12	2
CS Praveen Soni	12	11
CS Venkata Ramana R.	12	11
CS Rajesh Tarpara	12	12
CS Rupanjana De	12	10
CS Sandip Kumar Kejriwal	12	9
CS Suresh Pandey	12	10
Date of Meetings: 14.04.25, 15.06.25, 01.07.25, 25-26.07.25, 25.08.25, 10.11.25, 20-21.11.25, 27.12.25, 11.01.26, 19.01.26, 17-18.03.26, 27.03.26		
2. Executive Committee		
Name	Held*	Attended
CS B. Narasimhan	7	6
CS Dhananjay Shukla	7	7
Sh. Inder Deep Singh Dhariwal	7	1
CS Manish Gupta	5	5
CS Dwarakanath C.	7	7
CS Pawan G. Chandak	7	7
CS Sandip Kumar Kejriwal	5	2
CS Manoj Kumar Purbey	2	1
CS Venkata Ramana R.	2	2
Date of Meetings: 02.06.25, 16.07.25, 10.11.25, 19.11.25, 09.01.26, 06-07.03.26, 11.03.26		
3. Finance Committee		
Name	Held*	Attended
CS Dhananjay Shukla	3	3
CS Mohankumar A.	4	0

CS Manoj Kumar Purbey	3	3
CS Venkata Ramana R.	3	3
CS Rajesh Tarpara	3	2
CS Pawan G. Chandak	4	4
CS Praveen Soni	4	2
CS Dwarakanath C.	1	1
CS Ashish Karodia	1	1
CS Sandip Kumar Kejriwal	1	0
CS Suresh Pandey	1	1
Date of Meetings: 16.07.25, 18.08.25, 13.01.26, 05.03.26		
4. Examination Committee		
Name	Held*	Attended
CS Dhananjay Shukla	7	5
CS Pawan G. Chandak	8	6
CS B. Narasimhan	8	5
CS Ashish Karodia	7	5
CS N P S Chawla	8	0
CS Rupanjana De	8	5
CS Suresh Pandey	8	4
CS Dwarakanath C.	1	1
CS Rajesh Tarpara	1	1
Date of Meetings: 05.04.25, 13.05.25, 14.07.25, 14.08.25, 05.10.25, 18.11.25, 16.01.26, 18.02.26		
5. Financial Services Committee		
Name	Held*	Attended
CS B. Narasimhan	5	5
CS Dwarakanath C.	3	3
CS Ashish Karodia	5	2
CS Manoj Kumar Purbey	5	5
CS Rajesh Tarpara	5	4
CS Rupanjana De	3	2
CS Suresh Pandey	3	2
CS Mohankumar A.	2	0
CS N P S Chawla	2	0
CS Sandip Kumar Kejriwal	2	1
Dates of Meetings: 03.06.25, 04.11.25, 15.01.26, 12.02.26, 13.03.26		
6. Corporate Laws and Governance Committee		
Name	Held*	Attended
CS Manish Gupta	4	4
Dr. Ashok Kumar Mishra	4	3
CS Ashish Karodia	4	3

CS Dwarakanath C.	3	3
CS Venkata Ramana R.	4	4
CS Rajesh Tarpara	4	4
CS Sandip Kumar Kejriwal	3	3
CS Mohankumar A.	3	0
CS Dhananjay Shukla	1	1
CS Manoj Kumar Purbey	1	1
Date of Meetings: 13.06.25, 26.08.25, 20.11.25, 17.03.26		
7. Professional Development Committee		
Name	Held*	Attended
CS Dhananjay Shukla	3	3
Sh. Sanjay Shorey	5	0
CS B. Narasimhan	3	3
CS Manoj Kumar Purbey	3	2
CS Praveen Soni	5	5
CS Venkata Ramana R.	5	5
CS Rajesh Tarpara	5	5
CS Sandip Kumar Kejriwal	3	1
CS Manish Gupta	2	1
CS N P S Chawla	2	0
CS Rupanjana De	2	2
CS Suresh Pandey	2	1
Date of Meetings: 02.06.25, 30.07.25, 18.11.25, 18.02.26, 25.02.26		
8. Training & Educational Facilities Committee		
Name	Held*	Attended
CS Pawan G. Chandak	7	7
CS Manish Gupta	7	6
CS Mohankumar A.	10	2
CS Ashish Karodia	10	7
CS Dwarakanath C.	10	9
CS Suresh Pandey	7	6
Sh. Balamurugan D.	10	0
CS N P S Chawla	7	0
CS Dhananjay Shukla	3	3
CS B. Narasimhan	3	3
CS Manoj Kumar Purbey	3	2
CS Sandip Kumar Kejriwal	3	0
Date of Meetings: 30.04.25, 03.06.25, 17.07.25, 24.09.25, 03.10.25, 29.10.25, 17.11.25, 12.02.26, 05.03.26, 25.03.26		
9. Practising Company Secretaries Committee		
Name	Held*	Attended
CS Praveen Soni	6	6
CS Manish Gupta	6	4
CS Dwarakanath C.	6	4

CS Suresh Pandey	6	5
CS Rupanjana De	7	5
CS Mohankumar A.	7	0
CS Sandip Kumar Kejriwal	6	4
CS Rajesh Tarpara	1	1
CS B. Narasimhan	1	1
CS Venkata Ramana R.	1	1
CS Dhananjay Shukla	1	1
CS Ashish Karodia	1	0
Date of Meetings: 02.06.25, 16.07.25, 19.08.25, 22.09.25, 19.11.25, 26.12.25, 13.02.26		
10. Information Technology Committee		
Name	Held*	Attended
CS Manoj Kumar Purbey	5	5
CS Manish Gupta	4	1
CS Praveen Soni	5	5
CS Venkata Ramana R.	5	4
CS Rajesh Tarpara	5	5
CS Rupanjana De	5	3
CS Suresh Pandey	4	2
CS Dhananjay Shukla	1	0
CS Mohankumar A.	1	0
CS N P S Chawla	1	0
Date of Meeting: 29.04.25, 08.08.25, 07.11.25, 24.12.25, 11.02.26		
11. Chapter Development & Coordination Committee		
Name	Held*	Attended
CS Sandip Kumar Kejriwal	4	4
CS Mohankumar A.	4	0
CS Ashish Karodia	4	4
CS Dwarakanath C.	4	4
CS N P S Chawla	4	0
CS Venkata Ramana R.	4	4
CS Suresh Pandey	4	2
Date of Meetings: 31.07.25, 05.08.25, 09.10.25, 10.01.26		
12. PMQ Course Committee		
Name	Held*	Attended
CS Rajesh Tarpara	3	3
CS Mohankumar A.	3	0
CS Ashish Karodia	3	3
CS N P S Chawla	3	1
CS Venkata Ramana R.	3	3
CS Praveen Soni	3	3
CS Dwarakanath C.	3	2
Date of Meetings: 01.07.25, 03.10.25, 19.12.25		

13. Placement Committee		
Name	Held*	Attended
CS Suresh Pandey	2	2
CS Mohankumar A.	2	1
CS Manoj Kumar Purbey	2	0
CS N P S Chawla	2	0
CS Praveen Soni	2	1
CS Rupanjana De	2	1
CS Sandip Kumar Kejriwal	2	2
Date of Meetings: 08.05.25, 10.03.26		
14. ICSI-CCGRT Management Committee		
Name	Held*	Attended
CS Dhananjay Shukla	4	4
CS Ashish Karodia	4	4
CS Manish Gupta	4	3
CS Venkata Ramana R.	4	4
CS Sandip Kumar Kejriwal	4	3
CS Dwarakanath C.	3	3
Date of Meetings: 04.06.25, 15.07.25, 24.12.25, 05.02.26		
15. Regulation and Election Reforms Committee		
Name	Held*	Attended
CS Dwarakanath C.	3	3
CS Manish Gupta	3	2
CS Ashish Karodia	3	2
CS Venkata Ramana R.	3	3
CS Rupanjana De	3	1
CS Sandip Kumar Kejriwal	3	1
CS Suresh Pandey	3	2
Date of Meetings: 09.06.25, 05.08.25, 15.10.25		
16. International Affairs Committee		
Name	Held*	Attended
CS Rupanjana De	3	3
CS B. Narasimhan	3	3
CS Mohankumar A.	3	0
CS Ashish Karodia	3	2
CS Manoj Kumar Purbey	3	1
CS N P S Chawla	3	0
CS Sandip Kumar Kejriwal	3	0
Date of Meetings: 13.05.25, 23.07.25, 19.11.25		
17. Centralised Infrastructure Committee		
Name	Held*	Attended
CS Dhananjay Shukla	1	1
CS Manish Gupta	1	1
CS Ashish Karodia	1	1
CS Rajesh Tarpara	1	1

CS Sandip Kumar Kejriwal	1	1
CS Venkata Ramana R.	1	1
Date of Meeting: 05.02.26		
18. Publication Committee		
Name	Held*	Attended
CS Praveen Soni	1	1
Dr. Ashok Kumar Mishra	1	1
CS Manoj Kumar Purbey	1	0
CS Mohankumar A.	1	0
CS N P S Chawla	1	0
CS Rupanjana De	1	1
CS Suresh Pandey	1	1
Date of Meeting: 12.02.26		
19. Professional Research Committee		
Name	Held*	Attended
CS Rupanjana De	1	1
CS Ashish Karodia	1	1
CS Rajesh Tarpara	1	1
CS N P S Chawla	1	0
CS Sandip Kumar Kejriwal	1	1
Date of Meeting: 16.03.26		
20. Board of Discipline		
Name	Held*	Attended
CS B. Narasimhan	5	5
CS Sandip Kumar Kejriwal	5	5
CS Asish Mohan	5	5
Date of Meetings: 22-23.04.25, 08-09.07.25, 19.08.25, 04.11.25, 29.01.26		
21. Disciplinary Committee		
Name	Held*	Attended
CS Dhananjay Shukla	8	8
Sh. Sushil Kumar	10	7
Sh. Sunil Dadhe	10	10
CS Manish Gupta	10	10
CS Dwarakanath C.	10	7
CS Pawan G. Chandak	2	2
Date of Meetings: 09.06.25, 10.06.25, 22.07.25, 25.09.25, 14.10.25, 16.12.25, 17.12.25, 13.01.26, 10.03.26, 11.03.26		
22. Academic Board		
Name	Held*	Attended
CS Ranjeet Pandey	3	3
Dr. Alka Mittal	2	1
Dr. Anil Kumar	2	2
Dr. Jitendra Mohan Bhardwaj	3	3
CS Makarand Joshi	3	3

Dr. R. Venkata Rao	2	1
Dr. Saleena Kuzhuppil Basheer	2	2
CS Sanjeev Grover	2	1
CS Pankaj Tiwari	2	1
Prof. Bindu S Ronald	1	1
Dr. Asim Kumar Mishra	1	1
Dr. Shital Jhunjhunwala	1	1
CS Pradeep Ramakrishnan	1	1
CS Harish Kumar	1	1
Sh. Biju Varkkey	1	1
Date of Meetings: 11.04.25, 05.07.25, 20.03.26		
23. Auditing Standards Board		
Name	Held*	Attended
CS Vineet K Chaudhary	3	3
CS Dwarkanath C.	3	1
CS Manoj Kumar Purbey	3	2
CS Praveen Soni	3	1
CS Amit Kaushal	3	3
CS G. V. Srinivas Murthy	3	3
CS Jagdish Patra	3	2
CS Venkataraman K.	3	3
CS Kuldeep Dayal Das Ruchandani	3	2
CS Kumudini Dinesh Bhalerao	3	1
CS Manoj Rajaram Hurkat	3	3
CS Pankaj Virmani	3	2
CS Ravi Sharma	3	3
CS Sachin Agarwal	3	3
CS Alok Narayan Pandey	3	2
Sh. Vishal Jhaveri	3	0
Date of Meetings: 24.05.25, 04.07.25, 22-23.11.25		
24. Editorial Advisory Board		
Name	Held*	Attended
CS N P S Chawla	1	0
Dr. Ashok Kumar Mishra	1	1
CS Praveen Soni	1	1
CS Rajesh Tarpara	1	0
CS Rupanjana De	1	1
CS (Prof.) Anjali Gupta	1	1
CS Apoorva Kumar	1	1
CS Bimal Jain	1	0
CS (Dr.) D.K. Jain	1	1
CS Nitin Somani	1	0
CS Pranav Kumar	1	1
CS (Prof.) Rabi Narayan Kar	1	1

CS Sheik Latheef	1	1
CS (Dr.) Sudheendhra Putty	1	1
CS Sushil Kumar Kandoi	1	1
Date of Meeting: 17.07.25		
25. ESG and Sustainability Board		
Name	Held*	Attended
CS Ranjeet Pandey	4	4
CS Ashish Garg	4	4
CS Venkata Ramana R.	4	4
CS Rajesh Tarpara	4	3
CS Abhinav Agarwal	4	3
Ms. Aruna C. Newton	3	2
CS Bhasker Joshi	4	2
CS J. Sundharesan	4	4
CS Mangal Kulkarni (Ms.)	4	4
CS Pankaj Chourasia	4	4
CS S. Sudhakar	4	3
CS Sachin Mishra	4	4
CS Shashi Bhushan Singh	4	4
CS Shujath Bin Ali	4	4
CS Pradeep Ramakrishnan	4	2
Sh. Rajesh Kumar Dangeti	3	0
Dr. Harish Ahuja	4	0
CS Pramod Kumar Rai	4	4
Ms. Swati Tewari	4	1
CS Sachin Jain	3	2
Date of Meetings: 01.05.25, 19.07.25, 20-21.09.25, 16.01.26		
26. MSME and Startup Board		
Name	Held*	Attended
CS Rajiv Bajaj	4	4
CS Sandip Kumar Kejriwal	4	0
CS Venkata Ramana R.	4	3
CS (Dr.) Ajay Garg	4	4
CS (Dr.) Ajay Jaiswal	4	4
CS Ajay Sancheti	4	4
CS Anil Rustagi	4	3
Wg. Cdr. Anthony Anish (Retd.)	4	2
CS Bala Nadar	4	3
CS Devender Suhag	4	1
CS Gaurav Arora	4	3
Sh. Gaurav Mahani	4	3
CS L. N. Joshi	4	3
CS N. Balasubramanian	4	3

CS Rajesh Kumar Loomba	4	1
Sh. Rajiv Chawla	4	1
CS Sachin Khurana	4	2
CS Yogesh Khakre	4	2
Date of Meetings: 23.04.25, 02.07.25, 01.10.25, 14.01.26		
27. Peer Review Board		
Name	Held*	Attended
CS Mohankumar A.	3	3
CS Ashish Karodia	3	2
CS Manoj Kumar Purbey	3	2
CS Sandip Kumar Kejriwal	3	2
CS Nesar Ahmad	3	1
CS Ram Sahay	3	3
CS V. Sreedharan	3	3
Date of Meetings: 23.04.25, 28.07.25, 17.11.25		
28. Professional Skills Enhancement Board		
Name	Held*	Attended
CS Devendra V. Deshpande	3	3
CS N P S Chawla	3	0
CS Sandip Kumar Kejriwal	3	0
CS Suresh Pandey	3	1
CS B. Renganathan	3	2
CS Jude Dsouza	3	2
CS Mahesh Anant Athavale	3	3
CS P. Sivakumar	3	3
CS Raghavendra Joshi	3	3
CA Rajat Jain	3	2
Dr. Suneel Keswani	3	3
CS Unnati Kanani	3	2
CS Vikas Agarwal	3	1
CS Yogesh Kumar	3	2
Date of Meetings: 01.05.25, 02.06.25, 04.09.25		
29. Quality Review Board		
Name	Held*	Attended
Sh. Rakesh Mohan	1	1
Sh. Jyoti Prakash Gadia	1	1
Ms. Deepna Gokulram	1	1
CS Pawan G. Chandak	1	1
Sh. Pramod Kumar Rai	1	1
Date of Meeting: 12.11.25		
30. Secretarial Standards Board		
Name	Held*	Attended
CS Nagendra D. Rao	2	2
CS Mohankumar A.	2	0

CS Praveen Soni	2	1
CS Ajay Jaiswal	2	0
CS Awanish Dwivedi	2	1
CS B. Shanmugasundaram	2	2
CS Kalidas Ramaswami	2	1
CS Makarand Joshi	2	2
CS Pankaj Tandon	2	1
CS Prajot Tungare	2	2
CS Rajni Kant	2	1
CS Rudra Pandey	2	1
CS Sanjeev Grover	2	1
CS Savithri Parekh	2	2
CS Sudhakar Saraswatula	2	2
CMA Avijit Goswami	2	0
CA Babu Abraham Kallivayalil	2	0
Sh. Pradeep Ramakrishnan	2	2
CS Manikantha AGS	1	1
Sh. Vishal Bhat	1	1
Date of Meetings: 03.05.25, 30-31.08.25		

REGIONWISE LIST (CITIES) OF EXAMINATION CENTRES – CS EXAMINATIONS

EAST		NORTH				SOUTH		WEST			
1	ASANSOL	1	AGRA	43	LUDHIANA	1	BALLARY	1	AHMEDABAD ZONE I	43	PUNE ZONE III
2	BHAGALPUR	2	AJMER	44	MATHURA	2	BELAGAVI	2	AHMEDABAD ZONE II	44	PUNE ZONE IV
3	BHUBANESWAR I	3	ALIGARH	45	MEERUT	3	BENGALURU ZONE I	3	AHMEDABAD ZONE III	45	RAIPUR
4	BHUBANESWAR II	4	ALWAR	46	MODINAGAR	4	BENGALURU ZONE II	4	AHMEDABAD ZONE IV	46	RAJKOT
5	BOKARO	5	AMBALA	47	MORADABAD	5	BENGALURU ZONE III	5	AHMEDNAGAR	47	RATLAM
6	DHANBAD	6	AMRITSAR	48	MUZAFFARNAGAR	6	BENGALURU ZONE IV	6	AKOLA	48	SAGAR
7	GAYA	7	BAREILLY	49	NOIDA	7	CHENNAI ZONE I	7	AMRAVATI	49	SATARA
8	GUWAHATI	8	BEAWAR	50	PALI	8	CHENNAI ZONE II	8	BHAYANDER	50	SOLAPUR
9	HOOGHLY	9	BHILWARA	51	PANIPAT	9	CHENNAI ZONE III	9	BHILAI	51	SURAT
10	HOWRAH	10	BHIWANI	52	PATIALA	10	CHENNAI ZONE IV	10	BHOPAL	52	THANE ZONE I
11	IMPHAL	11	BIKANER	53	PRAYAGRAJ	11	CHENNAI ZONE V	11	BILASPUR	53	THANE ZONE II
12	JAMSHEDPUR	12	CHANDIGARH	54	REWARI	12	CHENNAI ZONE VI	12	CHANDRAPUR	54	THANE ZONE III
13	KOLKATA ZONE I	13	CHITTORGARH	55	ROHTAK	13	CHENNAI ZONE VII	13	CHHATRAPATI SAMBAHAJINAGAR	55	UJJAIN
14	KOLKATA ZONE II	14	DEHRADUN	56	SHIMLA	14	COIMBATORE	14	DEWAS	56	VADODARA
15	KOLKATA ZONE III	15	DELHI ZONE I	57	SIKAR	15	ERNAKULAM	15	GANDHIDHAM	57	VAPI
16	KOLKATA ZONE IV	16	DELHI ZONE II	58	SONEPAT	16	ERODE	16	GANDHINAGAR		
17	MUZAFFARPUR	17	DELHI ZONE III	59	SRINAGAR	17	GUNTUR-AMARAVATI	17	GWALIOR		
18	PATNA	18	DELHI ZONE IV	60	UDAIPUR	18	HUBLI-DHARWAD	18	INDORE		
19	RANCHI	19	DELHI ZONE V	61	VARANASI	19	HYDERABAD ZONE I	19	JABALPUR		
20	ROURKELA	20	DELHI ZONE VI	62	YAMUNA NAGAR	20	HYDERABAD ZONE II	20	JALGAON		
21	SAMBALPUR	21	DELHI ZONE VII			21	HYDERABAD ZONE III	21	JAMNAGAR		
22	SILIGURI	22	DELHI ZONE VIII			22	KANNUR	22	KATNI		
		23	FARIDABAD			23	KOLLAM	23	KOLHAPUR		
		24	GHAZIABAD			24	KOTTAYAM	24	LATUR		
		25	GORAKHPUR			25	KOZHIKODE	25	MIRAJ-SANGLI		
		26	GREATER NOIDA			26	MADURAI	26	MUMBAI ZONE I		
		27	GURUGRAM			27	MANGALURU	27	MUMBAI ZONE II		
		28	HALDWANI			28	MYSURU	28	MUMBAI ZONE III		
		29	HISAR			29	NELLORE	29	MUMBAI ZONE IV		
		30	JAIPUR ZONE I			30	PALAKKAD	30	MUMBAI ZONE V		
		31	JAIPUR ZONE II			31	PUDUCHERRY	31	MUMBAI ZONE VI		
		32	JAIPUR ZONE III			32	SALEM	32	MUMBAI ZONE VII		
		33	JAIPUR ZONE IV			33	SHIMOGA	33	MUMBAI ZONE VIII		
		34	JALANDHAR			34	SIRSI	34	NAGPUR		
		35	JAMMU			35	THIRUVANANTHAPURAM	35	NANDED		
		36	JHANSI			36	THRISSUR	36	NASHIK		
		37	JHUNJHUNU			37	TIRUCHIRAPALLI	37	NAVI MUMBAI ZONE I		
		38	JODHPUR			38	TIRUNELVELI	38	NAVI MUMBAI ZONE II		
		39	KANPUR			39	TIRUPPUR	39	PANAJI		
		40	KARNAL			40	UDUPI	40	PIMPRI-CHINCHWAD		
		41	KOTA			41	VIJAYAWADA	41	PUNE ZONE I		
		42	LUCKNOW			42	VISAKHAPATNAM	42	PUNE ZONE II		
OVERSEAS CENTRE: DUBAI											

ANNEXURE D

MAJOR ACTIVITIES OF THE INSTITUTE FROM 01 APRIL, 2026 TO 31 AUGUST, 2026

During the period from 01 April, 2026 to August, 2026, the following major activities were undertaken and matters decided upon by the Council:

1. New Recognitions:

- a. IFSCA: Recognition to PCS under 'Framework for Preferential Issues and QIP under IFSCA (Listing) Regulations, 2024
- b. Recognition to CS professionals for Senior Executive Programme of Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
- c. PCS to undertake certification for allegiance with Gold Standards set by IAGES

2. Key decisions in Council Meetings:

- a. Placing the Regional/ Local Language name of the respective Regional / Chapter Offices of ICSI and Hindi name before the English name of the ICSI in the design of the ICSI Logo-Masthead
- b. Acquisition of Property for Thrissur Chapter, Pune Chapter; Land for Nashik Chapter
- c. Empanelment of Govt. agencies on deposit work basis to deliver the services on prospective infrastructural project/works
- d. ICSI Social Impact Assessment Standards (ICSI SIAS) approved for onward submission to the SEBI
- e. Implementation of a Single Sign-on uniform and Integrated digital platform for Students, Members, Employees and other Stakeholders through Business Process Reengineering (BPR)
- f. ICSI Elections-2026 in electronic mode, comprising of booth-based venue voting (anywhere voting in the Region) and remote e-voting (instead of postal ballot).
- g. Constitution of Taskforce on Artificial Intelligence and Digital Governance and Taskforce on Digital Personal Data Protection (DPDP) Act and Cyber Laws
- h. Limits for financial assistance under CSBF enhanced from Rs. 10,00,000/- to Rs. 15,00,000/- (Fee limit also enhanced).

3. Events Conducted:

- a. 27th National Conference of Practising Company Secretaries held on 13-14 June, 2026 at Pune in the presence of Prof. (Dr.) Gourav Vallabh, Member (Part-time), Economic Advisory Council to the Prime Minister.
- b. Days like PCS Day, GST Day, celebrated Pan India across all CCGRTs, Regional and Chapter Offices
- c. First Bi-annual Convocations held for all 4 regions at Guwahati (EIRO), Amritsar (NIRO), Ahmedabad (WIRO), Thiruvananthapuram (SIRO)
- d. ICSI PSU Conference at Ahmedabad
- e. ICSI AI Conference at Indore
- f. Master Knowledge Series 6.0 initiated

4. Social Initiatives / Collaborative activities:

- a. SME Fund Raising Conclave held at Guwahati, ICSI Noida and Manesar (A SEBI initiative in collaboration with BSE and AIBI)
- b. ICSI Outreach Programme for NGOs on registration and Listing on SSEs (with NABARD) at Bhubaneswar and Bengaluru
- c. MoUs signed for software benefits, knowledge enrichment and health benefits of Members.

5. Major Publications released:

- a. Revised Guidance Note on Related Party Transactions
- b. Corporate Governance: From Compliance to Excellence (Version 5.0)
- c. Handbook on Business Responsibility and Sustainability (Version 4.0)
- d. Guidance Note on SCR for InvITs
- e. Guidance Note on SCR for REITs
- f. Guidance Note on Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 (Revised Edition, 2026)
- g. ICSI Auditing Standards (CSAS-1 to CSAS- 4), Revised Edition 2026

6. Enhancing Global Presence:

- a. 19th IPFDP at Japan from 26 May, 2026 to 02 June, 2026
- b. 5th International Conference (Mauritius) 03-05 August, 2026
- c. Online French Language Course
- d. ICSI India-Australia Facilitation Centre
- e. ICSI Participation in
 - i. ICGN Summer Conference (Amsterdam) (25-26 June, 2026)
 - ii. XX Anniversary International Forum on Corporate Governance (Moscow, Russia) (09-10 July, 2026)

7. Infrastructural Expansions:

- a. Foundation Stone Laying Ceremony conducted for Gurugram Chapter
- b. ICSI Hyderabad Chapter – new premises inaugurated

8. Student related activities:

- a. First Examinations conducted for Restructured CSEET
- b. Purview of Alternate CLDP to include Students who have passed Professional Programme 05 years prior and have completed or are exempt from Long-Term Practical Training AND Students residing in foreign countries.
- c. Approved the Exposure Draft of New Syllabus 2027 comprising of scheme of papers, Mode of Examination and Assessment Pattern, for Stakeholder' Consultation
- d. Accorded approval for revision of the eligibility criteria for registration to the Company Secretary Executive Entrance Test (CSEET) by permitting provisional registration of students who have passed Class X/Matriculation.
- e. Accorded approval for constitution of the ICSI Students' Benevolent Fund (SBF) for providing financial assistance to registered students facing unforeseen emergencies.

Thakur Vaidyanath Aiyar & Co
Chartered Accountants
221-223 Deen Dayal Marg,
New Delhi-110002
Ph. No. 011-23236958/59/60
Email: tvandeca@gmail.com

S K Mittal & Co
Chartered Accountants
MITTAL HOUSE, E-29
SOUTH EXTENSION PART - II
NEW DELHI - 110049
Tel: 26258517 - 41640694
Fax: 26255204

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF COUNCIL OF
THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA ("The ICSI")

Report on the accompanied Financial Statements of The Institute of Company Secretaries of India

Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of The Institute of Company Secretaries of India ("The Institute") which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Income & Expenditure Account, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as "financial statements") in which are incorporated the returns / financial statements audited by Auditors of the Institute's Regional Councils and Chapters.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and read with notes on accounts and matters described in the emphasis of matters and other matters paragraph of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Company Secretaries Act, 1980 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- i. in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Institute as at March 31, 2026;
- ii. in the case of Income and Expenditure Account, of the Surplus of the Institute for the year ended on that date and,
- iii. in the case of the Cash Flow Statement, of the Cash Flow for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) as issued by the Institute of Chartered Accountants of India and generally accepted in India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the accompanied Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the accompanied financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the accompanied financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following matter in the Notes to the Financial Statements:

- i. As referred to in Note 29(2)(B)(17), the information required under Accounting Standard-18 with respect to Key Management Personnel (KMP) as per section 16(1) of the Company Secretaries Act, 1980 (as amended from time to time) is yet to be notified by the competent authority and hence disclosure is not required till the notification of the same by the competent authority.

Our opinion has not been modified in respect of the above matter.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation of these accompanied financial statements in accordance with the Company Secretaries Act, 1980 ("the Act") that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with accounting principles generally accepted in India,

including applicable Accounting Standards. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate or to cease operations of the Institute, or has no realistic alternative but to do so.

The Council of the Institute is also responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of Financial Statement

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditors' Report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical

requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

We did not audit the financial statements/information of four Regional Offices including 76 Chapters which are included in the financial statements of the Institute whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 86,94,86,268/- at the year ended March 31, 2026 and total revenues of Rs. 28,55,87,714/- for the year ended March 31, 2026 and Cash and Cash Equivalent of Rs. 5,05,17,689/- at March 31, 2026, as considered in the financial statements.

The financial statements/information of these Regional Offices and Chapters have been audited by the other Auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these offices, is based solely on the report of such Auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory requirements

Further, we report that:

- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b. In our opinion proper books of accounts are maintained in conformity with requirement of the Company Secretaries Act, 1980 so far it appears from examination of books records and proper returns received from other offices;
- c. The Balance Sheet, the Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
- d. The financial statements disclose the financial impact of pending litigations on the financial position of the ICSI (refer Note 29(2)(B)1).
- e. The Institute did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- f. In our opinion, the Balance Sheet, the Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India.

For THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000038N

(M.P. Thakur)
Partner
Membership No.052473
UDIN:26052473AYJHPE3822

Place: New Delhi
Date: 29-08-2026

For S K MITTAL & Co
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 001135N

(S. Murthy)
Partner
Membership No. 072290
UDIN: 26072290OZLACN2598

Place: New Delhi
Date: 29-08-2026

**THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2026**

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	NOTE NO.	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025
I. SOURCES AND LIABILITIES			
(1) Reserves & Surplus			
(a) Reserve & Surplus	1	9,74,32,40,720	8,99,55,99,968
(b) Earmarked Funds	2	1,09,10,81,817	1,25,34,40,530
SUB-TOTAL		10,83,43,22,537	10,24,90,40,498
(2) Non- Current Liabilities			
(a) Long Term Borrowings		-	-
(b) Long Term Liabilities		39,000	35,500
(c) Long Term Provisions		-	-
SUB-TOTAL		39,000	35,500
(3) Current Liabilities			
(a) Short Term Borrowings		-	-
(b) Sundry Creditors	3	7,94,42,138	6,77,25,670
(c) Other Current Liabilities	4	28,01,49,327	25,12,27,421
(d) Short term Provisions	5	12,13,20,074	11,01,58,646
SUB-TOTAL		48,09,11,539	42,91,11,737
TOTAL		11,31,52,73,076	10,67,81,87,734
II. ASSETS			
(1) Non-current Assets			
(a) Property, Plant & Equipment	6		
(i) Tangible Assets		1,91,60,57,481	1,72,40,47,300
(ii) Intangible Assets		55,46,425	86,85,601
(iii) Capital Work in Progress	7	20,32,94,394	23,52,59,224
SUB-TOTAL		2,12,48,98,301	1,96,79,92,125
(b) Non-current Investments	8	5,99,74,90,420	5,40,59,07,254
(c) Other Non-current Assets	9	86,41,191	2,69,81,014
(d) Long Term Loans & Advances		11,44,270	12,36,766
SUB-TOTAL		8,13,21,74,181	7,40,21,17,158
(2) Current Assets			
(a) Current Investments	10	2,01,42,82,249	2,07,70,80,507
(b) Inventories	11	73,45,352	73,48,040
(c) Sundry Debtors	12	1,65,09,436	5,07,33,145
(d) Cash and Cash Equivalents	13	26,65,15,971	22,68,69,527
(e) Other current Assets	14	87,84,45,887	91,40,39,358
SUB-TOTAL		3,18,30,98,895	3,27,60,70,577
TOTAL		11,31,52,73,076	10,67,81,87,734
ACCOUNTING POLICIES AND OTHER NOTES TO THE ACCOUNTS	29		

Notes referred to above form an integral part of the Financial Statements

Shree Prakash
Director (Finance)

CS Asish Mohan
Secretary

CS Dwarakanath Chennur
Vice President

CS Pawan G Chandak
President

As per our report of even date
For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.

For S K Mittal & Co.

Chartered Accountants
Firm Registration Number: 000038N

(M. P. Thakur)
Partner
(Membership No. 052473)

Place: New Delhi
Date: 29-08-2026

Chartered Accountants
Firm Registration Number: 001135N

(S. Murthy)
Partner
(Membership No. 072290)

Place: New Delhi
Date: 29-08-2026

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	Note No.	For the year ended	
		31st March 2026	31st March 2025
INCOME			
Income from Activities	15	1,73,93,52,326	1,46,69,28,651
Interest on Investments	16	54,20,37,312	54,67,23,993
Other Income	17	6,00,20,492	4,60,92,908
Other Services- Income	18	9,87,69,548	10,19,13,713
TOTAL INCOME		2,44,01,79,678	2,16,16,59,265
EXPENDITURE			
Employee Benefit Expenses	19	65,73,73,751	69,56,80,657
Study Material & Others / Oral Education Expense		11,48,13,395	13,88,78,799
Publications & Branding Expenses		1,08,19,810	82,51,945
Examinations Expenses	20	20,31,17,791	21,91,09,932
Travelling and Conveyance Expense	21	2,27,33,152	2,32,17,498
Programmes / Seminars Expenses	22	33,28,94,048	23,79,20,442
Career Awareness and Promotion Expense		2,15,03,184	1,99,62,843
Chartered Secretary Journal & Bulletins		2,58,56,510	2,82,30,989
Depreciation & Amortization	6	9,80,03,909	9,06,79,050
Legal Services	23	57,93,617	81,80,294
Professional Services	24	1,48,34,157	79,09,854
Electricity and Water		2,42,66,473	2,61,14,404
Communication Expenses	25	95,05,180	79,03,513
Other Expenses	26	18,59,59,787	16,62,06,079
Other Services- Expense	27	9,77,91,632	10,15,06,923
TOTAL EXPENDITURE		1,82,52,66,396	1,77,97,53,222
Surplus before Exceptional items/ Extra Ordinary Items		61,49,13,282	38,19,06,043
Add / (Less) to Surplus:			
Exceptional Items	28	2,68,37,803	5,28,70,250
Surplus before Extra Ordinary Items		64,17,51,085	43,47,76,293
Add / (Less) to Surplus:			
Extra Ordinary Items		-	-
Surplus after Extra Ordinary Items		64,17,51,085	43,47,76,293
Appropriation to Funds / Reserves :			

- Performance related incentive Fund		1,64,02,700	1,49,10,893
- Interest to Earmarked Fund		10,62,96,603	10,90,51,664
- CS Benevolent Fund		12,96,831	8,19,987
- Building & Technology Development Reserve		-	20,00,000
Appropriations		12,39,96,134	12,67,82,544
Net Surplus transferred to General Reserve		51,77,54,951	30,79,93,749
TOTAL		64,17,51,085	43,47,76,293
ACCOUNTING POLICIES AND OTHER NOTES TO THE ACCOUNTS	29		

Notes referred to above form an integral part of the Financial Statements

For and on behalf of the Institute

Shree Prakash
Director (Finance)

CS Asish Mohan
Secretary

CS Dwarakanath Chennur
Vice President

CS Pawan G Chandak
President

As per our report of even date
For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number: 000038N

For S K Mittal & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number: 001135N

(M. P. Thakur)
Partner
(Membership No. 052473)

(S. Murthy)
Partner
(Membership No. 072290)

Place: New Delhi
Date: 29-08-2026

Place: New Delhi
Date: 29-08-2026

**THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026**

(Amount in Rs.)

	2025-26	2024-25
Cash Flow from Operating Activity		
Net Surplus after Prior period, Extra ordinary and Exceptional items as per I & E Account	64,17,51,085	43,47,76,294
Adjustment for:		
Add : Depreciation on Fixed Assets	9,80,03,909	9,06,79,050
Add : Actuarial Loss on Leave Encashment	0	1,89,10,134
Add : Loss on Sale of Assets/ Stock	35,72,081	2,01,438
Cash flow from operation after adjustment for non cash expenses	74,33,27,075	54,45,66,916
Less: : Income from Investment	54,20,37,312	54,67,23,993
: Surplus on Disposal of Assets	31,373	3,67,12,341
: Adjustment related to Purchase of Assets from Funds utilised in Prior Periods	16,22,483	62,60,400
Actuarial Gain on Pension Fund	2,36,68,938	99,29,364
Actuarial Gain on Leave Encashment	93,42,695	-
: Contribution for Trusts/ Funds	12,96,831	8,19,987
Operating Surplus before Working Capital and Funds Changes	16,53,27,443	(5,58,79,169)
Increase /(Decrease) in Current Assets and Current Liabilities		

	(Increase)/Decrease in Inventory	2,688		(31,32,148)	
	(Increase)/Decrease in Sundry Debtors net of bad debts	3,42,23,709		(43,68,776)	
	(Increase)/Decrease in Other Current Assets	5,92,62,409		1,51,30,524	
	(Increase)/Decrease in Long Term Loans & Advances	92,496		(1,00,130)	
	(Increase)/Decrease in Other Non Current Assets	1,83,39,823		3,50,89,305	
	Increase/(Decrease) in Sundry Creditors	1,17,16,468		(4,31,00,838)	
	Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	2,89,21,906		5,23,14,400	
	Increase/(Decrease) in Short Term Provisions	1,11,61,428		5,20,68,183	
	Increase/(Decrease) in Non- Current Liabilities	3,500		(8,500)	
	Receipts (Utilisation) in Award for Corporate Governance Funds (Net)	(1,28,15,433)		(77,55,349)	
	Receipts (Utilisation) Staff Training Fund	(6,46,020)		(3,50,920)	
	Receipts (Utilisation)/ (Transfer) from Leave Encashment Fund	(3,14,31,937)		(2,37,38,144)	
	Receipts (Utilisation) Endowment Prize Award Fund	(4,94,878)		(3,01,292)	
	Receipts (Utilisation) Professional Development Fund	1,34,21,694		44,97,036	
	Receipts (Utilisation) Performance Related Incentive Fund	(1,64,48,323)	11,53,09,531	(1,49,10,893)	6,13,32,458
Net cash generated from operating activity			28,06,36,973		54,53,289
Cash flow from Investing Activity					
	Income from Investments	54,20,37,312		54,67,23,993	
	Sale Proceeds of Redemption of Investments/ Mutual Funds (Non-Current)	56,66,73,524		36,74,17,727	
	Sale Proceeds of Redemption of Investments/ Mutual Funds (Current)	1,96,12,85,688		61,71,70,225	
	Acquisition of Investments/ Mutual Fund Units (Non- Current)	(1,84,47,56,691)		(1,17,69,80,551)	
	Acquisition of Investments/ Mutual Fund Units (Current)	(1,21,19,87,430)		(15,05,47,294)	
	Sale Proceeds of Fixed Assets	35,45,607		3,89,00,453	
	Contribution for Endowment Prize Award Fund	2,00,000		4,00,000	
	Contribution for Infrastructure Fund	-		20,00,000	
	Acquisition of Fixed Assets including WIP	(25,21,75,107)		(11,04,90,829)	
Net Cash used in Investing Activity			(23,51,77,097)		13,45,93,724
Cash Generated From Financing Activities					
	Addition in General Reserve and Corpus Donations	60,08,411		7,10,790	
	Increase/(Decrease) in Library Reserve (Net)	81,640		62,912	
	Increase/(Decrease) in Building Reserve excluding appropriation from I & E (Net)	-		(23,02,203)	
	(Increase)/Decrease in Contribution / Utilisation to/from RC / Chapters towards assets	(2,67,98,288)		(4,28,70,083)	
	Increase/(Decrease) in Other Reserve and Funds (Net)	(36,29,194)		(38,230)	
	Increase/(Decrease) in Capital Reserve	1,85,24,000		1,34,70,000	

Net cash generated from Financing Activities		(58,13,431)		(3,09,66,814)
Net Cash Flow for the Year ended as on 31st March 2026 (A)		3,96,46,445		10,90,80,199
Cash and cash equivalent at the beginning of the year (B)		22,68,69,527		11,77,89,329
Cash and cash equivalent at the end of the year		26,65,15,971		22,68,69,527

Note:				
1	The above Cash Flow Statement has been derived using the Indirect method prescribed in AS-3.			
2	Enclosed Notes 1 to 29 form an intergral part of the Cash Flow Statement.			
3	Cash and cash equivalents include:			
a	Cash, Cheques/Drafts/Postal Orders & Postage Stamps.	4,90,223		6,32,481
b	Balances with Scheduled Banks			
	- In Savings Bank accounts (incl Term deposits)	26,60,25,748		22,62,37,046
		26,65,15,971		22,68,69,527

For and on behalf of the Institute

Shree Prakash
Director (Finance)

CS Asish Mohan
Secretary

CS Dwarakanath Chennur
Vice President

CS Pawan G Chandak
President

As per our report of even date
For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number: 000038N

For S K Mittal & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number: 001135N

(M. P. Thakur)
Partner
(Membership No. 052473)

(S. Murthy)
Partner
(Membership No. 072290)

Place: New Delhi
Date: 29-08-2026

Place: New Delhi
Date: 29-08-2026

RESERVES & SURPLUS

NOTE - 1
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	As at 31st March 2026		As at 31st March 2025	
(1) CAPITAL RESERVE				
As per last Balance Sheet		16,34,53,040		14,99,83,040
Add: Entrance Fees from Members				
- Associate Members	1,63,34,000		1,17,12,000	
- Fellow Members	21,90,000	1,85,24,000	17,58,000	1,34,70,000
Sub-Total (1)		18,19,77,040		16,34,53,040
(2) GENERAL RESERVE				
As per last Balance Sheet		8,69,39,48,137		8,30,42,74,904
Add : Additions during the year		32,01,681		7,63,821
Add : Corpus donation		-		58,450
Less : Donation Transferred		25,000		-
Add : Transfer from Infrastructure Fund		22,73,07,033		8,09,68,693
Add/(Less):Adjust/Transfer to Other Reserve		49,94,312		4,18,351
Less : Adjustment/ Utilisation during the year		-21,87,582		-5,29,832
		8,92,72,38,581		8,38,59,54,387
Surplus (Excess of Inc over Expe) from I & E		51,77,54,951		30,79,93,749

Sub-Total (2)		9,44,49,93,531		8,69,39,48,136
(3) OTHER THAN GENERAL RESERVE, IF ANY				
Office renovation Fund - As per Last B/S		1,05,502		1,05,502
Fixed Assets Reserve-As per Last B/S		73,220		73,220
Prize Distribution Fund- As per Last B/S		1,82,465		1,82,465
Sub-Total (3)		3,61,187		3,61,187
(4) Library Reserve				
As per last Balance Sheet		32,41,746		31,78,832
Add: Donation		41,672		30,375
Add : Interest		39,968		32,538
Less: Utilisation		74,217		-
Sub-Total (4)		33,97,603		32,41,745
(5) Building Reserve				
As per last Balance Sheet		12,45,27,399		12,50,38,501
Add: Donation		-		8,63,322
Less : Adjustment / utilisation		24,999		-13,74,424
Sub-Total (5)		12,45,52,398		12,45,27,399
(6) Infrastructure Reserve				
As per last Balance Sheet		3,28,33,593		3,28,33,593
Sub-Total (6)		3,28,33,593		3,28,33,593
(7) Other Reserve Account				
As per last Balance Sheet		82,358		82,358
Sub-Total (7)		82,358		82,358
(8) Other Reserve				
As per last Balance Sheet		91,80,558		92,18,788
Add: Transfer from / (to) Reserve		9,21,795		-
Add: Interest		1,33,431		1,00,430
Less: Utilisation/Adjustment during the year		-46,84,420		-1,38,660
Sub-Total (8)		55,51,364		91,80,558
(9) CONTRIBUTION TO / FROM TOWARDS L/BLDG / OTHER ASSETS				
Opening Balance : Contribution -Liabilities		9,41,52,498		1,08,42,035
Add: Contrib. from RC/Chap towards Liability		3,30,02,216		-1,95,56,057
Less: Contrib. to RC/Chapters towards Assets		-17,76,63,068		-2,33,14,026
Sub-Total (9)		-5,05,08,354		-3,20,28,048
Total : (1 to 9)		9,74,32,40,720		8,99,55,99,968

EARMARKED FUND

NOTE - 2

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	ICSI NATIONAL AWARD FOR EXCELLENCE IN CORPORATE GOVERNANCE FUND		STAFF TRAINING FUND		LEAVE ENCASHMENT FUND		ENDOWMENT FOR PRIZE AWARD FUND	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
As per last Balance Sheet	18,87,43,525	18,22,30,637	1,11,54,588	1,06,66,245	23,94,44,563	20,67,53,541	1,19,87,209	1,10,59,871
Add: Contribution during the year	-	-	-	-	-	-	2,00,000	4,00,000
Transfer from Gen Reserve	-	-	-	-	-	1,89,10,134	-	-
Add: Receipts during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
Add: Interest allocation	1,45,86,865	1,42,68,237	8,66,526	8,39,263	4,21,57,529	3,75,19,032	8,08,710	7,64,293
Sub-Total	20,33,30,390	19,64,98,874	1,20,21,114	1,15,05,508	28,16,02,092	26,31,82,707	1,29,95,919	1,22,24,164
Less: Utilised during the year	1,28,15,433	77,55,349	6,46,020	3,50,920	4,07,74,632	2,37,38,144	4,94,878	3,01,292
Balance as at the close of the year	19,05,14,957	18,87,43,525	1,13,75,094	1,11,54,588	24,08,27,460	23,94,44,563	1,25,01,041	1,19,22,872

PARTICULARS	PERFORMANCE RELATED INCENTIVE FUND		INFRASTRUCTURE FUND (incl. Land & Building Fund, Technology Development fund of SIRC)		PROFESSIONAL DEVELOPMENT FUND		TOTAL AMOUNT	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
As per last Balance Sheet	51,06,385	47,28,134	72,80,04,066	75,15,59,289	6,90,64,531	6,45,67,496	1,25,35,04,867	1,23,15,65,213
Add: Contribution during the year	1,64,02,700	1,49,10,893	-	-	1,34,21,694	44,97,035	3,00,24,394	1,98,07,928
Transfer from Gen Reserve	-	-	-	20,00,000	-	-	-	2,09,10,134
Add: Receipts during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
Add: Interest allocation	4,06,686	3,78,251	4,72,32,559	5,54,13,470	-	-	10,60,58,875	10,91,82,546
Sub-Total	2,19,15,771	2,00,17,278	77,52,36,625	80,89,72,759	8,24,86,225	6,90,64,531	1,38,95,88,136	1,38,14,65,821
Less: Transfer to GR on utilisation	-	-	-	-	-	-	-	-
Less: Utilised during the year	1,64,48,323	1,49,10,893	22,73,27,033	-	-	-	29,85,06,319	4,70,56,598
Less : On acquisition of Land & Bldg	-	-	-	8,09,68,693	-	-	-	8,09,68,693
Balance as at the close of the year	54,67,448	51,06,385	54,79,09,592	72,80,04,066	8,24,86,225	6,90,64,531	1,09,10,81,817	1,25,34,40,530

SUNDRY CREDITORS**NOTE - 3**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025
Supplies (Including dues to MSME- Refer Note no. 29-2 (B)-7)	3,63,95,337	1,19,53,168
Services and Other (Including dues to MSME- Refer Note no. 29-2 (B)-7)	4,30,46,801	5,54,08,622
Capital payment (CAPAX) through RO/C	-	3,63,880
Total :	7,94,42,138	6,77,25,670

OTHER CURRENT LIABILITIES**NOTE - 4**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025
Fee Received in advance		
- Student related Fee (Exam Fees)	13,51,43,822	12,02,85,266
- Membership Fee and others	1,54,62,708	1,29,62,431
Payable to Trusts / Funds/ Others (Including Liability towards Fixed Term Employees for Gratuity as per new Labour Laws [Refer Note No. 29-2 (B) (6)] *)	7,58,24,960	5,88,99,287
Security Deposits	1,06,66,449	1,02,64,552
Retention Money	2,34,35,690	3,49,04,938
Property Tax Payable	26,76,708	16,21,000
Income Tax Payable	91,20,097	35,16,721
GST Payable	10,76,655	55,99,384
Earnest Money Refundable	37,42,000	16,22,750
Other Payables	30,00,238	15,51,092
Total :	28,01,49,327	25,12,27,421

* Includes Rs. 35,13,644/- towards Liability for non-funded Gratuity for Fixed Term Employees as per new Labour laws [Refer Note No. 29-2 (B) (6)].

SHORT TERM PROVISIONS**NOTE - 5**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025
Provisions for Expenses	12,13,20,074	11,01,58,646
Total :	12,13,20,074	11,01,58,646

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

NOTE - 6

(Amount in Rs.)

Items		Gross Block				Depreciation / Amortization				Net Block	
		Cost as on 1.4.2025	Additions	Adjustment/ Transfer/ Sale	Total cost as on 31.3.2026	Total as on 1.4.2025	For the Year	Adjustment/ Transfer/ Sale	Total as on 31.3.2026	as on 31.3.2026	as on 31.3.2025
(i)	Tangible Assets										
	Land										
	Freehold	25,08,15,158	7,97,13,206	-	33,05,28,364	-	-	-	-	33,05,28,364	25,08,15,158
	Leasehold	30,24,50,802	-	-	30,24,50,802	3,32,09,713	32,51,451	-	3,64,61,164	26,59,89,638	26,92,41,089
	Building	1,47,14,38,972	15,47,78,619	14,90,000	1,62,47,27,591	44,99,04,229	5,35,82,005	-	50,34,86,234	1,12,12,41,357	1,02,15,34,743
	Furniture & Fixtures @ &	17,37,67,878	85,33,311	78,23,621	17,44,77,568	10,11,28,932	92,81,931	1,30,03,735	9,74,07,128	7,70,70,439	7,26,38,945
	Computer Peripherals	12,05,24,166	64,46,109	62,90,873	12,06,79,402	9,81,05,894	1,01,17,597	59,01,245	10,23,22,246	1,83,57,157	2,24,18,273
	Cooling Equipment	9,26,05,071	1,20,54,181	26,73,641	10,19,85,611	5,07,02,530	67,84,256	20,11,028	5,54,75,758	4,65,09,853	4,19,02,541
	Electrical Equipment	6,94,21,534	69,05,425	33,44,308	7,29,82,651	4,59,43,709	38,59,748	24,86,742	4,73,16,715	2,56,65,936	2,34,77,825
	Office Machines & Comm Equipment	6,14,55,264	1,44,67,639	1,11,86,357	6,47,36,546	4,48,62,570	42,32,981	95,75,230	3,95,20,321	2,52,16,225	1,65,92,694
	Other Equipment @	1,50,44,032	7,35,390	9,44,442	1,48,34,980	1,00,10,510	7,95,514	11,07,447	96,98,577	51,36,403	50,33,522
	Library Books	67,49,437	25,12,659	6,88,715	85,73,381	67,40,585	24,87,697	6,90,083	85,38,199	35,183	8,852
	Vehicles	17,46,662	-	2,938	17,43,724	13,63,003	76,732	2,938	14,36,797	3,06,927	3,83,659
	Current Year Total (i)	2,56,60,18,976	28,61,46,539	3,44,44,895	2,81,77,20,620	84,19,71,675	9,44,69,912	3,47,78,448	90,16,63,139	1,91,60,57,481	1,72,40,47,300
	Previous Year Total	2,44,71,83,758	14,09,37,705	2,21,02,038	2,56,60,19,425	77,27,81,838	8,88,41,387	1,96,51,102	84,19,72,123	1,72,40,47,302	1,67,44,01,930
(ii)	Intangible Assets										
	Software & Applications	4,76,64,663	4,73,398	-25,489	4,81,04,098	3,89,79,063	35,33,997	-44,613	4,25,57,673	55,46,425	86,85,601
	Current Year Total (ii)	4,76,64,663	4,73,398	-25,489	4,81,04,098	3,89,79,063	35,33,997	-44,613	4,25,57,673	55,46,425	86,85,601
	Previous Year Total	3,80,37,835	96,79,669	-25,167	4,76,64,663	3,71,77,620	18,37,662	36,219	3,89,79,063	86,85,600	8,60,215
	Current Year Total (i+ii)	2,61,36,83,639	28,66,19,937	3,44,19,406	2,86,58,24,718	88,09,50,738	9,80,03,909	3,47,33,835	94,42,20,812	1,92,16,03,906	1,73,27,32,901
	Previous Year Total (i+ii)	2,48,52,21,593	15,06,17,374	2,20,76,871	2,61,36,84,088	80,99,59,458	9,06,79,050	1,96,87,321	88,09,51,186	1,73,27,32,902	1,67,52,62,145

@ Includes Furniture and Fixtures of Rs.79,15,873/- and Other Equipments of Rs. 4,02,109/- by way of adjustment on account of assets purchased /paid by HQ during the F.Y. 2023-24 to CCGRT, Kolkata on 01-04-2024 and accordingly, Depreciation of Furniture and Fixtures and Other Equipments includes for F.Y. Rs. 7,91,587/- and Rs. 60,316/- respectively, Total being Rs. 8,51,903/-.

& Includes Reversal of Furniture and Fixtures (Cost Rs. 24,80,000/- and accumulated depreciation of Rs. 16,22,483/-) capitalised in FY 2014-15 related to Bengaluru Chapter for which a legal case is pending against the supplier before Honourable High Court of Karnataka.

CAPITAL WORK IN PROGRESS (CWIP)**NOTE - 7**
(Amount in Rs.)

Items	Gross Block			
	Costs on 1.4.2025	Additions/ Adjustment	Capitalisation/ Adj. during the year	Total cost as on 31.3.2026
A. TANGIBLE				
Land under acquisition	9,17,21,119	3,88,91,994	7,97,13,206	5,08,99,907
Capital Advance for Building acquisition [Refer note no. 29-2 (B)- (16)]	83,23,000	-	20,000	83,03,000
Capital Renovations/Improvements	13,52,15,105	18,84,35,039	17,95,58,657	14,40,91,487
Current Year Total (A)	23,52,59,224	22,73,27,033	25,92,91,863	20,32,94,394
Previous Year Total	26,91,25,370	8,09,68,693	11,48,34,838	23,52,59,225
B. INTANGIBLE ASSETS				
Softwares under development	-	-	-	-
Current Year Total (B)	-	-	-	-
Previous Year Total	-	64,09,756	64,09,756	-
Grand Total Current Year	23,52,59,224	22,73,27,033	25,92,91,863	20,32,94,394
Grand Total Previous Year	26,91,25,370	8,73,78,449	12,12,44,594	23,52,59,224

NON-CURRENT INVESTMENTS**NOTE - 8**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	AS ON 01.04.2025	ADDITIONS	MATURITY/ RDEMPTION/ AMORTI SATION	TRANSFER TO CURRENT	AS ON 31.03.2026
I. INVESTMENT IN GOVT. SECURITIES					
(i) GOI SAVING BONDS	10,58,000	-	-	-	10,58,000
SUB-TOTAL(I)	10,58,000	-	-	-	10,58,000
II. INVESTMENT IN DEBENTURES / BONDS					
(i) 8.70% LIC HSG 2029	9,47,71,319		11,98,436		9,35,72,883
(ii) 7.99% LIC HSG 2029	12,62,98,023		10,03,055		12,52,94,968
(iii) 7.03% NHAI 2040	39,60,74,578		3,23,831		39,57,50,747
(iv) 7.05% NHAI 2041	38,89,86,481		1,26,208	-	38,88,60,273
(v) 7.14% NHAI 2040	37,33,63,241		20,582		37,33,42,659
(vi) 7.26% NHAI 2038	8,78,96,527		1,41,905		8,77,54,622
(vii) 7.48% NHAI 2040	25,69,23,681		3,97,776		25,65,25,905
(viii) 7.90% AP SDL 2033	24,72,86,718	-	2,79,803		24,70,06,915
(ix) 7.85% Bihar SGS 2032	29,09,39,605	-	1,24,666		29,08,14,939
(x) NHAI 7.98% Bond 23.12.2049	10,71,777		2,991		10,68,786
(xi) HDFC 6.88% Bond 24.09.2031	9,94,000	-			9,94,000
(xii) LICHL 7.13% Bond 24.11.2031	19,87,000				19,87,000
(xiii) NHAI 6.99% Bond 28.05.2035	19,38,900	-			19,38,900
(xiv) 10.04% IRFC Bonds	10,95,500	-			10,95,500
(xv) 7.48% IRFC Bonds	19,72,500	-			19,72,500
(xvi) 8.27% NHAI Bonds	10,35,300	-			10,35,300
(xvii) 8.35% IRFC Bonds	20,99,200	-			20,99,200
(xviii) 8.79% IRRC Bonds	10,72,600	-			10,72,600

(xix)	7% PFC Bond 22.01.2031 (Face value 1000/-)	19,51,600				19,51,600
(xx)	7.54% IRFC Bonds	10,29,000				10,29,000
SUB-TOTAL(II)		2,27,87,87,550	-	36,19,253	-	2,27,51,68,297
III	INVESTMENT IN MUTUAL FUNDS					
(i)	SBI MF Direct Growth	8,99,98,750	29,50,00,000	-	-	38,49,98,750
(ii)	Canara Robeco MF Direct-Growth	5,74,98,750	18,65,00,000	-	-	24,39,98,750
(iii)	UTI MF - Direct- Growth	4,24,99,750	3,00,00,000	-	-	7,24,99,750
SUB-TOTAL(III)		18,99,97,251	51,15,00,000	-	-	70,14,97,251
IV	OTHER NON-CURRENT INVESTMENTS					
(A)	Fixed Deposits in Banks					
(i)	Canara	2,06,00,23,376	19,88,43,849	46,39,72,496	40,15,00,000	1,39,33,94,729
(ii)	Union Bank of India(CB)	22,97,43,698	11,94,45,606	2,27,86,776	-	32,64,02,527
(iii)	BOB	1,86,14,563	78,88,311	49,57,605	-	2,15,45,269
(iv)	State Bank of India (SBI)	30,69,66,716	1,59,85,763	4,49,002	28,50,00,000	3,75,03,477
(v)	Punjab National Bank	33,87,159	19,30,299	1,74,367	-	51,43,091
(vi)	Central Bank of India	46,36,507	52,34,22,114	-	-	52,80,58,621
(vii)	Bank of Maharashtra	24,56,535	7,604	4,92,155	-	19,71,984
(viii)	Karnataka Bank	5,13,961	57,891	-	-	5,71,852
(ix)	Indian Overseas Bank	3,43,81,977	4,14,15,637	2,72,29,561	-	4,85,68,053
(x)	Yes Bank	2,50,000	40,00,000	-	-	42,50,000
(xi)	UCO Bank	2,20,000	-	2,20,000	-	-
(xii)	IDBI Bank	44,84,500	45,70,000	42,10,000	-	48,44,500
(xiii)	Corporation Bank	25,95,241				25,95,241
(xiv)	Bank of India	-	14,98,819	11,28,819		3,70,000
(xv)	ICICI Bank	4,00,000	-			4,00,000
SUB-TOTAL(A)		2,66,86,74,234	91,90,65,893	52,56,20,781	68,65,00,000	2,37,56,19,345
(B)	Fixed Deposits with Institutions other than Banks					
(i)	TTDFC Ltd.	56,875	-	-	-	56,875
(ii)	Others	52,10,878	40,76,97,647	56,16,321	-	40,72,92,204
(iii)	Deposit with LIC Leave Encashment	9,81,15,685	64,93,151	3,18,17,169	-	7,27,91,667
SUB-TOTAL(B)		10,33,83,438	41,41,90,798	3,74,33,490	-	48,01,40,746
(C)	OTHERS (Specify nature)					
(i)	BACKBAY EXP PREM. SOC. LTD.	1,000				1,000
(ii)	BACKBAY EXP PREM. SOC. LTD.	5,781				5,781
(iii)	INVESTMENT IN SHARES (ICSI-IIP)	14,00,00,000				14,00,00,000
(iv)	INVESTMENT IN SHARES (ICSI-RVO)	2,00,00,000				2,00,00,000
(v)	INVESTMENT IN SHARES (ICSI-ADR)	15,00,000	-			15,00,000
(vi)	INVESTMENT IN SHARES (ICSI-ISA)	15,00,000	-			15,00,000
(vii)	INVESTMENT IN SHARES (ICSI-NCLT)	10,00,000	-			10,00,000
SUB-TOTAL(C)		16,40,06,781	-	-	-	16,40,06,781
SUB TOTAL (A+B+C)=IV		2,93,60,64,453	1,33,32,56,691	56,30,54,271	68,65,00,000	3,01,97,66,872
TOTAL (I+II+III+IV)		5,40,59,07,254	1,84,47,56,691	56,66,73,524	68,65,00,000	5,99,74,90,420

Net Market Value in respect of investment in Mutual Funds as on 31st March 2026, is Rs. 67,87,63,051/- (P.Y. Rs. 22,67,22,378/-) as against total Cost of Investment value of Rs. 69,99,97,250/- (P.Y. 18,99,97,250/-).

OTHER NON-CURRENT ASSETS

NOTE - 9
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025
(i) Secured, considered good		
(a) Loans to Regional Offices/ Chapters for Land/ Buildings [Refer Note No. 29-2 (B) (11)]	5,00,000	19,40,000
(b) Advances for Purchase of Land / Buildings (on behalf of Regional Offices/ Chapters)	-	1,69,08,252
(ii) Security Deposits	81,41,191	81,32,762
Total :	86,41,191	2,69,81,014

CURRENT INVESTMENTS

NOTE - 10
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	AS ON 1.4.2025	ADDITIONS	MATURITY/ RDEMPTION/ AMORTISATION	Transfer from Non- Current	AS ON 31.3.2026
I INVESTMENT IN BONDS/ SECURITIES					
(i) 8.70% IDFC First Bank LTD	5,00,06,307	-	5,00,06,307	-	-
SUB-TOTAL(I)	5,00,06,307	-	5,00,06,307	-	-
II OTHER CURRENT INVESTMENTS					
(A) Fixed Deposits in Banks					
(i) Indian Bank	3,14,69,107	17,20,153	42,41,250	-	2,89,48,010
(ii) Bank of Baroda	50,49,53,715	5,84,68,596	48,52,30,687	-	7,81,91,624
(iii) Bank of India	14,98,819	-	14,98,819	-	-
(iv) Canara Bank	4,79,28,606	1,64,22,121	3,70,50,724	40,15,00,000	42,88,00,003
(v) Central Bank of India	21,32,644	1,08,92,91,783	-	-	1,09,14,24,427
(vi) ICICI Bank	46,81,524	47,21,491	18,59,054	-	75,43,961
(vii) IDBI Bank	10,44,342	14,94,826	10,44,342	-	14,94,826
(viii) Indian Overseas Bank	2,16,13,051	9,31,710	71,87,081	-	1,53,57,680
(ix) Punjab National Bank (PNB)	43,46,259	12,05,241	-	-	55,51,500
(x) State Bank of India	3,77,96,729	2,96,16,281	1,57,84,549	28,50,00,000	33,66,28,461
(xi) UCO Bank	74,52,438	45,44,538	75,81,790	-	44,15,186
(xii) Corporation Bank	79,96,900	2,59,863	-	-	82,56,763
(xiii) Union Bank of India	1,00,72,10,066	33,10,827	1,00,28,51,085	-	76,69,808
SUB-TOTAL(II-A)	1,68,01,24,200	1,21,19,87,430	1,56,43,29,381	68,65,00,000	2,01,42,82,249
(B) Fixed Deposits with institutions other than Banks					
(i) PNB HFL	33,99,50,000	-	33,99,50,000	-	-
(ii) LIC HFL	70,00,000		70,00,000	-	-
SUB-TOTAL(II-B)	34,69,50,000	-	34,69,50,000	-	-
SUB TOTAL (II)	2,02,70,74,200	1,21,19,87,430	1,91,12,79,381	68,65,00,000	2,01,42,82,249
TOTAL (I+II)	2,07,70,80,507	1,21,19,87,430	1,96,12,85,688	68,65,00,000	2,01,42,82,249

INVENTORIES

NOTE - 11
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025
Publications & Study Material	58,02,358	60,59,445
Consumables, Stores & Others	15,42,994	12,88,595
Total	73,45,352	73,48,040

SUNDRY DEBTORS**NOTE - 12**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025
a) Sundry Debtors		
Secured, considered good	3,46,846	3,02,347
Unsecured, considered good	1,31,131	2,61,181
Doubtful	59,96,147	59,96,147
	64,74,124	65,59,675
Less : Provision for Doubtful Debtors	59,96,147	59,96,147
Sub-Total (a)	4,77,977	5,63,528
b) Others Sundry Debtors		
Secured, considered good	3,20,200	2,48,072
Unsecured, considered good	1,56,18,859	4,99,21,545
Doubtful	92,400	3,00,000
	1,60,31,459	5,04,69,617
Less : Provision for Doubtful Debtors	-	3,00,000
Sub-Total (b)	1,60,31,459	5,01,69,617
Total (a+b)	1,65,09,436	5,07,33,145

CASH AND CASH EQUIVALENTS**NOTE - 13**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025
Balances with Banks (including Linked Term Deposits of Rs. 9,43,95,003/- for CY and Rs. 10,49,52,324/- for PY related to HQ)	26,60,25,748	22,62,37,046
Cheques / Drafts / IPO / Stamps	29,443	8,103
Cash in hand	4,60,780	6,24,378
Total	26,65,15,971	22,68,69,527

OTHER CURRENT ASSETS**NOTE - 14**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025
Accrued Interst on investments	64,67,11,591	71,65,30,807
Prepaid Expenses	1,09,27,303	96,58,176
Security Deposit	44,86,863	35,20,327
GST ITC	1,07,64,424	1,21,11,824
Income Tax Refunds due up to P/Y	8,09,45,084	6,87,32,072
Tax Deducted at Source C/Y	2,26,14,558	3,61,69,152
ICSI Trusts/ Funds	8,64,66,093	5,45,26,930
Advance to Employees	9,35,622	2,69,614
Recoverable Others	45,74,353	87,57,894
Advance to Parties	1,00,19,996	37,62,562
Total :	87,84,45,887	91,40,39,358

INCOME FROM ACTIVITIES

NOTE - 15
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the Year ended			
	31st March 2026		31st March 2025	
Income from Members				
Annual Fees	16,83,09,468		16,38,35,580	
Other Fees	6,54,500	16,89,63,968	5,65,500	16,44,01,080
Income from Students				
Registration Fees	17,61,19,825		13,84,60,125	
Exemption Fees	3,48,58,000		3,17,03,750	
ODOP Reg. Fees	6,89,99,425		1,53,89,125	
Education Fees	55,29,94,818		50,14,90,550	
Examination Fees	31,63,63,855		30,52,07,750	
Oral Education Fee	1,86,79,117		2,63,52,534	
Other Fees	4,80,94,504	1,21,61,09,544	1,98,44,548	1,03,84,48,383
Sale of Publications				
Students	1,61,85,580		1,35,16,880	
Members	27,51,925	1,89,37,505	22,09,302	1,57,26,182
Programmes / Seminars				
Students	21,33,72,585		8,66,55,112	
Members	8,70,08,721	30,03,81,306	13,06,35,524	21,72,90,636
Courses : PMQ/ Certificate/Crash				
Students	39,69,000		26,88,500	
Members	2,57,29,503		2,31,59,600	
Others	52,61,500	3,49,60,003	52,14,271	3,10,62,371
TOTAL		1,73,93,52,326		1,46,69,28,651

INTEREST ON INVESTMENTS

NOTE - 16
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended	
	31st March 2026	31st March 2025
Interest on Investments and Deposits with Banks	54,20,37,312	54,67,23,993
TOTAL	54,20,37,312	54,67,23,993

OTHER INCOME

NOTE - 17
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended	
	31st March 2026	31st March 2025
Subscription to Journal / Bulletin /Newsletter	71,56,921	66,11,951
Actuarial Gain related to Pension Trust/ Leave Encashment		
(i) Pension Trust	2,36,68,938	99,29,364
(ii) Leave Encashment	93,42,695	-

Donations - General	-	35,200
Facility Charges at CCGRTs	11,99,966	2,96,500
Receipts from ICSI-IIP/RVO/ ISA/ ADR/ IGPI	98,79,811	87,33,852
Interest on income tax refunds	15,57,075	68,11,066
Sale of Waste Paper	4,50,843	4,88,012
Surplus on disposal of Assets (net of loss on sale)	11,157	1,29,952
Recoveries- Fine imposed through Disciplinary Proceedings	3,50,000	18,10,000
Other Miscellaneous Income / Receipts	64,03,086	1,12,47,011
TOTAL	6,00,20,492	4,60,92,908

OTHER SERVICES- INCOME**NOTE - 18**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended	
	31st March 2026	31st March 2025
Receipts from MCA- CRC Manesar	4,60,07,671	5,23,29,214
Receipts from MCA- CSC Manesar	49,50,435	26,42,123
Receipts from MCA- IEPFA	3,12,39,080	3,63,36,785
Receipts from MCA- C-Pace Manesar	1,08,47,656	61,46,071
Receipts from MCA- CPC Manesar	57,24,706	44,59,520
TOTAL	9,87,69,548	10,19,13,713

EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES**NOTE - 19**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended			
	31st March 2026		31st March 2025	
Salaries and Allowances		-		
HQ & CCGRT'S	41,28,61,475		40,72,76,825	
Regions/Chapter	15,12,93,273	56,41,54,748	14,27,56,289	55,00,33,114
Contribution for:				
Provident Fund	-			
HQ & CCGRT'S	78,80,392		45,95,612	
Regions/Chapter	17,14,012	95,94,404	13,80,067	59,75,679
New Pension Scheme (PFRDA)	-			
HQ & CCGRT'S	3,22,44,191		3,02,22,751	
Regions/Chapter	1,28,43,250	4,50,87,441	1,27,12,957	4,29,35,708
Gratuity				
HQ & CCGRT'S	85,55,853		3,90,02,071	
Regions/ Chapter	36,66,794		1,56,23,974	
Non Funded- FTEs (Liability towards Fixed Term Employees for Gratuity as per new Labour Laws [Refer Note No. 29-2 (B) (6)])	11,93,621	1,34,16,268	-	5,46,26,045
Leave Encashment Fund	-			
HQ & CCGRT'S	21,601		1,36,01,901	
Regions/Chapter	-	21,601	54,13,519	1,90,15,420
Staff Welfare				
HQ & CCGRT'S	1,91,94,544		1,68,70,847	
Regions/Chapter	59,04,745	2,50,99,289	62,23,844	2,30,94,691
TOTAL		65,73,73,751		69,56,80,657

EXAMINATION EXPENSES**NOTE - 20**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended	
	31st March 2026	31st March 2025
Honorarium to Paper setter/ Examiners	8,12,28,975	8,25,12,204
General Observer	86,44,413	1,01,53,751
Exam Centres	4,95,24,676	5,51,80,934
Despatch of Documents	2,58,60,064	2,79,67,552
Answer Books	63,91,940	41,09,218
Question Papers	84,20,000	1,23,25,000
Office Use Forms, Envelops, Canvas Bags etc.	2,53,797	3,32,876
Pass Certificates	1,81,781	7,73,975
Travelling	5,84,345	9,51,584
Exam Digitalisation of Records/Data	1,30,19,674	1,54,20,031
Exam Publishing E--Admit Card/ E-Result -CS Examination	6,13,600	7,08,000
Exam CSEET	74,45,514	72,89,523
Exam Others	9,49,012	13,85,284
TOTAL	20,31,17,791	21,91,09,932

TRAVELLING AND CONVEYANCE EXPENSES**NOTE - 21**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended	
	31st March 2026	31st March 2025
Travelling Expenses	2,18,55,405	2,22,75,425
Conveyance Expenses	8,77,747	9,42,073
TOTAL	2,27,33,152	2,32,17,498

PROGRAMMES / SEMINAR EXPENSES**NOTE - 22**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended	
	31st March 2026	31st March 2025
Programmes / Seminars of Members	17,25,94,121	16,11,44,705
Programmes / Seminars of Students	16,02,99,928	7,67,75,738
TOTAL	33,28,94,048	23,79,20,442

LEGAL SERVICES**NOTE - 23**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended			
	31st March 2026		31st March 2025	
Fees for Legal Services	57,93,617	57,93,617	81,80,294	81,80,294
TOTAL	57,93,617		81,80,294	

PROFESSIONAL SERVICES**NOTE - 24**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended			
	31st March 2026		31st March 2025	
Professional Services - Consultants	1,23,65,460		60,74,409	
Professional Services -Other than Consultants	24,68,697	1,48,34,157	18,35,445	79,09,854

TOTAL	1,48,34,157	79,09,854
--------------	--------------------	------------------

COMMUNICATION EXPENSES**NOTE - 25**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended			
	31st March 2026		31st March 2025	
- Telephone / Fax / E-mail / SMS	48,62,519		49,32,431	
- Courier / Postage	46,42,661	95,05,180	29,71,081	79,03,513
TOTAL	95,05,180		79,03,513	

OTHER EXPENSES**NOTE - 26**
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended			
	31st March 2026		31st March 2025	
Rent, Rates and Taxes		2,19,31,796		1,85,63,911
Stationery		74,73,429		88,07,147
Insurance		18,78,010		16,48,724
Repairs and Maintenance				
- Buildings	57,30,794		72,21,795	
- Computer	98,55,557		97,15,986	
- Other Assets	1,29,22,726		1,16,97,899	
- Vehicles	4,79,726	2,89,88,803	6,27,618	2,92,63,298
Office Expenses		1,73,82,785		1,66,16,484
Security and Housekeeping Expenses (Including Liability towards Gratuity for Fixed Term Employees as per new Labour laws) [Refer Note No. 29-2 (B) (6)]*		3,61,71,645		3,47,57,798
Newspapers and Periodicals		1,43,353		1,62,279
IT Expenses		4,18,18,228		3,36,76,986
Meeting expenses		39,02,850		35,31,307
Packing and Despatch		27,405		48,069
Election Expenses		47,412		-
Loss on sale of Assets (Net of Surplus)/Write-off of Stocks		15,82,239		2,31,782
Bank Charges		43,92,969		41,39,476
Student Scholarship and Awards		44,656		2,51,870
Statutory Auditors Remuneration:				
- Remuneration (Including reimbursement of Expenses)	22,05,940		21,48,029	
- Other Certification Services	68,850	22,74,790	1,11,010	22,59,039
Internal Audit Fees		24,93,174		19,15,523
Contribution to Appellate Authority		30,00,000		27,50,000
GST Input Reversal		4,20,519		1,16,889
Unclaimable GST Credit written off		48,389	1,51,000	1,51,000
Building Inauguration/ Foundation stone laying Exps.		-	7,14,762	7,14,762
Miscellaneous expenses		6,32,854		18,20,834
Bad Debts		4,41,550		1,32,070
Subscription & Membership		2,33,750		-
Late Fee/ Interest on GST/TDS		17,890		14,844
TDS / Income Tax Recoverable written off		14,798		61,251
CCGRT, Manesar Expenses #		48,42,955		-
Expenses related to IIP/ RVO/ ISA/ ADR/ IGPI		57,53,538		45,70,736
TOTAL		18,59,59,787		16,62,06,079

* Includes Rs. 5,17,870/- towards Liability for non-funded Gratuity for Fixed Term Employees (Security and Housekeeping staff) as per new Labour laws [Refer Note No. 29-2 (B) (6)].

Includes Expenses related to Operationalisation, Security Services, Housekeeping, Electricity etc. for running and maintenance of the CCGRT-Manesar.

OTHER SERVICES- EXPENSE

NOTE - 27
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended	
	31st March 2026	31st March 2025
CRC Manesar Expenses	4,55,52,151	5,24,13,359
CSC Manesar Expenses	49,01,420	26,15,964
MCA- IEPFA Expenses	3,09,29,783	3,59,77,017
C-Pace Manesar Expenses	1,07,40,253	60,85,217
CPC Manesar Expenses	56,68,025	44,15,366
TOTAL	9,77,91,632	10,15,06,923

EXCEPTIONAL ITEMS

NOTE - 28
(Amount in Rs.)

PARTICULARS	For the year ended	
	31st March 2026	31st March 2025
Exceptional Items Includes:		
Income		
(i) Prior Period Income	1,23,741	83,03,216
(ii) Excess Provisions Written Back	4,23,20,366	1,27,73,917
(iii) Surplus on Disposal of Asset (Building)	-	3,64,74,048
Sub-Total (a)	4,24,44,107	5,75,51,181
Expenses		
(i) Prior Period Expenses	4,51,494	45,87,834
(ii) Litigation Settlements of Vendors/ Ex-Employees	1,13,42,599	-
(iii) Loss on Disposal of Assets/ Stock	20,10,058	93,097
(iv) Employee Benefit Expenses (Liability towards Fixed Term Employees for Gratuity as per new Labour Laws [Refer Note No. 29-2 (B) (6)])	18,02,153	-
Sub-Total (b)	1,56,06,304	46,80,931
TOTAL (a)- (b)	2,68,37,803	5,28,70,250

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

NOTE-29

1. GENERAL INFORMATION

The Institute of Company Secretaries of India ("the Institute or ICSI") having its Head Office at New Delhi, was incorporated by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, on 4th October, 1968, as a Company limited by guarantee licensed under section 25 of the Companies Act, 1956 is recognised professional body in India to develop and regulate the profession of Company Secretaries in India. It is a premier national professional body.

Subsequently, the Ministry of Corporate Affairs, presented a Bill in Parliament to convert the Institute as Statutory Body and passed the Company Secretaries Act, 1980 in terms of which the Institute was converted as "The Institute of Company Secretaries of India" w.e.f. 1st January, 1981 for the purpose of regulating the profession of Company

Secretaries in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the Institute.

For the purpose, the Council has constituted 4 Regional offices, one each at Mumbai, Kolkata, Chennai and New Delhi, 4 Centre for Corporate Governance Research and Training at Mumbai, Hyderabad, Kolkata and Manesar and 76 chapters (including 7 Evolving Chapters) across India.

Institute functions under the jurisdiction of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The Institute provides high quality education to the students of Company Secretaries (CS) Course and sets best quality standards for CS Members.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

(A) ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation of Financial Statements

The Financial Statements are drawn up under historical cost convention and going concern basis and have been prepared in accordance with applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and generally accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP). All income & expenses are accounted on accrual basis unless otherwise stated. The accounting policies adopted in preparation of the financial statements consistent with applied by the Institute and are consistent with those used in previous year unless otherwise stated.

2. Uses of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) require management to make estimates and assumptions which affect the reported amounts of assets and liabilities and the reported income & expenditure and the disclosure of contingent liabilities at the date of Financial Statements and the reported amount of revenues and expenses during the year, actual results could differ from those estimates. Difference between the actual result and estimates are recognised in the period in which results are known/ materialised.

3. Basis of Classification of Current and Non-Current

Assets and Liabilities in the balance sheet have been classified as Current or Non- Current.

An Asset has been classified as Current if, it is expected to be realized in, or is intended for sale in the normal operating cycle, or it is held primarily for the purpose of being traded, or it is expected to be realized within twelve months after the reporting date, or it is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date.

All other Assets have been classified as Non-Current.

A Liability has been classified as Current when, it is expected to be settled in the normal operating cycle, or it is held primarily for the purpose of being traded, or it is expected to be settled within twelve months after the reporting date, or the Institute does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months.

All other Liabilities have been classified as Non-Current.

An operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash & cash equivalents.

4. Revenue Recognition

- a. The Entrance Fee is collected at the time of admission of a person as a Member and is directly credited to “Capital Reserve”.
- b. Fees (net of goods and service tax) received from Members are accounted for on cash basis; however, fees received in advance are carried over as a liability.
- c. Fee from students is recognised on cash basis.
- d. Examination fee is recognised in the year in which the examination is conducted.

- e. Income from sale of publications and other related items are recognised when the risks and rewards in the property are transferred to the buyer which is normally coincides with delivery of goods.
- f. Income from Investments
 - i) Dividend on investments is recognised on receipt basis.
 - ii) Income on interest-bearing securities and fixed deposits is recognised on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rates applicable on accrual basis.
- g. Receipt of Income/ Expenditure for Programmes/ Seminars is recognised on accrual basis in the Income & Expenditure Account.
- h. Donations –
 - (i) The amounts of voluntary contributions / donations received with a specific direction from the donors that they form the part of the Corpus are credited to Corpus Fund.
 - (ii) Donations received specifically are credited to the specific fund account.
 - (iii) Other donations are treated as income.

5. Investments-

- a. Investments are initially recorded at cost and the cost includes acquisition costs such as brokerage, fees and duties. Accrued interest paid at the time of purchase is set off against receipt of interest.
- b. Long term investments including Mutual Funds are carried at cost including acquisition expenses and diminution in value, other than temporary, if any, is provided for.
- c. Current investments are carried at lower of cost or fair value.
- d. Investments purchased at a premium are carried to the Balance sheet at face value and premium amounts amortized proportionately over the remaining tenure of investments.

6. Property, Plant and Equipment (PPE) / Depreciation and Amortization-

- a. Property, Plant and Equipment is recognised when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Institute and the cost of the item can be measured reliably. Property, Plant and Equipment are carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost of Property, Plant and Equipment comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use. Other incidental expenses attributable to acquisition of qualifying Property, Plant and Equipment up to the date the asset is ready for its intended use are also capitalised.
- b. Property, Plant and Equipment excluding Land are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.
- c. Intangible assets are recognised when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at historical cost less accumulated amortization and impairment losses, if any. The cost of intangible assets comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses attributable to acquisition of qualifying assets up to the date the asset is ready for its intended use.

Subsequent expenditure on intangible assets after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

- d. Land acquired on perpetual lease as well as on lease for over 99 years is treated as freehold land. Land acquired on lease for 99 years or less is treated as leasehold land.
- e. Freehold land is stated at cost. Leasehold land is stated at the amount of premium paid inclusive of stamp duty and registration charges for acquiring the lease rights. The value of leasehold land is amortized over the period of lease as

per straight line method.

- f. Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided on the Written Down Value method at the following rates as approved by the Council, based on the useful life of the respective assets:

Item	%
Buildings	5
Furniture and Fixtures	10
Lifts/Air Conditioners/Other Equipment	15
Vehicles	20
Computers& Mobiles	40

- g. Depreciation on additions to Fixed assets is provided on monthly pro-rata basis. No depreciation is charged in the year of sale.
- h. Fixed Assets costing Rs. 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase.
- i. Library books are depreciated at the rate of 100% in the year of purchase.
- j. Intangible Assets (Software) are amortized equally over a period of three years as per straight line method.
- k. Gain or Losses arising from sale/disposal / de-recognition of an asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the statement of Income & Expenditure Account of the relevant year.

7. Inventories

Inventories of papers, consumables, publications, study materials etc. are valued at lower of cost or net realizable value. The cost is determined on FIFO basis. However, inventories older than 1 year are valued at Rs. 1 only considering slow moving/non- moving/obsolete. Stock of Answer Books is charged off to the income and expenditure account in the year of purchase and valued at Nil at the end of the year.

8. Foreign Currency Transactions

- a. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount at the exchange rate prevailing as on the date of transactions.
- b. All incomes and expenses are translated at average rate. All monetary assets / liabilities are translated at the year-end rates whereas non-monetary assets are carried at the rate on the date of transaction.
- c. All incomes or expenses on account of exchange rate difference are recognised in the Income and Expenditure Account.

9. Employee Benefits

Defined Contribution Plan

- a. Contributions to Provident Fund Trust maintained by the Institute/ Contribution to National Pension Scheme (PFRDA) are recognised as expenses.

Defined Benefit Plan

- a. Contribution to Gratuity Fund Trust is made on the basis of valuation provided by LIC and recognised as an expense as per AS-15 (Revised).
- b. Contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation and recognised as an expense as per AS-15 (Revised).
- c. Provision for leave encashment is made on the basis of valuation provided by LIC and recognised as an expense as per AS-15 (Revised).

10. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the Balance Sheet comprise of cash at banks and in hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less including flexi deposit linked with bank account, which are subject to an insignificant risk of changes in value.

11. Cash Flow Statement

Cash Flows are reported using Indirect Method as set out in Accounting Standard -3 “Cash Flow Statements” whereby Surplus/(Deficit) before tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flow from operating, investing and finance activities of the Institute are segregated based on the available data and information.

12. Current Assets, Loans & Advances

Current Assets, Loan & Advances are stated in the Balance sheet on the assumption that on realization in the ordinary course of activity, the value will be equal to the aggregate amount shown.

Sundry Debtors & Advances outstanding for more than three years and doubtful for recovery in the opinion of management are provided for and stated net of provisions in the books of accounts.

13. Provisions

A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value other than staff welfare such as Gratuity, Leave Encashment and Pension and are determined based on best estimate required to settle the obligations at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

14. Grants / Reimbursement of expenses and Subsidy on Sale of Publications to Regional Offices & Chapters

Annual grants, reimbursement of expenses and subsidy on sale of publications to the Regional Offices and Chapters are accounted for on cash basis.

15. Contribution/Grants to Approved Funds/Institutions/Organizations

Allocation /Contributions to ICSI Students Education Fund Trust, ICSI National Award for Corporate Governance, ICSI Employees Medical Hospitalization Trust, Company Secretaries Benevolent Fund, ICSI Employees Benevolent Fund, Performance-related Incentive Fund, Professional Development Fund and Infrastructure Fund, are made based on the amount, as approved by the Council from time to time.

16. Allocations / Transfer to Reserves and Surplus and Earmarked Funds

- a. Grant for Building & Other Specific Funds received during the year is directly taken to General Reserve/ Specific Fund to the extent of unutilized amount.
- b. Income from investment of earmarked funds is allocated to the respective earmarked funds @8.00% p.a. on the average of Opening & Closing balances and the amount utilized therefrom is debited to such funds.

17. Old outstanding amounts under the heads of “Earnest Money Deposits, Retention Money, Security Deposits and Stale Cheques”

Undisputed amount outstanding for more than three years under the head of Earnest Money Deposits, Retention Money, Security Deposits and Stale Cheques remaining unpaid at the end of financial year is being written back and treated as Income for the year. Any subsequent claim out of the written back amount is being paid in the year of claim and booked as expenses for the year.

(B) NOTES TO ACCOUNTS**1. Contingent Liabilities**

(a) Claims against the Institute not acknowledged as debts:

(Amount in Rupees)

Sl. No.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
1	Income Tax Demand raised by ACIT for AY 2021-22 under appeal before CIT (A) against which TDS of Rs. 72,55,653/- has been withheld.	90,90,74,526/-	Nil
2	GST Demand raised by Dy. Commissioner, G. B. Nagar, U.P. vide order dated 30 th December, 2025 for FY 2018-19 under appeal before Commissioner-A (A-II) for which hearing has been held and order awaited.	52,70,040/-	Nil
3	GST Demand raised by Dy. Commissioner, G. B. Nagar, U.P. vide order dated 29 th June, 2025 for FY 2021-22 under appeal before Commissioner-A (A-II), hearing awaited.	5,66,58,342/-	Nil
4	Property Tax matter	35,531/-	35,531/-
5	Demand from TGIICL	1,36,73,413/-	1,36,73,413/-
6	Vendors claim under dispute	23,11,515/-	1,19,74,515/-
7	Others – Claims against Full & Final Settlement	89,729/-	89,729/-
	Total	98,71,13,096/-	2,57,73,188/-

(b) TRACES defaults pending adjustments with Income Tax Authorities amounting to Rs. 8,800/- (P.Y. Rs. 74,590/-).

2. An agreement was executed between the Institute and M/s Gurukul Online Learning Solutions Private Limited (GOLS) for e-learning for the Students of the Institute on Built, Operation and Transfer (BOT) basis. The agreement expired on 13.09.2015. GOLS failed to render accounts to the Institute from July, 2015 and also failed to transfer the portal to ICSI. Both the parties approached the Hon'ble Delhi High Court for initiating arbitration proceedings. Hon'ble High Court vide its order dated 06.03.2017 directed the parties to appear before Delhi International Arbitration Centre.

Institute has filed its statement of claim for Rs. 43,24,920/- towards its dues and Rs. 2,00,00,000/- towards damages. Delhi International Arbitration Centre has appointed Hon'ble Justice M L Mehta as Sole Arbitrator, Delhi Arbitration Council. GOLS has also filed its counter claim of Rs. 32.00 crores approx. in reply to the claim of the Institute.

Justice M L Mehta, Sole Arbitrator vide Award dated 23.01.2021 has rejected the counter claim of the GOLS and passed the award in favour of the ICSI for total sum of Rs. 1,00,89,479/- along with interest @ 8% p.a. on the award amount w.e.f. 22.05.2017 to 23.01.2021, payable within 30 days from the date of award and thereafter with interest @ 8% p.a. till realization. GOLS has also been directed to transfer "ICSI online" portal to the ICSI with complete data base and content within 15 days. However, the GOLS has not complied with the aforesaid award passed by the Sole Arbitrator.

M/s. Gurukul Online Learning Solutions Private Limited (GOLS) in year 2021 had filed a Petition u/s 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1994 against the Arbitration Award dated 23.01.2021 whereby Justice M L Mehta, Sole Arbitrator had rejected the counter claim of (GOLS) and passed an Award in favour of the ICSI. The next date of hearing in the matter is 30.09.2026.

Further, in the meantime, Institute in the year 2021 had filed an Execution Petition for implementation and execution of the Arbitration Award dated 23.01.2021 passed by Mr. Justice (Retd.) M.L. Mehta, Sole Arbitrator, Delhi International Arbitration Centre, New Delhi, in favour of the Award Holder (ICSI). The said Execution Petition was disposed of vide order dated 12th May, 2026 with the liberty to file an appropriate Execution Petition before the relevant Court, i.e., the High Court which has the competent jurisdiction where

its assets are located.

Accordingly, an Execution Petition has been filed by the Institute before High Court of Judicature at Bombay and the same is under objection in the registry of the High Court of Judicature at Bombay. The objections are being removed and matter is likely to be listed in the month of September, 2026 for hearing.

3. Capital Commitments and Other Commitments

- (i) The estimated amount for contracts remaining to be executed on capital account, net of advances is Rs. 32,08,97,773/- as on 31.03.2026 (P.Y. Rs. 18,63,89,221/-).
- (ii) Estimated amount of other commitments related to procurements of goods and services in the ordinary course of Institute functioning are not disclosed to avoid excessive details.

4. Management is of the opinion that except the assets retired from the active use/ discarded and written off during the year, no further impairment of any other assets as contemplated in Accounting Standard – 28 is required at the year end.

5. Employee Benefits

The disclosure of 'Employee Benefits' as defined in the Accounting Standard-15 are as under:-

Defined Contribution Plan

Employer's contribution to Defined Contribution Plan such as Provident Fund/ National Pension Scheme (NPS) is charged off during the financial year.

Employee's Provident Fund is administered by 'ICSI Employee's Provident Fund Trust'. National Pension Scheme (NPS) is managed by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

Defined Benefit Plan

(i) Gratuity

The Employer's Gratuity Fund Scheme managed by the Life Insurance Corporation of India is a 'Defined Benefit Plan'. The present value of obligation is determined by LIC based on actuarial valuation using Projected Unit Credit (P.U.C.) method as defined in the Accounting Standard-15. Details of the Gratuity Plan are as follows:-

(Rs. In Lacs)

Particulars	25-26	24-25	23-24	22-23	21-22
(I) Changes in present value of Obligation:					
Present value at the beginning of the year	2,679	2,173	2,050	1,549	-
Interest cost	194	158	149	112	-
Current service cost	123	99	96	95	-
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	(42)	398	(20)	296	-
Benefits paid	(220)	(148)	(101)	(2)	-
Present Value at the year end	2,734	2,679	2,173	2,050	-
(II) Changes in fair value of Plan Assets:					
Fair value of Plan Assets at beginning of the year	2,217	2,233	1,944	1,694	-
Expected/Actual return on Plan Assets	160	136	142	125	-
Contributions	3	-	256	251	-
Benefits paid	(220)	(148)	(101)	(117)	-
Fund Management Charges	-	(4)	(8)	(8)	-
Fair value of Plan Assets at the end of the year	2,159	2,217	2,233	1,944	-
(III) Amounts recognised in the Balance Sheet:					
Present value of Obligation at the end of the year	2,734	2,679	2,173	2,050	-

Fair value of Plan Assets as at the end of the year	2,159	2,217	2,233	1,944	-
Funded status	(575)	(463)	60	(106)	-
Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(575)	(463)	60	(106)	-
(IV) Expenses recognised in the Income & Expenditure Account:					
Current Service Cost	123	99	96	95	-
Interest Cost	194	158	149	112	-
Expected return on Plan Assets	(160)	(136)	(142)	(125)	-
Fund Management Charges	-	4	8	-	-
Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the year	(42)	398	(20)	296	-
(Gain) / Deficit to be recognized	115	522	90	378	-
Add:- Opening excess/deficit Amount/Plan/ Funded Asset available over present obligation	-	(60)	(150)	(392)	-
Net (Gain) / Deficit	115	463	(60)	(13)	-
(V) Funded Investment Details:					
Investment Details- Funded with LIC of India (100%)	2,159	2,217	2,233	1,944	-
(VI) Actuarial Assumptions:					
Discount Rate	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%	-
Future Pay Increase	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	-
Return on Plan Assets	7.63%	7.68%	6.78%	7.01%	-

(ii) Pension

‘Pension’ is administered by a separate Trust named as ‘ICSI Employees’ Pension Fund Trust’ and the actuarial valuation of Pension Benefit Plan Liability has been done by following P.U.C. method in terms of the Accounting Standard – 15. Details of the Pension Fund are as follows:-

(Rs. In Lacs)

Particulars	25-26	24-25	23-24	22-23	21-22
(I) Changes in present value of Obligation:					
Present value of obligations as at the beginning of the year	5,432	5,376	5,301	7,175	7,119
Interest cost	380	387	399	517	463
Current service cost	38	42	45	47	117
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	(229)	(101)	(103)	(837)	(278)
Benefits paid	(287)	(272)	(266)	(1,601)	(245)
Present Value at the year end	5,335	5,432	5,376	5,301	7,175
(II) Changes in fair value of Plan Assets:					
Fair value of Plan Assets at beginning of the year	5,956	5,801	5,632	6,602	6,356
Expected/Actual return on Plan Assets	459	472	395	462	477
Benefits paid	(287)	(272)	(266)	(1,601)	(245)
Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	(33)	(44)	39	168	15
Fair value of Plan Assets at the end of the year	6,095	5,956	5,801	5,632	6,602
(III) Amounts recognised in the Balance Sheet:					
Present value of Obligation at the end of the year	5,335	5,432	5,376	5,301	7,175
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	6,095	5,956	5,801	5,632	6,602
Funded status	761	524	425	331	(572)
Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	761	524	425	Nil	(572)

(IV) Expenses recognised in the Income & Expenditure Account:					
Current Service Cost	38	42	45	47	117
Interest Cost	380	387	399	517	463
Expected return on Plan Assets	(459)	(472)	(395)	(462)	(477)
Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the year	(196)	(56)	(142)	(1,005)	(293)
(Gain) / Deficit to be recognized	(237)	(99)	(94)	(904)	(190)
Add:- Opening excess/deficit Amount/Plan/ Funded Asset available over present obligation	-		(331)	331	-
Net (Gain) / Deficit	(237)	(99)	(425)	(572)	(190)
(V) Funded Investment Details:					
Funded Investment Details	Central and State Government Securities, PSU Bonds, Fixed Deposits with Scheduled Banks and Mutual Funds.				
(VI) Actuarial Assumptions:					
Discount Rate	7.25%	7.00%	7.20%	7.50%	7.20%
Future Pay Increase	10.00%	11.00%	11.00%	8.50%	8.50%
Return on Plan Assets	7.70%	7.70%	8.13%	7.00%	7.00%

(iii) Leave Encashment

The Leave Encashment Fund Scheme managed by the Life Insurance Corporation of India is a 'Defined Benefit Plan'. The present value of obligation is determined by LIC based on actuarial valuation using Projected Unit Credit (P.U.C.) method as defined in the Accounting Standard-15. Details of the Leave Encashment are as follows:-

(Rs. In Lacs)

Particulars	25-26	24-25	23-24	22-23	21-22
(I) Changes in present value of Obligation:					
Present value of obligations as at the beginning of the year	2,394	2,068	1,541	1,592	1,484
Interest cost	174	150	169	115	104
Past Service cost	-	-	796	Nil	Nil
Current service cost	248	225	169	90	90
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	(89)	190	(7)	(95)	168
Benefits paid	(318)	(238)	(601)	(161)	(254)
Present Value at the year end	2,408	2,394	2,068	1,541	1,592
(II) Changes in fair value of Plan Assets:					
Fair value of Plan Assets at beginning of the year	981	1,144	1,294	1,143	1,242
Expected/Actual return on Plan Assets	61	77	74	83	80
Contributions	4	-	381	325	75
Benefits paid	(318)	(238)	(601)	(251)	(254)
Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	-	-	0	Nil	Nil
Fund Management Charges	-	(2)	(4)	(5)	Nil
Fair value of Plan Assets at the end of the year	728	981	1,144	1,294	1,143
(III) Amounts recognised in the Balance Sheet:					
Present value of Obligation at the end of the year	2,408	2,394	2,068	1,541	1,592
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	728	981	1,144	1,294	1,143
Funded status	(1,680)	(1,413)	(924)	(247)	(449)
Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	-	-	-	(247)	(449)

6.

(IV) Expenses recognised in the Income & Expenditure Account:					
Current Service Cost	248	225	169	90	90
Interest Cost	174	150	169	115	104
Expected return on Plan Assets	(61)	(77)	(74)	(83)	(80)
Past Service cost	-	-	796	Nil	Nil
Fund Management Charges	-	2	4		168
Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the year	(89)	190	(7)	(95)	282
(Gain) / Deficit to be recognized	271	490	1,058	27	-
Less:- Allocated Return on Earmarked Funds	(422)	(375)	(338)		-
Add:- Opening excess/deficit Amount/Plan/ Funded Asset available over present obligation	-	(0)	(796)	(27)	(52)
Net (Gain) / Deficit	(150)	115	(76)	0	230
(V) Funded Investment Details:					
Investment Details- Funded with LIC of India (100%)	728	981	1,144	1,294	1,143
(VI) Actuarial Assumptions:					
Discount Rate	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%	7.00%
Future Pay Increase	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	8.50%
Return on Plan Assets	7.63%	7.68%	6.78%	7.01%	7.00%

Employees Benefit Expenses for Fixed Term Employees (FTEs) (Non-Funded)-

On November 21, 2025, the Government of India notified provisions of the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, ('Labour Codes') which consolidate twenty-nine existing Labour laws into a unified framework governing employee benefit during employment and post-employment. The Labour Codes, amongst other things, introduced changes including a uniform definition of wages and enhanced benefits relating to leave.

The Institute had reassessed the definition of wages of employee benefits, financial implications of these changes which had resulted an increase on account of past service cost for Rs. 18,02,153/- [Refer Note- 28] and on account of current service cost for Rs. 17,11,491/- [Refer note 19 for Rs. 11,93,621/- and note 26 for Rs. 5,17,870/-] due to implementation of Wage Code for Gratuity liability totaling Rs. 35,13,644/- [Refer Note-4] as determined by the actuary as per AS-15 (revised). The Institute continues to monitor the developments pertaining to Labour Codes and will evaluate impact, if any, on the measurement of liability pertaining to employee benefits Expenses for Fixed Terms Employees (FTEs) (Non-Funded) which would be implemented after Rules to be notified by the State Government as applicable to the Institute.

Details of the Gratuity liability (non-funded) as per report of the actuary is as follows:-

(Rs. In Lacs)

Particulars	25-26	24-25
(I) Changes in present value of Obligation:		
Present value at the beginning of the year	-	-
Past Service cost	18.02	-
Current service cost	17.11	-
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	-	-
Benefits paid	-	-
Present Value at the year end	35.14	-
(II) Changes in fair value of Plan Assets:		
Fair value of Plan Assets at beginning of the year	-	-
Expected/Actual return on Plan Assets	-	-
Contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Fair value of Plan Assets at the end of the year	-	-
(III) Amounts recognised in the Balance Sheet:		
Present value of Obligation at the end of the year	35.14	-
Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(35.14)	-

(IV) Expenses recognised in the Income & Expenditure Account:		
Past Service cost	18.02	-
Current service cost	17.11	-
Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the year	-	-
(Gain) / Deficit to be recognized	-	-
Net (Gain) / Deficit	35.14	-
(V) Actuarial Assumptions:		
Discount Rate	7.25%	-

7. Disclosure relating to dues payable to suppliers registered under MSMED Act, based on the information available with the Institute is as under :

(Rs. In lacs)

Particulars	31 March 2026	31 March 2025
(a) Amount remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year:		
Principal	132.01	81.42
Interest	-	-
Total	132.01	81.42
(b) The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	-	-
(c) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act.	-	-
(d) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year.	-	-
(e) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act.	-	-

8. The Institute has issued communication to various parties/ vendors for their balance confirmation at the year end. Confirmation from a few of the parties are awaited.
9. The Institute operates predominantly in India and in one geographical segment as economic condition of whole India is same, further the core objective of Institute is development of profession of Company Secretary in India. Thus, all its operations fall under one segment only as per the meaning of AS 17, Segment Reporting.
10. Valuation of closing inventories of publications and other items are accounted for as per the accounting policies followed by the Institute based on the physical verification at the year end at HQ/ CCGRT's/ Regional offices/Chapters and necessary adjustments is being made in the books of accounts.
11. The break-up of Building Loan to Regional Offices and Chapters outstanding as at 31st March, 2026 are as under [Refer Note 9(i) (a)]:

(Amount in Rupees)

Sl. no.	Location	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
1	Faridabad Chapter	5,00,000	5,00,000
2	Kolhapur Chapter	--	14,40,000
	Total	5,00,000	19,40,000

12. Income Tax-

(i) The Institute of Company Secretaries of India has been registered u/s 12A of the Income Tax Act, 1961 and Income Tax returns has been filed u/s 11/12 of the Income Tax Act.

(ii) For the A.Y. 2021-22, vide Intimation u/s 143 (1) dated 14th December, 2022, CPC has raised demand of Rs. 81,99,10,138/- (including Interest) due to non- allowance of benefit of exemption u/s 11(2) of the Act amounting to Rs.

1,20,00,31,900/-. However, after filing appeal before CIT (A), an amount of Rs. 1,10,94,73,718/- has been allowed u/s 11(2) and thus restricted the addition of Rs. 9,05,58,182/-. Aggrieved by the order of the CIT (A), the Institute has filed an appeal before the Hon'ble ITAT Delhi.

Hon'ble ITAT Delhi vide order dated 27th March, 2024 directed the Assessing Officer to carry out the necessary verification of the claim and modify the assessment order. Accordingly, Assistant Commissioner of Income Tax, Circle Exemption 2(1), Delhi vide order u/s 254 r.w.s section 143 (1) dated 21st July, 2025, has given effect of the Order of Hon'ble ITAT by allowing the relief of Rs. 9,05,58,182/-, resulting into net assessable Income as Nil, however, no effect of TDS refund of Rs. 72,55,653/- due was given.

Further, ACIT has sought additional information / documents including investment details during December 2025 to March 2026 for which various replies were submitted by the Institute. Subsequently, an e-signed order was passed by ACIT dated 31st March 2026 u/s 254 r.w.s section 143 (1) and a demand has been raised due to non-allowance of benefit of exemption u/s 11(2) of the Act amounting to Rs. 1,20,00,31,900/- and treated the entire exemption as Income with demand of Rs. 90,90,74,526/- including interest.

Aggrieved against the aforesaid order, Institute has filed an appeal to before CIT (Appeal) on 28th April, 2026 for waiver of demand. The said appeal is yet to be heard.

(iii) For the A.Y. 2022-23, CPC vide intimation u/s 143(1) dated 7th March, 2023 has completed the assessment on returned income and a refund of Rs. 6,37,96,900/- including interest was granted / received.

Subsequently, ACIT, Circle Exemption 2(1), Delhi vide Notice u/s 148A (1) dated 27th March, 2026 of the Income Tax Act, 1961 has initiated the assessment proceeding u/s 147 of the Act. Against the aforesaid notice u/s 147 dated 27th March, 2026, Institute has filed e proceeding response on 20th June, 2026.

(iv) For the A.Y. 2023-24, CPC vide intimation u/s 143(1) dated 13th November, 2024 has completed the assessment on returned income and a refund of Rs. 6,68,09,430/- including interest was granted/ received.

Subsequently, ACIT, Circle Exemption 2(1), Delhi vide Notice u/s 148A (1) of the Income Tax Act, 1961 dated 27th March, 2026 has initiated the assessment proceeding u/s 147 of the Act. Against the aforesaid notice u/s 147 dated 27th March, 2026, Institute has filed e proceeding response on 24th June, 2026.

(v) For the A.Y. 2024-25, CPC vide intimation u/s 143(1) dated 17th April, 2025 has completed the assessment on returned income and TDS refund of Rs. 2,55,12,170/- was granted against refund due as per ITR of Rs. 6,15,23,106/- resulting into short refund of Rs. 3,75,68,016/- due to credit mismatch.

Against the credit mismatch, the Institute had filed rectification u/s 154 of the Income Tax Act, 1961 dated 16th January, 2026. Thereafter, ACIT, Circle Exemption 2(1), Delhi vide Notice u/s 148A (1) of the Income Tax Act, 1961 dated 27th March, 2026 has initiated the assessment proceeding u/s 147 of the Act. Against the aforesaid notice u/s 147 dated 27th March, 2026, Institute has filed e- proceeding response on 24th June, 2026.

13. Goods and Services Tax (GST)-

(i) In respect of FY 2018-19, Deputy Commissioner Gautam Buddha Nagar UP vide order dated 30th December 2025 raised a demand of ₹52.70 lakh (comprising of tax Rs.15.95 Lakhs, interest Rs.20.80 Lakhs, and penalty Rs.15.95 Lakhs) under Section 74 of the CGST/ UPGST Act on account of non-payment of GST on sponsorship income reported in Table 5(c) of GSTR-9. Institute has submitted detailed replies, reconciliation along with the relevant supporting for figures reported in the GST returns. However, the demand was confirmed by the Department. Institute has filed an appeal on 27th March 2026 before the first Additional Commissioner (Appeal II) Noida U.P under section 107. The appeal has been heard on 4th July for which the order is awaited.

(ii) In respect of FY 2021-22, Deputy Commissioner Gautam Buddha Nagar UP vide order dated 27th December 2025 raised a demand of Rs. 566.58 Lakhs (comprising of Tax Rs.303.80 Lakhs, Interest Rs. 232.40 Lakhs, Penalty Rs.30.38 Lakhs) against the Institute u/s 73 of the CGST Act based on discrepancies relating to Reverse Charge Mechanism (RCM) transactions, credit/debit notes, input tax credit reconciliation and reporting differences in GST returns (GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-9 and GSTR-9C). Institute has submitted detailed reconciliations along with the supporting documents with a request to drop the demand; however, the demand was confirmed by the adjudicating authority.

Against the aforesaid order, appeal was filed before the Commissioner Appeal (Appeal II) Noida U.P on 25th March 2026 and the same was admitted. The hearing fixed on 4th May 2026 could not be heard, next date of hearing is awaited.

14. Institute has paid an amount of Rs. 2,88,56,250/- to Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Ltd. (now

Telangana Industrial Infrastructure Corporation Ltd.) towards cost of land for allotment of total area of 4918 sqmt (1.215Acre) at IP-Uppal, Hyderabad out of which:

- (i) Agreement to Sale executed and registered for 3140 sq. mt. in 1st phase;
- (ii) Supplementary agreement to sale executed and registered for 912 sq. mt. in 2nd phase; and
- (iii) Execution of agreement to Sale and possession for 866 sq. mt. in 3rd phase is yet to be done.

Request was made to Telangana Industrial Infrastructure Corporation Ltd. for execution of sale deed. Further, a Writ Petition vide no. 31594/2014 dated 18-10-2014 has been filed by Uppal Industrial Association in the High Court of State of Telangana for Interim stay on construction work which was vacated by the court vide order dated 24-08-2015 in favor of the Institute. Finally, Court has dismissed the writ petition vide order dated 15th March, 2024.

The Institute, while approaching TGIICL for execution of Sale Deed for the land allotted in 1st phase, the Telangana Industrial Infrastructure Corporation Ltd. in response, issued a letter dated 20th July, 2024 demanding payment of Rs. 1,15,87,638/- towards Delay Condonation fee @3% process fee for each delayed year and GST @18% of Rs. 20,85,775/- ; i.e., total amount Rs. 1,36,73,413/- against delay in execution of Sale Deed of 1st phase of Land.

Further, the Council has approved to deposit the penalty amount of Rs. 1,36,73,413/- to Telangana Industrial Infrastructure Corporation Ltd. (TGIICL), '*under protest*', and that, where the penalty amount required to be deposited under protest is less than the aforesaid amount, the approval shall be deemed to be restricted to such lower amount.

15. The Institute had entered into an Agreement for Sale dated 31.03.2015 for purchase of one portion of Fifth Floor of multi storied building "THE GRACE (Previous Name – NASA)" in Indore for a total consideration of Rs. 3,21,00,000/- and a sum of Rs. 80,25,000/- was paid as part payment of the total agreed consideration. As per the terms of the aforesaid Agreement for Sale, Mr. Sirajuddin Malik and others (the Defendants) had to provide a NOC from MPFC and the Occupancy Certificate from Indore Municipal Corporation within the period of four months (15 days extension period) from the date of Agreement for Sale. The Sale Deed could not be executed because the Defendants failed to provide NOC from MPFC and the Occupancy Certificate in compliance of the terms of the Agreement for Sale dated 31.03.2015. Total expenditure incurred in this regard including stamp duty and registration is Rs. 83,03,000/-. Amount is kept and shown as Capital Work in Progress (CWIP) as matter is under sub judice.

The Institute had filed a Suit for Declaration and Permanent Injunction before Hon'ble District Court, Indore against Mr. Sirajuddin Malik, Ms. Salma, Mr. Murtuza Malik and M/s. Kabeer Reality Pvt. Ltd., (herein after referred to as Defendants) for Specific performance of an Agreement for Sale dated 31.03.2015.

On 27.09.2025, the Court directed the defendants to pay the total earnest money amounting to Rs. 80,25,000/- (Rs. Eighty Lakh, Twenty-Five Thousand only) to the Institute within 60 days with an interest of Rs. 50,72,240/- which is at the rate of 12% per annum from the date of execution of the agreement i.e., 31.03.2015 till the date of filing of the Suit and at the rate of 6% per annum from the date of filing of the Suit till the date of payment. In addition, the defendants were directed to pay Rs. 6,28,800/- (Rupees Six Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred only) to the Institute for the registration expenses incurred before execution of the agreement, professional service charges and legal opinion and compensation for cancellation of agreement. Total amount payable as per above is Rs. 1,37,26,040/-.

An Execution Petition has been filed by the Institute as the Defendants have failed to comply with the aforesaid Order. On 15.07.2026, by not depositing the decretal amount within the stipulated time, the Learned Executing Court has been pleased to issue a Recovery warrant against the judgment-debtor. Next date of hearing in the matter is 27.09.2026.

Further, the Defendants have challenged the aforesaid Order / Judgement dated 27.09.2025 before Hon'ble Madhya Pradesh High Court (Indore Bench), whereby the court has granted interim protection to the extent of the amount of Rs. 6,28,800/- and the operation of the Trial Court's Order regarding the said amount has been stayed till the next date of hearing 09.09.2026 before the Hon'ble High Court (copy of the Appeal is yet to be received in the Institute).

In addition, a Criminal Complaint (Criminal Suit- Trial no. 3135 of 2017- ICSI Vs. Sirajuddin Malik & Others) has also been filed against Mr. Sirajuddin Malik, Mrs. Salma and Mr. Murtaza Malik of M/s Kabeer Reality Pvt. Ltd., on 4th July 2017 in the court of First-Class Magistrate (Criminal), Indore under Section 420, 416, 120-B, 323, 294 and 506 of IPC for cheating and fraud in respect of Agreement for Sale dated 31.03.2015. Next date of hearing is 18.09.2026.

16. The Financial Statements of the Institute for the year ended 31st March, 2026 has been prepared as per the existing format in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

17. The information required under Accounting Standard-18 with respect to Key Management Personnel (KMP) as per

section 16 (1) of the Company Secretaries Act, 1980 (as amended from time to time) yet to be notified by the competent authority and hence disclosure is not required till the notification of the same by the competent authority.

18. In case of Inter Unit Balances relating to Assets and Liabilities of Regional Offices with their respective chapters, an amount of Rs. 3,52,573/- as on 31st March, 2026 (Net payable by ROs to Chapters before the year end in respect of share of Surplus of Programmes etc. which was not considered by the Chapters) has been considered in consolidation of the books of accounts of the Institute.

19. The details of earning of Income & Expenditure incurred in foreign currency are as under:

Particulars	Currency	FY 2025-26		FY 2024-25	
		Foreign Currency	Indian Rupees	Foreign Currency	Indian Rupees
a. Earnings in Foreign Currency					
Delegate Fees	SGD	--	--	500	29,292
International affairs and Conferences	USD	13,565	12,07,487	--	--
Total INR			12,07,487		29,292
b. Expenditure in foreign Currency					
Membership fee	GBP	675	86,820	2,970	3,21,614
	USD	--		1,5000	13,13,452
International affairs and Conferences	AED	54,032	13,06,892	75,189	17,92,821
	AUD	31,045	18,17,084	3,679	2,11,879
	SGD	--		2,500	1,60,217
Dubai Exam Centre	AED	18,024	4,67,403	19,562	4,83,991
PMQ Examination	AED	5,250	1,47,217	--	--
Total INR			38,25,416		42,83,974

20. Previous year's figures have been regrouped/ rearranged/ recast wherever considered necessary to make it comparable with the current year's classification/ disclosures.

For and on behalf of the Council of the Institute

Shree Prakash
Director (Finance)

CS Asish Mohan
Secretary

CS Dwarakanath Chennur
Vice President

CS Pawan G Chandak
President

As per our report of even date

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
FRN 000038N

(M. P. Thakur)
Partner
(Membership No. 052473)

Place: New Delhi
Date: 29.08.2026

For S K Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN 001135N

(S. Murthy)
Partner
(Membership No. 072290)

Place: New Delhi
Date: 29.08.2026